

सीवाईसी (एसईसी) - 102

बौद्धिक संपदा मुद्दे

और

साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य

विधि विद्यालय



उत्तराखंड ओपन

विश्वविद्यालय

तीन पानी बाईपास रोड, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, हल्द्वानी - 263139 फोन नंबर - 05946 - 261122, 261123 टोल फ्री नंबर

18001804025 फैक्स नंबर - 05946-264232, ईमेल-
info@uou.ac.in, <http://uou.ac.in>

अध्ययन बोर्ड

प्रोफेसर ए.के. नवीन, निदेशक, स्कूल ऑफ लॉ,
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हलद्वानी, नैनीताल।

प्रोफेसर एसडी शर्मा,
विधि संकाय, एसएस जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड।

प्रोफेसर ए.के. पंत,
डीन, विधि संकाय, एसएस जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड।

प्रोफेसर एस.के. चड्ढा,
विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

डॉ. दीपांकु ज्योशी, सहायक प्रोफेसर एवं समन्वयक
स्कूल ऑफ लॉ, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हलद्वानी, (नैनीताल)।

इकाई लेखन

यूनिट लेखक	इकाई
[1] सुश्री सपना अग्रवाल, अधिवक्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	इकाई- 1, 2,3,4
[2] डॉ. रजित शर्मा, सहायक प्रोफेसर, लॉ कॉलेज, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून उत्तराखंड	इकाई- 5,6,7
[3] डॉ. अनुपम मन्हास, विभागाध्यक्ष, विधि संकाय कैरियर प्वाइंट, विश्वविद्यालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	इकाई- 8,9,10
[4] डॉ. सुशीम शुक्ला, सहायक प्रोफेसर, लॉ कॉलेज, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून उत्तराखंड	इकाई- 11,12, 13,14

संपादक

डॉ. दीपांकु ज्योशी, सहायक प्रोफेसर और समन्वयक,
स्कूल ऑफ लॉ, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हलद्वानी, (नैनीताल)

कॉपीराइट © उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हलद्वानी, नैनीताल

संस्करण- 2024, सीमित प्रसार के लिए पूर्व-प्रकाशन प्रति

आईएसबीएन-

प्रकाशन- अध्ययन एवं प्रकाशन निदेशालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हलद्वानी, नैनीताल।

ई-मेल: studies@uou.ac.in

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबर स्पेस-भारतीय

परिप्रेक्ष्य

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	इकाई	पृष्ठ सं.
1	सॉफ्टवेयर की तकनीक को समझना	4 - 31
2	इंटरनेट में कॉपीराइट	32 - 52
3	अधिकार क्षेत्र के मुद्दे और कॉपीराइट	53 - 70
4	उल्लंघन, उल्लंघन के उपचार	71 - 107
5	पेटेंट को समझना	108 - 119
6	पेटेंट का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ	120 - 131
7	कंप्यूटर संबंधी पेटेंट पर भारत की स्थिति	132 - 143
8	ट्रेडमार्क को समझना	144 - 152
9	भारत में ट्रेडमार्क कानून	153 - 164
10	इंटरनेट में ट्रेडमार्क	165 - 177
11	डोमेन नाम पंजीकरण	178 - 183
12	डोमेन नाम विवाद और WIPO V डेटाबेस	184 - 191
13	डेटाबेस की सुरक्षा	192 - 199
14	डेटाबेस पर भारतीय कानून	200 - 205

इकाई 1

प्रौद्योगिकी को समझना

सॉफ्टवेयर

संरचना

- 1.1 परिचय
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 विषय
 - 1.3.1 कंप्यूटर विज्ञान – एक परिचय
 - 1.3.1.1 इंटरनेट
 - 1.3.1.2 सॉफ्टवेयर
 - 1.3.2 एल्गोरिदम और कोडिंग
 - 1.3.2.1 सॉफ्टवेयर विकास
 - 1.3.2.2 भाषा मॉडलिंग
 - 1.3.2.3 प्रोग्रामिंग तकनीक
 - 1.3.2.3.1 संरचित प्रोग्रामिंग
 - 1.3.2.3.2 मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग
 - 1.3.2.3.3 ऊपर से नीचे की ओर डिज़ाइन
 - 1.3.2.3.4 नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण
 - 1.3.2.3.5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
 - 1.3.3 कंप्यूटर नेटवर्किंग
 - 1.3.4 नेटवर्क सुरक्षा
- 1.4 सारांश
- 1.5 शब्दावली
- 1.6 एसएक्यूएस
- 1.7 संदर्भ
- 1.8 सुझाए गए पठन सामग्री
- 1.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न
- 1.10 उत्तर SAQS

1.1 परिचय

सॉफ्टवेयर तकनीक इस युग की सबसे तेजी से बढ़ती तकनीक है। 80 के दशक से, इंजीनियरिंग और प्रबंधन दोनों के लिए सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं ने पिछले 25 वर्षों में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया है।

इंटरनेट के आगमन के साथ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में वृद्धि किसी भी कल्पना से परे है।

इंटरनेट पूरी दुनिया को एक गांव में बदल देता है। मानव जीवन का हर पहलू सॉफ्टवेयर की तकनीक से प्रभावित और प्रेरित होता है। इस क्षेत्र में भारी विकास के बावजूद, जैसा कि हम आज देख रहे हैं, ऐसे कई पहलू हैं, जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। रॉबर्ट क्रिगली ने सही कहा है- "अगर ऑटोमोबाइल ने कंप्यूटर के समान विकास किया होता, तो आज एक रोल्स रॉयस की कीमत 100 डॉलर होती, एक गैलन में दस लाख मील चलती और साल में एक बार फटने से उसमें सवार सभी लोग मर जाते"।¹

यद्यपि यह बहुत व्यापक विषय है, फिर भी वर्तमान इकाई में हम सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित हर पहलू या कोने को छूने की कोशिश करेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें समझ सकेंगे:

- कंप्यूटर विज्ञान का सामान्य परिचय
- कंप्यूटर का इतिहास
- कंप्यूटर के घटक
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
- एल्गोरिदम, कोडिंग और सॉफ्टवेयर विकास
- विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग की तकनीकें
- इंटरनेट और इंटरनेट नेटवर्क
- कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर भाषाएँ
- नेटवर्क सुरक्षा

1.3 विषय

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, उपकरण, मॉड्यूल और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन बनाने में मदद करती है। पिछले दशक में यह क्षेत्र नाटकीय रूप से विकसित हुआ है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का समामेलन है। सॉफ्टवेयर/कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एक सामान्य शब्द है जो विकास विधियों, प्रोग्रामिंग भाषाओं और उन्हें समर्थन देने वाले उपकरणों को कवर करता है जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर के विकास में किया जा सकता है।

1.3.1 कंप्यूटर विज्ञान - एक परिचय

कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो डेटा को सार्थक जानकारी में बदलता है। कंप्यूटर मूल रूप से पाँच प्रमुख कार्य करता है, चाहे उनका आकार और बनावट कुछ भी हो। ये हैं 1) यह इनपुट के माध्यम से डेटा या निर्देश स्वीकार करता है, 2) यह डेटा संग्रहीत करता है, 3) यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार डेटा को संसाधित कर सकता है, 4) यह आउटपुट के रूप में परिणाम देता है, और 5)।

कंप्यूटर का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पहले बेबीलोनिया (मेसोपोटामिया) में शुरू होता है, जब एबैकस का जन्म हुआ था, जो एक लकड़ी का रैक था जिसमें दो क्षैतिज तार लगे होते थे और उन पर मोती परोये जाते थे।

यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, जिसे पास्कलाइन कहा जाता था। 50 के दशक की शुरुआत में दो महत्वपूर्ण

इंजीनियरिंग खोजों ने इलेक्ट्रॉनिक-कंप्यूटर क्षेत्र की छवि बदल दी। ये खोजें चुंबकीय कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर-सर्किट एलिमेंट थीं। 1980 के दशक के अंत तक, कुछ

¹ चेरिस्तोफ एबर्ट द्वारा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास।

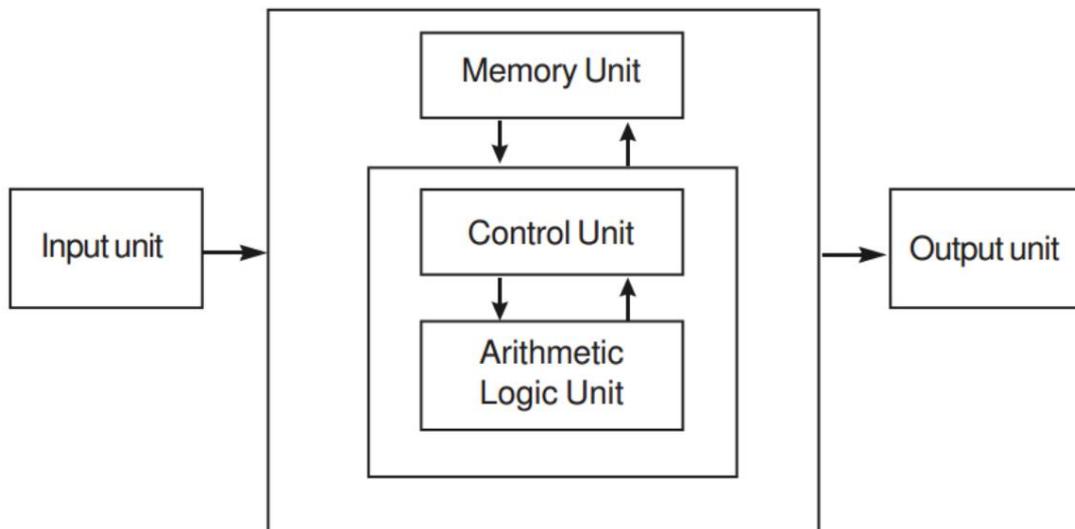
पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसरों द्वारा चलाए जाते थे, जो एक समय में 32 बिट्स डेटा को संभालते थे, तथा प्रति सेकंड लगभग 4,000,000 निर्देशों को संसाधित कर सकते थे।

टूरिंग मशीन

आधुनिक कंप्यूटिंग के पीछे के आधारभूत सिद्धांतों में से एक टूरिंग मशीनों की अवधारणा है³ टूरिंग मशीन, कई अन्य मॉडलों के साथ, सभी कंप्यूटरों के पीछे अंतर्निहित तर्क का प्रतिनिधित्व करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। टूरिंग मशीन (जो सैद्धांतिक निर्माण हैं) एक अमूर्त अवधारणा है जिसका उपयोग एक प्रकार की मशीन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे अनिश्चित स्थान और समय दिए जाने पर, किसी भी चीज़ की गणना करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड की भी। एक साधारण टूरिंग मशीन में सैद्धांतिक रूप से अनंत आकार का एक टेप होता है जिसमें सेल या टेप पर अनुभाग होते हैं। प्रत्येक सेल पर एक प्रतीक होता है, जिसे हेड द्वारा लिखा जाता है, और जो मशीन की वर्तमान स्थिति को संशोधित करता है।⁴

कंप्यूटर के घटक

कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। कंप्यूटर को किसी ऐसी चीज़ की जरूरत होती है जो हार्डवेयर को निर्देश दे कि उसे क्या करना है। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसी के लिए किया जाता है। आंतरिक हार्डवेयर तीन मुख्य कार्य प्रदान करता है। सबसे पहले, यह प्रोसेसिंग कार्यक्षमता प्रदान करता है। कंप्यूटर में मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) है। दूसरी कार्यक्षमता अल्पकालिक डेटा स्टोरेज है।



चित्र - 1. कंप्यूटर का संगठन

यह रैंडम एक्सेस मेमोरी या RAM का उपयोग करके किया जाता है। लंबे समय तक स्टोरेज के लिए हम कई तरह के स्टोरेज माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD।

² विस्तृत जानकारी के लिए देखें यूनिट-3; कंप्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी पर अवलोकन

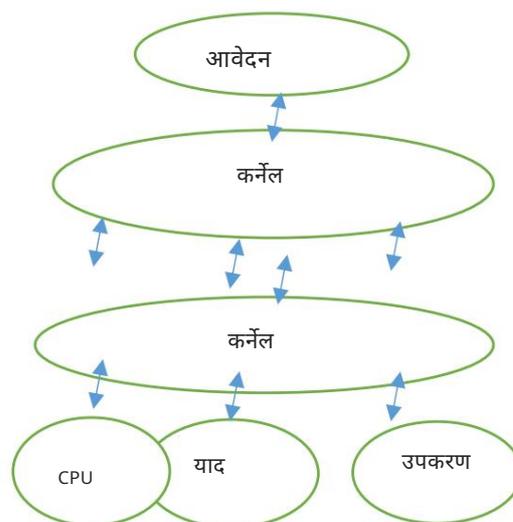
³ इसका नाम कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन टूरिंग के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार टूरिंग मशीन की कल्पना की थी।

⁴ https://en.wikiversity.org/wiki/Introduction_to_Turing_Machines

इनपुट के तीन मुख्य स्रोत हैं- कीबोर्ड, माउस, टचस्क्रीन। कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस को उससे कनेक्ट करना होगा। उदाहरण के लिए- मॉनिटर, ऑडियो, प्रिंटर, प्लॉटर।

गुठली

कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्नेल कहलाता है। कर्नेल CPU की मदद करता है। रैम, हार्ड ड्राइव और अन्य डिवाइस सभी एक दूसरे से बात करते हैं। कर्नेल एप्लिकेशन को जोड़ता है कंप्यूटर के हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर का रूपांतरण (चित्र 2)



चित्र - 2

कर्नेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। सिस्टम में हर चीज़ पर इसका पूरा नियंत्रण होता है। ज़्यादातर, बूटलोडर के बाद, यह स्टार्ट-अप पर लोड होने वाले पहले प्रोग्राम में से एक है। यह स्टार्ट-अप के बाकी हिस्सों के साथ-साथ सॉफ्टवेयर से इनपुट/आउटपुट अनुरोधों को संभालता है, उन्हें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा-प्रोसेसिंग निर्देशों में अनुवाद करता है। यह मेमोरी और कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जैसे बाह्य उपकरणों को संभालता है। कर्नेल अपने कार्य करता है, जैसे कि प्रक्रियाओं को चलाना, हार्ड डिस्क जैसे हार्डवेयर उपकरणों का प्रबंधन करना और इस संरक्षित कर्नेल स्पेस में रुकावटों को संभालना।

6

1.3.1.1 इंटरनेट

इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर में अरबों डिवाइस को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट (TCP/IP) का उपयोग करती है। एक वेब ब्राउज़र (जिसे आमतौर पर ब्राउज़र के रूप में संदर्भित किया जाता है) एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जो डेटा को पुनर्प्राप्त करने, प्रस्तुत करने और ट्रैवर्स करने के लिए उपयोग किया जाता है।

⁵ विस्तृत जानकारी के लिए देखें यूनिट-3; कंप्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी पर अवलोकन

⁶ [https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_\(operating_system\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(operating_system))

वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संसाधन⁷ .

वेब सर्च इंजन⁸ एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी

खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक मेल (ईमेल या ई-मेल) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके लोगों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान करने का एक तरीका है। ईमेल ने पहली बार 1960 के दशक में सीमित उपयोग में प्रवेश किया और 1970 के दशक के मध्य तक वह रूप ले लिया जिसे अब ईमेल के रूप में जाना जाता है। ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क पर काम करता है, जो आज मुख्य रूप से इंटरनेट है। कुछ शुरुआती ईमेल सिस्टम में लेखक और प्राप्तकर्ता दोनों को एक ही समय में ऑनलाइन होना आवश्यक था, जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग के समान है। आज के ईमेल सिस्टम स्टोर-एंड-फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित हैं। ईमेल सर्वर संदेशों को स्वीकार करते हैं, अग्रेषित करते हैं, वितरित करते हैं और संग्रहीत करते हैं। न तो उपयोगकर्ताओं और न ही उनके कंप्यूटरों को एक साथ ऑनलाइन होने की आवश्यकता होती है; उन्हें केवल थोड़े समय के लिए, आम तौर पर किसी मेल सर्वर या वेबमेल इंटरफ़ेस से, संदेश भेजने या प्राप्त करने में लगने वाले समय के लिए कनेक्ट होने की आवश्यकता होती है।

सोशल मीडिया, जो आज के युवाओं के लिए सबसे लोकप्रिय मंच है, कंप्यूटर-मध्यस्थ तकनीक है जो वर्चुअल समुदायों और नेटवर्क के माध्यम से सूचना, विचार, कैरियर रुचियों और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों के निर्माण और साझाकरण की सुविधा प्रदान करती है। उदाहरण हैं: फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि।

इंटरनेट संचार सेवाओं में वॉयस ओवर आईपी, फ़ाइल ट्रांसफ़र, फ़ाइल शेयरिंग और स्क्रीन शेयरिंग शामिल हैं। वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (जिसे वॉयस ओवर आईपी, वीओआईपी या आईपी टेलीफोनी भी कहा जाता है) इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर वॉयस संचार और मल्टीमीडिया सत्रों की डिलीवरी के लिए एक पद्धति और तकनीकों का समूह है। इंटरनेट टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड फोन सेवा शब्द विशेष रूप से सार्वजनिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (PSTN) के बजाय सार्वजनिक इंटरनेट पर संचार सेवाओं (वॉयस, फैक्स, एसएमएस, वॉयस-मैसेजिंग) के प्रावधान को संदर्भित करते हैं। सर्किट-स्विचड नेटवर्क पर प्रसारित होने के बजाय, वीओआईपी सूचना पैकेटीकृत होती है, और पैकेट-स्विचड नेटवर्क पर आईपी पैकेट के रूप में संचरण होता है। वीओआईपी समर्पित फोन, स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस डिवाइस पर उपलब्ध है। कॉल और एसएमएस टेक्स्ट संदेश 3G/4G या वाई-फाई पर भेजे जा सकते हैं। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल (FTP) एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फ़ाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है।

कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क एक डिजिटल दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर को डेटा का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है। नेटवर्क किए गए कंप्यूटिंग डिवाइस केवल या वायरलेस मीडिया का उपयोग करके स्थापित कनेक्शनों पर पैकेट के रूप में एक दूसरे को डेटा पास करते हैं। राउटर एक ऐसा उपकरण है जो नेटवर्क पते (आईपी एड्रेस) के आधार पर विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग नेटवर्क नोड्स को तार के माध्यम से जोड़ने के लिए किया जाता है जो मूल रूप से डिजिटल नेटवर्क ट्रैफ़िक के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग सिग्नल का उत्पादन करने के लिए डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करके। फ़ायरवॉल एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग नेटवर्क सुरक्षा और पहुँच नियमों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो अपरिचित स्रोतों से पहुँच अनुरोधों को अस्वीकार करते हुए पहचाने गए लोगों से कार्रवाई की अनुमति देता है।¹⁰

⁷ विश्वव्यापी वेब के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखें इकाई-3; कम्प्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी पर अवलोकन
⁸ वही.

⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Email>

¹⁰ https://en.wikiversity.org/wiki/Internet_Fundamentals/Networking

इंटरनेट सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक असुरक्षित चैनल का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे घुसपैठ या धोखाधड़ी का उच्च जोखिम होता है, जैसे कि फ़िशिंग, ऑनलाइन वायरस, ट्रोजन, वर्म, और बहुत कुछ। किसी कंप्यूटर उपयोगकर्ता को धोखा दिया जा सकता है या उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले कंप्यूटर पर सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इंटरनेट सुरक्षा विशेष रूप से इंटरनेट से संबंधित कंप्यूटर सुरक्षा की एक शाखा है, जिसमें अक्सर ब्राउज़र सुरक्षा शामिल होती है, लेकिन अधिक सामान्य स्तर पर नेटवर्क सुरक्षा भी शामिल होती है, क्योंकि यह अन्य अनुप्रयोगों या ऑपरेटिंग सिस्टम पर लागू होती है। इसका उद्देश्य इंटरनेट पर हमलों के खिलाफ उपयोग करने के लिए नियम और उपाय स्थापित करना है। मैलवेयर, (दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर) कोई भी सॉफ़्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर संचालन को बाधित करने, संवेदनशील जानकारी एकत्र करने या निजी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मैलवेयर में ऐसा सॉफ़्टवेयर शामिल नहीं है जो किसी कमी के कारण अनजाने में नुकसान पहुँचाता है। बैडवेयर शब्द का उपयोग कभी-कभी किया जाता है, और इसे सच्चे (दुर्भावनापूर्ण) मैलवेयर और अनजाने में हानिकारक सॉफ़्टवेयर दोनों पर लागू किया जाता है। बॉटनेट ज़ोंबी कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जिसे रोबोट या बॉट द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है जो बॉटनेट के निर्माता के लिए बड़े पैमाने पर दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है। कंप्यूटर वायरस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर पर मौजूद अन्य फ़ाइलों या संरचनाओं को संक्रमित करके अपनी संरचनाओं या प्रभावों की नकल कर सकते हैं। वायरस का आम उपयोग डेटा चुराने के लिए कंप्यूटर पर कब्ज़ा करना है। कंप्यूटर वर्म ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में अपनी नकल कर सकते हैं, और पूरे नेटवर्क में दुर्भावनापूर्ण कार्य कर सकते हैं।

रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो संक्रमित कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है, और प्रतिबंध को हटाने के लिए मैलवेयर के निर्माता (निर्माताओं) से फिरौती की मांग करता है। स्केयरवेयर दुर्भावनापूर्ण पेलोड वाला घोटाला सॉफ़्टवेयर है, जो आमतौर पर सीमित या बिना किसी लाभ के होता है और जिसे कुछ अनैतिक विपणन प्रथाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। बिक्री दृष्टिकोण सदमे, चिंता या किसी खतरे की धारणा को पैदा करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करता है, जो आम तौर पर एक अनजान उपयोगकर्ता को लक्षित करता है। स्पाइवेयर उन प्रोग्रामों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर गतिविधि की गुप्त रूप से निगरानी करते हैं और उपयोगकर्ता की सहमति के बिना उस जानकारी को दूसरों को रिपोर्ट करते हैं। ट्रोजन हॉर्स, जिसे आमतौर पर ट्रोजन के रूप में जाना जाता है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर के लिए एक सामान्य शब्द है जो हानिरहित होने का दिखावा करता है, ताकि उपयोगकर्ता स्वेच्छा से इसे कंप्यूटर पर डाउनलोड करने की अनुमति दे। कीलॉगर, कीस्ट्रोक लॉगिंग, जिसे अक्सर कीलॉगिंग या कीबोर्ड कैप्चरिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है, कीबोर्ड पर दबाए गए कुंजियों को रिकॉर्ड करने (लॉगिंग) की क्रिया है। डिनायल -ऑफ-सर्विस अटैक (DoS अटैक) या डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस अटैक (DDoS अटैक) किसी कंप्यूटर संसाधन को उसके इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बनाने का प्रयास है। फ़िशिंग तब होती है जब हमलावर ईमेल या वेब पेज के ज़रिए किसी भरोसेमंद इकाई होने का दिखावा करता है।¹¹

एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर और इंटरनेट सुरक्षा प्रोग्राम वायरस का पता लगाकर और उसे नष्ट करके प्रोग्राम करने योग्य डिवाइस को हमले से बचा सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर एक सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को पासवर्ड स्टोर करने और व्यवस्थित करने में मदद करता है।¹²

हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML)¹³ वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए मानक मार्कअप भाषा है। वेब ब्राउज़र वेब सर्वर या स्थानीय स्टोरेज से HTML दस्तावेज़ प्राप्त करते हैं और उन्हें मल्टीमीडिया वेब पेज में प्रस्तुत करते हैं।

कैस्केडिंग स्टाइल शीट (सीएसएस) एक स्टाइल शीट भाषा है जिसका उपयोग मार्कअप भाषा में लिखे गए दस्तावेज़ की प्रस्तुति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ, CSS एक है

¹¹ https://en.wikiversity.org/wiki/Internet_Fundamentals/Security

¹² वही.

¹³ विस्तृत जानकारी के लिए देखें यूनिट-3; कंप्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी पर अवलोकन

अधिकांश वेबसाइटों द्वारा दृश्य रूप से आकर्षक वेबपेज, वेब अनुप्रयोगों के लिए उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और कई मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली आधारशिला तकनीक। HTML और CSS के साथ, जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड वाइड वेब सामग्री इंजीनियरिंग की तीन मुख्य तकनीकों में से एक है। इसका उपयोग वेबपेजों को इंटरैक्टिव बनाने और वीडियो गेम सहित ऑनलाइन प्रोग्राम प्रदान करने के लिए किया जाता है।

कंप्यूटर ग्राफ़िक्स कंप्यूटर का उपयोग करके बनाई गई तस्वीरें और फ़िल्में हैं। कंप्यूटर ग्राफ़िक विकास ने कई प्रकार के मीडिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और इसने एनीमेशन, फ़िल्में, विज्ञापन, वीडियो गेम और आम तौर पर ग्राफ़िक डिज़ाइन में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर एनीमेशन कंप्यूटर के उपयोग के माध्यम से चलती हुई छवियाँ बनाने की कला है। मल्टीमीडिया वह सामग्री है जो पाठ, ऑडियो, चित्र, एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिव सामग्री जैसे विभिन्न सामग्री रूपों के संयोजन का उपयोग करती है।¹⁵

डेटाबेस डेटा का एक संगठित संग्रह है। रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट, व्यू और अन्य तत्वों का संग्रह है। डेटाबेस-मैनेजमेंट सिस्टम (DBMS) एक कंप्यूटर-सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन है जो डेटा को कैचर और विश्लेषण करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं, अन्य एप्लिकेशन और डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करता है।¹⁶

वर्ल्ड वाइड वेब (संक्षिप्त रूप में WWW या वेब) एक सूचना स्थान है जहाँ दस्तावेज़ों और अन्य वेब संसाधनों को यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) द्वारा पहचाना जाता है, हाइपरटेक्स्ट लिंक द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, और इंटरनेट के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। हाइपरलिंक, या केवल एक लिंक, डेटा का संदर्भ है जिसे पाठक सीधे क्लिक करके, टैप करके या मॉडरन अनुसरण कर सकता है। हाइपरलिंक एक संपूर्ण दस्तावेज़ या दस्तावेज़ के भीतर एक विशिष्ट तत्व को इंगित करता है। हाइपरटेक्स्ट हाइपरलिंक वाला टेक्स्ट है। एक सॉफ़्टवेयर सिस्टम जो हाइपरटेक्स्ट को देखने और बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, एक हाइपरटेक्स्ट सिस्टम है, और हाइपरलिंक बनाना हाइपरलिंक करना (या केवल लिंक करना) है। हाइपरलिंक का अनुसरण करने वाले उपयोगकर्ता को हाइपरटेक्स्ट नेविगेट या ब्राउज़ करना कहा जाता है। मुख्य दस्तावेज़, जिसमें हाइपरलिंक होता है उसे स्रोत दस्तावेज़ के रूप में जाना जाता है। हाइपरलिंक का उपयोग अक्सर

अमल में लाना

संदर्भ तंत्र जैसे

जैसा

टेबल

सामग्री, फ़ुटनोट, ग्रंथ सूची, अनुक्रमणिका, पत्र और शब्दावलिियाँ। हाइपरलिंक दो प्रकार के होते हैं- इनलाइन लिंक और एंकर।

इनलाइन लिंक दूरस्थ सामग्री को बिना सामग्री को एम्बेड किए प्रदर्शित करता है। दूरस्थ सामग्री को उपयोगकर्ता द्वारा लिंक का चयन करके या उसके बिना एक्सेस किया जा सकता है।

एंकर हाइपरलिंक एक लिंक है जो दस्तावेज़ के एक हिस्से से जुड़ा होता है, आम तौर पर पाठ, हालांकि जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका के राजनीतिक मानचित्र में प्रत्येक देश के बारे में अधिक जानकारी के लिए हाइपरलिंक किया जा सकता है।¹⁷

वेब डिज़ाइन एक ऐसी तकनीक है जिसमें डिज़ाइन की रचनात्मकता होती है। वेब डेवलपमेंट ऐसी वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया है जिसमें स्थिर सामग्री प्रदर्शित करने से परे कार्यक्षमता होती है। जबकि वेब डिज़ाइन का संबंध वेबसाइट के लेआउट, लुक और फील और सौंदर्य से है, वेब

¹⁴ वही.

¹⁵ https://en.wikiversity.org/wiki/Internet_Fundamentals/Graphics_and_Multimedia

¹⁶ https://en.wikiversity.org/wiki/Internet_Fundamentals/Databases

¹⁷ <https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink>

विकास का संबंध इस बात से है कि सामग्री किस प्रकार वितरित की जाए, उसे कहां संग्रहित किया जाए, उसे कौन संपादित कर सकता है, तथा दर्शक उसके साथ क्या कर सकते हैं।

1.3.1.2 सॉफ्टवेयर

कंप्यूटर में दो भाग होते हैं: सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में डेटा या कंप्यूटर निर्देश होते हैं, जबकि सिस्टम का निर्माण भौतिक हार्डवेयर से होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे की आवश्यकता होती है और दोनों को ही वास्तविक रूप से अपने आप इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

अधिकांशतः सॉफ्टवेयर उच्च-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं जो प्राकृतिक भाषाओं के करीब होती हैं, जिससे प्रोग्रामर के लिए मशीन भाषाओं की तुलना में अधिक कुशलता से उपयोग करना आसान हो जाता है। उच्च-स्तरीय भाषाओं को कंपाइलर या इंटरप्रेटर या दोनों के संयोजन का उपयोग करके मशीन भाषा में अनुवादित किया जाता है। सॉफ्टवेयर को निम्न-स्तरीय असेंबली भाषा में भी लिखा जा सकता है, जिसका कंप्यूटर की मशीन भाषा निर्देशों से मजबूत पत्राचार होता है और इसे असेंबलर का उपयोग करके मशीन भाषा में अनुवादित किया जाता है।

18

अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री कंप्यूटर के मूल संचालन से परे विशेष कार्य निष्पादित करें या मनोरंजन कार्य प्रदान करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य उद्देश्य (वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउज़र, आदि) हो सकता है या उसका कोई विशिष्ट उद्देश्य (अकाउंटिंग, ट्रक शेड्यूलिंग, आदि) हो सकता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को सीधे संचालित करता है, उपयोगकर्ताओं और अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा आवश्यक बुनियादी कार्यक्षमता प्रदान करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और उपयोगिताएँ शामिल हैं।

ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर के आवश्यक संग्रह हैं जो संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और उन पर "ऊपर" चलने वाले अन्य सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करते हैं। पर्यवेक्षी कार्यक्रम, बूट लोडर, शेल और विंडो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग हैं। डिवाइस ड्राइवर

जो कंप्यूटर से जुड़े किसी खास प्रकार के डिवाइस को संचालित या नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम अपने कंप्यूटर से प्रिंटर जोड़ते हैं, तो हमें प्रिंटर को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर को आम तौर पर एक से ज्यादा डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें उपयोगकर्ताओं को उनके कंप्यूटर के रखरखाव और देखभाल में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर का कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से गहरा संबंध है। वास्तव में, ये अवांछनीय सॉफ्टवेयर हैं।

सर्वर सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन शामिल हैं, जो आम तौर पर वेब सर्वर पर चलते हैं और वेब ब्राउज़र को गतिशील रूप से जनरेट किए गए वेब पेज आउटपुट करते हैं, उदाहरण के लिए PHP, Java, ASP.NET, या यहां तक कि जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके जो सर्वर पर चलता है। आधुनिक समय में इनमें आमतौर पर वेब ब्राउज़र में चलाने के लिए कुछ जावास्क्रिप्ट शामिल होते हैं, जिस स्थिति में वे आम तौर पर आंशिक रूप से सर्वर पर और आंशिक रूप से वेब ब्राउज़र में चलते हैं।

¹⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/Software>

प्लगइन्स और एक्सटेंशन ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी अन्य सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को बढ़ाते या संशोधित करते हैं, और कार्य करने के लिए उस सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता होती है;

एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सिस्टम, एक ही उपयोग या कुछ उपयोगों के लिए समर्पित डिवाइस जैसे कि कार और टेलीविज़न के भीतर फ़र्मवेयर के रूप में रहता है। एम्बेडेड सिस्टम संदर्भ में कभी-कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है।

हालाँकि, कुछ एम्बेडेड सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, और ये सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर को बनाए रखते हैं। माइक्रोकॉड एक विशेष, अपेक्षाकृत अस्पष्ट प्रकार का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है जो प्रोसेसर को खुद बताता है कि मशीन कोड को कैसे निष्पादित किया जाए, इसलिए यह वास्तव में मशीन कोड से निचले स्तर का है।

प्रोग्रामिंग उपकरण भी प्रोग्राम या एप्लिकेशन के रूप में सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स (जिन्हें प्रोग्रामर, कोडर, हैकर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहा जाता है) सॉफ्टवेयर बनाने, डीबग करने, रखरखाव (अर्थात् सुधार या ठीक करने) या अन्यथा समर्थन करने के लिए करते हैं।

सॉफ्टवेयर एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा जाता है। कई प्रोग्रामिंग भाषाएँ अस्तित्व में हैं, और प्रत्येक में कम से कम एक कार्यान्वयन है, जिनमें से प्रत्येक में प्रोग्रामिंग उपकरणों का अपना सेट शामिल है। ये उपकरण अपेक्षाकृत स्व-निहित प्रोग्राम हो सकते हैं जैसे कि कंपाइलर, डिबगर, इंटरप्रिटर, लिंकर और टेक्स्ट एडिटर, जिन्हें किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है; या वे एक एकीकृत विकास वातावरण (IDE) बना सकते हैं, जो ऐसे स्व-निहित उपकरणों की अधिकांश या सभी कार्यक्षमता को जोड़ता है। IDE या तो संबंधित व्यक्तिगत उपकरणों को लागू करके या उनकी कार्यक्षमता को नए तरीके से फिर से लागू करके ऐसा कर सकते हैं। एक IDE विशिष्ट कार्यों को करना आसान बना सकता है, जैसे कि किसी विशेष प्रोजेक्ट में फ़ाइलों में खोज करना। कई प्रोग्रामिंग भाषा कार्यान्वयन व्यक्तिगत उपकरणों या IDE का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करते हैं।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के स्टोरेज यानी हार्ड ड्राइव या मेमोरी में "लोड" करना होता है। एक बार सॉफ्टवेयर लोड हो जाने के बाद, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को निष्पादित करने में सक्षम हो जाता है।

इसमें एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हार्डवेयर तक निर्देश भेजना शामिल है, जो अंततः मशीन कोड के रूप में निर्देश प्राप्त करता है। प्रत्येक निर्देश कंप्यूटर को एक ऑपरेशन करने के लिए प्रेरित करता है - डेटा को स्थानांतरित करना, गणना करना, या निर्देशों के नियंत्रण प्रवाह को बदलना।

सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर Microsoft Office, Microsoft Windows और Linux जैसे वाणिज्यिक और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। यदि सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण (बग वाला) है, तो यह किसी व्यक्ति के काम को मिटा सकता है, कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है और अन्य अप्रत्याशित चीजें कर सकता है। दोषों और त्रुटियों को "बग" कहा जाता है जिन्हें अक्सर अल्फा और बीटा परीक्षण के दौरान खोजा जाता है। सॉफ्टवेयर अक्सर सॉफ्टवेयर एजिंग के रूप में जाना जाता है, जो अदृश्य बग के संयोजन से उत्पन्न होने वाली प्रगतिशील प्रदर्शन गिरावट है।

सॉफ्टवेयर परीक्षण के ज़रिए कई बग खोजे और हटाए जाते हैं (डीबग किए जाते हैं¹⁹)। हालाँकि, सॉफ्टवेयर परीक्षण शायद ही कभी हर बग को हटा पाता है। कुछ प्रोग्रामर कहते हैं कि "हर प्रोग्राम में कम से कम एक बग और होता है"। सॉफ्टवेयर विकास की वॉटरफ़ॉल विधि में, अलग-अलग परीक्षण दल आमतौर पर नियोजित होते हैं, लेकिन नए तरीकों में, जिन्हें सामूहिक रूप से एजाइल सॉफ्टवेयर विकास कहा जाता है, डेवलपर्स अक्सर अपना सारा परीक्षण खुद करते हैं, और सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन करते हैं

¹⁹ शब्दावली देखें

उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों से नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त करने के लिए। सॉफ्टवेयर का परीक्षण यूनिट परीक्षण, प्रतिगमन परीक्षण और अन्य तरीकों से किया जा सकता है, जो मैन्युअल रूप से या सबसे आम तौर पर स्वचालित रूप से किया जाता है, क्योंकि परीक्षण किए जाने वाले कोड की मात्रा काफी बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए, नासा के पास कई ऑपरेटिंग सिस्टम और संचार कार्यों के लिए बेहद कठोर सॉफ्टवेयर परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। कई नासा-आधारित संचालन कमांड प्रोग्राम के माध्यम से एक-दूसरे से बातचीत करते हैं और एक-दूसरे की पहचान करते हैं। यह नासा में काम करने वाले कई लोगों को समग्र रूप से कार्यात्मक प्रणालियों की जांच और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। कमांड सॉफ्टवेयर वाले प्रोग्राम हार्डवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम संचालन को एक साथ बहुत आसानी से काम करने में सक्षम बनाते हैं।

सॉफ्टवेयर का लाइसेंस उपयोगकर्ता को लाइसेंस प्राप्त वातावरण में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार देता है, और मुफ्त सॉफ्टवेयर लाइसेंस के मामले में, प्रतिलिपियाँ बनाने के अधिकार जैसे अन्य अधिकार भी प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन और कार्यान्वयन सॉफ्टवेयर की जटिलता के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, Microsoft Word के डिज़ाइन और निर्माण में Microsoft Notepad के डिज़ाइन और विकास की तुलना में बहुत अधिक समय लगा क्योंकि बाद वाले में बहुत अधिक बुनियादी कार्यक्षमता है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर कहा जाता है, इन सभी शब्दों का अर्थ समान है। प्रोग्रामर के लिए अधिक अनौपचारिक शब्द भी मौजूद हैं जैसे "कोडर" और "हैकर" - हालाँकि बाद वाले शब्द का उपयोग भ्रम पैदा कर सकता है, क्योंकि इसका उपयोग अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अवैध रूप से कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है।

1.3.2 एल्गोरिदम और कोडिंग

एल्गोरिदम की अवधारणा कंप्यूटर विज्ञान के मूल में है। एल्गोरिदम किसी निश्चित समस्या का चरण-दर-चरण समाधान है। मनुष्य के लिए चीजों की अनंत श्रृंखला लिखना असंभव माना जाता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसी प्रक्रिया बनाने में सक्षम हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर उस श्रृंखला के उन हिस्सों को उत्पन्न कर सकता है जो किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए प्रासंगिक हैं। इस प्रकार बनाए गए चरणों की विशिष्ट सूची एक एल्गोरिदम का निर्माण करती है। एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने के लिए चरण-दर-चरण निर्देशों की एक श्रृंखला है। छद्म कोड एक एल्गोरिदम है जिसे इस तरह से लिखा जाता है कि यह कंप्यूटर कोड जैसा दिखता है। गणित और कंप्यूटर विज्ञान में, एक एल्गोरिदम समस्याओं के एक वर्ग को हल करने का एक स्पष्ट विनिर्देश है। एल्गोरिदम गणना, डेटा प्रोसेसिंग और स्वचालित तर्क कार्य कर सकते हैं।

स्वचालित तर्क, कंप्यूटर विज्ञान और गणितीय तर्क का एक क्षेत्र है जो तर्क के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए समर्पित है। स्वचालित तर्क का अध्ययन कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में मदद करता है जो कंप्यूटर को पूरी तरह से या लगभग पूरी तरह से स्वचालित रूप से तर्क करने की अनुमति देता है। हालाँकि स्वचालित तर्क को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उप-क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इसका सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और यहाँ तक कि दर्शन से भी संबंध है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ और नहीं बल्कि निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने पर एक विशिष्ट कार्य करता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक हिस्सा जो एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्य करता है उसे एल्गोरिदम के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, लाइब्रेरी और संबंधित डेटा के संग्रह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को कार्यात्मक रेखाओं के साथ वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर।

²⁰ <https://en.wikipedia.org/wiki/Software>

एल्गोरिदम नियमों का एक समूह है जो संक्रियाओं के अनुक्रम को सटीक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें सभी कंप्यूटर प्रोग्राम शामिल होते हैं, जिनमें वे प्रोग्राम भी शामिल हैं जो संख्यात्मक गणना नहीं करते हैं।

एल्गोरिदम कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के तरीके के लिए आवश्यक हैं। कई कंप्यूटर प्रोग्राम में एल्गोरिदम होते हैं जो किसी निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट निर्देशों (एक विशिष्ट क्रम में) का विवरण देते हैं, जैसे कि कर्मचारियों के पेचेक की गणना करना या छात्रों के रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करना। कंप्यूटर सिस्टम में, एक एल्गोरिदम मूल रूप से तर्क का एक उदाहरण है²¹ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स द्वारा सॉफ्टवेयर में लिखा गया, ताकि इच्छित "लक्ष्य" कंप्यूटरों के लिए दिए गए इनपुट से आउटपुट तैयार करने में प्रभावी हो।²²

कोडिंग का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो सकता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड को डिजाइन करने, लिखने, जांचने, डिबग करने या समस्या निवारण करने और बनाए रखने की प्रक्रिया है (C++ प्रोग्रामिंग के लिए संकलन भाषा का एक उदाहरण है)। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटिंग समस्या के मूल निर्माण से लेकर निष्पादन योग्य कंप्यूटर प्रोग्राम तक ले जाती है।

प्रोग्रामिंग में विश्लेषण, समझ विकसित करना, एल्गोरिदम बनाना, एल्गोरिदम की आवश्यकताओं का सत्यापन, उनकी शुद्धता और संसाधनों की खपत, तथा लक्ष्य प्रोग्रामिंग भाषा में एल्गोरिदम का कार्यान्वयन (आमतौर पर कोडिंग के रूप में संदर्भित) जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। स्रोत कोड एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग का उद्देश्य निर्देशों का एक क्रम खोजना है जो किसी विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने या किसी दी गई समस्या को हल करने में स्वचालित होगा। इस प्रकार प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया में अक्सर कई अलग-अलग विषयों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसमें एप्लिकेशन डोमेन, विशेष एल्गोरिदम और औपचारिक तर्क का ज्ञान शामिल है।

1.3.2.1 सॉफ्टवेयर विकास

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित कार्यों में परीक्षण, डिबगिंग और सोर्स कोड का रखरखाव, बिल्ड सिस्टम का कार्यान्वयन और कंप्यूटर प्रोग्राम के मशीन कोड जैसे व्युत्पन्न कलाकृतियों का प्रबंधन शामिल है। इसे अक्सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग तकनीकों को सॉफ्टवेयर विकास प्रथाओं के साथ जोड़ती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक व्यवस्थित तरीके से सॉफ्टवेयर के विकास के लिए इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग है। सॉफ्टवेयर विकास एक लंबी और व्यापक प्रक्रिया है जिसमें एक टीम वर्क शामिल है और इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं-

- समस्या का विश्लेषण
- बाजार अनुसंधान

²¹ 1950 और 1960 के दशक में शोधकर्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि जब मानव ज्ञान को **गणितीय संकेतन** के साथ तर्क का उपयोग करके व्यक्त किया जा सकेगा, तर्क करने वाली मशीन या कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाना संभव होगा। मानवीय तर्क की जटिलता के कारण यह अपेक्षा से अधिक कठिन था। **लॉजिक प्रोग्रामिंग** में, एक प्रोग्राम में स्वयंसिद्धों और नियमों का एक सेट होता है। **प्रोलॉग** जैसे लॉजिक प्रोग्रामिंग सिस्टम किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयंसिद्धों और नियमों के परिणामों की गणना करें। आज, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** के क्षेत्रों में तर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और **कंप्यूटर विज्ञान**, और ये क्षेत्र औपचारिक और अनौपचारिक तर्क में समस्याओं का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं। **तर्क सिद्धांत** यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे तर्क को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर लागू किया जा रहा है।(<https://en.wikipedia.org/wiki/Logic>)

²² विकिपीडिया

- प्रस्तावित व्यावसायिक समाधान के लिए आवश्यकताओं को एकत्रित करना
- सॉफ्टवेयर-आधारित समाधान के लिए योजना या डिज़ाइन तैयार करना
- सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन (कोडिंग)
- सॉफ्टवेयर का परीक्षण
- तैनाती
- रखरखाव और बग फिक्सिंग

आवश्यकताओं को स्थापित करने के बाद, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दस्तावेज़ में स्थापित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या तो जटिल प्रणालियों की अवधारणा, रूपरेखा, कार्यान्वयन, कमीशनिंग और अंततः संशोधन में शामिल सभी गतिविधियों को संदर्भित कर सकता है या आवश्यकताओं के विनिर्देशन के बाद और प्रोग्रामिंग से पहले की गतिविधि को संदर्भित कर सकता है, जैसा कि एक स्टाइलिज़्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रक्रिया में होता है।

सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में आमतौर पर समस्या का समाधान और सॉफ्टवेयर समाधान की योजना बनाना शामिल होता है। इसमें निम्न-स्तरीय घटक और एल्गोरिदम डिज़ाइन और उच्च-स्तरीय आर्किटेक्चर डिज़ाइन दोनों शामिल हैं।

सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक या अधिक समस्याओं के लिए सॉफ्टवेयर समाधान लागू करने की प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के मुख्य घटकों में से एक सॉफ्टवेयर आवश्यकता विश्लेषण (SRA) है। SRA सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाने वाले विनिर्देशों को सूचीबद्ध करता है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया का वह हिस्सा है जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वास्तव में प्रोजेक्ट के लिए कोड प्रोग्राम करते हैं। सॉफ्टवेयर परीक्षण सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण चरण है। प्रक्रिया का यह हिस्सा सुनिश्चित करता है कि दोषों को जल्द से जल्द पहचाना जाए। कुछ प्रक्रियाओं में, जिन्हें आम तौर पर परीक्षण-संचालित विकास के रूप में जाना जाता है, कार्यान्वयन से ठीक पहले परीक्षण विकसित किए जा सकते हैं और कार्यान्वयन की शुद्धता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। भविष्य के रखरखाव और संवर्द्धन के उद्देश्य से, विकास के दौरान सॉफ्टवेयर के आंतरिक डिज़ाइन का दस्तावेज़ीकरण किया जाता है। इसमें API लिखना भी शामिल हो सकता है, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक। विकासशील टीम द्वारा चुनी गई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रक्रिया यह निर्धारित करेगी कि कितना आंतरिक दस्तावेज़ीकरण (यदि कोई हो) आवश्यक है। योजना-संचालित मॉडल (उदाहरण के लिए, Waterfall23) आम तौर पर Agile24 की तुलना में अधिक दस्तावेज़ तैयार करते हैं मॉडल।

सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण और समर्थन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तभी प्रभावी होता है जब उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए।

नए खोजे गए दोषों या आवश्यकताओं से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर को बनाए रखने और उसे बेहतर बनाने में काफी समय और प्रयास लग सकता है, क्योंकि छूटी हुई आवश्यकताएं सॉफ्टवेयर को पुनः डिज़ाइन करने के लिए बाध्य कर सकती हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग (CASE) सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों और विधियों के एक सेट का वैज्ञानिक अनुप्रयोग है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले, दोष-मुक्त और रखरखाव योग्य सॉफ्टवेयर उत्पाद प्राप्त होते हैं।

23 वाटरफॉल मॉडल एक अपेक्षाकृत रैखिक अनुक्रमिक डिज़ाइन है इंजीनियरिंग डिज़ाइन के कुछ क्षेत्रों के लिए दृष्टिकोण। सॉफ्टवेयर विकास में, यह कम पुनरावृत्तीय और लचीले दृष्टिकोणों में से एक है, क्योंकि प्रगति मुख्यतः एक ही दिशा में प्रवाहित होती है (इसने की तरह "नीचे की ओर") गर्भाधान, दीक्षा, विश्लेषण के चरणों के माध्यम से, डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण, तैनाती

और रखरखाव. (https://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model)

24 एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर विकास के लिए एक दृष्टिकोण का वर्णन करता है जिसके तहत स्वयं-संगठन के सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से आवश्यकताएं और समाधान विकसित होते हैं और क्रॉस-फ़ंक्शनल टीमों और उनके ग्राहक/अंत उपयोगकर्ता(ओं)। [1] यह अनुकूली योजना, विकासवादी विकास, शीघ्र वितरण और निरंतर सुधार की वकालत करता है, और यह परिवर्तन के प्रति तीव्र और लचीली प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। (https://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development)

यह सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में उपयोग किए जा सकने वाले स्वचालित उपकरणों के साथ सूचना प्रणालियों के विकास के लिए विधियों को भी संदर्भित करता है। "कंप्यूटर-सहायता प्राप्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग" (CASE) शब्द का अर्थ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर कोड के स्वचालित विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर से हो सकता है। CASE कार्यों में विश्लेषण, डिजाइन और प्रोग्रामिंग शामिल हैं।

CASE उपकरण वांछित प्रोग्रामिंग भाषा में संरचित कंप्यूटर कोड को डिजाइन करने, दस्तावेजीकरण करने और उत्पादन करने के तरीकों को स्वचालित करते हैं। CASE सॉफ्टवेयर विकास और सॉफ्टवेयर रखरखाव प्रक्रियाओं में कंप्यूटर सहायता को बढ़ावा देता है। साथ ही यह सॉफ्टवेयर विकास और रखरखाव के लिए एक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण है।

एकीकृत विकास वातावरण (IDE) जिसे एकीकृत डिजाइन वातावरण या एकीकृत डिबगिंग वातावरण के रूप में भी जाना जाता है, एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर विकास के लिए व्यापक सुविधाएँ प्रदान करता है। एक IDE में आम तौर पर निम्न शामिल होते हैं: 1) सोर्स कोड एडिटर, जो एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसे खास तौर पर प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड को संपादित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन हो सकता है या इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट (IDE) या वेब ब्राउज़र में बनाया जा सकता है। सोर्स कोड एडिटर सबसे बुनियादी प्रोग्रामिंग टूल हैं, क्योंकि प्रोग्रामर का मूल काम सोर्स कोड लिखना और संपादित करना है। उदाहरण हैं: एटम, ब्रैकेट्स, एक्लिप्स, एमेक्स (क्रॉस-प्लेटफॉर्म, जिसमें यूनिक्स, लिनक्स, मैकओएस, विंडोज शामिल हैं), गोडिड (क्रॉस-प्लेटफॉर्म, जिसमें लिनक्स, मैकओएस, विंडोज शामिल हैं), माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो बिल्ट-इन एडिटर (विंडोज), नेटबीन्स, नोटपैड++ (विंडोज)। 2) कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा (स्रोत भाषा) में लिखे गए कंप्यूटर कोड को दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा (लक्ष्य भाषा) में बदल देता है। कंपाइलर एक प्रकार के अनुवादक हैं जो डिजिटल उपकरणों, मुख्य रूप से कंप्यूटर का समर्थन करते हैं। कंपाइलर नाम मुख्य रूप से उन प्रोग्रामों के लिए उपयोग किया जाता है जो एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम बनाने के लिए उच्च-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा से स्रोत कोड को निम्न-स्तरीय भाषा (जैसे, असेंबली भाषा, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड) में अनुवाद करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में, एक इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सीधे प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों को निष्पादित करता है, यानी निष्पादित करता है, बिना उन्हें पहले मशीन भाषा प्रोग्राम में संकलित किए जाने की आवश्यकता के।

एक इंटरप्रेटर आमतौर पर प्रोग्राम निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक रणनीति का उपयोग करता है:

1. स्रोत कोड को पार्स करें और उसका व्यवहार सीधे निष्पादित करें;
2. स्रोत कोड को कुछ कुशल मध्यवर्ती प्रतिनिधित्व में अनुवाद करें और तुरंत
इसे निष्पादित करें;
3. संकलक द्वारा बनाए गए संग्रहीत पूर्व संकलित कोड[1] को स्पष्ट रूप से निष्पादित करें जो इंटरप्रेटर सिस्टम का हिस्सा है

3) बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स, जो एक सॉफ्टवेयर बिल्ड के निर्माण और संबंधित प्रक्रियाओं को स्वचालित करने की प्रक्रिया है, जिसमें शामिल हैं: कंप्यूटर स्रोत कोड को बाइनरी कोड में संकलित करना, स्वचालित रूप से चलने वाले बाइनरी को पैकेजिंग करना 4)

कोड, और परीक्षण.

डीबगर: डीबगर या डिबगिंग टूल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग अन्य प्रोग्रामों ("लक्ष्य" प्रोग्राम) का परीक्षण और डीबग करने के लिए किया जाता है। जांचे जाने वाले कोड को वैकल्पिक रूप से एक इंस्ट्रक्शन सेट सिम्युलेटर (ISS) पर चलाया जा सकता है, एक ऐसी तकनीक जो विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करने पर रुकने की अपनी क्षमता में बहुत अधिक शक्ति देती है, लेकिन जो आमतौर पर उचित (या समान) पर सीधे कोड निष्पादित करने की तुलना में कुछ हद तक धीमी होगी।

प्रोसेसर। कुछ डिबगर इस प्रभाव को सीमित करने के लिए दो प्रकार के ऑपरेशन, पूर्ण या आंशिक सिमुलेशन प्रदान करते हैं।

"ट्रैप" तब होता है जब प्रोग्राम प्रोग्रामिंग बग या अमान्य डेटा के कारण सामान्य रूप से जारी नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, प्रोग्राम ने CPU के वर्तमान संस्करण पर उपलब्ध न होने वाले निर्देश का उपयोग करने का प्रयास किया हो सकता है या अनुपलब्ध या संरक्षित मेमोरी तक पहुँचने का प्रयास किया हो सकता है। जब प्रोग्राम "ट्रैप" करता है या किसी पूर्व निर्धारित स्थिति तक पहुँचता है, तो डिबगर आम तौर पर मूल कोड में स्थान दिखाता है यदि यह स्रोत-स्तरीय डिबगर या प्रतीकात्मक डिबगर है, जिसे अब एकीकृत विकास वातावरण में आम तौर पर देखा जाता है। यदि यह निम्न-स्तरीय डिबगर या मशीन-भाषा डिबगर है तो यह डिसअसेंबली में लाइन दिखाता है (जब तक कि इसमें मूल स्रोत कोड तक ऑनलाइन पहुँच न हो और असेंबली या संकलन से कोड का उपयुक्त भाग प्रदर्शित न कर सके)।

IDE को समान उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के साथ घनिष्ठ घटक प्रदान करके प्रोग्रामर उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आम तौर पर एक IDE एक विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा के लिए समर्पित होता है, ताकि एक ऐसा फीचर सेट प्रदान किया जा सके जो भाषा के प्रोग्रामिंग प्रतिमानों से सबसे अधिक मेल खाता हो।

1.3.2.2 मॉडलिंग भाषा

मॉडलिंग भाषा एक संरचना में सूचना या किसी भी कृत्रिम वह भाषा जिसका प्रयोग किया जा सकता है को ज्ञान या सिस्टम को व्यक्त करती है जिसे नियमों के एक सुसंगत सेट द्वारा परिभाषित किया जाता है। नियमों का उपयोग संरचना में घटकों के अर्थ की व्याख्या के लिए किया जाता है। मॉडलिंग भाषा ग्राफ़िकल या टेक्स्टुअल हो सकती है। ग्राफ़िकल मॉडलिंग भाषाएँ नामित प्रतीकों के साथ आरेख तकनीकों का उपयोग करती हैं जो अवधारणाओं और रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो प्रतीकों को जोड़ती हैं और जो संबंधों का प्रतिनिधित्व करती हैं और बाधाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न अन्य ग्राफ़िकल एनोटेशन हैं।

टेक्स्टुअल मॉडलिंग भाषाएँ आम तौर पर कंप्यूटर-व्याख्या योग्य अभिव्यक्तियों बनाने के लिए मापदंडों के साथ मानकीकृत कीवर्ड का उपयोग करती हैं। सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ग्राफ़िकल मॉडलिंग भाषाओं के उदाहरण हैं:

- बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन (BPMN, और XML फॉर्म BPML) इसका एक उदाहरण है एक प्रक्रिया मॉडलिंग भाषा का।
- एक्सप्रेस और एक्सप्रेस-जी (आईएसओ 10303-11) एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है। उद्देश्य डेटा मॉडलिंग भाषा।
- विस्तारित एंटरप्राइज़ मॉडलिंग भाषा (ईईएमएल) का उपयोग आमतौर पर व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। परतों के पार मॉडलिंग।
- फ्लोचार्ट एक एल्गोरिथम या चरणबद्ध प्रक्रिया का एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है,
- सॉफ़्टवेयर-गहन के लिए फंडामेंटल मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स (एफएमसी) मॉडलिंग भाषा सिस्टम.²⁵
- आईडीईएफ मॉडलिंग भाषाओं का एक परिवार है, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय हैं कार्यात्मक मॉडलिंग के लिए आईडीईएफ0, सूचना मॉडलिंग के लिए आईडीईएफ1एक्स, और ऑन्टोलॉजी मॉडलिंग के लिए आईडीईएफ5।

LePUS3 एक ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड विज़ुअल डिज़ाइन विवरण भाषा और एक औपचारिक विनिर्देश भाषा है जो मुख्य रूप से बड़े ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड (जावा, सी ++, सी #) प्रोग्राम और डिज़ाइन पैटर्न के मॉडलिंग के लिए उपयुक्त है।

²⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Software_development

- विनिर्देशन और विवरण भाषा (एसडीएल) एक विनिर्देशन भाषा है जो प्रतिक्रियाशील और वितरित प्रणालियों के व्यवहार के स्पष्ट विनिर्देशन और विवरण पर लक्षित है।
- यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज (UML) एक सामान्य प्रयोजन मॉडलिंग भाषा है जो सॉफ्टवेयर-गहन प्रणालियों को निर्दिष्ट करने के लिए एक उद्योग मानक है। UML 2.0, वर्तमान संस्करण, तेरह अलग-अलग आरेख तकनीकों का समर्थन करता है और इसमें व्यापक उपकरण समर्थन है।

सभी मॉडलिंग भाषाएँ निष्पादन योग्य नहीं होती हैं, और जो हैं, उनके लिए उनका उपयोग करना जरूरी नहीं है कि प्रोग्रामर की अब जरूरत नहीं है। इसके विपरीत, निष्पादन योग्य मॉडलिंग भाषाओं का उद्देश्य कुशल प्रोग्रामर की उत्पादकता को बढ़ाना है, ताकि वे अधिक कठिन समस्याओं, जैसे कि समानांतर कंप्यूटिंग और वितरित सिस्टम को संबोधित कर सकें।

प्रोग्रामिंग प्रतिमान कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक मौलिक शैली है, जो सामान्यतः परियोजना प्रबंधन पद्धति (जैसे वाटरफॉल या एजाइल) द्वारा निर्धारित नहीं होती है।

प्रतिमान किसी कार्यक्रम के तत्वों (जैसे ऑब्जेक्ट, फंक्शन, चर, बाधाएँ) और गणना को शामिल करने वाले चरणों (जैसे असाइनमेंट, मूल्यांकन, निरंतरता, डेटा प्रवाह) का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं और अमूर्तताओं में भिन्न होते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा कई प्रतिमानों का समर्थन कर सकती है। उदाहरण के लिए, C++ या ऑब्जेक्ट पास्कल में लिखे गए प्रोग्राम पूरी तरह से प्रक्रियात्मक या पूरी तरह से ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड हो सकते हैं, या उनमें दोनों प्रतिमानों के तत्व हो सकते हैं। जिस तरह अलग-अलग इंजीनियरिंग अलग-अलग कार्यप्रणाली की वकालत करती है, उसी तरह अलग-अलग प्रोग्रामिंग भाषाएँ अलग-अलग प्रोग्रामिंग प्रतिमानों की वकालत करती हैं। कुछ भाषाओं को एक प्रतिमान का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि अन्य प्रोग्रामिंग भाषाएँ कई प्रतिमानों का समर्थन करती हैं।²⁶

समूह सॉफ्टवेयर में

1.3.2.3 प्रोग्रामिंग तकनीक

सॉफ्टवेयर डिजाइन करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें तकनीक और कला दोनों शामिल हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का बाजार बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है। डिजाइनिंग का उद्देश्य अलग-अलग हो सकता है।

कुछ निम्नलिखित हैं: डिजाइनिंग के उद्देश्य क्या हैं।

प्रौद्योगिकी के विकास के साथ पुरानी प्रणाली के रखरखाव की लागत बढ़ सकती है और पुरानी प्रणाली की दक्षता कम हो सकती है। इसलिए समाधान पुरानी प्रणाली को बदलकर नई प्रणाली लगाना है।

- किसी संस्था या कंपनी से सॉफ्टवेयर विकसित करने की मांग हो सकती है, जो उनकी आवश्यकता को पूरा करे।
- किसी भी कंपनी या कार्य समूह की उत्पादकता बढ़ाना नए सॉफ्टवेयर विकसित करने का एक अन्य उद्देश्य हो सकता है।
- प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो सकती है।

1.3.2.3.1 संरचित प्रोग्रामिंग

संरचित प्रोग्रामिंग एक तार्किक प्रोग्रामिंग विधि है जिसे ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) का अग्रदूत माना जाता है। प्रोग्राम को कई बुनियादी संरचनाओं में विभाजित किया गया है।

इन संरचनाओं को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। प्रोग्राम को पढ़ना और समझना आसान होता है। नुटियाँ

²⁶ पूर्वोक्त

संरचना प्रोग्रामिंग में विभिन्न नियंत्रण संरचनाएं जैसे स्विच-केस, अगर-तो-अन्यथा, जबकि, आदि प्रोग्रामर को प्रोग्राम के प्रवाह को आसानी से डिकोड करने की अनुमति देती हैं।

इसे "गोटो लेस" प्रोग्रामिंग कहा जाता है क्योंकि बिना शर्त ब्रांचिंग के लिए गोटो का उपयोग दृढ़ता से टाला जाता है। गोटो खराब प्रोग्राम डिज़ाइन का संकेत है, इसलिए कई डिज़ाइनिंग अवधारणाएँ इसका पक्ष नहीं ले रही हैं, लेकिन इसका उपयोग सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में व्यापक रूप से किया जाता है। नुकसान यह है कि, अधिक मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। जब मॉड्यूल की संख्या निश्चित सीमा से बाहर होती है, तो प्रोग्राम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होता है।²⁷

1.3.2.3.2 मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग

मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें मॉड्यूल या स्किड कहा जाता है जिन्हें स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है और फिर विभिन्न प्रणालियों में उपयोग किया जा सकता है। यह तार्किक रूप से प्रोग्राम का अलग-अलग हिस्सा है। मॉड्यूल स्वतंत्र और आसानी से प्रबंधित करने योग्य होते हैं। मॉड्यूल को अलग-अलग डीबग और परीक्षण किया जाता है और सिस्टम बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। शीर्ष मॉड्यूल को रूट या बॉस मॉड्यूल कहा जाता है जो ऊपर से नीचे तक सभी उप-मॉड्यूल पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर नहीं।

1.3.2.3.3 ऊपर से नीचे की ओर डिज़ाइन

टॉप-डाउन दृष्टिकोण, जिसे चरणबद्ध डिज़ाइन के रूप में भी जाना जाता है, अनिवार्य रूप से एक सिस्टम को तोड़ना है ताकि इसे बनाने वाले उप-प्रणालियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। टॉप-डाउन दृष्टिकोण में सिस्टम का अवलोकन तैयार किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रथम-स्तरीय उप-प्रणाली को निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन उसका विवरण नहीं दिया जाता है।

कभी-कभी इसे अमेरिकी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह 1970 के दशक में FBI (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण था। यह अपराध स्थल को ध्यान से देखने और अपराधी के बारे में वहां मिले सबूतों से निष्कर्ष निकालने से शुरू होता है।

टॉप डाउन दृष्टिकोण में, सबसे पहले, अन्य उप मॉड्यूलों को नियंत्रित करने के लिए पर्यवेक्षक कार्यक्रम की पहचान की जाती है।

मुख्य मॉड्यूल को उप-मॉड्यूल में, उप-मॉड्यूल को उप-मॉड्यूल में और इसी प्रकार आगे भी विभाजित किया जाता है।

जब भी वांछित मॉड्यूल स्तर प्राप्त नहीं होता है, मॉड्यूल का अपघटन जारी रहता है।

सबसे पहले शीर्ष मॉड्यूल का परीक्षण किया जाता है, और फिर उप-मॉड्यूलों को एक-एक करके संयोजित किया जाता है और उनका परीक्षण किया जाता है।

1.3.2.3.4 नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण

नियोजन की इस पद्धति में, उद्देश्यों को परिभाषित करना और उन्हें नीचे से ऊपर तक प्राप्त करने के तरीके तय किए जाते हैं। सबसे पहले, संगठनात्मक पदानुक्रम के निचले स्तर पर अपेक्षाकृत करीबी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। फिर उन्हें धीरे-धीरे उच्च और उच्चतर स्तर पर वैश्विक लक्ष्यों और वैश्विक रणनीति के ढांचे में एकीकृत किया जाता है। सबसे पहले निचली परत के मॉड्यूल डिज़ाइन किए जाते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है, फिर दूसरी परत के मॉड्यूल डिज़ाइन किए जाते हैं और उन्हें निचली परत के साथ जोड़ा जाता है और संयुक्त मॉड्यूल का परीक्षण किया जाता है। इस तरह, डिज़ाइनिंग और परीक्षण नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। हालाँकि सॉफ़्टवेयर डिज़ाइनिंग में एक तरह की डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी सिर्फ़ शुद्ध टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच का। कई डिज़ाइनर हाइब्रिड तरह के दृष्टिकोण की सलाह देते हैं जिसमें टॉप डाउन और बॉटम अप, दोनों दृष्टिकोणों का इस्तेमाल किया जाता है।

²⁷ <http://www.sciencehq.com/computing-technology/programming-techniques.html>

²⁸ वही

1.3.2.3.5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग

OOP में प्रक्रियाओं पर नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट्स पर जोर दिया जाता है। सभी प्रोग्रामिंग गतिविधियाँ ऑब्जेक्ट्स के इर्द-गिर्द घूमती हैं। यह प्रोग्रामिंग के बॉटम अप दृष्टिकोण का समर्थन करता है। OOP के चार सिद्धांत हैं

एनकैप्सुलेशन, अमूर्तता, विरासत और बहुरूपता। कम आवश्यक सुविधाओं पर आवश्यक सुविधाओं के उपयोग को अमूर्तता कहा जाता है। OOP में, डेटा अमूर्तता के लिए कई डिवाइस का उपयोग किया जाता है जैसे कि क्लास, एनकैप्सुलेशन, डेटा छिपाना आदि। एक क्लास समान वस्तुओं का संग्रह है। ऑब्जेक्ट क्लास के सदस्य हैं। एक बार क्लास घोषित होने के बाद, इसके कई सदस्यों को प्रोग्राम में आसानी से बनाया जा सकता है। कई रूपों में खोजने की क्षमता को बहुरूपता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, + गणितीय ऑपरेटर है, यह एक साथ जुड़ा हुआ है और संख्याएँ देता है। यहाँ, ऑपरेटर + का संख्यात्मक डेटा और स्ट्रिंग्स के लिए अलग व्यवहार है। ठीक उसी तरह, एक बार घोषित फ़ंक्शन का अलग अर्थ होता है जिसे फ़ंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। यदि ऑपरेटर का अलग अर्थ है, तो इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाता है। एनकैप्सुलेशन OOP की एक बहुत ही असामान्य विशेषता है जिसमें डेटा और फ़ंक्शन एकल इकाई में बंधे होते हैं। एनकैप्सुलेशन सार्वजनिक विधियों तक पहुँच को प्रतिबंधित करके डेटा कार्यान्वयन को छिपाने का तंत्र है। डेटा और फ़ंक्शन को क्लास में एनकैप्सुलेट किया जाता है। बाहरी दुनिया या बाहरी फ़ंक्शन डेटा तक नहीं पहुँच सकता है। यह सार्वजनिक इंटरफ़ेस के पीछे वस्तुओं के निजी तत्वों को छुपाता है। वंशानुक्रम वर्ग का एक पदानुक्रम है जिसमें आधार वर्ग के कुछ गुण व्युत्पन्न वर्ग में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

1.3.3 कंप्यूटर नेटवर्किंग

कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क एक डिजिटल दूरसंचार नेटवर्क है जो नोड्स को संसाधन साझा करने की अनुमति देता है। एक भौतिक नेटवर्क नोड DCE (डेटा संचार उपकरण) जैसे कि मॉडेम, हब, ब्रिज या स्विच हो सकता है; या डेटा टर्मिनल उपकरण (DTE) जैसे कि डिजिटल टेलीफोन हैंडसेट, प्रिंटर या होस्ट कंप्यूटर। नेटवर्क कंप्यूटर डिवाइस जो डेटा को उत्पन्न, रूट और समाप्त करते हैं उन्हें नेटवर्क नोड कहा जाता है। नोड्स में व्यक्तिगत कंप्यूटर, फ़ोन, सर्वर और साथ ही नेटवर्किंग हार्डवेयर जैसे होस्ट शामिल हो सकते हैं। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने में सक्षम होती है, चाहे उनका एक दूसरे से सीधा संबंध हो या न हो, उन्हें एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में, एप्लिकेशन-विशिष्ट संचार प्रोटोकॉल²⁹ अन्य अधिक सामान्य संचार प्रोटोकॉल पर स्तरित (यानी पेलोड के रूप में ले जाए जाते हैं) होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस दुर्जेय संग्रह को इसे मज़बूती से चलाने के लिए कुशल नेटवर्क प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे एप्लीकेशन और सेवाओं का समर्थन करते हैं जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुँच, डिजिटल वीडियो, डिजिटल ऑडियो, एप्लीकेशन और स्टोरेज सर्वर, प्रिंटर और फैक्स मशीन का साझा उपयोग, और ईमेल और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ-साथ कई अन्य का उपयोग। कंप्यूटर नेटवर्क अपने सिग्नल ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांसमिशन माध्यम, नेटवर्क ट्रैफ़िक को व्यवस्थित करने के लिए संचार प्रोटोकॉल, नेटवर्क के आकार, टोपोलॉजी, ट्रैफ़िक नियंत्रण तंत्र और संगठनात्मक इरादों में भिन्न होते हैं। सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है, जो पूरी दुनिया को एक गाँव में बदल देता है। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा सुगम किए गए पारस्परिक संचार, उपयोगकर्ताओं को ईमेल, इंस्टैंट मैसेजिंग, ऑनलाइन चैट, टेलीफोन, वीडियो टेलीफोन कॉल और वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से कुशलतापूर्वक और आसानी से संवाद करने की अनुमति देते हैं। एक नेटवर्क फ़ाइलों, डेटा और अन्य प्रकार की जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है। यह अधिकृत उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों पर संग्रहीत जानकारी तक पहुँचने की क्षमता देता है।

²⁹ शब्दावली देखें

कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग सुरक्षा हैकर्स द्वारा नेटवर्क से जुड़े उपकरणों पर कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर वर्म तैनात करने के लिए किया जा सकता है, या इन उपकरणों को सेवा निषेध हमले के माध्यम से नेटवर्क तक पहुंचने से रोकने के लिए किया जा सकता है³⁰ .

कंप्यूटर नेटवर्क में ज्यादातर जानकारी पैकेट में भेजी जाती है। नेटवर्क पैकेट डेटा की एक फॉर्मेटेड इकाई है (बिट्स या बाइट्स की एक सूची, जो आमतौर पर कुछ दसियों बाइट्स से लेकर कुछ किलोबाइट्स तक लंबी होती है) जिसे पैकेट-स्विच नेटवर्क द्वारा भेजा जाता है। पैकेट नेटवर्क के ज़रिए अपने गंतव्य तक भेजे जाते हैं। पैकेट के पहुंचने के बाद उन्हें उनके मूल संदेश में फिर से जोड़ दिया जाता है।

कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच डेटा का आदान-प्रदान नोड्स के बीच कनेक्शन का उपयोग करके किया जाता है। ये नोड्स या डेटा लिंक वायर्ड या वायरलेस मीडिया पर स्थापित किए जाते हैं।

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें: 1.3.3

वायर्ड प्रौद्योगिकियाँ:

- कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल केबल टेलीविजन सिस्टम, कार्यालय भवनों और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लिए अन्य कार्य-स्थलों पर व्यापक रूप से किया जाता है। ट्रांसमिशन की गति 200 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड से लेकर 500 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड से अधिक तक होती है।
- आईटीयू-टी जी.एच.एन. प्रौद्योगिकी उच्च गति (1 गीगाबिट/सेकंड तक) स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क बनाने के लिए मौजूदा घरेलू तारों (समाक्षीय केबल, फोन लाइनों और बिजली लाइनों) का उपयोग करती है।
- ट्विस्टेड पेयर तार सभी दूरसंचार के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम है। कंप्यूटर नेटवर्क केबलिंग (IEEE 802.3 द्वारा परिभाषित वायर्ड ईथरनेट) में तांबे की केबलिंग के 4 जोड़े होते हैं जिनका उपयोग आवाज़ और डेटा ट्रांसमिशन दोनों के लिए किया जा सकता है। ट्रांसमिशन की गति 2 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड से लेकर 10 बिलियन बिट्स प्रति सेकंड तक होती है।
- ऑप्टिकल फाइबर एक ग्लास फाइबर है। यह प्रकाश की तरंगों को ले जाता है जो डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक साथ प्रकाश की कई तरंग दैर्ध्य ले जा सकते हैं, जो डेटा भेजने की दर को बहुत बढ़ा देता है, और प्रति सेकंड ट्रिलियन बिट्स तक की डेटा दर को सक्षम करने में मदद करता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग बहुत अधिक डेटा दरों को ले जाने वाले केबल के लंबे रन के लिए किया जा सकता है, और महाद्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए अंडरसी केबल के लिए उपयोग किया जाता है।

वायरलेस प्रौद्योगिकियाँ:

- स्थलीय माइक्रोवेव - स्थलीय माइक्रोवेव संचार पृथ्वी-आधारित का उपयोग करता है
उपग्रह डिशों के सदृश ट्रांसमीटर और रिसीवर।
- संचार उपग्रह - उपग्रह माइक्रोवेव रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार करते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। उपग्रह अंतरिक्ष में, आमतौर पर भूमध्य रेखा से 35,400 किमी (22,000 मील) ऊपर भू-समकालिक कक्षा में स्थित होते हैं। ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली प्रणालियाँ आवाज़, डेटा और टीवी सिग्नल प्राप्त करने और रिले करने में सक्षम हैं।
- सेलुलर और पीसीएस सिस्टम कई रेडियो संचार तकनीकों का उपयोग करते हैं। सिस्टम कवर किए गए क्षेत्र को कई भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक कम-शक्ति ट्रांसमीटर या रेडियो रिले एंटीना डिवाइस होता है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कॉल रिले करता है।

³⁰ सेवा निषेध हमला (DoS हमला) एक साइबर हमला है जिसमें अपराधी किसी मशीन या नेटवर्क संसाधन को उसके इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बनाना चाहता है अस्थायी या अनिश्चित काल के लिए सेवाओं को बाधित करके एक मेज़बान का इंटरनेट से जुड़ा हुआ। (विकिपीडिया)

- रेडियो और स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीकें - वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डिजिटल सेलुलर के समान एक उच्च-आवृत्ति रेडियो तकनीक और एक कम-आवृत्ति रेडियो तकनीक का उपयोग करते हैं। वायरलेस LAN एक सीमित क्षेत्र में कई उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक का उपयोग करते हैं। IEEE 802.11 ओपन-स्टैंडर्ड वायरलेस रेडियो-वेव तकनीक के एक सामान्य फ्लेवर को परिभाषित करता है जिसे Wifi के रूप में जाना जाता है।
- मुक्त-स्थान ऑप्टिकल संचार के लिए दृश्य या अदृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। अधिकांश मामलों में, दृष्टि-रेखा प्रसार का उपयोग किया जाता है, जो संचार उपकरणों की भौतिक स्थिति को सीमित करता है।

लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, स्कूल, कार्यालय भवन या इमारतों के एक-दूसरे से सटे समूह में कंप्यूटर और डिवाइस को जोड़ता है। LAN को राउटर का उपयोग करके WAN (वाइड एरिया नेटवर्क) से जोड़ा जा सकता है।

वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर, देश या यहां तक कि अंतरमहाद्वीपीय दूरियों को कवर करता है। WAN तकनीकें आम तौर पर OSI संदर्भ मॉडल [ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल (OSI मॉडल)] की निचली तीन परतों पर काम करती हैं, ये हैं, भौतिक परत, डेटा लिंक परत और नेटवर्क परत।

ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल (OSI मॉडल) एक वैचारिक मॉडल है जो किसी कंप्यूटिंग सिस्टम के संचार कार्यों को उसकी अंतर्निहित आंतरिक संरचना और तकनीक की परवाह किए बिना उसकी विशेषता और मानकीकरण करता है। इसका लक्ष्य मानक प्रोटोकॉल के साथ विविध संचार प्रणालियों की अंतर-संचालनीयता है।

होम एरिया नेटवर्क (HAN) एक आवासीय LAN है जिसका उपयोग आम तौर पर घर में तैनात डिजिटल उपकरणों के बीच संचार के लिए किया जाता है, आमतौर पर कुछ व्यक्तिगत कंप्यूटर और सहायक उपकरण, जैसे प्रिंटर, मोबाइल और iPad। HAN में इंटरनेट एक्सेस अक्सर केबल टीवी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL) प्रदाता के माध्यम से एक ब्रॉडबैंड सेवा होती है।

स्टोरेज एरिया नेटवर्क (SAN) एक समर्पित नेटवर्क है जो समेकित, ब्लॉक स्तरीय डेटा भंडारण तक पहुंच प्रदान करता है।

कैंपस एरिया नेटवर्क (CAN), जैसा कि नाम से पता चलता है, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर LAN के अंतर्संबंध से बना होता है। उदाहरण के लिए, कोई उद्यम, विश्वविद्यालय, सरकार आदि।

बैंक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है जो विभिन्न LAN या उप-नेटवर्क के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक बड़ी कंपनी दुनिया भर में स्थित विभागों को जोड़ने के लिए बैंकबोन नेटवर्क लागू कर सकती है।

उद्यम निजी क्षेत्र एक नेटवर्क है जिसे एक एकल संगठन अपने कार्यालय स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए बनाता है।

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) एक ओवरले नेटवर्क है जिसमें नोड्स के बीच कुछ लिंक भौतिक तारों के बजाय किसी बड़े नेटवर्क (जैसे, इंटरनेट) में खुले कनेक्शन या वर्चुअल सर्किट द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, VPN का उपयोग मजबूत सुरक्षा सुविधाओं वाले अंतर्निहित नेटवर्क पर विभिन्न उपयोगकर्ता समुदायों के ट्रैफिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [23]

ग्लोबल एरिया नेटवर्क (GAN) एक नेटवर्क है जिसका उपयोग वायरलेस LAN, सैटेलाइट कवरेज क्षेत्रों आदि की एक मनमाना संख्या में मोबाइल का समर्थन करने के लिए किया जाता है। मोबाइल संचार में मुख्य चुनौती उपयोगकर्ता संचार को एक स्थानीय कवरेज क्षेत्र से दूसरे तक पहुंचाना है।

नेटवर्क का प्रबंधन आम तौर पर उन संगठनों द्वारा किया जाता है जो उनके मालिक होते हैं। निजी उद्यम नेटवर्क इंटरनेट और एक्स्ट्रा नेट के संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। वे इंटरनेट तक नेटवर्क पहुंच भी प्रदान कर सकते हैं, जिसका कोई एकल स्वामी नहीं है और जो वस्तुतः असीमित वैश्विक कनेक्टिविटी की अनुमति देता है।³¹

डार्कनेट एक ओवरले नेटवर्क है, जो आम तौर पर इंटरनेट पर चलता है और जिसे केवल विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्कनेट एक गुमनाम नेटवर्क है, जहाँ कनेक्शन केवल विश्वसनीय साथियों के बीच बनाए जाते हैं - जिन्हें कभी-कभी "मित्र" (F2F) कहा जाता है - गैर-मानक प्रोटोकॉल और पोर्ट का उपयोग करके। फ्रेंड-टू-फ्रेंड या F2F कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जिसमें उपयोगकर्ता केवल उन लोगों के साथ सीधे संपर्क बनाते हैं जिन्हें वे जानते हैं। प्रमाणीकरण के लिए पासवर्ड या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा सकता है। डार्कनेट अन्य वितरित पीयर टू पीयर नेटवर्क से अलग है क्योंकि साझाकरण गुमनाम है (यानी, आईपी पता सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाता है), और इसलिए उपयोगकर्ता सरकारी या कॉर्पोरेट हस्तक्षेप के डर के बिना संवाद कर सकते हैं।

रूटिंग नेटवर्क ट्रैफिक ले जाने के लिए नेटवर्क पथों का चयन करने की प्रक्रिया है। रूटिंग कई प्रकार के नेटवर्क के लिए की जाती है, जिसमें सर्किट स्विचिंग नेटवर्क और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क शामिल हैं।

पैकेट स्विच नेटवर्क में, रूटिंग नेटवर्क पैकेट को उनके स्रोत से मध्यवर्ती नोड्स के माध्यम से उनके अंतिम गंतव्य की ओर निर्देशित करता है। मध्यवर्ती नोड्स आमतौर पर नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जैसे राउटर, ब्रिज, गेटवे, फ़ायरवॉल या स्विच। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर भी पैकेट को अग्रणी कर सकते हैं और रूटिंग कर सकते हैं, हालांकि वे विशेष हार्डवेयर नहीं हैं और सीमित प्रदर्शन से ग्रस्त हो सकते हैं। आमतौर पर कई रूट होते हैं जिन्हें लिया जा सकता है, और उनमें से चुनने के लिए, यह तय करने के लिए विभिन्न तत्वों पर विचार किया जा सकता है कि कौन से रूट में प्रवेश करना है

नेटवर्क कंजेशन तब होता है जब कोई लिंक या नोड इतना अधिक डेटा ले जा रहा होता है कि उसकी सेवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। नेटवर्क कंजेशन सेवा की कम गुणवत्ता है जो तब होती है जब कोई नेटवर्क नोड या लिंक अपनी क्षमता से अधिक डेटा ले जा रहा होता है। कंजेशन कोलैप्स वह स्थिति है जिसमें कंजेशन उपयोगी संचार को रोकता है या सीमित करता है। कंजेशन कोलैप्स आम तौर पर नेटवर्क में चोक पॉइंट पर होता है, जहाँ आने वाला ट्रैफिक आउटगोइंग बैंडविड्थ से अधिक होता है। LAN और WAN के बीच कनेक्शन पॉइंट आम चोक पॉइंट होते हैं। नेटवर्क कोलैप्स से बचने के लिए कंजेशन कंट्रोल और कंजेशन अवॉइडेंस तकनीकों का उपयोग करते हैं।

1.3.4 नेटवर्क सुरक्षा

कंप्यूटर नेटवर्क और उसके नेटवर्क-सुलभ संसाधनों तक अनधिकृत पहुंच, दुरुपयोग, संशोधन या अस्वीकृति को रोकने और निगरानी करने के लिए, उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

1.3.4 नेटवर्क प्रशासकों द्वारा अपनाया गया। नेटवर्क सुरक्षा नेटवर्क में डेटा तक पहुँच का प्राधिकरण है, जिसे नेटवर्क प्रशासक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपयोगकर्ताओं को एक आईडी सौंपी जाती है

³¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network

और पासवर्ड जो उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सूचना और कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करता है। नेटवर्क सुरक्षा का उपयोग सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क पर, व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों के बीच दैनिक लेनदेन और संचार को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है।

नेटवर्क निगरानी

कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थानांतरित किए जा रहे डेटा की निगरानी को नेटवर्क सर्विलांस कहा जाता है।

निगरानी अक्सर गुप्त रूप से की जाती है और सरकारों, निगमों, आपराधिक संगठनों या व्यक्तियों द्वारा या उनके इशारे पर की जा सकती है। यह कानूनी हो भी सकता है और नहीं भी और इसके लिए न्यायालय या अन्य स्वतंत्र एजेंसी से प्राधिकरण की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी।

कंप्यूटर और नेटवर्क निगरानी कार्यक्रम आज व्यापक रूप से प्रचलित हैं, और लगभग सभी इंटरनेट ट्रैफिक पर अवैध गतिविधि के सुराग के लिए निगरानी की जा सकती है।

सामाजिक सौहार्द बनाए रखने, खतरों को पहचानने और निगरानी करने तथा असामाजिक या आपराधिक गतिविधियों को रोकने या उनकी जांच करने के लिए सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए निगरानी बहुत उपयोगी है। 'संपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम' जैसे कार्यक्रमों, हार्ड स्पीड निगरानी कंप्यूटर और बायोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर जैसी तकनीकों और साइबर अपराध कानूनों के आगमन के साथ अब सरकारों के पास नागरिकों की गतिविधियों पर नज़र रखने की अभूतपूर्व क्षमता है।

इसके विपरीत कई नागरिक अधिकार और अन्य समूहों और गैर सरकारी संगठनों ने चिंता व्यक्त की है कि नागरिकों की बढ़ती निगरानी से बड़े पैमाने पर निगरानी वाला समाज बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित हो सकती है और गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस तरह की आशंकाओं के कारण हेप्टिंग बनाम एटी एंड टी32 जैसे कई मुकदमे हुए हैं। हैक्टीविस्ट समूह 'एनोनिमस' ने "कठोर निगरानी" के विरोध में सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया है।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) दो संचार पक्षों के बीच यात्रा करने वाले डेटा की निर्बाध सुरक्षा का एक डिजिटल संचार प्रतिमान है। इसमें मूल पक्ष डेटा को एन्क्रिप्ट करता है ताकि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही इसे डिक्लिप्ट कर सके, तीसरे पक्ष पर कोई निर्भरता नहीं। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मध्यस्थों, जैसे कि आईपी या एसपी, को संचार की खोज या छेड़छाड़ करने से रोकता है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आम तौर पर गोपनीयता और अखंडता दोनों की रक्षा करता है।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के उदाहरणों में वेब ट्रैफिक के लिए HTTPS, ईमेल के लिए PGP, त्वरित संदेश के लिए OTR, टेलीफोन के लिए ZRTP और रेडियो के लिए TETRA शामिल हैं।

आम सर्वर-आधारित संचार प्रणालियों में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन शामिल नहीं होता है। ये प्रणालियाँ केवल क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार की सुरक्षा की गारंटी दे सकती हैं। वे संचार करने वाले पक्षों के बीच सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देते। गैर-E2EE प्रणालियों के उदाहरण हैं Google Talk, Yahoo Messenger, Facebook और Dropbox। कुछ ऐसी प्रणालियाँ, उदाहरण के लिए LavaBit और SecretInk, ने खुद को "एंड-टू-एंड" एन्क्रिप्शन की पेशकश करने वाला भी बताया है, जबकि वे ऐसा नहीं करती हैं। कुछ प्रणालियाँ जो आम तौर पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की पेशकश करती हैं

³² "क्या अमेरिका एक निगरानी समाज में बदल रहा है?" अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनिन। 13 मार्च 2009 को पुनःप्राप्त।

& "बड़ा राक्षस, कमजोर जंजीरें: अमेरिकी निगरानी समाज का विकास" (पीडीएफ)। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनिन। 15 जनवरी, 2003। 13 मार्च, 2009 को पुनःप्राप्त। (https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network)

एन्क्रिप्शन में एक पिछला दरवाजा शामिल हो गया है जो संचार करने वाले पक्षों के बीच एन्क्रिप्शन कुंजी पर बातचीत को विफल कर देता है, उदाहरण के लिए स्काइप या हशमेल।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रतिमान सीधे संचार के अंतिम बिंदुओं पर जोखिमों को संबोधित नहीं करता है, जैसे कि क्लाइंट का तकनीकी शोषण, खराब गुणवत्ता वाले यादृच्छिक संख्या जनरेटर, या कुंजी एस्क्रो। E2EE ट्रैफिक विश्लेषण को भी संबोधित नहीं करता है, जो कि अंतिम बिंदुओं की पहचान और भेजे जाने वाले संदेशों के समय और मात्रा जैसी चीजों से संबंधित है।³³

एसएसएल/टीएलएस

1990 के दशक के मध्य में वर्ल्ड वाइड वेब पर ई-कॉमर्स की शुरुआत और तेजी से विकास ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार के प्रमाणीकरण और एन्क्रिप्शन की आवश्यकता थी। नेटस्केप ने नए मानक पर पहला प्रयास किया। उस समय, प्रमुख वेब ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर था। नेटस्केप ने सुरक्षित सॉकेट लेयर (SSL) नामक एक मानक बनाया। SSL को प्रमाणपत्र वाले सर्वर की आवश्यकता होती है। जब कोई क्लाइंट SSL-सुरक्षित सर्वर तक पहुँच का अनुरोध करता है, तो सर्वर क्लाइंट को प्रमाणपत्र की एक प्रति भेजता है। SSL क्लाइंट इस प्रमाणपत्र की जाँच करता है (सभी वेब ब्राउज़र CA रूट प्रमाणपत्रों की एक विस्तृत सूची के साथ आते हैं), और यदि प्रमाणपत्र जाँच में विफल हो जाता है, तो सर्वर प्रमाणित हो जाता है और क्लाइंट सत्र में उपयोग के लिए एक सममित-कुंजी सिफर पर बातचीत करता है। सत्र अब SSL सर्वर और SSL क्लाइंट के बीच एक बहुत ही सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सुरंग में है।³⁴

1.4 सारांश

आज सॉफ्टवेयर तकनीक सबसे तेजी से बढ़ती हुई तकनीक है। सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी के मूल में है। आज हमारे जीवन का हर हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर है।

कंप्यूटर डेटा के रूप में ली गई जानकारी पर काम करता है। पूरे डेटा का विश्लेषण करने के बाद यह आउटपुट के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। संबंधित सॉफ्टवेयर की मदद से इसकी विश्लेषण गति अद्भुत है। दूसरे शब्दों में सॉफ्टवेयर डेटा को कच्चे माल के रूप में लेता है और इसे अंतिम उत्पाद के रूप में उपयोगी जानकारी में बदल देता है।

सॉफ्टवेयर की प्रयोज्यता किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसकी प्रयोज्यता अब हर क्षेत्र में फैल चुकी है, यानी धरती, हवा, अंतरिक्ष और पानी। कंप्यूटर (हार्डवेयर) और सॉफ्टवेयर एक सिक्के के दो पहलू हैं।

इन्हें एक साथ सॉफ्टवेयर की तकनीक के रूप में जाना जाता है। कर्नेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। कर्नेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम को कंप्यूटर के हार्डवेयर से जोड़ता है।

इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर में अरबों डिवाइस को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट (TCP/IP) का उपयोग करती है। एक वेब सर्च इंजन (गूगल याहू आदि) एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंटरनेट संचार सेवाओं में वॉयस ओवर आईपी, फ़ाइल ट्रांसफ़र, फ़ाइल शेयरिंग और स्क्रीन शेयरिंग शामिल हैं। वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वॉयस ओवर आईपी, वीओआईपी या आईपी टेलीफोनी भी) इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर वॉयस संचार और मल्टीमीडिया सत्रों की डिलीवरी के लिए एक पद्धति और तकनीकों का समूह है। एक कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क एक डिजिटल दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर को केबल या केबल का उपयोग करके स्थापित कनेक्शनों में पैकेट के रूप में डेटा का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है।

³³ विकिपीडिया

³⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network

वायरलेस मीडिया। मैलवेयर, बॉटनेट, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वर्म्स, रैनसमवेयर, स्केयरवेयर, स्पाइवेयर, ट्रोजन हॉर्स, की लॉगर, कीस्ट्रोक लॉगिंग आदि दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जिनका उद्देश्य लक्षित कंप्यूटर फ़ाइलों, अनुप्रयोगों और कंप्यूटर के कामकाज को नुकसान पहुंचाना है। एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर और इंटरनेट सुरक्षा प्रोग्राम वायरस का पता लगाकर और उन्हें खत्म करके प्रोग्राम करने योग्य डिवाइस को हमले से बचा सकते हैं।

HTML वेब पेज और वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए मानक मार्कअप भाषा है। CSS एक स्टाइल शीट भाषा है जिसका उपयोग मार्कअप भाषा में लिखे गए दस्तावेज़ की प्रस्तुति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफ़िक्स कंप्यूटर का उपयोग करके बनाए गए चित्र और फ़िल्में हैं। मल्टीमीडिया वह सामग्री है जो पाठ, ऑडियो, चित्र, एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिव सामग्री जैसे विभिन्न सामग्री रूपों के संयोजन का उपयोग करती है।

एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर, सिस्टम सॉफ़्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर सॉफ़्टवेयर, प्लगइन्स और एक्सटेंशन, एम्बेडेड सॉफ़्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सॉफ़्टवेयर के उदाहरण हैं। दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर या मैलवेयर वह सॉफ़्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है।

सॉफ़्टवेयर एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा जाता है। सॉफ़्टवेयर की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर Microsoft Office, Microsoft Windows और Linux जैसे वाणिज्यिक और सिस्टम सॉफ़्टवेयर के लिए। यदि सॉफ़्टवेयर दोषपूर्ण (बग) है, तो यह किसी व्यक्ति के काम को मिला सकता है, कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है और अन्य अप्रत्याशित चीजें कर सकता है। दोषों और त्रुटियों को "बग" कहा जाता है जिन्हें अक्सर अल्फा और बीटा परीक्षण के दौरान खोजा जाता है। सॉफ़्टवेयर का लाइसेंस उपयोगकर्ता को लाइसेंस प्राप्त वातावरण में सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार देता है, और मुफ्त सॉफ़्टवेयर लाइसेंस के मामले में, प्रतिलिपियाँ बनाने के अधिकार जैसे अन्य अधिकार भी प्रदान करता है।

कंप्यूटर को काम करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम का वह भाग जो एक सुपरिभाषित कार्य करता है, उसे एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम की अवधारणा कंप्यूटर विज्ञान के मूल में है। एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध निर्देशों की एक श्रृंखला है। एल्गोरिदम गणना, डेटा प्रोसेसिंग और स्वचालित तर्क कार्य कर सकते हैं। कोडिंग का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो सकता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के स्रोत कोड को डिजाइन करने, लिखने, परीक्षण करने, डिबग करने या समस्या निवारण करने और बनाए रखने की प्रक्रिया है (C++ प्रोग्रामिंग के लिए संकलन भाषा का एक उदाहरण है)। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटिंग समस्या के मूल निर्माण से लेकर निष्पादन योग्य कंप्यूटर प्रोग्राम तक ले जाती है। प्रोग्रामिंग में विश्लेषण, समझ विकसित करना, एल्गोरिदम बनाना, एल्गोरिदम की आवश्यकताओं का सत्यापन जिसमें उनकी शुद्धता और संसाधन खपत शामिल है, और लक्ष्य प्रोग्रामिंग भाषा में एल्गोरिदम का कार्यान्वयन (आमतौर पर कोडिंग के रूप में संदर्भित) जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ़्टवेयर के विकास के लिए इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग है। सॉफ़्टवेयर विकास एक लंबी और व्यापक प्रक्रिया है जिसमें टीम वर्क शामिल है और इसमें कई चरण शामिल हैं। जैसे: समस्या का विश्लेषण, बाजार अनुसंधान, प्रस्तावित व्यावसायिक समाधान के लिए आवश्यकताओं को इकट्ठा करना, सॉफ़्टवेयर-आधारित समाधान के लिए एक योजना या डिजाइन तैयार करना, सॉफ़्टवेयर का कार्यान्वयन (कोडिंग), सॉफ़्टवेयर का परीक्षण, परिनिर्माण, रखरखाव और बग फिक्सिंग। मॉडलिंग भाषा कोई भी कृत्रिम भाषा है जिसका उपयोग किसी संरचना में सूचना या ज्ञान या सिस्टम को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है जिसे एक सुसंगत द्वारा परिभाषित किया जाता है

नियमों का सेट। यह ग्राफिकल या टेक्स्टुअल हो सकता है। सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाना एक जटिल विधि है जिसमें तकनीक और कला दोनों शामिल हैं। डिज़ाइनिंग का उद्देश्य अलग-अलग हो सकता है। प्रोग्रामिंग के उद्देश्य और तकनीकों पर ऊपर की इकाई में चर्चा की गई है।

कंप्यूटर नेटवर्क और उसके नेटवर्क-पहुंच योग्य संसाधनों की अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग, संशोधन या अस्वीकृति को रोकने और निगरानी करने के लिए, नेटवर्क प्रशासकों द्वारा विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। नेटवर्क निगरानी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और सुरक्षित सॉकेट लेयर कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनका उपयोग नेटवर्क सुरक्षा में किया जाता है।

1.5 शब्दावली

1. दुर्भावनापूर्ण: नुकसान पहुंचाने का इरादा; नुकसान पहुंचाने का इरादा
2. IPS या ASPs: इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट तक पहुँचने, उसका उपयोग करने या उसमें भाग लेने के लिए सेवाएँ प्रदान करता है। एप्लिकेशन सेवा प्रदाता (ASP) एक व्यवसाय है जो नेटवर्क पर ग्राहकों को कंप्यूटर-आधारित सेवाएँ प्रदान करता है; जैसे कि किसी विशेष सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन (जैसे ग्राहक संबंध प्रबंधन) तक पहुँच एक मानक प्रोटोकॉल (जैसे HTTP) का उपयोग करके।
3. HTTPS: HTTPS कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (HTTP) का एक विस्तार है, और इंटरनेट पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
4. पीजीपी: प्रिटी-गुड-प्राइवैसी एक एन्क्रिप्शन प्रोग्राम है जो क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा प्रदान करता है डेटा संचार के लिए गोपनीयता और प्रमाणीकरण।
5. ओटीआर: ऑफ-द-रिकॉर्ड मैसेजिंग (ओटीआर) एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो त्वरित संदेश वार्तालाप के लिए एन्क्रिप्शन।
6. इंस्टेंट मैसेजिंग: इंस्टेंट मैसेजिंग (IM) तकनीक इंटरनेट पर ऑनलाइन टेक्स्ट ट्रांसमिशन का एक प्रकार है।
चैट करें वास्तविक समय प्रदान करता है
मैसेंजर लोकल एरिया नेटवर्क पर इसी तरह काम करता है। छोटे संदेश आम तौर पर दो पक्षों के बीच भेजे जाते हैं, जब प्रत्येक उपयोगकर्ता एक विचार पूरा करने और "भेजें" का चयन करता है।
7. ZRTP: ZRTP ("Z" इसके आविष्कारक, ज़िम्मेदार का संदर्भ है; "RTP" का अर्थ है रियल-टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल) एक क्रिप्टोग्राफिक कुंजी-अनुबंध प्रोटोकॉल है, जो रियल-टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पर आधारित वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) फोन टेलीफोनी कॉल में दो अंत बिंदुओं के बीच एन्क्रिप्शन के लिए कुंजियों पर बातचीत करने के लिए है।
8. TETRA: टेट्राट्रियल ट्रंकड रेडियो (TETRA; जिसे पहले ट्रांस-यूरोपियन ट्रंकड रेडियो के नाम से जाना जाता था), ट्रंकड रेडियो सिस्टम के लिए एक यूरोपीय मानक है, यह एक पेशेवर मोबाइल रेडियो और दो-तरफ़ा ट्रांसीवर विनिर्देश है। TETRA को विशेष रूप से सरकारी एजेंसियों, आपातकालीन सेवाओं, (पुलिस बल, अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस) सार्वजनिक सुरक्षा नेटवर्क, ट्रेन रेडियो के लिए रेल परिवहन कर्मचारियों, परिवहन सेवाओं और सेना द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया था।
9. डीबगिंग: सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में डीबगिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि किसी प्रोग्राम में दोष होने से उसके लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।
उपयोगकर्ताओं.
10. तर्कशास्त्र : तर्कशास्त्र, जिसका मूल अर्थ "शब्द" या "जो बोला जाता है" था, लेकिन अब इसका अर्थ "विचार" या "कारण" हो गया है, यह सत्य के सबसे सामान्य नियमों से संबंधित विषय है, और अब इसे आम तौर पर सत्य के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में माना जाता है।

वैध अनुमान का रूप। वैध अनुमान वह है जिसमें अनुमान की मान्यताओं और उसके निष्कर्ष के बीच तार्किक समर्थन का एक विशिष्ट संबंध होता है।

ऐतिहासिक रूप से, तर्कशास्त्र का अध्ययन दर्शनशास्त्र (प्राचीन काल से) और गणित (19वीं शताब्दी के मध्य से) में किया जाता रहा है, और हाल ही में तर्कशास्त्र का अध्ययन कंप्यूटर विज्ञान, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान और अन्य क्षेत्रों में किया जाने लगा है।

11. प्रोलॉग: प्रोलॉग एक सामान्य प्रयोजन तर्क प्रोग्रामिंग भाषा है जो निम्न से सम्बंधित है
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान।
12. एपीआई: कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API)
अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए सबरूटीन परिभाषाओं, प्रोटोकॉल और उपकरणों का ज्ञान।
13. संचार प्रोटोकॉल: संचार प्रोटोकॉल नियमों की एक प्रणाली है जो संचार प्रणाली की दो या अधिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की भौतिक मात्रा के माध्यम से सूचना संचारित करने की अनुमति देती है। प्रोटोकॉल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन द्वारा कार्यान्वित किए जा सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जिसे TCP/IP भी कहा जाता है, सभी आधुनिक नेटवर्किंग की नींव है।

1.6 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न

- (i) कंप्यूटर के मूल घटक क्या हैं?
- (ii) वेब पेज और वेब अनुप्रयोग बनाने के लिए मानक मार्कअप भाषा का नाम बताइए।
- (iii) सर्वर सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए।
- (iv) क्या कम्प्यूटर प्रोग्राम कॉपीराइट कानून के अंतर्गत आता है?
- (v) ऊपर से नीचे तक का दृष्टिकोण जिसे कभी-कभी अमेरिकी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। क्यों?
- (vi) ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार सिद्धांत क्या हैं?

2. रिक्त स्थान भरें

- (i) यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, जिसे ----- कहा जाता था।
- (ii) ----- सोशल मीडिया के उदाहरण हैं।
- (iii) ----- ऐसे प्रोग्राम हैं जो अपनी संरचनाओं या प्रभावों को दोहरा सकते हैं
कंप्यूटर पर अन्य फ़ाइलों या संरचनाओं को संक्रमित करना।
- (iv) ----- एक एल्गोरिथ्म है जो कंप्यूटर कोड जैसा दिखता है।
- (v) अनेक रूपों में खोजने की क्षमता को ----- कहते हैं।
- (vi) ----- सार्वजनिक विधियों तक पहुंच को प्रतिबंधित करके डेटा कार्यान्वयन को छिपाने का तंत्र है।
- (vii) एक LAN को ----- का उपयोग करके WAN (वाइड एरिया नेटवर्क) से जोड़ा जा सकता है।
- (viii) कंप्यूटर के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर को ----- कहा जाता है।

3. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न

- (*) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सामेलन है। (सत्य/असत्य)

- (ii) कम्प्यूटर वर्म्स एक कीट है। (सत्य/असत्य)
- (iii) सॉफ्टवेयर केवल एक ही प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। (सत्य/असत्य)
- (iv) एल्गोरिदम गणना, डेटा प्रसंस्करण और स्वचालित तर्क कार्य नहीं कर सकते हैं। (सत्य/असत्य)
- (v) नेटवर्क कंजेशन तब होता है जब कोई लिंक या नोड कम डेटा ले जा रहा होता है इसकी सेवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। (सत्य/असत्य)
- (vi) एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आमतौर पर डिजिटल संचार की गोपनीयता और अखंडता की रक्षा करता है। (सत्य/असत्य)
- (vii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सीपीयू, रैम और अन्य घटक सभी एक साथ काम करते हैं। (सत्य/असत्य)

1.7 संदर्भ

1. https://en.wikiversity.org/wiki/Introduction_to_Turing_Machines
2. [https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_\(operating_system\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(operating_system))
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/Email>
4. https://en.wikiversity.org/wiki/Internet_Fundamentals/Networking
5. https://en.wikiversity.org/wiki/Internet_Fundamentals/Security
6. https://en.wikiversity.org/wiki/Internet_Fundamentals/Graphics_and_Multimedia
7. https://en.wikiversity.org/wiki/Internet_Fundamentals/Databases
8. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink>
9. <https://en.wikipedia.org/wiki/Software>
10. <https://en.wikipedia.org/wiki/Software>
11. https://en.wikipedia.org/wiki/Software_development
12. <http://www.sciencehq.com/computing-technology/programming-techniques.html>
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
14. साइबर कानून के मूल सिद्धांत और उभरता हुआ न्यायशास्त्र; इकाई- 3; अवलोकन कम्प्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी
15. साइबर और ई-कॉमर्स कानून, पीएम बख्शी और आरके सूरी
16. गुप्ता एवं अग्रवाल, साइबर लॉ; प्रथम संस्करण, प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी
17. मिश्रा जेपी, साइबर कानूनों का परिचय, केंद्रीय कानून प्रकाशन: प्रथम संस्करण: 2012.

1.8 सुझाए गए पठन सामग्री

1. विकिपीडिया
2. <http://www.sciencehq.com/computing-technology/programming-techniques.html>
3. मिश्रा जेपी, साइबर कानूनों का परिचय, केंद्रीय कानून प्रकाशन: प्रथम संस्करण: 2012.
4. पवन दुग्गल, साइबर कानून पर पाठ्यपुस्तक, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स, 2014 संस्करण।
5. साइबर और ई-कॉमर्स कानून, पीएम बख्शी और आरके सूरी
6. गुप्ता एवं अग्रवाल, साइबर लॉ; प्रथम संस्करण, प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी

1.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें:

(i) कर्नेल (ii)

इंटरनेट (iii)

इलेक्ट्रॉनिक मेल

(iv) सोशल मीडिया

(v) सीएसएस

(vi) वर्ल्ड वाइड वेब

(vii) हाइपरलिंक

2. सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें।

3. मॉडलिंग भाषा का संक्षेप में वर्णन करें।

4. बग फिक्सिंग या डिबगिंग पर राइट का संक्षिप्त नोट।

5. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं? यह सॉफ्टवेयर पर कैसे लागू होता है? विकास?

6. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटिंग समस्या के मूल निर्माण से लेकर निष्पादन योग्य कंप्यूटर प्रोग्राम तक ले जाती है। अपने शब्दों में समझाइए।

7. एल्गोरिदम और कोडिंग से आप क्या समझते हैं? क्या एल्गोरिदम कंप्यूटर विज्ञान का मूल है?

8. राइट ने प्रोग्रामिंग के टॉप डाउन और बॉटम अप दृष्टिकोण के बीच अंतर बताया तकनीक।

9. कंप्यूटर नेटवर्किंग पर एक निबंध लिखें।

10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें:

(i) वायर्ड प्रौद्योगिकियां

(ii) वायरलेस प्रौद्योगिकियां

(iii) लैन

(iv) वैन

(v) हान

(vi) वीपीएन

(vii) नेटवर्क भीड़भाड़

(viii) एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

(ix) नेटवर्क निगरानी

11. कंप्यूटर नेटवर्क और उसके नेटवर्क-सुलभ संसाधनों तक अनधिकृत पहुंच, दुरुपयोग, संशोधन या इनकार को रोकने और निगरानी करने के लिए, उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न सुरक्षा उपाय किए जाते हैं?

12. फ्रेंड-टू-फ्रेंड या F2F कंप्यूटर नेटवर्क क्या है?

1.10 उत्तर

एसएक्यूएस

1. (i) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर; 1.3.1 देखें (ii) हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML); देखें (iv) हां; 1.3.1.2 देखें
1.3.1.1 (iii) PHP, जावा, ASP.NET; 1.3.1.2 देखें

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [31]

(v) क्योंकि यह 1970 के दशक में एफबीआई (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण था; 1.3.2.3.3 देखें (vi) एनकैप्सुलेशन, अमूर्तता, विरासत और बहुरूपता; 1.3.2.3.5 देखें

2. (i) पास्कलीन; देखें 1.3.1 1.3.1.1

(ii) फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब; देखें

(iii) कम्प्यूटर वायरस; 1.3.1.1 देखें (iv) स्यूडोकोड; 1.3.2 देखें (v) बहुरूपता; 1.3.2;3;5 देखें (vi) एनकैप्सुलेशन; 1.3.2.3.5 देखें (vii)

देखें 1.3.3

राउटर;

(viii) कर्नेल; देखें 1.3.1

3. (i) सत्य; 1.3 देखें (ii) असत्य; 1.3.1.3 देखें (iii) असत्य; 1.3.1.2 देखें (iv) असत्य; 1.3.2 देखें

(v) असत्य; 1.3.3 देखें (vi) सत्य; 1.3.4 देखें (vii) सत्य; 1.3.1 देखें

टर्मिनल और आधुनिक प्रश्न:

1. (i) 1.3.1 देखें 1.3.1.1

(ii) 1.3.1.1 देखें (iii) 1.3.1.1 देखें (iv) 1.3.1.1 देखें (vi) 1.3.1.1 देखें (vii) 1.3.1.1 देखें

(viii)

देखें

2. 1.3.1.2 देखें

3. 1.3.2.2 देखें

4. 1.3.2.1 देखें

5. 1.3.2.1 देखें

6. 1.3.2 देखें

7. 1.3.2 देखें

8. 1.3.2.3 देखें

9. 1.3.3 देखें

10. (i)-(vi) 1.3.3 देखें

(vii)-(ix) 1.3.4 देखें

11. 1.3.4 देखें

12. 1.3.3 देखें

युनिट 2

इंटरनेट में कॉपीराइट

संरचना

2.1 परिचय

2.2 उद्देश्य

2.3 विषय

2.3.1 भारत में कॉपीराइट कानून - एक संक्षिप्त अवलोकन

2.3.1.1 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1983

2.3.1.2 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1984

2.3.1.3 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1992

2.3.1.4 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1994

2.3.1.5 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1999

2.3.1.6 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम) 2012

2.3.2 कॉपीराइट संरक्षण का विषय

2.3.3 डब्ल्यूआईपीओ इंटरनेट संधियाँ

2.3.3.1 डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि के तहत संरक्षित अधिकार

2.3.3.2 तकनीकी सुरक्षा उपाय और अधिकार प्रबंधन सूचना (टीपीएमएस/आरएमआई)

2.3.3.3 पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के लिए कॉपीराइट सीमाओं और अपवादों पर संधि प्रस्ताव

2.3.4 कॉपीराइट कानून इंटरनेट पर किसी भी कार्य की सुरक्षा कैसे करता है

2.3.4.1 कॉपीराइट का पंजीकरण

2.3.4.2 बहुआयामी विचारों का संरक्षण

2.3.4.4 वितरण और संचार का अधिकार

2.3.4.5 डिजिटल कार्यों में उचित उपयोग

2.3.4.6 इंटरनेट पाइरेसी से सुरक्षा

2.4 सारांश

2.5 शब्दावली

2.6 एसएक्यूएस

2.7 संदर्भ

2.8 सुझाए गए पठन सामग्री

2.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

2.10 उत्तर SAQS

2.1 परिचय

कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क को 'बौद्धिक संपदा' माना जाता है। हर वह काम जो मौलिक है और मानव बुद्धि का परिणाम है, बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आता है और मालिक या आविष्कारक का उस पर कुछ विशेष अधिकार होता है। पेटेंट में डिवाइस, सूत्र, उपकरण और ऐसी कोई भी चीज़ शामिल है जिसकी उपयोगिता है और जिसे कानून नियंत्रित करता है, आविष्कारकों को अपने आविष्कार के डिज़ाइन की नकल करने का विशेष अधिकार देता है। ट्रेडमार्क एक शब्द, वाक्यांश या लोगो है जो किसी उत्पाद, सेवा या व्यक्ति या कंपनी की पहचान करता है जो अपने ग्राहकों को उत्पाद या सेवा प्रदान करता है। कॉपीराइट कला, संगीत नाटकों, फिल्मों, साहित्य और विद्वानों के काम पर लागू होता है, यह दूसरों को काम की नकल करने से रोकता है।

इंटरनेट तकनीक किसी भी अन्य तकनीक की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। इंटरनेट पर लागू होने वाले कॉपीराइट सहित कोई भी कानून संसद या न्यायालय द्वारा अपने पूर्ववर्ती के माध्यम से स्थापित किया गया है। इंटरनेट के बारे में यह एक आम धारणा है कि ऑनलाइन पोस्ट की गई किसी भी चीज़ को कॉपी या डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता अलग है। ऑनलाइन सामग्री पर भी कॉपीराइट होता है। वर्तमान इकाई में हम इंटरनेट पर कॉपीराइट के मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें समझ सकेंगे-

- कॉपीराइट क्या है?
- कॉपीराइट का विषय और अर्थ
- "इंटरनेट संधि" क्या होती है?
- भारतीय कॉपीराइट अधिनियम इंटरनेट पर कॉपीराइट मामले की सुरक्षा कैसे करता है
- टीएमपी और आरएमपी क्या हैं?
- इंटरनेट पर कॉपीराइट सामग्री का उचित उपयोग, कानून द्वारा अनुमत

2.3 विषय

2.3.1 भारत में कॉपीराइट कानून - एक संक्षिप्त अवलोकन

इंटरनेट पर कॉपीराइट की प्रयोज्यता पर चर्चा करने से पहले, आइए कॉपीराइट के बारे में चर्चा करें - इसका अर्थ, इतिहास, भारत में कानून आदि।

प्राचीन काल से ही भारत में तथाकथित 'बौद्धिक संपदा अधिकार' जैसी कोई अवधारणा नहीं रही है। ज्ञान हमेशा सार्वजनिक डोमेन में होता है और बिना किसी प्रतिबंध के सभी के लिए उपलब्ध होता है। अधिकांश विकासशील देशों की तरह, भारत को भी आधुनिक कॉपीराइट कानून अपने औपनिवेशिक शासन से उपहार के रूप में मिला।

स्वतंत्रता से पहले भारत में कॉपीराइट कानून कॉपीराइट अधिनियम 1847 द्वारा शासित था, जो भारत के लिए पहला कॉपीराइट अधिनियम था और फिर 1914 का अधिनियम जो कुछ संशोधनों के साथ 1911 के ब्रिटिश कॉपीराइट अधिनियम की प्रतिकृति था। यह कानून 1957 तक देश का कानून बना रहा।³⁵

संसद में कॉपीराइट अधिनियम 1957 पारित करने के उद्देश्य और कारण निम्नानुसार बताए गए:

³⁵ अनुच्छेद 372; विद्यमान कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन

"कॉपीराइट से संबंधित मौजूदा कानून यू.के. के कॉपीराइट अधिनियम 1911 में निहित है, जिसे भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1914 द्वारा संशोधित किया गया है। इस तथ्य के अलावा कि यू.के. अधिनियम भारत की परिवर्तित संवैधानिक स्थिति के साथ मेल नहीं खाता है, बढ़ती जन चेतना और लेखकों के अधिकारों और दायित्वों तथा पिछले 50 वर्षों के दौरान मौजूदा कानून के कामकाज में प्राप्त अनुभव के आलोक में कॉपीराइट के विषय पर एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर कानून बनाना आवश्यक है। प्रसारण, लिथोग्राफी आदि जैसे संचार के नए और उन्नत साधन भी मौजूदा कानून में कुछ संशोधनों की मांग करते हैं। कॉपीराइट के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए, जिन्हें भारत स्वीकार कर सकता है। इसलिए कॉपीराइट के कानून का पूर्ण संशोधन अपरिहार्य प्रतीत होता है।"³⁶

कॉपीराइट से संबंधित मामले भारतीय संविधान की सूची-1 37 की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत आते हैं, जो कि संघ सूची है और यह केंद्रीय कानून का विषय है। इस प्रकार, इस विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद को है।

भारत कॉपीराइट कानून के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अधिकांश महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सदस्य है, जिसमें 1886 का बर्न कन्वेंशन (जैसा कि 1971 में पेरिस में संशोधित किया गया), 1951 का यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, 1961 का रोम कन्वेंशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स) शामिल हैं। लेकिन भारत WIPO कॉपीराइट संधि (WCT) और WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WPPT) का सदस्य नहीं है।

2.3.1.1 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1983

प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण वैश्विक पायरेसी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसलिए 1971 में पेरिस में बर्न और यूनाइटेड कॉपीराइट कन्वेंशन को संशोधित किया गया और जनता के व्यापक हितों के लिए विकासशील देशों को विदेशी कार्यों तक पहुँच के लिए विशेष रियायतें दी गईं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विकास के अनुरूप कॉपीराइट संशोधन अधिनियम, 1983 लागू हुआ।

2.3.1.2 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1984

प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के कारण कॉपीराइट कानून में और संशोधन किया गया। यह संशोधन वीडियो फिल्म को शामिल करने, डुप्लीकेशन उपकरण लाने, कंप्यूटर प्रोग्राम की सुरक्षा, दंड में वृद्धि और कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकारों के उल्लंघन को आर्थिक अपराध घोषित करने आदि से संबंधित था।

2.3.1.3 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1992

इस बार कॉपीराइट संरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई और अब कॉपीराइट की कुल अवधि आजीवन प्लस सामान्यतः 60 वर्ष हो गयी है।

2.3.1.4 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1994

³⁶ जैसा कि पी. नारायणन, कॉपीराइट एवं औद्योगिक डिजाइन कानून, ईस्टर्न लॉ हाउस, 2nd डी में उल्लेख किया गया है सं., 1995, पृ. 7.; http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/61938/11/11_chapter%204.pdf

³⁷ अनुसूची 7, सूची I प्रविष्टि 49, पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन; कॉपीराइट, ट्रेड-मार्क और व्यापारिक चिह्न।

³⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_India

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [35]

यह संशोधन ट्रिप्स समझौते के अनुरूप भारतीय कॉपीराइट कानून में लाया गया और कॉपीराइट अधिनियम 1957 में बड़े बदलाव किए गए। इसने कॉपीराइट कानून के कई प्रावधानों में संशोधन किया, जिसमें कंप्यूटर की उल्लंघनकारी प्रतिक्रिया के उपयोग से संबंधित अपराधों में बदलाव शामिल हैं।

कार्यक्रम.

2.3.1.5 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम), 1999

ये संशोधन भारतीय कॉपीराइट कानून को यथावत बनाए रखने के लिए किए गए थे।

अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट कानून के समान फुटेज और समय की तकनीकी उन्नति के कारण विकसित आधुनिक तंत्र के उपयोग से बौद्धिक संपदा की रक्षा करना। यह संशोधन मुख्य रूप से धारा 38, 40 ए, 42 ए और 52 आदि जैसी कुछ धाराओं से संबंधित था। इन धाराओं के तहत संसद ने ट्रिप्स समझौते द्वारा दुनिया भर में लागू किए गए परिवर्तनों से निपटने के लिए कुछ बदलाव किए। कलाकार के अधिकार जो पहले 25 साल के लिए संरक्षित थे, इस संशोधन में 50 साल तक बढ़ा दिए गए। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन केंद्र सरकार को अधिनियम के अध्याय-VIII को कुछ अन्य देशों में प्रसारण संगठनों और कलाकारों पर लागू करने की शक्ति थी, जिसे इस संशोधन द्वारा डाला गया है।

2.3.1.6 कॉपीराइट (संशोधन अधिनियम) 2012

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में इस संशोधन को एक बड़ा कदम माना गया है, जिसने अधिनियम को WIPO कॉपीराइट संधि (WCT) और WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WPPT) के अनुरूप बना दिया है, जिसे संयुक्त रूप से "WIPO इंटरनेट संधि" के रूप में जाना जाता है। कॉपीराइट की सुरक्षा को ऑनलाइन और डिजिटल वातावरण तक विस्तारित करने के लिए यह नीतिगत पहल अनिवार्य थी।³⁹

2.3.2 कॉपीराइट संरक्षण का विषय

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 के प्रावधान स्पष्ट रूप से उन कार्यों के बारे में बताते हैं जिनमें कॉपीराइट रहेगा या नहीं रहेगा। धारा 13 इस प्रकार है-

(1) इस धारा के उपबंधों तथा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सम्पूर्ण भारत में निम्नलिखित प्रकार की कृतियों में कॉपीराइट विद्यमान रहेगा, अर्थात्:-

(क) मौलिक साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्य;

(ख) सिनेमैटोग्राफ फिल्मों; और

(ग) ध्वनि रिकॉर्डिंग.

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य पर, उस कार्य को छोड़कर जिस पर धारा 40 या धारा 41 के उपबंध लागू होते हैं, कॉपीराइट तब तक विद्यमान नहीं होगा, जब तक कि,—

(i) किसी प्रकाशित कृति की दशा में, कृति भारत में पहली बार प्रकाशित हुई है, या जहां कृति भारत के बाहर पहली बार प्रकाशित हुई है, वहां लेखक ऐसे प्रकाशन की तारीख को भारत का नागरिक है, या ऐसी दशा में जहां लेखक की उस तारीख को मृत्यु हो गई थी, वहां वह अपनी मृत्यु के समय भारत का नागरिक था;

³⁹ <http://www.livelaw.in/reflections-five-years-copyright-amendment-act-2012/>

(ii) वास्तुकला संबंधी कार्य के अलावा किसी अप्रकाशित कार्य के मामले में, लेखक उस कार्य के निर्माण की तिथि पर भारत का नागरिक है या भारत का अधिवासी है; और

(iii) वास्तुकला संबंधी कार्य की स्थिति में, कार्य भारत में स्थित है।

स्पष्टीकरण.- संयुक्त लेखकत्व वाली किसी कृति की दशा में, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कॉपीराइट प्रदान करने वाली शर्तें कृति के सभी लेखकों द्वारा पूरी की जाएंगी।

(3) कॉपीराइट अस्तित्व में नहीं रहेगा - (क) किसी सिनेमैटोग्राफ फिल्म में यदि फिल्म का कोई बड़ा हिस्सा किसी अन्य कार्य के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है;

(ख) किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कृति के संबंध में की गई किसी ध्वनि रिकॉर्डिंग में, यदि ध्वनि रिकॉर्डिंग करते समय ऐसी कृति के कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया हो।

(4) किसी चलचित्र फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट किसी ऐसे कार्य में पृथक कॉपीराइट को प्रभावित नहीं करेगा जिसके संबंध में या जिसके किसी महत्वपूर्ण भाग के संबंध में, यथास्थिति, फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाई गई है।

(5) वास्तुकला के कार्य के मामले में, कॉपीराइट केवल कलात्मक चरित्र और डिजाइन तक ही सीमित रहेगा तथा निर्माण की प्रक्रियाओं या विधियों तक विस्तारित नहीं होगा।

यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 40 केंद्र सरकार को विदेशी कृतियों पर भी कॉपीराइट लागू करने का अधिकार देती है। इस अधिनियम की धारा 41 कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कृतियों के लिए प्रावधान प्रदान करती है।

कॉपीराइट का अर्थ⁴⁰— इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “कॉपीराइट” का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी कार्य या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग के संबंध में निम्नलिखित में से किसी कार्य को करने या करने के लिए प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार है, अर्थात:—

(क) किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कृति की दशा में, जो कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं है,—

(i) किसी भी भौतिक रूप में कार्य का पुनरुत्पादन करना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किसी भी माध्यम में उसका भंडारण भी शामिल है;

(ii) कार्य की प्रतियां जनता को जारी करना, जो पहले से प्रचलन में न हों;

(iii) कार्य को सार्वजनिक रूप से करना, या जनता को संप्रेषित करना;

(iv) कार्य के संबंध में कोई सिनेमैटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाना;

(v) कार्य का कोई अनुवाद करना; (vi) कार्य का कोई रूपान्तरण करना;

(vii) कार्य के अनुवाद या रूपांतरण के संबंध में, उप-खंड (i) से (vi) में कार्य के संबंध में निर्दिष्ट कार्यों में से कोई भी कार्य करना;

(ख) कम्प्यूटर प्रोग्राम की दशा में,—

(i) खंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई कार्य करना;

⁴⁰ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [37]

(ii) कंप्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति को बेचना या व्यावसायिक किराये पर देना या बिक्री या व्यावसायिक किराये के लिए प्रस्ताव देना:

बशर्ते कि ऐसा वाणिज्यिक किराया उन कम्प्यूटर प्रोग्रामों के संबंध में लागू नहीं होगा जहां प्रोग्राम स्वयं किराये का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है।

(ग) किसी कलात्मक कार्य की दशा में,—

(i) किसी भी भौतिक रूप में कार्य को पुनः प्रस्तुत करना, जिसमें शामिल हैं-

(ए) इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से किसी भी माध्यम में इसका भंडारण; या

(बी) द्वि-आयामी कार्य का त्रि-आयामों में चित्रण; या

(सी) त्रि-आयामी कार्य का दो-आयामों में चित्रण;

(ii) कार्य को जनता तक संप्रेषित करना;

(iii) जनता को कार्य की प्रतियां जारी करना, जो पहले से प्रचलन में न हों;

(iv) किसी सिनेमैटोग्राफ फिल्म में कार्य को शामिल करना;

(v) कार्य का कोई भी अनुकूलन करना;

(vi) कार्य के अनुकूलन के संबंध में उप-खंड (i) से (iv) में कार्य के संबंध में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करना;

(घ) सिनेमैटोग्राफ फिल्म की दशा में,—

(i) फिल्म की प्रतिलिपि बनाना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(ए) किसी छवि का फोटोग्राफ जो उसका भाग हो; या

(बी) इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से किसी भी माध्यम में इसका भंडारण;

(ii) किसी भी प्रतिलिपि को बेचना या व्यावसायिक किराये पर देना या बिक्री के लिए या ऐसे किराये के लिए प्रस्ताव देना

(iii) फिल्म को जनता तक पहुंचाना;

(ङ) ध्वनि रिकॉर्डिंग के मामले में,—

(i) इसे सम्मिलित करते हुए कोई अन्य ध्वनि रिकॉर्डिंग करना [जिसके अंतर्गत इसे इलेक्ट्रॉनिक या अन्य साधनों द्वारा किसी भी माध्यम में संग्रहीत करना भी है;

(ii) ध्वनि रिकॉर्डिंग की किसी प्रति को बेचना या व्यावसायिक किराये पर देना या बिक्री के लिए या ऐसे किराये के लिए प्रस्ताव देना;

(iii) ध्वनि रिकॉर्डिंग को जनता तक पहुँचाना।

2.3.3 डब्ल्यूआईपीओ इंटरनेट संधियों

पिछले कई दशकों में तकनीकी प्रगति के साथ कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। इंटरनेट के ज़रिए कार्यों का प्रसार नवीनतम विकास है जो कॉपीराइट से संबंधित नए सवाल उठाता है।

साइबरस्पेस में कॉपीराइट सुरक्षा के लिए नए मानकों को आकार देने के लिए चल रही अंतरराष्ट्रीय बहस में WIPO गहराई से शामिल है। संगठन WIPO कॉपीराइट का प्रबंधन करता है

संधि और WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, जिन्हें साथ में "इंटरनेट संधि" के रूप में जाना जाता है। दोनों ने इंटरनेट या अन्य डिजिटल नेटवर्क पर रचनात्मक कार्यों तक अनधिकृत पहुंच और उपयोग को रोकने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय मानदंड निर्धारित किए हैं।

डब्ल्यूसीटी साहित्यिक और कलात्मक कार्यों, जैसे लेखन और कंप्यूटर प्रोग्राम; मूल डेटाबेस; संगीत कार्य; दृश्य-श्रव्य कार्य; ललित कला और फोटोग्राफ के कार्यों के लेखकों के संरक्षण से संबंधित है; जबकि डब्ल्यूपीपीटी कलाकारों और फोनोग्राम के उत्पादकों के लेखकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है।

दोनों संधियों के तहत देशों को बुनियादी अधिकारों का एक ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे रचनाकारों को यह नियंत्रित करने और/या मुआवजा पाने की अनुमति मिलती है कि उनकी रचनाओं का उपयोग और आनंद दूसरों द्वारा किस तरह से किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संधियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि जब उनके कार्यों को इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, तो उन अधिकारों के मालिकों को पर्याप्त और प्रभावी रूप से संरक्षित किया जाता रहेगा। इस प्रकार संधियाँ स्पष्ट करती हैं कि मौजूदा अधिकार डिजिटल वातावरण में लागू होते रहते हैं। वे नए ऑनलाइन अधिकार भी बनाते हैं। अधिकारों के मालिकों और आम जनता के बीच हितों का उचित संतुलन बनाए रखने के लिए, 41 संधियाँ आगे स्पष्ट करती हैं कि देशों के पास डिजिटल वातावरण में अधिकारों के लिए अपवाद या सीमाएँ स्थापित करने में उचित लचीलापन है। देश, उचित परिस्थितियों में, गैर-लाभकारी शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्यों जैसे सार्वजनिक हित में समझे जाने वाले उपयोगों के लिए अपवाद दे सकते हैं।

संधियों में देशों से न केवल स्वयं अधिकार प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि अधिकारों के लिए दो प्रकार के तकनीकी सहायक भी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकार धारक अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने कार्यों को ऑनलाइन लाइसेंस देने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। पहला, जिसे "विरोधी-परिहार" प्रावधान के रूप में जाना जाता है, "हैकिंग" की समस्या से निपटता है: इसके लिए देशों से अधिकार धारकों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपायों (जैसे एन्क्रिप्शन) के परिहार के विरुद्ध पर्याप्त कानूनी सुरक्षा और प्रभावी उपाय प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। दूसरे प्रकार के तकनीकी सहायक इलेक्ट्रॉनिक "अधिकार प्रबंधन सूचना" के जानबूझकर परिवर्तन या विलोपन को प्रतिबंधित करने के लिए देशों की आवश्यकता के द्वारा ऑनलाइन बाज़ार की विश्वसनीयता और अखंडता की रक्षा करते हैं: अर्थात्, वह सूचना जो किसी भी संरक्षित सामग्री के साथ होती है, और जो कार्य, उसके निर्माता, कलाकार या स्वामी और उसके उपयोग के लिए नियम और शर्तों की पहचान करती है।⁴²

2.3.3.1 डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि के तहत संरक्षित अधिकार

WIPO कॉपीराइट संधि (WCT) बर्न कन्वेंशन के तहत एक विशेष समझौता है। यह डिजिटल वातावरण में कार्यों और लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। WCT कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किए जाने वाले निम्नलिखित दो विषयों का उल्लेख करता है:⁴³

(#) कंप्यूटर प्रोग्राम, चाहे उनकी अभिव्यक्ति का तरीका या रूप कुछ भी हो; और

⁴¹ प्रस्तावना, WIPO कॉपीराइट संधि, 1996

⁴² http://www.wipo.int/copyright/en/activities/internet_treaties.html

⁴³ http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html

- (ii) किसी भी रूप में डेटा या अन्य सामग्री ("डेटाबेस") का संकलन, जो उनकी सामग्री के चयन या व्यवस्था के कारण बौद्धिक रचनाएं बनती हैं।
(जहां डेटाबेस ऐसी रचना नहीं करता है, वह इस संधि के दायरे से बाहर है।)

लेखकों को दिए गए अधिकारों के संबंध में, बर्न कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के अलावा, संधि निम्नलिखित अधिकार भी प्रदान करती है:

- वितरण का अधिकार जनता को उत्पाद उपलब्ध कराने को अधिकृत करने का अधिकार है।
किसी कार्य की मूल प्रतियाँ या प्रतिलिपियाँ बिक्री या स्वामित्व के अन्य हस्तांतरण के माध्यम से।
- किराये का अधिकार मूल संपत्ति को जनता को वाणिज्यिक किराये पर देने का अधिकार है।
और तीन प्रकार की कृतियों की प्रतियाँ:
 - (i) कम्प्यूटर प्रोग्राम (सिवाय इसके कि कम्प्यूटर प्रोग्राम स्वयं किराये का अनिवार्य उद्देश्य न हो);
 - (ii) सिनेमैटोग्राफिक कार्य (लेकिन केवल उन मामलों में जहां वाणिज्यिक किराये के कारण ऐसे कार्यों की बड़े पैमाने पर नकल हो रही है, जिससे पुनरुत्पादन का विशेष अधिकार भौतिक रूप से प्रभावित हो रहा है); तथा
 - (iii) अनुबंधकारी पक्षों के राष्ट्रीय कानून में निर्धारित फोनोग्राम में सन्निहित कार्य (उन देशों को छोड़कर, जिनमें 15 अप्रैल, 1994 से ऐसे किराये के न्यायसंगत पारिश्रमिक के लिए एक प्रणाली लागू है)।
- जनता से संचार का अधिकार, जनता को तार या वायरलेस माध्यम से किसी भी संचार को अधिकृत करने का अधिकार है, जिसमें "कार्यों को जनता के लिए इस तरह से उपलब्ध कराना शामिल है कि जनता के सदस्य उस कार्य को किसी स्थान से और व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा चुने गए समय पर एक्सेस कर सकें"। उद्धृत अभिव्यक्ति, विशेष रूप से, इंटरनेट के माध्यम से ऑन-डिमांड, इंटरैक्टिव संचार को कवर करती है।

सीमाओं और अपवादों के संबंध में, WCT के अनुच्छेद 10 में बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 9(2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सीमाओं और अपवादों को निर्धारित करने के लिए तथाकथित "तीन चरण" परीक्षण को शामिल किया गया है, जो सभी अधिकारों पर लागू होता है। WCT के साथ सहमत कथन में प्रावधान है कि बर्न कन्वेंशन के अनुपालन में राष्ट्रीय कानून में स्थापित ऐसी सीमाएँ और अपवाद डिजिटल वातावरण तक बढ़ाए जा सकते हैं।

अनुबंध करने वाले राज्य डिजिटल वातावरण के लिए उपयुक्त नए अपवाद और सीमाएँ बना सकते हैं। मौजूदा सीमाओं और अपवादों का विस्तार या नई सीमाओं और अपवादों का निर्माण तभी संभव है जब "तीन-चरणीय" परीक्षण की शर्तें पूरी हों।

अवधि के संबंध में, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए संरक्षण की अवधि कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए।

संधि में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग और प्रयोग किसी औपचारिकता के अधीन नहीं हो सकता।

यह संधि अनुबंधकारी पक्षों को लेखकों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के संबंध में प्रयुक्त तकनीकी उपायों (जैसे, एन्क्रिप्शन) के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी उपाय प्रदान करने, तथा जानकारी को हटाने या बदलने के विरुद्ध कानूनी उपाय प्रदान करने के लिए बाध्य करती है, जैसे कि कुछ डेटा जो कार्यों या उनके लेखकों की पहचान करते हैं, जो उनके अधिकारों के प्रबंधन (जैसे, लाइसेंसिंग, रॉयल्टी का संग्रहण और वितरण) के लिए आवश्यक है ("अधिकार प्रबंधन सूचना")।

संधि प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को अपनी कानूनी प्रणाली के अनुसार संधि के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए बाध्य करती है। विशेष रूप से, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कानून के तहत प्रवर्तन प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं ताकि प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जा सके।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [40]

संधि द्वारा कवर किए गए अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी कृत्य के खिलाफ कार्रवाई। ऐसी कार्रवाई में उल्लंघन को रोकने के लिए त्वरित उपाय शामिल होने चाहिए, साथ ही ऐसे उपाय भी शामिल होने चाहिए जो आगे के उल्लंघन को रोकने में सहायक हों।

संधि अनुबंधकारी पक्षों की एक सभा की स्थापना करती है जिसका मुख्य कार्य संधि के रखरखाव और विकास से संबंधित मामलों को संबोधित करना है। यह संधि से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को WIPO के सचिवालय को सौंपता है।

यह संधि 1996 में संपन्न हुई तथा 2002 में लागू हुई।

यह संधि WIPO के सदस्य देशों और यूरोपीय समुदाय के लिए खुली है। संधि द्वारा गठित सभा अन्य अंतर-सरकारी संगठनों को संधि का हिस्सा बनने के लिए स्वीकार करने का निर्णय ले सकती है। अनुसमर्थन या परिग्रहण के दस्तावेज़ WIPO के महानिदेशक के पास जमा किए जाने चाहिए।

2.3.3.2 तकनीकी संरक्षण उपाय और अधिकार प्रबंधन सूचना (टीपीएम/आरएमआई)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संरक्षित सामग्री की अनधिकृत नकल को रोका जा सके या उसका पता लगाया जा सके, डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि (डब्ल्यूसीटी) में टीपीएम और आरएमआई से संबंधित नए प्रावधान शामिल किए गए।

टीपीएम तकनीकी सुरक्षा उपाय हैं जो डिजिटल प्रारूप में संरक्षित कार्य की कई बार कॉपी करने से रोकते हैं। इसमें उन डिवाइस की संख्या सीमित करना शामिल है जिन पर किसी गाने को कॉपी किया जा सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जो उपभोक्ता को ऑप्टिकल डिस्क से संरक्षित कार्य की कॉपी करने की अनुमति नहीं देता है।

डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि के अनुच्छेद 11 "तकनीकी उपायों से संबंधित दायित्व" के अनुसार अनुबंध करने वाले पक्षों को यह आवश्यक है कि वे

"...इस संधि या बर्न कन्वेंशन के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग के संबंध में लेखकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रभावी तकनीकी उपायों की अवहेलना के विरुद्ध पर्याप्त कानूनी संरक्षण और प्रभावी कानूनी उपाय प्रदान करना तथा उनके कार्यों के संबंध में ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित करना, जो संबंधित लेखकों द्वारा अधिकृत नहीं हैं या कानून द्वारा अनुमत नहीं हैं।"⁴⁴

RMI को आम तौर पर संरक्षित कार्य पर लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य के स्वामी का लेबल हमेशा कार्य में अंतर्निहित रहे। उदाहरण के लिए, किसी मूवी के मामले में, फिल्म स्टूडियो RMI का उपयोग कर सकता है जिसे मूवी में लोगों के रूप में रखा जाएगा। इसे वीडियो या संरक्षित कार्य के साथ मेटाडेटा के रूप में भी संग्रहीत किया जा सकता है।

डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि का अनुच्छेद 12 "अधिकार प्रबंधन से संबंधित दायित्व सूचना" के लिए अनुबंध करने वाले पक्षों को यह आवश्यक है कि वे

(1) अनुबंध करने वाले पक्ष निम्नलिखित में से किसी भी कार्य को जानबूझकर करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त और प्रभावी कानूनी उपचार प्रदान करेंगे, या नागरिक उपचार के संबंध में

⁴⁴ WIPO कॉपीराइट संधि- http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111709.pdf

यह जानने के लिए उचित आधार होना कि यह इस संधि या बर्न कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए किसी भी अधिकार के उल्लंघन को प्रेरित, सक्षम, सुविधाजनक या छुपाएगा:

(i) बिना अनुमति के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अधिकार प्रबंधन जानकारी को हटाना या बदलना;

(ii) बिना प्राधिकार के, किसी कार्य या कार्य की प्रतियों को वितरित करना, आयात करना, प्रसारित करना या जनता को संप्रेषित करना, यह जानते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक अधिकार प्रबंधन सूचना को बिना प्राधिकार के हटा दिया गया है या बदल दिया गया है।"

(2) जैसा कि इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, "अधिकार प्रबंधन सूचना" का अर्थ ऐसी सूचना है जो कार्य, कार्य के लेखक, कार्य में किसी अधिकार के स्वामी, या कार्य के उपयोग की शर्तों और नियमों के बारे में सूचना, और ऐसी सूचना को दर्शाने वाले किसी भी संख्या या कोड की पहचान करती है, जब सूचना की इनमें से कोई भी वस्तु कार्य की प्रतिलिपि के साथ संलग्न होती है या किसी कार्य को जनता तक पहुंचाने के संबंध में प्रकट होती है।⁴⁵

डब्ल्यूआईपीओ प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, 1996 (डब्ल्यूपीपीटी) के अनुच्छेद 18 और 19 में कहा गया है कि राज्यों को तकनीकी सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के मामले में कानूनी उपाय के प्रावधान करने के अलावा टीपीएम और आरएमआई के लिए कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए।

अनुच्छेद 18: तकनीकी उपायों से संबंधित दायित्व-

"अनुबंध करने वाले पक्ष, प्रभावी तकनीकी उपायों की अवहेलना के विरुद्ध पर्याप्त कानूनी संरक्षण और प्रभावी कानूनी उपाय प्रदान करेंगे, जिनका उपयोग फोनोग्राम के कलाकारों या उत्पादकों द्वारा इस संधि के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग के संबंध में किया जाता है और जो उनके प्रदर्शन या फोनोग्राम के संबंध में ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित करते हैं, जो कलाकारों या संबंधित फोनोग्राम के उत्पादकों द्वारा अधिकृत नहीं हैं या कानून द्वारा अनुमत नहीं हैं।"

अनुच्छेद 19: अधिकार प्रबंधन सूचना से संबंधित दायित्व-

(1) अनुबंध करने वाले पक्ष निम्नलिखित में से किसी भी कार्य को जानबूझकर करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त और प्रभावी कानूनी उपचार प्रदान करेंगे, या नागरिक उपचार के संबंध में यह जानने के लिए उचित आधार हैं, कि यह इस संधि द्वारा कवर किए गए किसी भी अधिकार के उल्लंघन को प्रेरित, सक्षम, सुविधाजनक या छुपाएगा:

(i) बिना अधिकार के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अधिकार प्रबंधन जानकारी को हटाना या बदलना;

(ii) बिना प्राधिकरण के, प्रदर्शनों, निश्चित प्रदर्शनों या फोनोग्राम की प्रतियों को वितरित करना, वितरण के लिए आयात करना, प्रसारित करना, संचार करना या जनता के लिए उपलब्ध कराना, यह जानते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक अधिकार प्रबंधन जानकारी को बिना प्राधिकरण के बदल दिया गया है।

(2) जैसा कि इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, "अधिकार प्रबंधन सूचना" का अर्थ ऐसी सूचना है जो कलाकार, कलाकार के प्रदर्शन, फोनोग्राम के निर्माता, फोनोग्राम, प्रदर्शन या फोनोग्राम में किसी भी अधिकार के स्वामी तथा ऐसी सूचना को दर्शाने वाले किसी भी अंक या कोड की पहचान करती है, जब सूचना की इनमें से कोई भी वस्तु किसी निश्चित प्रदर्शन या फोनोग्राम की प्रतिलिपि के साथ संलग्न हो या किसी निश्चित प्रदर्शन या फोनोग्राम को जनता के लिए संप्रेषित करने या उपलब्ध कराने के संबंध में प्रकट हो।⁴⁶

⁴⁵ पूर्वोक्त

⁴⁶ डब्ल्यूआईपीओ प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि- [http://www.niscair.res.in/jinfo/JIPR/JIPR%202\(3\)%20\(WIPO-Performance%20and%20Phonograms%20Treaty\).pdf](http://www.niscair.res.in/jinfo/JIPR/JIPR%202(3)%20(WIPO-Performance%20and%20Phonograms%20Treaty).pdf)

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [42]

संयुक्त राज्य अमेरिका में, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ("DMCA") ने बौद्धिक संपदा की नकल करने में कुछ तकनीकी बाधाओं को दरकिनार करने के संबंध में संधि प्रावधानों को लागू किया है। यूरोपीय संघ।

यूरोपीय संघ में, सूचना समाज में कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के कुछ पहलुओं के सामंजस्य पर यूरोपीय संसद और 22 मई, 2001 की परिषद के यूरोपीय निर्देश 2001/29/EC में विरोधी-परिहार नियमों को लागू किया गया था।

ऑस्ट्रेलिया कॉपीराइट अधिनियम की धारा 116 में "एक्सेस कंट्रोल तकनीकी सुरक्षा उपायों" की अवहेलना को प्रतिबंधित करता है। वर्तमान में कानून ऐसे उपायों की अवहेलना करने के साथ-साथ इसे सक्षम करने के लिए उपकरणों के निर्माण और वितरण के लिए दंड लगाता है।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भारत WPPT और WCT दोनों संधियों पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि संधियों में कॉपीराइट के सख्त प्रावधान हैं जो भारत द्वारा वर्तमान में अपनाए जा रहे सुलभता के कई लक्ष्यों को कमजोर करते हैं।⁴⁷ हालांकि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 को WCT और WPPT के साथ सुसंगत बनाने के लिए कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 पेश किया गया था।

2.3.3.3 कॉपीराइट सीमाओं और पर संधि प्रस्ताव

पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के लिए अपवाद

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन (IFLA) वर्तमान में कॉपीराइट सीमाओं और अपवादों के लिए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन का मसौदा तैयार करने के लिए WIPO के सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये अपवाद और सीमाएँ पुस्तकालयों के लिए अपने संग्रह को संरक्षित करने, सामग्री उधार देने और शिक्षा और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने/समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं। इस संधि प्रस्ताव का मसौदा मुख्य रूप से एनजीओ और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा पुस्तकालयाध्यक्षों और बौद्धिक संपदा विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में तैयार किया जा रहा है। IFLA ने पुस्तकालयों और अभिलेखागार के लिए कॉपीराइट सीमाओं और अपवादों पर संधि प्रस्ताव तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद (ICA), पुस्तकालयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना (EIFL) और कॉर्पोरेशन इनोवार्ट के साथ सहयोग किया है।

संधि में प्रस्तावित कुछ बातें इस प्रकार हैं:

- समानांतर आयात (अर्थात् विदेश से पुस्तकें खरीदना)
- किसी सीमा और अपवाद के तहत पुनरुत्पादित कार्यों और सामग्रियों का सीमा पार उपयोग
- पुस्तकालय उधार
- पुस्तकालय दस्तावेज़ आपूर्ति
- पुस्तकालय और अभिलेखीय सामग्रियों का संरक्षण
- संबंधित अधिकारों के तहत कार्यों और अन्य सामग्री का उपयोग विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए विकलांग
- शिक्षा, अनुसंधान और निजी अध्ययन के लिए कार्यों का उपयोग
- व्यक्तिगत एवं निजी उद्देश्यों के लिए कार्यों का उपयोग
- वापस लिए गए और वापस लिए गए कार्यों तक पहुंच
- अनाथ कार्य

47 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन - इंटरनेट और समाज केंद्र; <https://cis-india.org/telecom/knowledge-repository-on-internet-access/wipo>

इसमें यह भी प्रस्ताव है:

- कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के अपवादों का सम्मान करने का दायित्व
- तकनीकी संरक्षण उपायों से संबंधित दायित्व
- पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के लिए दायित्व की सीमा

संघि प्रस्ताव सभी देशों के लिए एक बुनियादी आधार का सुझाव देता है, राष्ट्रीय कॉपीराइट कानूनों के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है जो लचीला और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। यह सामंजस्य या 'एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त' दृष्टिकोण को लागू करने का प्रयास नहीं करता है।

इसे WIPO सदस्य देशों के विकास के स्तर और विशिष्टताओं के अनुसार सामान्य आवश्यकताओं के साथ-साथ भेदभाव को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि प्रस्ताव में कुछ प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना अनिवार्य बनाया गया है, लेकिन अधिकांश मामलों में बर्न कन्वेंशन में निर्धारित "निष्पक्ष व्यवहार" के अंतरराष्ट्रीय मानक का उपयोग करते हुए कार्यान्वयन के लिए लचीलापन है।

2.3.4 कॉपीराइट कानून किसी भी कार्य की सुरक्षा कैसे करता है

इंटरनेट

2.3.4.1 कॉपीराइट का पंजीकरण

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 44 से 50 में कॉपीराइट के पंजीकरण के प्रावधान शामिल थे। हालांकि कॉपीराइट का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह कार्य को प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान करता है।⁴⁸ हालांकि कॉपीराइट तब भी अस्तित्व में रहता है जब कार्य बनाया जाता है और उसे भौतिक रूप दिया जाता है। कार्य के किसी भी विवाद के मामले में कॉपीराइट का पंजीकरण कानून की अदालत में सबूत प्रदान करता है। उक्त अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, "कॉपीराइट का रजिस्टर उसमें दर्ज विवरणों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा और उसमें दर्ज किसी भी प्रविष्टि की प्रतिलिपि होने का दावा करने वाले दस्तावेज़ या उसके अंश, कॉपीराइट रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित और कॉपीराइट कार्यालय की मुहर के साथ सील किए गए सभी न्यायालयों में बिना किसी अतिरिक्त सबूत या मूल प्रस्तुत किए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे।"

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत धारा 44 में कार्यालय में एक रजिस्टर बनाए रखने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 44 के अनुसार, - "कॉपीराइट कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसे कॉपीराइट रजिस्टर कहा जाएगा जिसमें कार्यों के नाम या शीर्षक और लेखकों, प्रकाशकों और कॉपीराइट के मालिकों के नाम और पते और ऐसे अन्य विवरण दर्ज किए जा सकते हैं जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।"

इंटरनेट पर कॉपीराइट सामग्री विशेष वेबसाइटों पर उपलब्ध होती है। जो लेखक या काम के कानूनी स्वामी के स्वामित्व में होती हैं। वेबसाइटें आम तौर पर टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ध्वनि और वीडियो का संयोजन होती हैं। इसलिए, प्रत्येक श्रेणी के काम को संबंधित भाग के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है, जैसे कि साहित्यिक कार्य के अंतर्गत टेक्स्ट। चित्रों के अंतर्गत इमेज। ध्वनि रिकॉर्डिंग के अंतर्गत ध्वनि इत्यादि। वेबसाइटें सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर प्रोग्राम की श्रेणी के अंतर्गत कॉपीराइट किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब है,

" शब्दों में व्यक्त निर्देशों का एक सेट,

⁴⁸ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 48

कोड, योजना या किसी अन्य रूप में, जिसमें मशीन पठनीय माध्यम भी शामिल है, कंप्यूटर को कोई विशेष कार्य करने या कोई विशेष परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।" 49

2.3.4.2 बहुआयामी विचारों का संरक्षण

डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने अतीत की तुलना में कहीं अधिक बहुमुखी प्रतिभा के साथ काम करना संभव बना दिया है। काम मल्टीमीडिया के रूप में हो सकता है, वह सामग्री जो पाठ, ऑडियो, चित्र, एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिव सामग्री जैसे विभिन्न रूपों के संयोजन का उपयोग करती है।

मल्टीमीडिया उस मीडिया से भिन्न है जो केवल अल्पविकसित कंप्यूटर डिस्प्ले का उपयोग करता है, जैसे केवल पाठ या मुद्रित या हस्त-निर्मित सामग्री के पारंपरिक रूप।

मल्टीमीडिया को कंप्यूटरीकृत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सूचना सामग्री प्रसंस्करण उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड और चलाया, प्रदर्शित, इंटरैक्ट या एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन यह लाइव प्रदर्शन का हिस्सा भी हो सकता है। मल्टीमीडिया डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइस हैं जिनका उपयोग मल्टीमीडिया सामग्री को संग्रहीत करने और उसका अनुभव करने के लिए किया जाता है। 50

डिजिटल तकनीक की मदद से विभिन्न श्रेणियों के अधिक से अधिक कार्य अभिव्यक्ति के एक ही माध्यम में तय किए जा रहे हैं। कॉपीराइट द्वारा संरक्षित कार्य प्रकार के आधार पर कम से कम विभेदित होते जा रहे हैं और एक दूसरे के अधिक से अधिक समतुल्य होते जा रहे हैं क्योंकि वे एक ही माध्यम में हैं। एक ही मंच पर उपलब्ध विभिन्न कार्यों की जटिलता ने भविष्य के लिए वर्तमान कॉपीराइट कानूनों के तहत एक अलग श्रेणी बनाने के विचार को जन्म दिया है।

उपयोगकर्ता अपने तरीके से काम के साथ बातचीत कर सकता है जो पहले असंभव था यानी बदलाव और परिवर्धन करना और यहां तक कि मौजूदा काम से एक नया काम बनाना। यह एक बड़ा मुद्दा नहीं होता, अगर सभी वर्गों के कामों के अधिकार समान होते। लेकिन भारत के वर्तमान कॉपीराइट कानून में अधिकारों के मामले में विभिन्न वर्गों के कामों के बीच अंतर किया गया है।

उदाहरण के लिए, साहित्यिक कृति और सिनेमैटोग्राफिक फिल्म या ध्वनि में अधिकार अलग-अलग होते हैं। साहित्यिक कृति में कोई किराया अधिकार नहीं होता, जबकि सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों में ऐसा अधिकार होता है। इसके अलावा, चूंकि एक ओर साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कृतियों और दूसरी ओर सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के बीच लेखकत्व का मानदंड अलग-अलग है, इसलिए सवाल उठता है कि घटक भागों के अपने व्यक्तिगत संयोजन में मल्टीमीडिया कृति किस तरह की सुरक्षा प्राप्त करती है। इस मुद्दे का महत्व इस तथ्य में निहित है कि प्रासंगिक वर्गीकरण में अलग-अलग कानूनी परिणाम शामिल हैं और मल्टीमीडिया कृति की मौजूदगी कॉपीराइट कानून के तहत मौजूदा वर्गीकरण को चुनौती देती है। यह इस हद तक एक नया प्रकार का कार्य नहीं है कि मल्टीमीडिया उत्पाद एक या कई, पहले से मौजूद श्रेणियों के अंतर्गत आ सकता है। मल्टीमीडिया कृति के व्यक्तिगत तत्वों की सुरक्षा को समग्र रूप से मल्टीमीडिया उत्पादन की सुरक्षा के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। कॉपीराइट अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, व्यक्तिगत योगदानों को अलग-अलग निपटाना संभव है, भले ही व्यक्तिगत तत्वों को एक ही कृति में मिला दिया गया हो। किसी विशेष मल्टीमीडिया उत्पाद का वास्तविक वर्गीकरण कार्य के प्रकार तथा प्रत्येक व्यक्तिगत मल्टीमीडिया उत्पाद की विभिन्न एवं विशिष्ट विशेषताओं पर निर्भर करेगा।

इसलिए, इसका फैसला केस-दर-केस आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार अंतिम व्याख्या, न्यायालयों के हाथों में होगी।

⁴⁹ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(ffc)

⁵⁰ <https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia>

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(f)51 के अर्थ में मल्टीमीडिया उत्पादों को सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के समान कार्य के रूप में माना और माना जा सकता है। बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 2(5) के अर्थ में मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को साहित्यिक या कलात्मक कार्यों के संग्रह के रूप में वर्गीकृत और माना जाना संभव लगता है और वे ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 10(2) के अर्थ में डेटा या अन्य सामग्री के संकलन की श्रेणी में भी आ सकते हैं। एक विचार यह भी है कि मल्टीमीडिया कार्य को कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मल्टीमीडिया कार्य में एक सॉफ्टवेयर घटक होगा। चूंकि कॉपीराइट अधिनियम में साहित्यिक कार्यों से अलग कंप्यूटर प्रोग्राम के अधिकारों और लेखकत्व के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं, इसलिए यह एक संभावित समाधान हो सकता है। हालांकि, अधिनियम की धारा 1352 और कलाकारों के अधिकारों के संदर्भ में मल्टीमीडिया में शामिल कार्यों में अलग-अलग कॉपीराइट के प्रतिधारण पर मुद्दे उठ सकते हैं⁵³

उत्पाद में.

वर्तमान में, पहले से मौजूद कार्यों को मिलाकर बड़ी संख्या में मल्टी-मीडिया कार्य बनाए जा रहे हैं। मल्टी-मीडिया कार्यों का वर्गीकरण एक मुद्दा है, यह अभी भी तय होना बाकी है कि क्या मल्टीमीडिया कार्यों को कॉपीराइट के शासन के तहत संरक्षित कार्यों की एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए।

2.3.4.3 डिजिटल माध्यम में पुनरुत्पादन का अधिकार

प्रजनन का अधिकार कॉपीराइट का सबसे बुनियादी हिस्सा है। इस सवाल के बारे में WCT सहमत कथन के अनुसार कि, 'क्या डिजिटल कॉपी करना प्रजनन है, यह कहा गया है, "बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 में निर्धारित प्रजनन अधिकार, और उसके तहत अनुमत अपवाद, डिजिटल वातावरण में पूरी तरह से लागू होते हैं, विशेष रूप से डिजिटल रूप में कार्यों के उपयोग के लिए। यह समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में डिजिटल रूप में संरक्षित कार्य का भंडारण बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 के अर्थ के भीतर प्रजनन का गठन करता है।"⁵⁴

वास्तविक समस्या तब उत्पन्न होती है जब इंटरनेट संचार में होने वाली क्षणिक या आकस्मिक पुनरुत्पादन डिजिटल माध्यम में पुनरुत्पादन के अधिकार के बारे में समस्या उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए जब कोई खरीदार किसी पुस्तक स्टॉल पर जाता है, तो वह पुस्तक ब्राउज़ कर सकता है और पुस्तक खरीदने या न खरीदने का निर्णय ले सकता है।

इंटरनेट के मामले में यह ब्राउज़िंग केवल उसके (खरीदार के) कंप्यूटर की रैम में पुस्तक की डिजिटल प्रतिकृति के बाद ही हो सकती है। क्या यह प्रतिकृति प्रतिकृति के अधिकार के दायरे में आती है। यह प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है।

भारतीय कॉपीराइट कानून में डिजिटल माध्यम में पुनरुत्पादन का अधिकार शामिल है। इसमें कहा गया है, 'साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कार्य के मामले में, किसी भी भौतिक रूप में कार्य को पुनरुत्पादित करने का अधिकार, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी माध्यम में इसे संग्रहीत करना शामिल है⁵⁵ इसके अलावा, किसी भी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कार्य के मामले में, किसी भी भौतिक रूप में कार्य को पुनरुत्पादित करने का अधिकार, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी माध्यम में इसे संग्रहीत करना शामिल है।

⁵¹ 'सिनेमैटोग्राफ फिल्म' का तात्पर्य दृश्य रिकॉर्डिंग के किसी भी कार्य से है और इसमें ऐसी दृश्य रिकॉर्डिंग के साथ ध्वनि रिकॉर्डिंग भी शामिल है और 'सिनेमैटोग्राफ' का अर्थ वीडियो फिल्मों सहित सिनेमैटोग्राफी के अनुरूप किसी भी प्रक्रिया द्वारा निर्मित किसी भी कार्य के रूप में लगाया जाएगा।'

⁵² धारा 13(4) - "सिनेमैटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट किसी ऐसे कार्य में अलग से कॉपीराइट को प्रभावित नहीं करेगा जिसके संबंध में या जिसके किसी बड़े हिस्से के संबंध में, फिल्म या, जैसा भी मामला हो, ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाई गई है।"

⁵³ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 38

⁵⁴http://14.139.60.114:8080/jspui/bitstream/123456789/935/1/007_Copyright%20Law%20and%20the%20Intern et.pdf

⁵⁵ अनुच्छेद 1(4) के संबंध में WCT का सहमत वक्तव्य; http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=381455

⁵⁶ टीसीजेम्स, सुप्रा नोट्स; पृ.430

⁵⁷ धारा 14 (ए), भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957

कम्प्यूटर प्रोग्राम, ध्वनि रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों और कलात्मक कार्य के लिए 'पुनरुत्पादन' शब्द में 'इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी माध्यम में उसका भंडारण' भी शामिल है, 58

2.3.4.4 वितरण और संचार का अधिकार

कोई भी कार्य, जो कम्प्यूटर मेमोरी में किसी वेबसाइट के रूप में संग्रहीत है और जिसे जनता अपनी सुविधानुसार देख सकती है, वह उस कार्य का जनता तक संचार माना जाता है।

WIPO समितियों में एक समझौता हुआ कि इंटरनेट या इसी तरह के नेटवर्क पर कार्यों का प्रसारण लेखक या कॉपीराइट स्वामी के प्राधिकरण के अनन्य अधिकार का विषय होना चाहिए। बर्न कन्वेंशन जनता को संचार और वितरण के अधिकार के लिए पूर्ण कवरेज प्रदान नहीं करता है। WCT इस मुद्दे पर काम करता है और जनता को संचार के अधिकार की प्रयोज्यता को सभी श्रेणियों के कार्यों तक बढ़ाता है और स्पष्ट करता है कि, यह अधिकार कानूनी-चरित्र-मुक्त तरीके से वर्णित इंटरैक्टिव सिस्टम में प्रसारण को भी कवर करता है।⁵⁹ यह संधि के अनुच्छेद 8 में शामिल है, जो कहता है, "बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लेखकों को अपने कार्यों के बारे में जनता को किसी भी संचार को अधिकृत करने का अनन्य अधिकार प्राप्त होगा, तार या वायरलेस माध्यम से, जिसमें उनके कार्यों को जनता के लिए इस तरह से उपलब्ध कराना शामिल है कि जनता के सदस्य इन कार्यों को उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए स्थान और समय से एक्सेस कर सकें।"

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (एफएफ) में 'जनता को संचार' की परिभाषा भी दी गई है, जो इस प्रकार है-

"जनता को संप्रेषित करना" का अर्थ है किसी भी कार्य या प्रदर्शन को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसकी भौतिक प्रतियां जारी करने के अलावा प्रदर्शन या प्रसार के किसी अन्य माध्यम से देखने, सुनने या अन्यथा आनंद लेने के लिए उपलब्ध कराना, चाहे एक साथ या व्यक्तिगत रूप से चुने गए स्थानों और समय पर, इस बात की परवाह किए बिना कि जनता का कोई भी सदस्य वास्तव में उपलब्ध कराए गए कार्य या प्रदर्शन को देखता है, सुनता है या अन्यथा आनंद लेता है।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपग्रह या केबल या किसी अन्य माध्यम से एक साथ संचार किसी होटल या छात्रावास के आवासीय कमरों सहित एक से अधिक घरों या निवास स्थानों को किया गया संचार जनता के लिए संचार माना जाएगा।⁶⁰

इस प्रकार भारतीय कॉपीराइट कानून में जनता को संचार का अधिकार WCT द्वारा दी गई परिभाषा के पूर्णतः अनुकूल माना जाता है।

2.3.4.5 डिजिटल कार्यों में उचित उपयोग

डब्ल्यूसीटी की प्रस्तावना में कहा गया है, "अनुबंध करने वाले पक्ष... लेखकों के अधिकारों और व्यापक सार्वजनिक हित, विशेष रूप से शिक्षा, अनुसंधान और सूचना तक पहुंच के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, जैसा कि बर्न कन्वेंशन में परिलक्षित होता है"

⁵⁸ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14; विभिन्न खंड 1999 के अधिनियम 49 द्वारा तथा 2012 के अधिनियम 27 द्वारा प्रतिस्थापित

⁵⁹ देखिये, "छात्रावास";

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wct_wppt.pdf

⁶⁰ 2012 के अधिनियम सं. 27 की धारा 2(iii) द्वारा प्रतिस्थापित।

इसलिए बड़े समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कलात्मक, वैज्ञानिक और अन्य कार्यों के लेखकों और रचनाकारों को दिए गए विशेष अधिकार समय के अनुसार सीमित हैं। साथ ही कॉपीराइट किए गए कार्य का उपयोग शैक्षणिक, शोध और विधायी या न्यायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

भारतीय कॉपीराइट कानून कॉपीराइट किए गए कार्य के उचित उपयोग की अनुमति देता है। एक "गैर-लाभकारी पुस्तकालय या गैर-लाभकारी शैक्षणिक संस्थान" बिना किसी किराए का भुगतान किए कंप्यूटर प्रोग्राम, ध्वनि रिकॉर्डिंग, दृश्य रिकॉर्डिंग या सिनेमैटोग्राफ फिल्म का उपयोग करने की अनुमति देता है।⁶¹

धारा 52 (ए) में कहा गया है कि, [(i) निजी या व्यक्तिगत उपयोग, जिसमें अनुसंधान भी शामिल है; (ii) आलोचना या समीक्षा, चाहे उस कार्य की हो या किसी अन्य कार्य की; (iii) वर्तमान घटनाओं और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, जिसमें सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान की रिपोर्टिंग भी शामिल है], के प्रयोजनों के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी भी कार्य का भंडारण, जिसमें किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का आकस्मिक भंडारण भी शामिल है, जो उक्त प्रयोजनों के लिए स्वयं उल्लंघनकारी प्रतिलिपि नहीं है, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

इसके अलावा इस धारा में कहा गया है कि डिजिटल कार्य (कम्प्यूटर प्रोग्राम) के मामले में, निम्नलिखित कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे-

- हानि, विनाश या क्षति के विरुद्ध अस्थायी संरक्षण के रूप में बैक-अप प्रतियां बनाना, ताकि कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सके जिसके लिए उसे आपूर्ति किया गया था;
- गैर-वाणिज्यिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से प्राप्त प्रतिलिपि से कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतिलिपि बनाना या उसका अनुकूलन करना;
- किसी कार्य या प्रदर्शन का तकनीकी दृष्टि से क्षणिक या आकस्मिक भंडारण जनता तक इलेक्ट्रॉनिक संचरण या संचार की प्रक्रिया;
- किसी गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा किसी कार्य को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी माध्यम में संरक्षित करने के लिए संग्रहीत करना, यदि पुस्तकालय के पास पहले से ही कार्य की गैर-डिजिटल प्रति मौजूद है;⁶²

2.3.5.6 इंटरनेट पाइरेसी से सुरक्षा

इस इकाई के पिछले भाग में हमने तकनीकी सुरक्षा उपायों और अधिकार प्रबंधन सूचना के बारे में चर्चा की थी, जो WIPO कॉपीराइट संधि द्वारा शुरू किए गए नए तकनीकी सुरक्षा उपाय हैं। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में दो नई धाराएँ- 65A और 65B पेश की गई हैं, जो तकनीकी उपायों के लिए सुरक्षा और अधिकार प्रबंधन सूचना के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं।

65ए. प्रौद्योगिकीय उपायों का संरक्षण।-- (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के संरक्षण के प्रयोजन के लिए लागू किए गए प्रभावी प्रौद्योगिकीय उपाय को ऐसे अधिकारों का अतिक्रमण करने के आशय से बाधित करेगा, वह दो वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति को निम्नलिखित से नहीं रोकेगी,—

(क) इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिषिद्ध न किए गए किसी प्रयोजन के लिए इसमें निर्दिष्ट कोई कार्य करना:

⁶¹ धारा 2 (एफए); भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957

⁶² पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण को सुगम बनाने के लिए कॉपीराइट (संशोधन) विधेयक 2012 द्वारा यह नया खंड (एन) पेश किया गया था।

बशर्ते कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए किसी तकनीकी उपाय का परिहार करने में सहायता करता है, तो उसे ऐसे अन्य व्यक्ति का पूर्ण रिकार्ड रखना होगा, जिसमें उसका नाम, पता तथा उसकी पहचान के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक विवरण तथा वह प्रयोजन जिसके लिए उसे परिहार करने में सहायता की गई है, सम्मिलित होगा; या

(ख) विधिपूर्वक प्राप्त एन्क्रिप्टेड प्रति का उपयोग करके एन्क्रिप्शन अनुसंधान करने के लिए आवश्यक कोई भी कार्य करना; या

(ग) कोई विधिसम्मत जांच करना; या

(घ) किसी कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए उसके स्वामी की अनुमति से कोई आवश्यक कार्य करना; या

(ई) ऑपरेटर; या

(च) किसी उपयोगकर्ता की पहचान या निगरानी के लिए अभिप्रेत तकनीकी उपायों को दरकिनार करने के लिए आवश्यक कोई कार्य करना; या

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक उपाय करना।

उपरोक्त प्रावधान WCT के अनुच्छेद 11 और WPPT के अनुच्छेद 18 से उत्पन्न हुए हैं।⁶³ जबकि 65A की उपधारा (1) तकनीकी उपायों यानी डिजिटल पाइरेसी को दरकिनार करना, कारावास के साथ दंडनीय अपराध बनाती है, इस खंड की उपधारा (2) इसके उचित उपयोग की अनुमति देती है।

इस प्रकार उपधारा (2) कुछ अपवाद प्रदान करती है।

65बी. अधिकार प्रबंधन सूचना का संरक्षण। - कोई भी व्यक्ति, जो जानबूझकर, -

(i) बिना अधिकार के किसी अधिकार प्रबंधन जानकारी को हटाता या बदलता है, या

(ii) बिना प्राधिकार के किसी कार्य या प्रदर्शन की प्रतियां वितरित करता है, वितरण के लिए आयात करता है, प्रसारित करता है या जनता को संप्रेषित करता है, यह जानते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक अधिकार प्रबंधन सूचना को बिना प्राधिकार के हटा दिया गया है या बदल दिया गया है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकेगा और जुर्माना भी देना होगा:

बशर्ते कि यदि किसी कार्य में अधिकार प्रबंधन सूचना के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो ऐसे कार्य में कॉपीराइट का स्वामी ऐसे कृत्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अध्याय XII के अंतर्गत प्रदत्त सिविल उपचारों का लाभ भी उठा सकेगा।

धारा 65बी के उपरोक्त प्रावधान भी डब्ल्यूसीटी के अनुच्छेद 12 और डब्ल्यूपीपीटी के अनुच्छेद 19 से निकलते हैं।

नई तकनीक कॉपीराइट सुरक्षा के प्रशासन को काफी मुश्किल बना देती है। इंटरनेट की मदद से आज किसी भी काम को एक सेकंड में पूरी दुनिया में प्रसारित करना संभव हो सकता है। परिधि (अवैध हैकिंग) तकनीक में विकास किसी भी सुरक्षा उपाय को बेकार बना देता है। इसलिए इंटरनेट पर उपरोक्त कानूनी सुरक्षा अपर्याप्त लगती है।

प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न समस्या को प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अधिक कुशल कानूनों द्वारा हल करने की आवश्यकता है। आज प्रौद्योगिकी कानून से अधिक तेजी से विकसित हो रही है। इसलिए कॉपीराइट कार्य पर अधिक ध्यान देने और सार्वभौमिक समाधान की आवश्यकता है

⁶³ इस इकाई में पहले वर्णित

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 5 सितंबर 2016 को एक अधिसूचना जारी की। कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इंटरनेट प्रसारण कंपनियों को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 31डी के तहत प्रसारण संगठन के दायरे में आती हैं। तदनुसार, ऐसी इंटरनेट प्रसारण कंपनियों को वैधानिक लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए।

कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 में धारा 31डी को शामिल किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी "प्रसारण संगठन किसी भी साहित्यिक, संगीतमय कार्य या ध्वनि रिकॉर्डिंग के बारे में जनता को सूचित करता है", कॉपीराइट अधिनियम के तहत अनुपालन का पालन करेगा, जिसमें प्रसारण, अवधि, क्षेत्रीय कवरेज की पूर्व सूचना देना और प्रत्येक कार्य में अधिकारों के स्वामी को रॉयल्टी का भुगतान करना, लेखकों और कलाकारों के नामों की घोषणा करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसमें साहित्यिक या संगीतमय कार्य में किसी भी संशोधन या परिवर्तन के लिए पूर्व सूचना की निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अलावा, प्रसारणकर्ता को रिकॉर्ड, खाता बही बनाए रखना होता है और कॉपीराइट के मालिकों को प्रतियां प्रदान करनी होती हैं।

2.5 सारांश

कॉपीराइट 'बौद्धिक संपदा अधिकार' का ही एक हिस्सा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति बौद्धिक संपदा पर किसी भी व्यक्तिगत अधिकार का समर्थन नहीं करती थी। तब ज्ञान हमेशा आम लोगों की भलाई और मदद के लिए होता था। यह लाभ कमाने की वस्तु नहीं थी।

अधिकांश देशों की तरह भारत को भी आधुनिक कॉपीराइट कानून औपनिवेशिक शासन की देन है। 1957 तक भारत में कॉपीराइट कानून कॉपीराइट अधिनियम 1847 के तहत संचालित होता था। जब संसद ने भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 पारित किया। कॉपीराइट से संबंधित मामले सूची I की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत आते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को इस विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में 2012 के संशोधन अधिनियम को एक बड़ा कदम माना जाता है, जिसने अधिनियम को WIPO कॉपीराइट संधि (WCT) और WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WPPT) के अनुरूप बनाया, जिन्हें एक साथ "WIPO इंटरनेट संधि" के रूप में जाना जाता है। यह कॉपीराइट की सुरक्षा को ऑनलाइन और डिजिटल वातावरण तक बढ़ाता है।

कॉपीराइट की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शर्त यह है कि बौद्धिक कार्य मौलिक होना चाहिए तथा अभिव्यक्ति के मूर्त माध्यम में होना चाहिए। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 13 कॉपीराइट की सुरक्षा के विषय-वस्तु के बारे में बताती है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14 में कॉपीराइट का अर्थ दिया गया है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन साइबरस्पेस में कॉपीराइट सुरक्षा के लिए नए मानकों को आकार देने के लिए चल रही अंतरराष्ट्रीय बहस में गहराई से शामिल है। WIPO कॉपीराइट संधि साहित्यिक और कलात्मक कार्यों, जैसे लेखन और कंप्यूटर प्रोग्राम; मूल डेटाबेस; संगीत कार्य; दृश्य-श्रव्य कार्य; ललित कला और फोटो के कार्यों के लेखकों के लिए सुरक्षा से संबंधित है; जबकि WPPT कलाकारों और फोनोग्राम के निर्माताओं के लेखकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। अधिकारों के मालिकों और आम जनता के बीच हितों का उचित संतुलन बनाए रखने के लिए, संधियाँ आगे स्पष्ट करती हैं कि देशों के पास डिजिटल वातावरण में अधिकारों के लिए अपवाद या सीमाएँ स्थापित करने में उचित लचीलापन है। भारतीय कॉपीराइट कानून

कॉपीराइट किए गए कार्य के उचित उपयोग की अनुमति दें। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 में कॉपीराइट किए गए कार्य के उचित उपयोग के बारे में प्रावधान हैं।

कॉपीराइट संधियों में देशों को न केवल स्वयं अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता होती है, बल्कि अधिकारों के लिए दो प्रकार के तकनीकी सहायक भी प्रदान करने होते हैं, जैसे कि "विरोधी-परिहार" प्रावधान, "हैकिंग" और "अधिकार प्रबंधन सूचना" की समस्या से निपटता है : ऐसी सूचना जो किसी भी संरक्षित सामग्री के साथ होती है, और जो कार्य, उसके निर्माता, कलाकार या मालिक और उसके उपयोग के लिए नियम और शर्तों की पहचान करती है। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में दो नई धाराएँ- 65A और 65B पेश की गई हैं, जो तकनीकी उपायों के लिए सुरक्षा और अधिकार प्रबंधन सूचना के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं।

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 44 से 50 में कॉपीराइट के पंजीकरण के प्रावधान शामिल थे। हालांकि कॉपीराइट का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह कार्य को प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान करता है।

मल्टीमीडिया में वह सामग्री होती है जिसमें विभिन्न रूपों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिव सामग्री का संयोजन होता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न कार्यों की जटिलता ने भविष्य के लिए वर्तमान कॉपीराइट कानूनों के तहत एक अलग श्रेणी बनाने पर विचार को जन्म दिया है। वर्तमान में, पहले से मौजूद कार्यों को मिलाकर बड़ी संख्या में मल्टीमीडिया कार्य बनाए जा रहे हैं। मल्टीमीडिया कार्यों का वर्गीकरण एक मुद्दा है।

पुनरुत्पादन का अधिकार कॉपीराइट का सबसे बुनियादी तत्व है। वास्तविक समस्या तब उत्पन्न होती है जब इंटरनेट संचार में होने वाली क्षणिक या आकस्मिक पुनरुत्पादन डिजिटल माध्यम में पुनरुत्पादन के अधिकार के बारे में समस्या उत्पन्न करती है। भारतीय कॉपीराइट कानून में डिजिटल माध्यम में पुनरुत्पादन के अधिकार को शामिल किया गया है।¹⁶⁴

अंत में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पर कॉपीराइट एक जटिल मुद्दा है। आज तकनीक कानून से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसमें कानूनी, नैतिक और तकनीकी मुद्दे भी शामिल हैं।

2.5 शब्दावली

- ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद 10(2): ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद 10(2) इस प्रकार है, "डेटा या अन्य सामग्री का संकलन, चाहे वह मशीन पठनीय हो या अन्य रूप में, जो उनकी सामग्री के चयन या व्यवस्था के कारण बौद्धिक रचनाएँ हैं, उन्हें उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा। ऐसा संरक्षण, जो डेटा या सामग्री तक ही सीमित नहीं होगा, डेटा या सामग्री में मौजूद किसी भी कॉपीराइट के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।"
- बर्न कन्वेंशन का अनुच्छेद 2(5): बर्न कन्वेंशन का अनुच्छेद 2 संरक्षित कार्यों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 2(5) में लिखा है, "साहित्यिक या कलात्मक कार्यों जैसे विश्वकोश और संकलनों का संग्रह, जो अपनी सामग्री के चयन और व्यवस्था के कारण बौद्धिक रचनाएँ हैं, उन्हें ऐसे संग्रह का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक कार्य के कॉपीराइट पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संरक्षित किया जाएगा।"
- रैम: रैंडम-एक्सेस मेमोरी (रैम) कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का एक रूप है जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा और मशीन कोड को संग्रहीत करता है।

⁶⁴ धारा 14

4. WEF: इसका मतलब है "प्रभाव से"। उदाहरण के लिए, जब किसी अधिसूचना में लिखा होता है कि नए नियम 1 मार्च, 2018 से लागू होंगे, तो इसका मतलब है कि नए नियम 1 मार्च से लागू होंगे या लागू/पालन किए जाएंगे।

2018, उस विशेष दिन के 12:00 बजे से शुरू होगा।

2.6 एसएक्यूएस

2. लघु उत्तरीय प्रश्न

(i) कॉपीराइट के विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार किसके पास है? (ii) किस संशोधन अधिनियम से कलाकार के अधिकारों को, जो पहले 25 वर्षों के लिए संरक्षित थे, बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया?

(iii) क्या संरक्षित कार्य का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में डिजिटल रूप में भंडारण अपराध माना जाएगा?
एक पुनरुत्पादन?

3. रिक्त स्थान भरें

(ix) भारत के लिए पहला कॉपीराइट अधिनियम ----- की प्रतिकृति था जिसमें कुछ संशोधन किए गए थे।
संशोधन.

(x) वेबसाइटों सॉफ्टवेयर हैं इसलिए इन्हें ----- श्रेणी के अंतर्गत कॉपीराइट किया जा सकता है

4. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न

(i) भारत को आधुनिक कॉपीराइट कानून औपनिवेशिक शासन से उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। (सत्य/असत्य)

(ii) भारत डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि (डब्ल्यूसीटी) और डब्ल्यूआईपीओ का सदस्य नहीं है
प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WPPT). (सत्य/असत्य)

2.7 संदर्भ

1. <https://novojuris.com/2016/09/13/indian-copyright-act-now-covers-internet-and-online-streaming-statutory-licensing-requirements/>
2. <http://www.livelaw.in/reflections-five-years-copyright-amendment-act-2012/>
3. http://shodhnga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/61938/1/11_chapter%204.pdf
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_India
5. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957
6. http://www.wipo.int/copyright/en/activities/internet_treaties.html
7. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html
8. डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि, 1996 WIPO कॉपीराइट संधि-
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111709.pdf
9. डब्ल्यूआईपीओ प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि-[http://www.niscair.res.in/jinfo/JIPR/JIPR%20\(3\)%20\(WIPOPerformance%20and%20फोनोग्रामस%20संधि\).pdf](http://www.niscair.res.in/jinfo/JIPR/JIPR%20(3)%20(WIPOPerformance%20and%20फोनोग्रामस%20संधि).pdf)
10. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन - इंटरनेट और समाज केंद्र; <https://cisindia.org/telecom/knowledge-repository-on-internet-access/wipo>
11. <https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia>
12. http://14.139.60.114:8080/jspui/bitstream/123456789/935/1/007_Copyright%20Law%20और%20द%20इंटरनेट.pdf
13. http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wct_wppt.pdf
14. भारत का संविधान

2.8 सुझाए गए पठन सामग्री

1. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957
2. डब्ल्यूआईपीओ प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि
3. डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि
4. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
5. बर्न कन्वेंशन

2.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. भारतीय संविधान में कॉपीराइट कार्य के उचित उपयोग के प्रावधान से आप क्या समझते हैं?
कॉपीराइट अधिनियम?
2. तकनीकी संरक्षण उपायों और अधिकार प्रबंधन सूचना का वर्णन करें - डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि द्वारा शुरू किए गए नए तकनीकी सुरक्षा उपाय।
3. 'यद्यपि भारत डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि का सदस्य नहीं है, फिर भी भारतीय कॉपीराइट कानून में जनता को संचार का अधिकार डब्ल्यूसीटी द्वारा दी गई परिभाषा के पूर्णतः अनुकूल माना जाता है।' टिप्पणी करें।
4. 'कॉपीराइट के तहत मल्टीमीडिया की सुरक्षा' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

2.10 उत्तर

एसएक्यूएस

1. (i) केन्द्र सरकार; 2.3.1 देखें (ii) कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1999; 2.3.1.5 देखें (iii) हां; 2.3.4.3 देखें
2. (i) ब्रिटिश कॉपीराइट अधिनियम 1911; 2.3.1 देखें (ii) कम्प्यूटर प्रोग्राम; देखें 2.3.4.1
3. (i) सत्य; 2.3.1 देखें (ii) सत्य; 2.3.1 देखें

अंतिम प्रश्न और आधुनिक प्रश्न

1. 2.3.4.5 देखें
2. 2.3.6 देखें
3. 2.3.4.4 देखें
4. 2.3.4.2 देखें

इकाई 3

अधिकार क्षेत्र के मुद्दे और कॉपीराइट

संरचना

3.1 परिचय

3.2 उद्देश्य

3.3 विषय

3.3.1 क्षेत्राधिकार की अवधारणा

3.3.1.1 किसी देश की कानूनी प्रणाली के भीतर अधिकार क्षेत्र

3.3.1.2 भारत में विभिन्न न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

3.3.1.3 इंटरनेट पर अधिकार क्षेत्र के मुद्दे

3.3.2 अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट कानून का विकास: एक संक्षिप्त इतिहास

3.3.3 क्षेत्राधिकार और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम

3.3.3.1 सहमति द्वारा अधिकार क्षेत्र

3.3.3.2 भारत के अनिवासी पर अधिकार क्षेत्र

3.3.4 ऑनलाइन कॉपीराइट मुद्दा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: लंबी भुजा वाला क्षेत्राधिकार प्रदान करना

3.3.5 संबंधित क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीय पहलू कॉपीराइट

3.3.5.1 क्षेत्राधिकार के सिद्धांत

3.3.5.2 मुकदमा दायर करने के स्थान के बारे में प्रश्न

3.3.5.2.1 यूरोप में स्थिति

3.3.5.2.2 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति

3.4 सारांश

3.5 शब्दावली

3.6 एसएक्यूएस

3.7 संदर्भ

3.8 सुझाए गए पठन सामग्री

3.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

3.10 उत्तर SAQS

3.1 परिचय

कॉपीराइट एक विशेष और आबंटित करने योग्य कानूनी अधिकार है, जो रचनाकार या मूल निर्माता को साहित्यिक या संगीत सामग्री को छापने, प्रकाशित करने, प्रदर्शन करने, फिल्माने या रिकॉर्ड करने के लिए दिया जाता है। ये विशेष अधिकार एक निश्चित समय अवधि के लिए दिए जाते हैं। अधिकार क्षेत्र कानूनी निर्णय और निर्णय लेने की आधिकारिक शक्ति है।

अधिकार क्षेत्र क्षेत्र से बंधा होता है। हर न्यायालय की अपनी क्षेत्रीय सीमा होती है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय की कानूनी निर्णय लेने या कानून लागू करने की शक्ति। हर देश की अपनी क्षेत्रीय सीमा होती है। किसी देश में शुरू किया गया काम सिर्फ उसके देश तक सीमित नहीं रह सकता। इस डिजिटल युग में दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है और डिजिटल दुनिया की कोई भौतिक सीमा नहीं है।

इंटरनेट किसी भी काम को करने का सबसे आसान और सस्ता माध्यम बन गया है। इसलिए डिजिटल दुनिया में, जिसकी कोई भौतिक सीमा नहीं है, कानून और अधिकार क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा जो भौतिक सीमाओं तक सीमित है, बहुत जटिल और तत्काल रुचि का है।

पिछली इकाई में हमने कॉपीराइट और उससे संबंधित कानूनों के बारे में पढ़ा। इस इकाई में हम अधिकार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और कॉपीराइट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें समझ सकेंगे-

- क्षेत्राधिकार की अवधारणा • क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण • क्षेत्राधिकार के विभिन्न सिद्धांत • इंटरनेट और क्षेत्राधिकार के मुद्दे • भारतीय कॉपीराइट कानून और क्षेत्राधिकार के मुद्दे • भारत के गैर-निवास पर क्षेत्राधिकार कैसे लागू होता है • कॉपीराइट के मामले में लंबी भुजा वाला क्षेत्राधिकार • कॉपीराइट के मुद्दों पर विभिन्न देशों में क्षेत्राधिकार वाली अदालत

3.3 विषय

3.3.1 क्षेत्राधिकार की अवधारणा

'अधिकार क्षेत्र' वह अवधारणा है जिसके तहत किसी भी कानूनी प्रणाली में, किसी मामले की सुनवाई या निर्धारण करने की शक्ति किसी उपयुक्त न्यायालय में निहित होती है। किसी भी कानूनी प्रणाली की न्याय वितरण प्रणाली 'अदालतों' नामक संरचनाओं के माध्यम से संचालित होती है और इस तरह की कार्यक्षमता का प्रारंभिक बिंदु 'अधिकार क्षेत्र' होता है जिसके द्वारा न्यायालय का फैसला कानून के अनुसार किए जाने वाले उचित 'निर्णय' के रूप में मान्य हो जाता है। अधिकार क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायालय की कुछ मामलों की सुनवाई करने की शक्ति को सीमित करता है। यदि न्यायालय उचित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, तो प्रत्येक न्यायालय संभवतः उनके पास लाए गए प्रत्येक मामले की सुनवाई कर सकता है, जिससे भ्रामक और विरोधाभासी परिणाम सामने आएंगे।⁶⁵

3.3.1.1 किसी देश की कानूनी प्रणाली के भीतर अधिकार क्षेत्र

किसी देश की कानूनी प्रणाली अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होती है, जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:^{66 a.} आर्थिक अधिकार क्षेत्र

ख. विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार ग. प्रादेशिक
मामले का क्षेत्राधिकार

क. आर्थिक क्षेत्राधिकार- यहाँ क्षेत्राधिकार विवाद के मूल्य की एक निर्धारित मौद्रिक सीमा पर संचालित होता है और तदनुसार न्यायालयों से संपर्क किया जाना चाहिए। ख. विषय वस्तु क्षेत्राधिकार: विषय वस्तु क्षेत्राधिकार विवादों के प्रकार के आधार पर क्षेत्राधिकार की प्रकृति को निर्दिष्ट करता है। उदाहरण के लिए, तलाक पर विवाद शुरू करने के लिए एक पारिवारिक न्यायालय होगा।

प्रादेशिक मामले का अधिकार क्षेत्र: अधिकार क्षेत्र के प्रादेशिक मामले में भौगोलिक कारक शामिल होता है, जहां विवाद को एक विशेष प्रकार के न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है।

3.3.1.2 भारत में विभिन्न न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

भारतीय संदर्भ में, अधिकार क्षेत्र का मुद्दा एक समान है क्योंकि कानून पूरे देश और सभी राज्यों के लिए बनाए गए हैं। इंटरनेट के आगमन और सूचना के प्रसारण और सीमाओं के पार व्यापार के लेन-देन के साथ, कानूनी मोर्चे पर कई मुद्दे सामने आए हैं।

अधिकार क्षेत्र के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण न्यायालय को यह पूछने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या उसके पास उसके समक्ष लाए गए मामले पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय, वित्तीय या विषय वस्तु अधिकार क्षेत्र है। इंटरनेट के साथ, 'क्षेत्रीय' अधिकार क्षेत्र का प्रश्न काफी हद तक इस तथ्य के कारण जटिल हो जाता है कि इंटरनेट सीमाहीन है।⁶⁷

3.3.1.3 इंटरनेट पर अधिकार क्षेत्र के मुद्दे

इंटरनेट दुनिया के हर देश को छूता है। यह सार्वभौमिकता व्यवसाय के लिए एक उपकरण के रूप में इसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा है और साथ ही यह अद्वितीय व्यावसायिक जोखिम भी पैदा करता है। दुनिया भर में पहुँच वेबसाइट संचालकों और इंटरनेट प्रकाशकों को दुनिया भर की अदालतों में जाने की संभावना के सामने उजागर करती है। इसलिए व्यवसायों को यह निर्धारित करना चाहिए कि उन्हें किस हद तक विभिन्न स्थानीय कानूनों का पालन करना चाहिए; उन्हें न केवल यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्हें कहाँ मुकदमा चलाने की उम्मीद करनी चाहिए, बल्कि यह भी कि किस क्षेत्राधिकार का कानून लागू होगा। हाल के कई मामले वेबसाइटों के उन देशों के कानूनों के अधीन होने के बढ़ते खतरों को दर्शाते हैं जिनके बाहर वे स्थित हैं। ये मामले यह भी दर्शाते हैं कि सभी वेबसाइटें समान नहीं बनाई गई हैं, और अधिकार क्षेत्र के प्रश्न अक्सर किसी व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और कार्रवाई के विशेष कारण पर निर्भर करते हैं। इन कारकों के साथ-साथ इंटरनेट के तेजी से विकास और कई अदालतों और नियामकों की तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण अधिकार क्षेत्र से संबंधित कानून का एक बढ़ता हुआ और अक्सर असंगत निकाय बन गया है। हालाँकि, धीरे-धीरे एक पैटर्न उभर रहा है जो सुझाव देता है कि एक वेब साइट को केवल उस राज्य के कानूनों के अधीन होना चाहिए जिसमें उसका सर्वर स्थित है, हालाँकि यह परिणाम काफी हद तक वेब साइट की अन्तर्क्रियाशीलता और इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस हद तक किसी विशेष फ़ोरम को लक्षित करता है। फिर भी, व्यवसायों के लिए अधिक स्थिर कानूनी ढांचे की आवश्यकता ने सार्वभौमिक और पूर्वानुमानित कानून बनाने के लिए कई प्रयासों को जन्म दिया है।

⁶⁷ देखें इकाई 6. अधिकार क्षेत्र का भारतीय संदर्भ; साइबर कानून के मूल सिद्धांत और उभरते मुद्दे न्यायशास्त्र सा

⁶⁸ इकाई 7 देखें। इंटरनेट क्षेत्राधिकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति; साइबर क्षेत्राधिकार में मामले; साइबर के मूल सिद्धांत कानून और उभरता हुआ न्यायशास्त्र

3.3.2 अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट कानून का विकास:

संक्षिप्त इतिहास

हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि हर काम के लिए एक मूल निर्माता या रचयिता होता है। इसलिए किसी भी काम के लिए पूरी दुनिया में उस काम का एक ही मूल निर्माता होता है, लेकिन कॉपीराइट कानून के सार्वभौमिक न होने के कारण मूल निर्माता को दी जाने वाली सुरक्षा पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। इंटरनेट के आगमन के साथ यह स्थिति और भी बदतर हो गई है।

बौद्धिक संपदा अधिकार अपरिहार्य क्षेत्रीय हैं, इसका मतलब है कि इसे केवल एक क्षेत्र में ही संरक्षित किया जा सकता है। कॉपीराइट को राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत की आवश्यकता है। यदि कोई अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठता है, तो कॉपीराइट स्वामी को उस क्षेत्र का नागरिक माना जाएगा जिसमें मुद्दा उठता है और वह वहां कॉपीराइट कानूनों के संरक्षण का दावा कर सकता है।

अतीत में (17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान) किसी भी कॉपीराइट किए गए कार्य को किसी विदेशी देश में कॉपी करना आसान था। आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कारण यह स्थिति पूरी तरह बदल गई है।

बर्न कन्वेंशन, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, रोम कन्वेंशन और डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि।

कॉपीराइट उसी प्रणाली से विकसित हुआ है जिस तरह आविष्कारक को शाही पेटेंट अनुदान दिया जाता है। ब्रिटिश संप्रभु ने पेटेंटधारक को कुछ सम्मान, पद, विशेषाधिकार, मताधिकार या एकाधिकार प्रदान करने के लिए पत्र (पेटेंट) प्रदान किया, जिसमें आविष्कार में एकाधिकार अधिकार शामिल हैं। इसी तरह के शाही पेटेंट कुछ लेखकों और मुद्रकों को दिए गए थे, जिसके द्वारा पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को प्रकाशित करने का विशेष अधिकार प्राप्त था। ऐसे अनुदानों का उद्देश्य लेखकों या प्रकाशकों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं था, बल्कि सरकारी राजस्व बढ़ाना और प्रकाशन की सामग्री पर सरकार को नियंत्रण देना था। यह प्रणाली 15वीं शताब्दी के अंत में वेनिस के साथ-साथ 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड में भी प्रभावी थी, जहाँ लंदन स्टेशनर्स कंपनी ने पुस्तकों की छपाई पर एकाधिकार प्राप्त किया और स्टार चैंबर 69 की अदालत द्वारा विनियमित किया गया।

1710 में इंग्लैंड में पारित ऐनी का कानून कॉपीराइट कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसने मान्यता दी कि कॉपीराइट कानून के प्राथमिक लाभार्थी लेखक होने चाहिए और इस विचार को स्थापित किया कि ऐसे कॉपीराइट की अवधि सीमित होनी चाहिए (तब 28 वर्ष निर्धारित की गई थी), जिसके बाद काम सार्वजनिक डोमेन में चले जाएंगे। डेनमार्क (1741), संयुक्त राज्य अमेरिका (1790) और फ्रांस (1793) में भी इसी तरह के कानून बनाए गए थे। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकांश अन्य देशों ने ऐसे कानून बनाए जो देशी लेखकों के काम की रक्षा करते थे।¹⁷⁰

बाद में औद्योगिक युग में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ संचार के साधन बढ़े और साथ ही साथ देशी बौद्धिक संपदा की चोरी भी बढ़ी। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1852 में फ्रांस ने अपने कॉपीराइट कानूनों की सुरक्षा सभी लेखकों को दी, चाहे उनकी राष्ट्रियता कुछ भी हो। इसने कॉपीराइट के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया। 1886 में, 10 देशों के प्रतिनिधियों ने बर्न (स्विट्जरलैंड) में बर्न कन्वेंशन को अपनाया, जिसे औपचारिक रूप से कॉपीराइट के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है।

⁶⁹ स्टार चैंबर कोर्ट की स्थापना मध्ययुगीन राजा की परिषद द्वारा सामान्य कानून अदालतों के नियमित न्याय के पूरक के रूप में की गई थी। <https://www.britannica.com/topic/copyright#ref157949>

⁷⁰ <https://www.britannica.com/topic/copyright#ref157949>

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [57]

साहित्यिक और कलात्मक कार्य। इस प्रकार कॉपीराइट की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की शुरुआत हुई।

बर्न कन्वेंशन के मूल में यह प्रावधान था कि प्रत्येक अनुबंधकारी देश बर्न संघ के अन्य देशों में पहली बार प्रकाशित कार्यों तथा उन अप्रकाशित कार्यों के लिए स्वचालित संरक्षण प्रदान करेगा जिनके लेखक ऐसे अन्य देशों के नागरिक या निवासी हैं।

संरक्षण 'स्वचालित संरक्षण' के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।⁷¹ बर्न कन्वेंशन को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा 1979 में इसमें संशोधन किया गया। वर्तमान में विश्व के 195 देशों में से 176 देश इस पर हस्ताक्षरकर्ता हैं।

6 सितंबर 1952 को जिनेवा में सार्वभौमिक कॉपीराइट कन्वेंशन को अपनाया गया। यूसीसी के अनुसार, "सभी देशों में साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक कार्यों के कॉपीराइट संरक्षण को आश्रय देने की इच्छा से प्रेरित होकर, सभी देशों के लिए उपयुक्त कॉपीराइट संरक्षण की एक प्रणाली और एक सार्वभौमिक सम्मेलन में व्यक्त, पहले से ही लागू अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के अतिरिक्त और उन्हें नुकसान पहुँचाए बिना, व्यक्ति के अधिकारों के लिए सम्मान सुनिश्चित करेगा और साहित्य, विज्ञान और कला के विकास को प्रोत्साहित करेगा, इस बात पर सहमत हुए कि इस तरह की सार्वभौमिक कॉपीराइट प्रणाली व्यापक प्रसार की सुविधा प्रदान करेगी और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाएगी।"⁷² यूसीसी को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा उन राज्यों के लिए बर्न कन्वेंशन के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था, जो बर्न कन्वेंशन के पहलुओं से असहमत थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में बहुपक्षीय कॉपीराइट संरक्षण में भाग लेना चाहते थे।

रोम कन्वेंशन कलाकारों के लिए प्रदर्शनों में, फोनोग्राम के निर्माताओं के लिए फोनोग्राम में और प्रसारण संगठनों के लिए प्रसारण में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कुल हस्ताक्षरकर्ता देश 93 हैं।

WIPO कॉपीराइट संधि (WCT)⁷³ बर्न कन्वेंशन के तहत एक विशेष समझौता है जो डिजिटल वातावरण में कार्यों और उनके लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। बर्न कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के अलावा, उन्हें कुछ आर्थिक अधिकार भी दिए गए हैं। यह संधि कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किए जाने वाले दो विषयों से भी संबंधित है: (i) कंप्यूटर प्रोग्राम, चाहे उनकी अभिव्यक्ति का तरीका या रूप कुछ भी हो; और (ii) डेटा या अन्य सामग्री ("डेटाबेस") का संकलन। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश 96.74 हैं।

हम देखते हैं कि बर्न और यूसीसी साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कार्यों को कवर करते हैं। रोम और डब्ल्यूसीटी अतिरिक्त कार्यों के लिए संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का विस्तार करते हैं। यदि कार्य किसी एक सम्मेलन के अंतर्गत आता है, तो कॉपीराइट स्वामी राष्ट्रीय उपचार का लाभ उठा सकता है

3.3.3 क्षेत्राधिकार और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम

⁷¹ http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html यूसीसी

⁷² की प्रस्तावना;

http://www.tauvisual.com/copyrightlaws/convenzione_internazionale_copyright_ginevra1952.pdf

⁷³ यूनिट 3 देखें; इंटरनेट में कॉपीराइट <http://>

⁷⁴ www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 62 कॉपीराइट उल्लंघन से उत्पन्न मामलों पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताती है। यह धारा कहती है-

(1) किसी कार्य में कॉपीराइट के अतिक्रमण या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के अतिक्रमण के संबंध में इस अध्याय के अधीन उत्पन्न होने वाला प्रत्येक वाद या अन्य सिविल कार्यवाही अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में संस्थित की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, "अधिकार क्षेत्र रखने वाले जिला न्यायालय" में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा जिला न्यायालय सम्मिलित होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित करने के समय, वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित करने वाला व्यक्ति या जहां ऐसे एक से अधिक व्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।

उपधारा (1) के अनुसार कॉपीराइट के उल्लंघन के सभी मामलों में जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। धारा 62 की उपधारा (2) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 द्वारा स्थापित सामान्य नियम से अलग है। सीपीसी की धारा-20 में कहा गया है कि "प्रत्येक वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर-

(क) प्रतिवादी, या प्रतिवादियों में से प्रत्येक, जहां एक से अधिक हैं, वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, या कारोबार करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है; या (ख) प्रतिवादियों में से कोई, जहां एक से अधिक हैं, वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, या कारोबार करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, जैसा कि पूर्वोक्त है, ऐसी संस्था में सहमति देता है; या (ग) वाद का हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है।

स्पष्टीकरण-1. किसी निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय से अथवा किसी ऐसे स्थान पर उत्पन्न होने वाले किसी कारण के संबंध में, जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय है, ऐसे स्थान पर कारोबार करता है।

इसलिए 'कार्रवाई का कारण' चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 (सी) के तहत मुकदमे की वैधता निर्धारित करेगा। यहां अधिकार क्षेत्र का विकल्प मुख्य रूप से प्रतिवादी की सुविधा से शासित होता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 62 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के नियम को उलट देती है। यह वादी को वहां मुकदमा करने की अनुमति देता है जहां वादी, 'वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है'। इस अपवाद को बनाने के पीछे कारण यह था कि एक कलाकार या कॉपीराइट मालिक का अपने 'कार्य में कॉपीराइट' पर पूर्ण नियंत्रण और प्रभुत्व होना चाहिए। उसे मुकदमा करने का अधिकार है, चाहे वह कहीं भी रहता हो या रहने के लिए जाता हो या व्यवसाय करता हो या व्यवसाय करने के लिए जाता हो, चाहे कार्रवाई का कारण या उल्लंघन कहीं से भी उत्पन्न हो। भारत के राजपत्र में 23-11-1956 को प्रकाशित संयुक्त समिति की रिपोर्ट, जिसने धारा 62(2) की नींव रखी और उसका पूर्वानुमान लगाया, में कहा गया: "समिति की राय में कई लेखक उल्लंघन की कार्यवाही शुरू करने से डरते हैं क्योंकि जिस न्यायालय में ऐसी कार्यवाही शुरू की जानी है वह एक ऐसे स्थान पर स्थित है

⁷⁵ देखें इकाई-6; अधिकार क्षेत्र का भारतीय संदर्भ (साइबर कानून के मूल सिद्धांत और उभरता हुआ न्यायशास्त्र)

उनके सामान्य निवास स्थान से काफी दूरी पर। समिति का मानना है कि इस बाधा को हटाया जाना चाहिए और नए उप-खंड (2) में तदनुसार प्रावधान किया गया है कि उल्लंघन की कार्यवाही उस जिला न्यायालय में शुरू की जा सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कार्यवाही शुरू करने वाला व्यक्ति सामान्य रूप से निवास करता है, व्यवसाय करता है, आदि।

इस प्रकार इसने लेखक को आसानी और सुविधा प्रदान की, जो कॉपीराइट संरक्षण का मूल सार है।⁷⁶ 3.3.3.1 सहमति द्वारा अधिकार क्षेत्र

यदि अनुबंध करने वाले पक्ष विशेष रूप से किसी विशेष स्थान का क्षेत्राधिकार रखने के लिए सहमति देते हैं, तो यह पक्षों पर बाध्यकारी होगा और बाद में यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अदालत के पास सामान्य आधार पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। सुश्री नरीमन फिल्मस बनाम डेलीप आर मेहता और अन्य के मामले में, वादी 'ए' में अपना व्यवसाय चला रहे थे और प्रतिवादी 'बी' में रहता है। दोनों पक्षों ने सहमति से "'बी' पर कानूनी कार्यवाही करने का फैसला किया।⁷⁷ 3.3.3.2 भारत के अनिवासी पर क्षेत्राधिकार भारत में, बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहाँ न्यायालयों ने अनिवासी प्रतिवादियों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है। हाल ही में, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अधिकार क्षेत्र पर एक गरमागरम लड़े गए मामले में विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में कानून के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य की जांच की ⁷⁸। दिल्ली उच्च

न्यायालय में कार्यवाही शुरू होने के बाद, प्रतिवादियों ने इंडिया टीवी के खिलाफ एरिजोना में 'रिवर्स डोमेन नेम हाइजैकिंग' मुकदमा दायर

किया। न्यायालय दो मुद्दों से चिंतित था, अर्थात् (ए) अमेरिका में स्थित प्रतिवादियों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग, (बी) क्या प्रतिवादियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में दायर मुकदमे के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए?

इस मुद्दे पर न्यायालय ने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क और अन्य⁷⁹ में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया।

उक्त मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, 'भारत की अदालतें इंग्लैंड की अदालतों की तरह कानून और इक्विटी दोनों की अदालतें हैं। न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा-एक न्यायसंगत राहत- प्रदान करने के सिद्धांत, एंटी-सूट निषेधाज्ञा प्रदान करने को भी नियंत्रित करेंगे, जो कि निषेधाज्ञा की ही एक किस्म है। जब कोई न्यायालय अपने समक्ष किसी मुकदमे/कार्यवाही के पक्षकार को किसी अन्य न्यायालय, जिसमें विदेशी न्यायालय भी शामिल है, में मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने से रोकता है, तो उसे एंटी-सूट निषेधाज्ञा कहा जाता है। यह एक सामान्य आधार है कि भारत में न्यायालयों के पास किसी ऐसे पक्षकार को एंटी-सूट निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार है, जिस पर किसी उचित मामले में उसका व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्विटी न्यायालय व्यक्तिगत रूप से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। हालांकि, शिष्टाचार के नियम को ध्यान में रखते हुए, इस शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ऐसा निषेधाज्ञा, हालांकि किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित है, वास्तव में किसी अन्य न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप का कारण बनता है।

जहाँ तक इस देश की स्थिति का सवाल है, गैर-निवासी प्रतिवादियों के संबंध में अधिकार क्षेत्र से संबंधित कोई 'लंबी भुजा' वाला कानून नहीं है। इस प्रकार, यह देखना होगा कि क्या प्रतिवादी की गतिविधियों का फोरम राज्य (भारत) से पर्याप्त संबंध है; क्या कार्रवाई का कारण फोरम के भीतर प्रतिवादी की गतिविधियों से उत्पन्न होता है और क्या

⁷⁶<http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/researchjournals/rejour/jipr/Fulltextsearch/2004/November%202004/JIPR-vol%209-November%202004-pp%20557-567.htm>

⁷⁷ बौद्धिक संपदा कानून, डॉ. सीपी सिंह, इलाहाबाद विधि एजेंसी प्रकाशन। पी.164 सीएस (ओएस) संख्या 102/2007 में दिनांक 10.7.07 का निर्णय;

⁷⁸ MANU/DE11703/2000

⁷⁹ मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क बनाम डब्ल्यूएससी क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (2003) (4) एससीसी 341; MANU/SCI0039/2003

क्षेत्राधिकार का प्रयोग उचित होगा। उपर्युक्त समीक्षा यह भी स्थापित करती है कि भारत में न्यायपालिका किस तरह सक्रिय है और स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के अभाव में भी, भारत को शेष विश्व से अलग करने के बजाय कानून को एकरूप बनाने और सही संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है।⁸⁰

3.3.4 ऑनलाइन कॉपीराइट समस्या और जानकारी

प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: लंबी भुजा प्रदान करना

क्षेत्राधिकार

इंटरनेट एक अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय माध्यम है। इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति - इसकी वैश्विक पहुंच और इसकी कथित "सीमाहीन" वास्तुकला - किसी भी संप्रभु के लिए इसके उपयोग को विनियमित करने वाले कानूनों को परिभाषित करने और / या लागू करने के लिए कई न्यायिक जटिलताएं प्रस्तुत करती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 1 (2) कहती है, "इसका विस्तार पूरे भारत में होगा और इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान के अलावा, यह किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होगा।"

उपरोक्त धारा को उक्त अधिनियम की धारा 75 के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के प्रावधान अतिरिक्त-क्षेत्रीय अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। इस अधिनियम की धारा 75 इस प्रकार है,-

"भारत के बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन के लिए अधिनियम का लागू होना। (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होंगे, चाहे उसकी राष्ट्रियता कुछ भी हो। (2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन पर लागू होगा यदि अपराध या उल्लंघन का गठन करने वाले कार्य या आचरण में भारत में स्थित कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क शामिल है।"

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त करता है या पहुँच प्राप्त करता है, ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से कोई डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस या सूचना डाउनलोड करता है, उसकी प्रतिलिपि बनाता है या उसे निकालता है, जिसमें किसी हटाने योग्य भंडारण माध्यम में रखी या संग्रहीत सूचना या डेटा शामिल है, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद डेटा या प्रोग्राम को संशोधित, नष्ट, रिकॉर्ड, प्रेषित करता है और किसी भी तरह से किसी भी कंप्यूटर संसाधन को नष्ट, परिवर्तित, मिटा, जोड़ता, संशोधित या पुनर्व्यवस्थित करता है, मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति के बिना जो कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का प्रभारी है, तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को एक करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होगा।⁸¹ इस प्रकार कॉपीराइट स्वामी को सुरक्षा प्रदान की गई।

उक्त अधिनियम में यह भी कहा गया है कि मुआवजे की मात्रा का निर्धारण करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी अनुचित लाभ की प्राप्ति की राशि को, जहां कहीं भी मात्रात्मक हो, ध्यान में रखेगा।

⁸⁰ देखें इकाई-6; अधिकार क्षेत्र का भारतीय संदर्भ (साइबर कानून के मूल सिद्धांत और उभरते मुद्दे) न्यायशास्त्र सा)

⁸¹ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [61]

चूक के परिणामस्वरूप की गई क्षति, चूक के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुई हानि की राशि तथा चूक की बार-बार होने वाली प्रकृति।

इस प्रकार हम देखते हैं कि, यदि कॉपीराइट का उल्लंघन जानबूझकर और लाभ कमाने के लिए किया जाता है, तो निर्दोष उल्लंघन की तुलना में नुकसान की मात्रा अधिक होगी और प्रभावित व्यक्ति (जुमाना एक करोड़ रुपये तक हो सकता है) कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त निवारक है।

धारा 79 कुछ मामलों में आईएसपी को दायित्व से छूट देती है। कोई भी अपराध या उल्लंघन इंटरनेट सेवा प्रदाता की जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध या उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित तत्परता बरती थी, ऐसे मामलों में वह इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं होगा।

इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।⁸²

इंटरनेट/सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, धारा 1(2) के प्रावधानों को धारा 75 के साथ पढ़ने पर न्यायालयों को 'दीर्घ भुजा क्षेत्राधिकार' का अधिकार प्राप्त होता है। हालाँकि, इन प्रावधानों को लागू करना एक कठिन और थकाऊ काम है। धारा 81 एक गैर-बाधा खंड है, जो वर्तमान में लागू किसी भी अन्य असंगत कानून पर प्रभावी होगा। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक 'विशेष कानून' है, जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों को कवर करता है, इसलिए यह अन्य सभी असंगत और परस्पर विरोधी कानूनों पर प्रभावी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, एक विशेष अधिनियम होने के नाते, जो बाद के समय में है, अन्य अधिनियमों में उल्लिखित क्षेत्राधिकार प्रक्रियाओं पर प्रभावी होगा। दीर्घ भुजा क्षेत्राधिकार को शामिल करके, इसने पूरी दुनिया में अच्छी तरह से स्वीकृत अभ्यास के अनुसार काम किया है।

भारत संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) का एक हस्ताक्षरकर्ता है। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधान सुस्थापित और स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मानदंडों के अनुरूप हैं। इसलिए, न्यायालयों के पास ऑनलाइन कॉपीराइट मुद्दों से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा। वास्तव में, इन प्रावधानों की अनुपस्थिति में भी, भारत में न्यायालयों के पास सुस्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों को शामिल करने की शक्ति है, यदि वे नगरपालिका कानूनों के अनुरूप हैं और उनके साथ संघर्ष में नहीं हैं। ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बीरेंद्र बहादुर पांडे⁸³ मामले में, न्यायालय ने देखा कि राष्ट्रों की सद्भावना के लिए यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को नगरपालिका कानून में बिना किसी स्पष्ट विधायी मंजूरी के भी समायोजित किया जा सकता है, बशर्ते कि ये संसद के अधिनियमों के साथ संघर्ष में न हों। लेकिन अगर संघर्ष अपरिहार्य है, तो संसद को झुकना होगा। ऐसी धारणा है कि संसद ऐसे अधिकार क्षेत्र का दावा या ग्रहण नहीं करती जो राष्ट्रों की आम सहमति से स्थापित सीमाओं से परे हो और कानूनों की व्याख्या की जानी चाहिए, बशर्ते उनकी भाषा इसकी अनुमति दे, ताकि राष्ट्रों की सद्भावना या अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के साथ असंगत न हो। लेकिन यह सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब कोई अस्पष्टता हो और स्पष्ट रूप से व्यक्त इरादे के लिए रास्ता देना चाहिए। यदि वैधानिक

⁸² सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 81

⁸³ एआईआर 1984 एससी 667

अधिनियमों का अर्थ स्पष्ट है, इसलिए इनका अर्थ उनके अर्थ के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए, भले ही वे राष्ट्रों के समुदाय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हों।⁸⁴ यह अधिनियम किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन पर लागू होता है, यदि अपराध या उल्लंघन करने वाला कार्य या आचरण

भारत में स्थित कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, जो भारत में स्थित कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत है, तो ऐसे व्यक्ति पर भारत के कॉपीराइट कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंटरनेट की अनोखी विशेषताएं इसे दुनिया भर की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाती हैं, क्योंकि यह दुनिया के सभी देशों में स्थित कंप्यूटरों को शामिल करते हुए कंप्यूटरों का मजबूत और सघन नेटवर्क है। इसके अलावा, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अदालतों को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अलग-अलग अधिनियमों के दो प्रावधानों को संयोजित करने से रोकता है। इस प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 1(2), 75 और 81 के प्रावधानों को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 5385 के साथ पढ़ा जाए तो सभी प्रकार की अधिकार क्षेत्र की समस्याओं का एक व्यवहार्य समाधान प्रदान किया जा सकता है।

इन प्रावधानों को उन सुस्वीकृत 'न्यायक्षेत्र सिद्धांतों' से भी बल मिलता है, जिनका विश्व के लगभग सभी देशों में समान रूप से पालन किया जाता है। कॉपीराइट के ऑनलाइन उल्लंघन से संबंधित न्यायक्षेत्र संबंधी मुद्दों को संभालना आसान नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र की न्याय व्यवस्था इन उल्लंघनों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉपीराइट के इन उल्लंघनों से निपटने के लिए विभिन्न संधियाँ और पारस्परिक व्यवस्थाएँ अपनाई गई हैं। ये निश्चित रूप से उनके स्वामियों को मजबूत और प्रभावी कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होंगी। हालाँकि, इन कानूनों और व्यवस्थाओं की अंतिम सफलता संबंधित राष्ट्र की न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका पर निर्भर करेगी। यदि न्यायपालिका समय की मांग को समझते हुए कॉपीराइट उल्लंघनों को गंभीरता से लेती है, तो भविष्य में इनके उल्लंघन की संभावना नाममात्र हो जाती है।

3.3.5 क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीय पहलू

कॉपीराइट से संबंधित

3.3.5.1 अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकार क्षेत्र या सिद्धांतों के छह

आम तौर पर स्वीकृत आधार हैं जिनके तहत कोई राज्य किसी गतिविधि पर कानून का नियम निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र होने का दावा कर सकता है।

हैं:

1. व्यक्तिपरक क्षेत्रीयता 2. वस्तुनिष्ठ क्षेत्रीयता 3.

राष्ट्रीयता 4. सुरक्षात्मक सिद्धांत 5. निष्क्रिय

राष्ट्रीयता 6. सार्वभौमिकता

⁸⁴ एआईआर 1984 एससी 667

<http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/researchjournals/rejour/jipr/Fulltextsearch/2004/November%202004/JIPR-vol%209-November%202004-pp%20557-567.htm> धारा 53 में प्रावधान किया गया

⁸⁵ था, जिसके तहत आयतित उल्लंघनकारी प्रतियों को सीमा शुल्क आयुक्त को हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक सामान्य नियम के अनुसार, यहां तक कि जहां अधिकार क्षेत्र का एक आधार मौजूद है, वहां अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उचित होना चाहिए।

व्यक्तिपरक प्रादेशिकता अब तक छह में से सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई गतिविधि फोरम राज्य के क्षेत्र में होती है, तो फोरम राज्य के पास उस गतिविधि के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है। दुनिया में अधिकांश आपराधिक कानून इसी प्रकार के हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रादेशिकता वहां लागू होती है, जहां कार्रवाई फोरम राज्य के क्षेत्र के बाहर होती है, लेकिन उस गतिविधि का प्राथमिक प्रभाव फोरम राज्य के भीतर होता है।

राष्ट्रीयता अधिकार क्षेत्र का आधार है, जहां फोरम राज्य अभिनेता की राष्ट्रीयता के आधार पर किसी कार्रवाई के लिए कानून निर्धारित करने के अधिकार का दावा करता है। उदाहरण के लिए, नीदरलैंड के कानून के तहत, एक डच नागरिक "विदेश में किए गए अपराध के लिए हॉलैंड में अभियोजन के लिए उत्तरदायी है, जो नीदरलैंड के कानून के तहत दंडनीय है और जो उस देश के कानून के तहत भी दंडनीय है जहां अपराध किया गया था।" 86 कई अन्य नागरिक कानून देशों में भी इसी तरह के कानून हैं।

निष्क्रिय राष्ट्रीयता पीड़ित की राष्ट्रीयता पर आधारित अधिकार क्षेत्र का सिद्धांत है। निष्क्रिय और "सक्रिय" राष्ट्रीयता को अक्सर अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक साथ लागू किया जाता है क्योंकि किसी राज्य को किसी अपराध पर मुकदमा चलाने में अधिक रुचि होती है जब अपराधी और पीड़ित दोनों उस राज्य के नागरिक होते हैं। निष्क्रिय राष्ट्रीयता का उपयोग दो कारणों से शायद ही कभी किया जाता है। सबसे पहले, किसी राष्ट्र के लिए यह आग्रह करना अपमानजनक है कि विदेशी कानून उसके नागरिकों की विदेश में सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। दूसरा, पीड़ित पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है।

सुरक्षात्मक सिद्धांत किसी संप्रभु की अन्य स्थानों पर की गई कार्रवाइयों को दंडित करने की इच्छा को व्यक्त करता है, केवल इसलिए क्योंकि उसे उन कार्रवाइयों से खतरा महसूस होता है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल तब किया जाता है जब "पीड़ित" सरकार या संप्रभु खुद हो।

अधिकार क्षेत्र का अंतिम आधार सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र है, जिसे कभी-कभी "सार्वभौमिक हित" अधिकार क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, सार्वभौमिक हित अधिकार क्षेत्र किसी भी संप्रभु का समुद्री डाकुओं को पकड़ने और दंडित करने का अधिकार था। अधिकार क्षेत्र के इस रूप को पिछली डेढ़ सदी के दौरान और अधिक विस्तारित किया गया है ताकि इसमें अधिक से अधिक जुस कोजेन्स शामिल किए जा सकें: गुलामी, नरसंहार और अपहरण (हवाई डकैती)।

यद्यपि भविष्य में सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार स्वाभाविक रूप से इंटरनेट पाइरेसी, जैसे कि कंप्यूटर हैकिंग और वायरस तक विस्तारित हो सकता है, सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के पारंपरिक कल्लुए जैसे विकास को देखते हुए ऐसा विस्तार असंभव है। उतना ही महत्वपूर्ण, सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार पारंपरिक रूप से केवल बहुत गंभीर अपराधों को ही कवर करता है।⁸⁷

3.3.5.2 मुकदमा दायर करने के स्थान के बारे में प्रश्न

अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों में लेखक और आविष्कारक के कॉपीराइट की सुरक्षा के प्रावधानों के बारे में कहा गया है, लेकिन इनमें से कोई भी न्यायालय के बारे में नहीं बताता है, जिसके पास लेखक के अधिकार के उल्लंघन के मामले में अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार मुकदमा दायर करने के लिए, लेखक पारंपरिक अधिकार क्षेत्र पर निर्भर है।

3.3.5.2.1 यूरोप में स्थिति

⁸⁶ पब्लिक प्रॉसिच्यूटर/वाई., एचआर मई और सितंबर 1957, 24 अंतर्राष्ट्रीय एल. प्रतिनिधि 264, 265 (1957)।

⁸⁷ देखें इकाई 4- अधिकार क्षेत्र की अवधारणा; साइबर कानून के मूल सिद्धांत और उभरते हुए मुद्दे न्यायशास्त्र सा

27 सितंबर, 1968 के ब्रुसेल्स विनियमन और 16 सितंबर, 1988 के लुगानो कन्वेंशन द्वारा, EFTA सदस्यों ने अधिकार क्षेत्र के लिए सामान्य नियमों का एक सेट स्थापित किया। ब्रुसेल्स विनियमन यूरोपीय संघ (ईयू) के विभिन्न सदस्य राज्यों के व्यक्तियों के बीच विवादों पर लागू होता है। ब्रुसेल्स विनियमन विशेष रूप से नागरिक और वाणिज्यिक मामलों पर लागू होता है। ब्रुसेल्स विनियमन अधिकार क्षेत्र के संबंध में सामान्य नियम प्रदान करता है। मूल सिद्धांत यह है कि जिस यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में प्रतिवादी का निवास है, उसके न्यायालयों को विवाद की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा, भले ही प्रतिवादी की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। जबकि निवास का सिद्धांत अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने के लिए सामान्य नियम के रूप में कार्य करता है, एक प्रतिवादी पर, कुछ परिस्थितियों में, उस सदस्य राज्य के अलावा किसी अन्य सदस्य राज्य की अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है जिसमें वह निवास करता है। ब्रुसेल्स विनियमन, टोर्ट, डेलिक्ट या अर्ध-डेलिक्ट से संबंधित मामलों के बारे में 'विशेष अधिकार क्षेत्र' रखता है।⁸⁸ जिस सदस्य राज्य में हानिकारक घटना घटी है या हो सकती है, उसके न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र होगा।

यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि, अंग्रेजी न्यायालयों के पास यह निर्धारित करने का अधिकार है कि विदेशी कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है या नहीं। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अमेरिकी कॉपीराइट उल्लंघन की कार्रवाई अंग्रेजी न्यायालयों में न्यायोचित थी। हालाँकि उल्लंघनकारी कार्य अमेरिका में हो रहे थे, लेकिन प्रतिवादी एक यूके नागरिक था और यहाँ का निवासी था, जिसने अंग्रेजी न्यायालयों को उस पर व्यक्तिगत अधिकार दिया।⁸⁹

अंग्रेजी कानून के संबंध में, यूकेएससी ने ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी बनाम कॉम्पैनिया डे मोकाम्बिक और पॉटर बनाम ब्रोकर हिल प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के मामले में इस नियम को स्वीकार किया कि अंग्रेजी न्यायालय के पास विदेशी संपत्ति के शीर्षक या अधिकार के मुद्दों को निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, यूकेएससी ने कहा कि इस नियम को उन संपत्ति अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जहाँ अधिकारों का अस्तित्व पहले से ही स्थापित हो चुका है। नतीजतन, बशर्ते कि प्रतिवादी पर व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र स्थापित किया जा सके, विदेशी कॉपीराइट के उल्लंघन का दावा अंग्रेजी अदालतों द्वारा न्यायोचित है, भले ही यूके में या यूके कानून के तहत उल्लंघन का कोई कृत्य न हुआ हो।

इससे विदेशी दावेदारों के लिए यूरोपीय संघ के बाहर किए गए उल्लंघन के कृत्यों के लिए ब्रिटेन में ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ कार्यवाही करने का रास्ता साफ हो गया है, जो उस देश के कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। यूकेएससी का निर्णय आईपी अधिकारों की पारंपरिक 'स्थानीयकृत' धारणा से दूर जाने के स्पष्ट इरादे को दर्शाता है।⁹⁰

3.3.5.2.2 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति

अमेरिकी कानून में पक्षों पर व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र के लिए दो आधार हैं:

सबसे पहले, सामान्य अधिकार क्षेत्र तब मौजूद होता है जब प्रतिवादी का फोरम राज्य के साथ निरंतर और व्यवस्थित संपर्क होता है। यदि प्रतिवादी फोरम में रहता है, या फोरम के साथ "व्यवसाय" करता है, तो न्यायालय के पास उस पर सामान्य न्यायिक क्षमता होगी। दूसरे शब्दों में, फोरम उस प्रतिवादी के खिलाफ सभी क्षेत्रीय दावों की सुनवाई करने के लिए सक्षम है।

⁸⁸ ब्रुसेल्स I विनियमन के अनुच्छेद 5(3) लुकासफिल्म

⁸⁹ लिमिटेड और अन्य बनाम एंसवर्थ और अन्य [2011] आईपी एंड टी 733 <https://www.fieldfisher.com/>

⁹⁰ publications/2011/08/uk-supreme-court-rules-on-the-enforceability-of-foreign-copyright-in-uk

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [65]

दूसरा, विशिष्ट क्षेत्राधिकार प्रतिवादी द्वारा फोरम राज्य के प्रति निर्देशित उद्देश्यपूर्ण कृत्यों (उल्लंघन) पर आधारित है। न्यायालय के पास केवल फोरम में किए गए उल्लंघन से संबंधित दावे पर क्षेत्राधिकार होगा, न कि फोरम के बाहर किए गए उल्लंघनकारी कृत्यों पर।

इस तरह कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कार्रवाई के कारणों को किसी भी न्यायालय में लाया जा सकता है, जिसका प्रतिवादी पर अधिकार क्षेत्र है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ तक इंटरनेट उल्लंघन का संबंध है क्योंकि अधिकार क्षेत्र केवल लोकस डेलिवरी तक सीमित नहीं होगा (इंटरनेट उल्लंघन हर जगह होते हैं, इसलिए व्यवहार में उन्हें कहीं भी लागू नहीं किया जा सकता है)। हालाँकि, यह कुछ संभावित समस्याएँ भी प्रस्तुत करता है:

1. इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट पर किए गए कॉपीराइट उल्लंघन के लिए लक्षित प्रतिवादी बन सकते हैं, और उन मंचों पर दावे देर हो सकते हैं जहाँ ISP व्यवसाय के लिए पंजीकृत हैं। उदाहरण के लिए, चूँकि AOL वर्जीनिया में स्थित है, इसलिए वर्जीनिया की अदालतों को AOL के माध्यम से किए गए कॉपीराइट उल्लंघन और अपकृत्यों के दावों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। हालाँकि, कुछ अदालतें इस संबंध के आधार पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। जून 1999 में वर्जीनिया के एक न्यायाधीश ने AOL पर मानहानि के दावे पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि "सिर्फ इसलिए कि AOL यहाँ स्थित है, इसका मतलब यह नहीं है कि वर्जीनिया की अदालतें दुनिया भर में इंटरनेट संचार से जुड़े मुकदमों के लिए खुली हैं।"⁹¹

2. इसके अलावा, व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र के सामान्य आधारों के आधार पर, हाल के वर्षों में एक प्रवृत्ति उभरी है जो यू.एस. के बाहर "स्थित" वेबसाइटों (और उल्लंघनों) पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए लॉन्ग आर्म अधिकार क्षेत्र के आवेदन के पक्ष में है। अधिकार क्षेत्र को ऐसे विदेशी देशों में मान्यता नहीं दी जा सकती है जहाँ वास्तव में उल्लंघन हुआ हो और जहाँ यू.एस. के निर्णय को अंततः लागू किया जाना चाहिए।

एक अमेरिकी मामला, iCrave Tv, 92 एक दिलचस्प मामला है और यह इंटरनेट पर अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट उल्लंघन में अधिकार क्षेत्र और कानून के विकल्प के जटिल मुद्दों को दर्शाता है। iCrave TV, एक कनाडाई वेबसाइट थी जो कनाडाई कार्यक्रमों और सीमा पार से प्राप्त अमेरिकी टेलीविजन प्रोग्रामिंग से प्रसारण संकेतों को उठाती थी। iCrave ने फिर उन संकेतों को वीडियो स्ट्रीमिंग प्रारूप में परिवर्तित किया और उन्हें अपनी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया। iCrave TV ने दावा किया कि अमेरिकी प्रोग्रामिंग का अधिग्रहण, रूपांतरण और पुनर्वितरण कनाडाई कानून (प्रसारण प्रदर्शनों के द्वितीयक प्रसारण के संबंध में कनाडाई कानून से संबंधित) के तहत वैध था। सिद्धांत रूप में, iCrave TV ने अपनी वेबसाइट तक केवल कनाडाई उपयोगकर्ताओं की पहुंच को प्रतिबंधित किया; हालाँकि, एक कनाडाई टेलीफोन क्षेत्र कोड की पहचान और आपूर्ति करके इस प्रतिबंध को आसानी से दरकिनार किया जा सकता था।

अमेरिकी टीवी निर्माताओं ने पेंसिल्वेनिया के पश्चिमी जिले में संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया, जहां आईक्रेव टीवी के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय बिक्री प्रबंधक रहते थे। इस तथ्य के आधार पर अदालत ने कनाडाई व्यावसायिक इकाई पर सामान्य व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र पाया। कानून के विकल्प का निर्धारण करने के लिए, अदालत ने अमेरिका के साथ पर्याप्त लगाव के बिंदु पाए, जिससे कि इसे अनुमति दी जा सके।

⁹¹ बोचन बनाम लाफोर्टेन, 68 एफ.सप्प. 2डी 692 (ईडी वीए. 1999);

<https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.in/&httpsredir=1&article=1067&context=annlsurvey>

⁹² ट्वेंटीएथ सेंचुरी फॉक्स फिल्म कॉर्पोरेशन बनाम आईक्रेव टीवी, संख्या 00-121 (डब्ल्यूओ पा. 20 जनवरी, 2000)

प्रतिवादियों की गतिविधियों पर अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम के लागू होने का आरोप लगाया गया। इसके बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उल्लंघन अमेरिका के भीतर हुआ जब अमेरिकी नागरिकों ने कॉपीराइट सामग्री की अनधिकृत स्ट्रीमिंग प्राप्त की और देखी, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि स्ट्रीमिंग प्रसारण कनाडा में शुरू हुआ था।

इस मामले में, टीवी निर्माता केवल अमेरिका में उल्लंघन के बारे में चिंतित थे, क्योंकि वेबसाइट के आधे से अधिक ग्राहक अमेरिकी निवासी थे। लेकिन एक और धारणा यह हो सकती है कि, iCrave TV वेबसाइट को अन्य महाद्वीपों के अन्य देशों के लोगों द्वारा भी काफी संख्या में एक्सेस किया गया था।

कानून और अधिकार क्षेत्र के मौजूदा विकल्प के नियमों के तहत, उल्लंघन के लिए दुनिया भर में दावा आसानी से एक अमेरिकी अदालत में लाया जा सकता था और संभवतः उन्हीं कारणों से स्वीकार किया गया होगा। हालाँकि, लागू किए गए कानून का विकल्प अलग हो सकता है। लेक्स लोकी प्रोटेक्शनिस के अनुसार, अमेरिकी अदालत को हर उस देश के घरेलू कानूनों को लागू करना चाहिए जहाँ स्ट्रीम किए गए प्रसारण को प्राप्त किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रसारण "प्रसारण के द्वितीयक प्रसारण" के रूप में योग्य है या उल्लंघन के रूप में। यह प्रक्रिया न केवल महंगी और कठिन होगी (अनुवाद, विदेशी कानूनों का प्रमाण), बल्कि विवादास्पद भी होगी, क्योंकि अमेरिकी निर्णय अन्य देशों में लागू नहीं हो सकता है जो अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि, एक अमेरिकी अदालत को कनाडा में शुरू होने वाले और यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना या अन्य जगहों पर समाप्त होने वाले उल्लंघन से क्यों निपटना चाहिए? वैकल्पिक रूप से, निर्माता प्रत्येक घरेलू कॉपीराइट कानून के तहत, प्राप्ति के प्रत्येक देश में मुकदमा ला सकते हैं।

यदि मुकदमा कनाडा (प्रतिवादी के निवास का देश) में लाया गया होता, तो अन्य सभी देशों में निर्णय के लागू होने की संभावना बेहतर होती। कनाडाई न्यायालय उल्लंघन की बात से इनकार कर सकता था, इस आधार पर कि लेक्स लोकी प्रोटेक्शनिस कनाडाई कानून है (यानी, वह कानून जहाँ से प्रसारण शुरू हुआ, न कि रिसेप्शन के प्रत्येक देश के कानून)।⁹³

इस प्रकार हमने देखा है कि अधिकार क्षेत्र और कानून के मुद्दों का विकल्प स्वाभाविक रूप से संबंधित हैं और इनके लिए समरूप समाधान की आवश्यकता है। चूँकि इंटरनेट को "नो मैन्स लैंड" के रूप में माना जाता है, इसलिए इंटरनेट पर कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कानून और अधिकार क्षेत्र के विकल्प के मुद्दों को हल करने के लिए कोई एक सही समाधान नहीं है।

3.4 सारांश

अधिकार क्षेत्र कानूनी निर्णय और निर्णय लेने की आधिकारिक शक्ति है और यह क्षेत्र द्वारा सीमित है। कॉपीराइट एक विशेष और आर्बिट्ररी कानूनी अधिकार है, जो निर्माता या मूल निर्माता को साहित्यिक या संगीत सामग्री को छापने, प्रकाशित करने, प्रदर्शन करने, फिल्माने या रिकॉर्ड करने के लिए दिया जाता है और यह क्षेत्र द्वारा सीमित नहीं हो सकता है।

किसी देश की कानूनी प्रणाली अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होती है, जिसे विवाद के मूल्य, शामिल विवादों के प्रकार और भौगोलिक कारक के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जहाँ विवाद को किसी विशेष प्रकार के न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है।

⁹³ कॉपीराइट: डिजिटल युग में कानून और अधिकार क्षेत्र का चुनाव राकेल ज़ालबार्डर द्वारा; <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.in/&httpsredir=1&article=1067&context=annlsurvey>

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [67]

संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत में भी क्षेत्राधिकार एक समान है, क्योंकि कानून पूरे देश और सभी राज्यों के लिए बनाए गए हैं।

इंटरनेट की सार्वभौमिकता व्यापार के लिए एक उपकरण के रूप में इसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा है और साथ ही यह अद्वितीय व्यावसायिक जोखिम भी पैदा करता है। कई हालिया मामले वेब साइटों के बढ़ते खतरों को दर्शाते हैं जो उन देशों के कानूनों के अधीन हैं जिनके बाहर वे आधारित हैं, साथ ही अधिकार क्षेत्र के प्रश्न अक्सर एक व्यक्तिगत मामले में तथ्यों और कार्रवाई के विशेष कारण पर निर्भर करते हैं।

किसी भी कार्य के लिए पूरी दुनिया में उस कार्य का केवल एक ही मूल निर्माता होता है, लेकिन सार्वभौमिक कॉपीराइट कानून की कमी के कारण मूल निर्माता को दी जाने वाली सुरक्षा पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। कॉपीराइट को राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत की आवश्यकता है। यदि कोई अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठता है, तो कॉपीराइट स्वामी को उस क्षेत्र का नागरिक माना जाएगा जिसमें मुद्दा उठता है और वह वहां कॉपीराइट कानूनों के संरक्षण का दावा कर सकता है।

कॉपीराइट की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की शुरुआत 1886 में हुई, जब 10 देशों के प्रतिनिधियों ने बर्न (स्विट्जरलैंड) में बर्न कन्वेंशन को अपनाया, जिसे औपचारिक रूप से साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। 1996 में WIPO कॉपीराइट संधि (WCT) बर्न कन्वेंशन के तहत एक विशेष समझौता है जो डिजिटल वातावरण में कार्यों और उनके लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है।

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 62 कॉपीराइट उल्लंघन से उत्पन्न मामलों पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताती है। इसके अनुसार कॉपीराइट उल्लंघन के मुद्दों पर जिला न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 1 (2) को उक्त अधिनियम की धारा 75 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के प्रावधान अतिरिक्त-क्षेत्रीय अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि यदि कॉपीराइट का उल्लंघन जानबूझकर और लाभ कमाने के लिए किया जाता है, तो नुकसान की मात्रा निर्दोष उल्लंघन की तुलना में अधिक होगी और इसलिए प्रभावित होगा (जुर्माना एक करोड़ रुपये तक हो सकता है) जो कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त निवारक है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 1(2), 75 और 81 के प्रावधानों को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 53 के साथ पढ़ने पर सभी प्रकार की अधिकारिता संबंधी समस्याओं का व्यवहार्य समाधान मिल सकता है। इन प्रावधानों को सुविख्यात 'अधिकारिता सिद्धांतों' से भी बल मिलता है, जिनका दुनिया के लगभग सभी देशों में समान रूप से पालन किया जाता है।

यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि, अंग्रेजी न्यायालयों के पास यह निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है कि विदेशी कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है या नहीं। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अमेरिकी कॉपीराइट उल्लंघन की कार्रवाई अंग्रेजी न्यायालयों में न्यायोचित थी। हालाँकि उल्लंघनकारी कार्य अमेरिका में हो रहे थे, लेकिन प्रतिवादी एक यूके नागरिक था और यहाँ का निवासी था, जिसने अंग्रेजी न्यायालयों को उस पर व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र दिया। 94 यूएसए में विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्रतिवादी द्वारा फोरम राज्य की ओर निर्देशित उद्देश्यपूर्ण कृत्यों (उल्लंघन) पर आधारित है। न्यायालय के पास केवल फोरम में किए गए उल्लंघन से संबंधित दावे पर अधिकार क्षेत्र होगा, न कि फोरम के बाहर किए गए उल्लंघनकारी कृत्यों पर। इस तरह कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कार्रवाई के कारण लाए जा सकते हैं

⁹⁴ लुकासफिल्म लिमिटेड और अन्य बनाम एन्सवर्थ और अन्य [2011] आईपी एंड टी 733

कोई भी न्यायालय जिसके पास प्रतिवादी पर क्षेत्राधिकार हो। एक अमेरिकी मामला, iCrave Tv,95 एक दिलचस्प मामला है और अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट में अधिकार क्षेत्र और कानून के विकल्प के जटिल मुद्दों को स्पष्ट करें इंटरनेट पर उल्लंघन.

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की कानूनी प्रणाली कॉपीराइट उल्लंघनों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया करती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संधियाँ और पारस्परिक व्यवस्थाएँ अपनाई गई हैं।

कॉपीराइट के इन उल्लंघनों से निपटने में ये निश्चित रूप से मजबूत और

अपने मालिकों को प्रभावी कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करना। इन कानूनों की अंतिम सफलता और

हालाँकि, व्यवस्थाएँ न्यायपालिका द्वारा निर्भाई गई सक्रिय भूमिका पर निर्भर करेंगी।

संबंधित राष्ट्र। यदि न्यायपालिका समय की आवश्यकता को समझते हुए कॉपीराइट उल्लंघनों को गंभीरता से लेती है

यदि इन्हें गंभीरता से लिया जाए, तो भविष्य में इनके उल्लंघन की संभावना नाममात्र हो जाएगी।

3.5 शब्दावली

1. इन पर्सॉनम: इन पर्सॉनम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है "किसी विशेष व्यक्ति की ओर निर्देशित"। ऐसे मुकदमे में जिसमें मामला किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध हो, उस व्यक्ति को सम्मन और शिकायत के साथ तामिल किया जाना चाहिए ताकि न्यायालय को मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र मिल सके, और निर्णय उस व्यक्ति पर लागू होता है और इसे "इन पर्सॉनम निर्णय" कहा जाता है। इन पर्सॉनम को इन रेम से अलग किया जाता है, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के बजाय संपत्ति या "पूरी दुनिया" पर लागू होता है।
2. जूस कोजेन्स: जूस कोजेन्स (या ius कोजेन्स) एक लैटिन वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ है "बाध्यकारी कानून"। यह रोमन कानून में पहले से ही ज्ञात विचार से उपजा है कि कुछ कानूनी नियमों को अनुबंधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे मौलिक मूल्यों को बनाए रखते हैं। अधिकांश राज्य और लेखक इस बात से सहमत हैं कि जूस कोजेन्स अंतर्राष्ट्रीय कानून में मौजूद है। इन मामलों पर लगातार बहस के बावजूद, जूस कोजेन्स को अब संधियों के कानून के भीतर और बाहर कई कानूनी साधनों में संदर्भित किया जाता है। इसलिए जूस कोजेन्स एक अनिवार्य मानदंड है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक मौलिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है जिसे राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक ऐसे मानदंड के रूप में स्वीकार किया जाता है जिससे किसी भी तरह की छूट की अनुमति नहीं है।
3. ईएफटीए सदस्य: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो अपने चार सदस्य देशों - आइसलैंड, लिक्टेन्स्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड - और दुनिया भर में उनके व्यापारिक साझेदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
4. लोकस डेलिक्टी: लोकस डेलिक्टी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'अपराध का दृश्य'। वह स्थान जहाँ अपराध किया गया था।
5. लेक्स लोकी प्रोटेक्शनिस: लेक्स लोकी प्रोटेक्शनिस एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है, उस स्थान का कानून जहाँ सुरक्षा का दावा किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों, जैसे कॉपीराइट या पेटेंट के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर लागू कानून का विकल्प है।

3.6 एसएक्यूएस

⁹⁵ ट्वेंटीएथ सेंचुरी फॉक्स फिल्म कॉर्पोरेशन बनाम आईक्रेव टीवी, संख्या 00-121 (डब्ल्यूओ पा. 20 जनवरी, 2000)

5. लघु उत्तरीय प्रश्न (iv) इंटरनेट के लिए प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को क्या जटिल बनाता है? (v) कॉपीराइट अधिनियम की कौन सी धारा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के नियम को उलट देती है, जैसा कि नीचे दिया गया है

सिविल प्रक्रिया संहिता?

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की कौन सी धारा आईएसपी को दायित्व से राहत देती है कुछ मामलों में?

6. रिक्त स्थान भरें

(xi) जहां क्षेत्राधिकार विवाद के मूल्य की निर्धारित मौद्रिक सीमा पर संचालित होता है और तदनुसार न्यायालय से संपर्क करना पड़ता है, इसे ----- कहा जाता है।

(xii) भारतीय संदर्भ में, अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है -----क्योंकि कानून भारत के लिए बनाए गए हैं सम्पूर्ण देश एवं सभी राज्यों के लिए।

7. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न (i) अधिकार क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुछ मामलों की सुनवाई करने के लिए अदालत की शक्ति को सीमित करता है।

(सत्य/असत्य)

(ii) 1710 में इंग्लैंड में पारित ऐनी की संविधि ने लेखक के अधिकारों को मान्यता नहीं दी।

(सत्य/असत्य)

(iii) बर्न और यूसीसी साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कार्यों को कवर करते हैं। (सत्य/असत्य)

3.7 संदर्भ

1. [https://www.squirepattonboggs.com/~media/files/insights/publications/2012/10/international-aspects-of-copyright/files/international-aspects-of-copyright-practice-note.pdf](https://www.squirepattonboggs.com/~media/files/insights/publications/2012/10/international-aspects-of-copyright/files/international-aspects-of-copyright-practice-note/fileattachment/international-aspects-of-copyright-practice-note.pdf) 2. <https://www.britannica.com/topic/copyright#ref157949> 3.

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html 4. http://www.tauvisual.com/copyrightlaws/convenzione_internazionale_copyright_ginevra

1952.pdf 5.

<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/> 6. <http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/researchjournals/rejour/jipr/Fulltextsearch/2004/November%202004/JIPR-vol%209-November%202004-pp%20557-567.htm>

7. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 8. <https://www.fieldfisher.com/publications/2011/08/uk-supreme-court-rules-on-the-britain-in-foreign-copyright-law>

ब्रिटेन में विदेशी कॉपीराइट की प्रवर्तनीयता

9. <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.in/&httpsredir=1&article=1067&context=annlsurvey>

10. कॉपीराइट: डिजिटल युग में कानून और अधिकार क्षेत्र का चुनाव राकेल जालबार्ड द्वारा; <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.in/&httpsredir=1&article=1067&context=annlsurvey> 11. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957

3.8 सुझाए गए पठन सामग्री

1. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
3. सार्वभौमिक कॉपीराइट कन्वेंशन
4. <https://www.britannica.com/topic/copyright#ref157949>
5. <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/>

3.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. किसी देश की कानूनी प्रणाली में किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र पाए जाते हैं? संक्षेप में लिखें।
2. यह सार्वभौमिकता व्यवसाय के लिए एक उपकरण के रूप में इसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा है और साथ ही साथ यह बनाता भी है अद्वितीय व्यावसायिक जोखिम. टिप्पणी.
3. अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट कानून के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
4. डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि का क्या महत्व है?
5. कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मामलों पर भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों की व्याख्या करें।
6. 'धारा 62(2) लेखक को आसानी और सुविधा प्रदान करती है, जो कॉपीराइट का मूल सार है सुरक्षा.' टिप्पणी.
7. क्या आप मानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 दीर्घकालिक अधिकारिता प्रदान करता है? व्याख्या करना।
8. अधिकार क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का वर्णन करें।
9. क्या विदेशी कॉपीराइट उल्लंघन का मामला अंग्रेजी अदालतों में न्यायोचित है। टिप्पणी करें।
10. आईक्रेव टीवी का मामला , इंटरनेट पर अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट उल्लंघनों में अधिकार क्षेत्र और कानून के विकल्प की जटिल प्रकृति को दर्शाता है। टिप्पणी करें।
11. 'अधिकार क्षेत्र के मुद्दे और कॉपीराइट' पर एक निबंध लिखें।

3.10 उत्तर

SAQS 1.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (i) इंटरनेट की सीमाहीन वास्तुकला; 3.3.1 (xiii) देखें धारा 79; 3.3.4 देखें | (ii) धारा 62 (2); 3.3.3 देखें |
| अधिकारिता; 3.3.1.1 देखें 3. (i) सत्य; 3.3.1 देखें (ii) असत्य; | (ii) एकरूप; 3.3.1.2 देखें (iii) सत्य; |
| 3.3.2 देखें | 3.3.2 देखें |

टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न 1. 3.3.1.1 देखें 2. 3.3.1.3 देखें

3. 3.3.2 देखें
4. 3.3.2 देखें
5. 3.3.3 देखें
6. 3.3.3 देखें
7. 3.3.4 देखें
8. 3.3.5.1 देखें
9. 3.3.5.2.1 देखें
10. 3.3.5.2.2 देखें

इकाई 4

उल्लंघन, उल्लंघन के उपचार

संरचना

4.1 परिचय

4.2 उद्देश्य

4.3 विषय

4.3.1 कॉपीराइट का तर्कसंगत अर्थ

4.3.2 कॉपीराइट का उल्लंघन

4.3.2.1 जब कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ

4.3.2.1.1 कॉपीराइट का स्वामी

4.3.2.1.2 स्वामी को प्रदान किया गया अनन्य अधिकार कॉपीराइट

4.3.2.1.2.1 आर्थिक अधिकार

4.3.2.1.2.2 नैतिक अधिकार

4.3.2.1.3 जनता से संवाद

4.3.2.1.4 कॉपीराइट किए गए कार्य की बिक्री, किराये और व्यापार करके कॉपीराइट का उल्लंघन करना

4.3.2.1.5 ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों के संबंध में विशेष प्रावधान

4.3.2.1.6 भारत में उल्लंघनकारी प्रतियों का आयात

4.3.3 कुछ कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होंगे

4.3.4 उल्लंघन के लिए उपाय

4.3.4.1 नागरिक उपचार

4.3.4.1.1 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

4.3.4.1.2 कॉपीराइट के स्वामी की परिभाषा

4.3.4.1.3 कार्य के लेखक या प्रकाशक की धारणा

4.3.4.1.4 एंटीन पिलर ऑर्डर

4.3.4.1.5 कॉपीराइट के उल्लंघन के विरुद्ध निषेधाज्ञा

4.3.4.1.6 प्रतिपूरक नागरिक उपचार

4.3.4.1.7 पृथक अधिकारों का संरक्षण

4.3.4.1.8 निराधार कानूनी धमकी के मामले में उपाय कार्यवाही

4.3.4.1.9 निम्नलिखित कार्यों के मामले में सिविल उपचार उपलब्ध नहीं हैं: वास्तुकला

4.3.4.2 आपराधिक उपचार

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [72]

- 4.3.4.2.1 कॉपीराइट या अन्य अधिकारों के उल्लंघन का अपराध-
धारा 63
- 4.3.4.2.2 कंप्यूटर प्रोग्राम की उल्लंघनकारी प्रतियों का जानबूझकर उपयोग करना
- 4.3.4.2.3 उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्लेटों का कब्जा
- 4.3.4.2.4 रजिस्टर आदि में गलत प्रविष्टियां करना, गलत प्रविष्टियां प्रस्तुत करना या निविदा देना
- 4.3.4.2.5 किसी अधिकारी या अधिकारी को धोखा देने या प्रभावित करने के उद्देश्य से झूठे बयान देना
- 4.3.4.2.6 धारा 52ए का उल्लंघन
- 4.3.4.2.7 कंपनियों द्वारा अपराध
- 4.3.4.2.8 तकनीकी उपायों का संरक्षण और अधिकार प्रबंधन सूचना का संरक्षण
- 4.3.4.2.9 धारा 63 के तहत उल्लंघनकारी प्रतियां जप्त करने की पुलिस की शक्ति
- 4.3.4.3 प्रशासनिक उपाय
- 4.3.4.4 अपीलीय उपचार
 - 4.3.4.4.1 मजिस्ट्रेट के कुछ आदेशों के खिलाफ अपील - धारा 71
 - 4.3.4.4.2 कॉपीराइट रजिस्ट्रार और अपीलीय बोर्ड के आदेशों के खिलाफ अपील - धारा 72
- 4.3.4.5 कोई व्यक्ति दीवानी और आपराधिक उपचार प्राप्त कर सकता है
एक साथ
- 4.4 सारांश
- 4.5 शब्दावली

4.6 एसएक्यूएस

- 4.7 संदर्भ
- 4.8 सुझाए गए पठन सामग्री
- 4.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न
- 4.10 उत्तर SAQS

4.1 परिचय

पिछली इकाइयों में हमने कॉपीराइट, इसकी विषय-वस्तु और कॉपीराइट की परिभाषा के बारे में पढ़ा।

हमने कॉपीराइट कानून के विकास, इसकी सार्वभौमिकता के बारे में भी पढ़ा। कॉपीराइट संरक्षण विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हाल के वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास और इंटरनेट के आगमन ने कॉपीराइट पर गंभीर हमला किया है।

कॉपीराइट का उल्लंघन एक क्लिक के ज़रिए संभव है। कॉपीराइट सुरक्षा के अंतर्गत केंद्र 'मौलिकता' है। कॉपीराइट सामग्री की नकल, परिवर्तन या प्रतिलिपि बनाना मूल निर्माता की अनुमति के बिना उल्लंघन के अंतर्गत आता है। स्वामी के अधिकारों की रक्षा के लिए कॉपीराइट कानून उल्लंघनकर्ता को विभिन्न उपचार और दंड प्रदान करता है। निवारक के साथ-साथ दंडात्मक उपाय भी हैं।

काम के मालिक को राहत देने के लिए प्रतिपूरक उपाय प्रदान किए गए हैं। दूसरों के कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कारावास और जुर्माना, आपराधिक अपराध के रूप में प्रदान किया जाता है। भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत न्याय प्रदान करने के लिए प्रशासनिक और अपीलीय उपाय भी उपलब्ध हैं।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें समझ सकेंगे:

- वे कार्य जो कॉपीराइट किए गए कार्य को उल्लंघन योग्य बनाते हैं। • उल्लंघन का विषय • कॉपीराइट का स्वामी कौन है और कानून के तहत उसे कौन सा विशेष अधिकार प्रदान किया गया है।
भारतीय कॉपीराइट अधिनियम
- कार्य के स्वामी के आर्थिक और सामाजिक अधिकार • ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों के संबंध में विशेष प्रावधान क्या हैं • वे कार्य जो कॉपीराइट के उल्लंघन के रूप में नहीं गिने जाते हैं • कॉपीराइट के उल्लंघन के खिलाफ प्रदान किए गए सिविल उपचार • कॉपीराइट के उल्लंघन के खिलाफ प्रदान किए गए आपराधिक उपचार • कॉपीराइट के उल्लंघन के खिलाफ प्रदान किए गए प्रशासनिक उपचार • कॉपीराइट अधिनियम के तहत अदालत, कॉपीराइट रजिस्ट्रार और अपीलीय बोर्ड के आदेशों और अंतिम निर्णय के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति को प्रदान किए गए अपीलीय उपचार
- पुलिस और न्यायालय की आकस्मिक शक्ति

4.3 विषय

4.3.1 कॉपीराइट का तर्कसंगत अर्थ

रचनात्मकता और मौलिकता को संरक्षण और पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। रचनात्मकता आविष्कार की कुंजी है जो अंततः प्रगति की कुंजी है। यदि रचनात्मकता की सुरक्षा नहीं होगी, तो कोई भी आविष्कार के लिए समय और पैसा खर्च नहीं करेगा। कॉपीराइट के माध्यम से रचनात्मकता को पुरस्कृत करना और सृजन पर विशेष अधिकार देना अधिक सृजन करने और दूसरों को सृजन करने के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक है।

हम पहले ही उस विषय-वस्तु पर चर्चा कर चुके हैं जिसमें कॉपीराइट मौजूद है। यहाँ हम उन कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा करेंगे जिन्हें वर्तमान संशोधित कानून के तहत कॉपीराइट संरक्षण प्राप्त है:

- साक्षरता कार्य; • नाटकीय कार्य; • संगीत कार्य; • मूर्तिकला, चित्रकला, उत्कीर्णन, वास्तुकला और सभी सहित कलात्मक कार्य
ऐसे कार्य जिनमें कलात्मक शिल्प कौशल शामिल हो;⁹⁶
- सिनेमैटोग्राफ फिल्म; • ध्वनि रिकॉर्डिंग

⁹⁶ 1994 के अधिनियम सं. 38 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (10-5-1995 से)।

⁹⁷ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(सी)

- कंप्यूटर के रूप में साहित्यिक, नाटकीय कार्य या संगीतमय कार्य
प्रोग्राम या कंप्यूटर जनित प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है;
- कार्य का अनुकूलन, अनुवाद और पुनरुत्पादन;
- अप्रकाशित कार्यों का सृजन;98
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यों सहित विदेशी कार्य;
- साहित्यिक कृतियाँ जैसे कविताएँ, लेख, काल्पनिक रचनाएँ, तथ्यात्मक रचनाएँ
जैसे कि विश्वकोश, शब्दकोश आदि;
- परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तैयार;99
- छात्रों द्वारा तैयार शोध प्रबंध और शोध प्रबंध;100
- घरेलू और लेखा तथा घरेलू अंकगणित पर एक पुस्तक का संकलन;101
- स्कूल की पाठ्यपुस्तकें;102
- गाइड पुस्तकें;103
- शब्दकोश;104
- वैज्ञानिक प्रश्नों और उत्तरों की एक पुस्तक;105
- सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्नावली;106
- निर्णय के शीर्ष नोट;107
- व्याख्यान नोट्स सभी साहित्यिक कृतियों की श्रेणी में आते हैं जिनके लिए यह अधिकार है
कॉपीराइट संरक्षण.
- संगीत संबंधी कार्य जैसे गीत, ओपेरा, वाद्य संगीत आदि;
- कला और वास्तुकला के कार्य;
- फोटोग्राफ, तकनीकी चित्र, चलचित्र (सिनेमैटोग्राफ फिल्म),
कंप्यूटर प्रोग्राम आदि;
- कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस में स्थापित नाटक का लाइव प्रदर्शन
डिस्क आदि

ब्लैकवुड बनाम परशुरामन¹⁰⁸, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि: "साहित्यिक कृति का अनुवाद स्वयं एक साहित्यिक कृति है और कॉपीराइट संरक्षण का हकदार है, मूल कॉपीराइट के स्वामी की सहमति या लाइसेंस के बिना अनुवाद के प्रकाशन की प्रतिलिपि बनाना गलत होगा।"

उल्लंघन के बराबर है।

- ⁴¹ किसी शौकिया क्लब या समाज द्वारा किया गया प्रदर्शन, यदि प्रदर्शन भुगतान न करने वाले दर्शकों के लिए दिया जाता है, और

⁹⁸ जब कोई विचार या अभिव्यक्ति भौतिक रूप ले लेती है, तो वह कॉपीराइट के अंतर्गत आती है, चाहे वह प्रकाशित हो या नहीं।

⁹⁹ जगदीश प्रसाद बनाम परमेश्वर प्रसाद, एआईआर 1966 पैट 33।

¹⁰⁰ फतेह सिंह मेहता बनाम सिंघल, एआईआर 1990 राज 8(14)।

¹⁰¹ मनोहर लाल गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य(1 977) 79 पुंज एलआर 181 (डेल)

¹⁰² शेख गफूर बख्श एंड संस बनाम ज्वाला प्रसाद सिंघल, एआईआर 1921 सभी 95

¹⁰³ ई.एम. फोस्टर बनाम ए.एम. परशुराम, ए.आई.आर. 1964 एम.ए.डी. 331.

¹⁰⁴ गिविंदन बनाम गोपालकृष्णन, एआईआर 1955 एमएडी 319

¹⁰⁵ जोरल बनाम रॉल्स्टन (1857) 3 के एंड जे 708

¹⁰⁶ इंटरफर्म कंपैरिजन (ऑस्ट्रेलिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम लॉ सोसाइटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, (1977) आरपीसी 149

¹⁰⁷ एनटी रघुनाथन बनाम ऑल इंडिया रिपोर्टर, एआईआर 1971 जन्म. 48

¹⁰⁸ एआईआर 1959 एमएडी 410

- ii. कुछ विशेष प्रावधानों के तहत साहित्यिक, नाटकीय या संगीत कार्यों की ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाना स्थितियाँ।

4.3.2 कॉपीराइट का उल्लंघन

4.3.2.1 जब कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 में 'उल्लंघन' के बारे में बताया गया है। यह इस प्रकार है-

“किसी कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा—

(क) जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कॉपीराइट के स्वामी या कॉपीराइट रजिस्ट्रार द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या इस प्रकार दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के या इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई गई किसी शर्त के उल्लंघन में-

(i) कोई ऐसा कार्य करता है, जिसे करने का अनन्य अधिकार इस अधिनियम द्वारा कॉपीराइट के स्वामी को प्रदान किया गया है, या

(ii) किसी कार्य को जनता तक संप्रेषित करने के लिए किसी स्थान का उपयोग लाभ के लिए करने की अनुमति देता है, जहां ऐसा संप्रेषण कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, जब तक कि उसे इसकी जानकारी न हो और यह मानने का कोई उचित आधार न हो कि जनता तक ऐसा संप्रेषण कॉपीराइट का उल्लंघन होगा; या

(ख) जब कोई व्यक्ति-

(i) बिक्री या किराये के लिए बनाता है, या बेचता या किराये पर देता है, या व्यापारिक प्रदर्शन के माध्यम से या बिक्री या किराये के लिए प्रस्ताव देता है, या

(ii) या तो व्यापार के उद्देश्य से या इस सीमा तक वितरित करता है जिससे कॉपीराइट के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या

(iii) सार्वजनिक रूप से व्यापारिक प्रदर्शन के माध्यम से, या

(iv) भारत में कार्य की किसी भी उल्लंघनकारी प्रति का आयात:

बशर्ते कि उप-खण्ड (iv) की कोई बात आयातक के निजी और घरेलू उपयोग के लिए किसी कार्य की एक प्रति के आयात पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कृति का सिनेमैटोग्राफ फिल्म के रूप में पुनरुत्पादन “उल्लंघनकारी प्रतिलिपि” माना जाएगा।

इस प्रकार कॉपीराइट का उल्लंघन उन परिस्थितियों में होता है जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट स्वामी या कॉपीराइट रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना कोई कार्य करता है, जो सीधे हस्तक्षेप करते हैं

या परोक्ष रूप से कॉपीराइट स्वामी के अनन्य अधिकारों का हनन करता है। साथ ही कोई भी ऐसा कार्य जो किसी भी इस अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर कॉपीराइट स्वामी को दी गई शर्तों और नियम, अपराध बनाते हैं उल्लंघन। किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य से कोई लाभ कमाना, जिसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है उस कार्य पर कोई भी टिप्पणी करना उल्लंघन का कार्य है। भारत में उल्लंघनकारी प्रतियों का आयात करना यह कॉपीराइट का उल्लंघन भी है।

किसी भी कॉपीराइट साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक सामग्री से कोई भी वीडियो और ऑडियो बनाना स्वामी की अनुमति के बिना सामग्री का उपयोग कॉपीराइट के उल्लंघन के अंतर्गत आता है।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि, चुनाव के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं कॉपीराइट के विरुद्ध अपराध। पहली शर्त यह है कि, यदि किसी कार्य में इनमें से किसी के साथ समानता है पहले से मौजूद काम का उल्लंघन माना जाएगा। यहाँ यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है पहले से मौजूद कार्य सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, यह कॉपीराइट के तहत होना चाहिए भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। दूसरी शर्त यह है कि, उल्लंघन किया गया कार्य सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कॉपीराइट कार्य से प्राप्त।

4.3.2.1.1 कॉपीराइट का स्वामी

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51(ए) कहती है, "जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट के स्वामी या इस अधिनियम के तहत कॉपीराइट रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना..." यहाँ सवाल उठता है कि कॉपीराइट का स्वामी कौन है? आम तौर पर, किसी भी काम में लेखक कॉपीराइट का पहला स्वामी होता है¹¹⁰। धारा 2(डी) के अनुसार "लेखक का मतलब है"

(i) साहित्यिक या नाटकीय कार्य के संबंध में, कार्य का लेखक; (ii) संगीतमय कार्य के संबंध में, संगीतकार; (iii) फोटोग्राफ के अलावा किसी कलात्मक कार्य के संबंध में, कलाकार; (iv) फोटोग्राफ के संबंध में, फोटोग्राफ लेने वाला व्यक्ति; (v) सिनेमैटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग के संबंध में, निर्माता; और (vi) किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य के संबंध में जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया है, वह व्यक्ति जो कार्य का निर्माण कराता है;

(vii) सार्वजनिक रूप से दिए गए किसी संबोधन या भाषण के मामले में, वह व्यक्ति जिसने ऐसा संबोधन या भाषण दिया है या यदि ऐसे व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसा संबोधन या भाषण दिया है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति कॉपीराइट का प्रथम स्वामी होगा;

(viii) सरकारी कार्य के मामले में, सरकार किसी समझौते के अभाव में इसके विपरीत, कॉपीराइट का प्रथम स्वामी बनें;

(ix) किसी सार्वजनिक उपक्रम द्वारा या उसके निर्देशन या नियंत्रण के अधीन निर्मित या प्रथम बार प्रकाशित किसी कार्य की स्थिति में, ऐसा सार्वजनिक उपक्रम, किसी प्रतिकूल समझौते के अभाव में, कॉपीराइट का प्रथम स्वामी होगा;

संगीतमय ध्वनि रिकॉर्डिंग में कई अधिकार धारक होते हैं। प्रत्येक अधिकार धारक को लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, अर्थात् गीतकार, जो गीत के बोल देता है; संगीतकार; गायक, जो गीत गाता है; संगीतकार, जो पृष्ठभूमि संगीत देता है और कंपनी या व्यक्ति जिसने ध्वनि रिकॉर्डिंग का निर्माण किया है।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 30 कॉपीराइट के स्वामी को लिखित रूप में लाइसेंस द्वारा अधिकार में रुचि प्रदान करने का अधिकार देती है। अनुबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि किन अधिकारों को लाइसेंस दिया गया है और कितनी अवधि के लिए।

¹⁰⁹ सुमंगलम आर. जयलक्ष्मी बनाम मेटा म्यूजिकल्स, 2001 (1) RAJ 150; बौद्धिक संपदा अधिकार और कानून डॉ. जीबी रेड्डी; गोपिया लॉ एंजेंसी, पृ.144

¹¹⁰ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 17;

¹¹¹ संगीत रचना के संबंध में "संगीतकार" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संगीत की रचना करता है, चाहे वह कोई भी हो वह इसे किसी भी प्रकार के ग्राफिकल नोटेशन में रिकॉर्ड करता है; भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(ff)a);

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [77]

"इस अधिनियम के तहत कॉपीराइट रजिस्ट्रार" का अर्थ है इस अधिनियम के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार द्वारा कॉपीराइट रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त व्यक्ति या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कॉपीराइट का उप रजिस्ट्रार, जो कॉपीराइट रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के तहत रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है।

4.3.2.1.2 स्वामी को प्रदान किया गया अनन्य अधिकार

कॉपीराइट का

जैसा कि धारा 51 (ए) (आई) में कहा गया है, "इस अधिनियम द्वारा कॉपीराइट के स्वामी को ऐसा करने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है"। हम लेखक/स्वामी के अधिकारों पर निम्नलिखित चर्चा करते हैं:

4.3.2.1.2.1 आर्थिक अधिकार

साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कृति के मामले में (कम्प्यूटर प्रोग्राम को छोड़कर) स्वामी को निम्नलिखित आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं-

- (i) किसी भी भौतिक रूप में कार्य को पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में भंडारण शामिल है मध्यम;
- (ii) प्रतियां जारी करने का अधिकार, (पहले से प्रचलन में मौजूद प्रतियों को छोड़कर);
- (iii) जनता को प्रदर्शन या संचार करने का अधिकार;
- (iv) कोई भी सिनेमैटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाने का अधिकार;
- (v) अनुवाद या अनुकूलन का अधिकार या कार्य के अनुवाद या अनुकूलन के संबंध में ऊपर निर्दिष्ट कार्य करने का अधिकार [(i) से (vi)];

कलात्मक कार्य के मामले में स्वामी को पूर्वोक्त अधिकार के अतिरिक्त, द्वि-आयामी कार्य का त्रि-आयाम में चित्रण या त्रि-आयामी कार्य का द्वि-आयाम में चित्रण करने का अधिकार प्राप्त है।¹¹⁴

कम्प्यूटर प्रोग्राम के मामले में स्वामी को ऊपर वर्णित अधिकार प्राप्त है [(i) से (v)] तथा कम्प्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति को बेचने या व्यावसायिक किराये पर देने या बिक्री या व्यावसायिक किराये के लिए प्रस्ताव देने का अधिकार भी प्राप्त है: बशर्ते कि ऐसा व्यावसायिक किराया कम्प्यूटर प्रोग्राम के संबंध में लागू नहीं होगा, जहां प्रोग्राम स्वयं किराये का आवश्यक उद्देश्य नहीं है।¹¹⁵

¹¹² भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 10;

¹¹³ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 10 (2) के अनुसार, "कॉपीराइट का उप रजिस्ट्रार, कॉपीराइट रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन में इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा, जिन्हें रजिस्ट्रार समय-समय पर उसे सौंपे; और इस अधिनियम में कॉपीराइट रजिस्ट्रार के किसी संदर्भ में, ऐसे किसी कार्य का निर्वहन करते समय कॉपीराइट के उप रजिस्ट्रार के प्रति संदर्भ शामिल होगा।"

¹¹⁴ 2012 के अधिनियम सं. 27 की धारा 5(i) द्वारा प्रतिस्थापित, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14(c) के उपखंड (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित;

¹¹⁵ 1999 के अधिनियम सं. 49 की धारा 3 द्वारा (15-1-2000 से) भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14(ख) के उपखंड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [78]

सिनेमैटोग्राफ फिल्म के मामले में स्वामी को फिल्म की प्रतिलिपि बनाने का अधिकार है, जिसमें उसका भाग बनने वाली किसी छवि का फोटोग्राफ भी शामिल है, उसे इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से किसी भी माध्यम में संग्रहीत करने का अधिकार है, फिल्म की किसी भी प्रतिलिपि को बेचने या व्यावसायिक किराये पर देने या बिक्री या ऐसे किराये के लिए प्रस्ताव देने का अधिकार है और फिल्म को जनता को संप्रेषित करने का अधिकार है।¹¹⁶ ध्वनि रिकॉर्डिंग के मामले में स्वामी को सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं।¹¹⁷

किसी पेंटिंग, मूर्तिकला या रेखाचित्र की मूल प्रति, या किसी साहित्यिक या नाटकीय कृति या संगीत कृति की मूल पांडुलिपि के दस हजार रुपए (कृति में कॉपीराइट की अवधि समाप्त होने से पूर्व) से अधिक मूल्य पर पुनर्विक्रय की स्थिति में, ऐसी कृति का लेखक, यदि वह ऐसी कृति में कॉपीराइट के किसी समनुदेशन के बावजूद अधिकारों का प्रथम स्वामी था, तो उसे ऐसी मूल प्रति या पांडुलिपि के पुनर्विक्रय मूल्य में हिस्सा पाने का अधिकार होगा।¹¹⁸

इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक के पास एक ही कार्य में अनेक अधिकार होते हैं। अपने हित में लेखक (मौजूदा कार्य का या भविष्य के कार्य में कॉपीराइट का संभावित स्वामी) असाइनमेंट¹¹⁹ या लाइसेंस¹²⁰ के माध्यम से अपने अधिकार भी हस्तांतरित कर सकता है।

4.3.2.1.2.2 नैतिक अधिकार

भारतीय कॉपीराइट कानून किसी रचना के लेखक को कुछ विशेष अधिकार देता है। उक्त अधिनियम की धारा 57 इस प्रकार है:

“(1) लेखक के कॉपीराइट से स्वतंत्र रूप से और उक्त कॉपीराइट के पूर्णतः या आंशिक रूप से हस्तांतरण के बाद भी, किसी कार्य के लेखक को अधिकार होगा- (क) कार्य के लेखकत्व का दावा करने का; और (ख) उक्त कार्य के संबंध में किसी विकृति, विकृति, परिवर्तन या अन्य कार्य के संबंध में क्षति का दावा करने या रोकने का यदि ऐसी विकृति, विकृति, परिवर्तन या अन्य कार्य उसके सम्मान या ख्याति के लिए हानिकारक हो: परंतु लेखक को किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के किसी अनुकूलन के संबंध में क्षति का दावा करने या रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा, जिस पर धारा 52 की उपधारा (1) का खंड (एए) लागू होता है।¹²¹ स्पष्टीकरण।—

किसी कार्य को प्रदर्शित करने में विफलता या लेखक की संतुष्टि के अनुसार उसे प्रदर्शित न करना इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।¹²²

(2) उपधारा (1) द्वारा किसी कृति के लेखक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग लेखक के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकेगा।”

इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 30 के विशेष प्रावधान लेखक की सत्यनिष्ठा के अधिकार के साथ-साथ पितृत्व के अधिकार को भी बरकरार रखते हैं और इस प्रकार लेखक की मृत्यु के बाद भी उसके सम्मान की रक्षा करते हैं।

¹¹⁶ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14(डी);

¹¹⁷ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14(ई);

¹¹⁸ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51ए;

¹¹⁹ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 18;

¹²⁰ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 30;

¹²¹ उक्त खंड के अनुसार, किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम की प्रतिलिपि के वैध स्वामी द्वारा उसकी प्रतिलिपि बनाना या उसका अनुकूलन करना भारतीय कॉपीराइट कानून की धारा 57 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएगा।

¹²² 1994 के अधिनियम सं. 38 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।

यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि किसी कार्य को प्रदर्शित करने में विफलता या लेखक की संतुष्टि के लिए इसे प्रदर्शित न करना इस खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

श्रीमती मनु भंडारी बनाम कला विकास पिक्चर्स लिमिटेड¹²³ के मामले में कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 57 के संबंध में यह देखा गया: "धारा 57 लेखक के नैतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान है। इसका उद्देश्य कॉपीराइट को अधिकारों के सामान्य मामलों की तुलना में उच्चतर स्तर पर रखना है, धारा 57 की भाषा सबसे व्यापक आयाम की है। इसे केवल साहित्यिक अभिव्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। दृश्य-श्रव्य अभिव्यक्तियों भी सीधे इसके अंतर्गत आती हैं"।

4.3.2.1.3 जनता से संवाद

भारतीय कॉपीराइट कानून की धारा 51 के खंड (ए) (ii) के अनुसार: "किसी कार्य को जनता तक संप्रेषित करने के लिए किसी स्थान का उपयोग लाभ के लिए करने की अनुमति देता है, जहां ऐसा संप्रेषण कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, जब तक कि उसे इसकी जानकारी न हो और यह मानने का कोई उचित आधार न हो कि जनता के लिए ऐसा संप्रेषण कॉपीराइट का उल्लंघन होगा;"

जनता को संप्रेषण का अर्थ है: "किसी भी कार्य या प्रदर्शन को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखने, सुनने या अन्यथा आनंद लेने के लिए उपलब्ध कराना या उसकी भौतिक प्रतियां जारी करने के अलावा प्रदर्शन या प्रसार के किसी अन्य माध्यम से, चाहे एक साथ या व्यक्तिगत रूप से चुने गए स्थानों और समय पर, इस बात की परवाह किए बिना कि जनता का कोई सदस्य वास्तव में इस प्रकार उपलब्ध कराए गए कार्य या प्रदर्शन को देखता है, सुनता है या अन्यथा आनंद लेता है। स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपग्रह या केबल या किसी अन्य माध्यम से एक साथ संचार के माध्यम से किसी भी होटल या छात्रावास के आवासीय कमरों सहित एक से अधिक घरों या निवास स्थानों को संचार करना जनता को संचार माना जाएगा;"

इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कृति के लेखक या स्वामी की पूर्व अनुमति के बिना निम्नलिखित में से किसी भी कार्य के माध्यम से लाभ अर्जित करता है, तो उसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा:

- उस कार्य पर आधारित नाटक या नाटक दिखाएं;
- रेडियो या टेलीविज़न पर उस कार्य से संबंधित कहानियाँ बताना;
- इंटरनेट या किसी भी सोशल मीडिया (जो लाभ कमाने वाला प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब) पर जनता के लिए काम उपलब्ध कराया;
- उस कार्य पर आधारित फिल्म बनाना;
- कॉपीराइट किए गए कार्य के ऐसे नाटक, नाटक, फिल्म, गीत, चित्र, ध्वनि रिकॉर्डिंग को उपग्रह, केबल, इंटरनेट, रेडियो या इसी तरह के साधनों या एक निजी स्थान के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रसारित करना;
- किसी भी तस्वीर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता को दिखाना;
- उस कार्य की प्रतियां पुस्तक, डिस्क या किसी अन्य माध्यम से जनता को जारी करना
अन्य प्रौद्योगिकी'

¹²³ एआईआर 1987 डेल 13(17);

¹²⁴ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (एफएफ);

- धार्मिक या आधिकारिक समारोह के दौरान कार्य का निष्पादन;
- कोई अन्य कार्य जिसके माध्यम से कार्य एक व्यक्ति या हजारों लोगों को उपलब्ध कराया जाता है व्यक्ति

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त में से कोई भी कार्य करता है और संयोग से कोई भी व्यक्ति उस कार्य या प्रदर्शन को नहीं देखता, सुनता या अन्यथा उसका आनंद नहीं लेता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति निर्दोष है। इस तथ्य के बावजूद, यह जनता को कार्य का संचार करता है और उसका कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन है, जब तक कि उसे पता न हो और उसके पास यह मानने का कोई उचित आधार न हो कि जनता को ऐसा संचार कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। उदाहरण के लिए, एक केबल ऑपरेटर एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म प्रसारित कर सकता है जिसे कोई भी आम आदमी नहीं देख सकता। फिर भी यह

जनता के लिए एक संचार.

4.3.2.1.4 कॉपीराइट किए गए कार्य की बिक्री, किराये और व्यापार करके कॉपीराइट का उल्लंघन करना

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 का खंड (बी) इस प्रकार है:

जब कोई भी व्यक्ति—

- (i) बिक्री या किराये के लिए बनाता है, या बेचता या किराये पर देता है, या व्यापारिक प्रदर्शन के माध्यम से या बिक्री या किराये के लिए प्रस्ताव देता है, या
- (ii) या तो व्यापार के उद्देश्य से या इस सीमा तक वितरित करता है जिससे कॉपीराइट के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या
- (iii) सार्वजनिक रूप से व्यापार प्रदर्शन के माध्यम से;

उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि, कॉपीराइट कार्य का प्रकाशन, पुनरुत्पादन ऐसे कार्य का भौतिक रूप में रूपांतरण या अनुवाद उल्लंघन माना जाएगा कॉपीराइट का.

साहित्यिक कृतियों, पुस्तकों और अन्य मुद्रित सामग्रियों के अवैध पुनरुत्पादन के मामले में लाभ के लिए इन सामग्रियों का वितरण/बिक्री करना पाइरेसी कहलाता है और कॉपीराइट का उल्लंघन है। उल्लंघन आम तौर पर विदेशी और अच्छी स्वदेशी पुस्तकों में पाया जाता है, आम तौर पर चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य पेशेवर पुस्तकों, विश्वकोश और लोकप्रिय कथाओं के क्षेत्र में और पाइरेट्स द्वारा पहचाने गए सामान्य खुदरा विक्रेताओं द्वारा पुस्तकों के अन्य गैर-पायरेट किए गए संस्करण के साथ बेचा जाता है। इस प्रकार की पाइरेसी मौसमी प्रकृति की होती है और बिक्री के साथ छपाई की पूरी प्रक्रिया आम तौर पर एक या दो महीने के भीतर खत्म हो जाती है। कभी-कभी कुछ प्रसिद्ध प्रकाशक भी अनुबंध अवधि से परे किताबें बेचकर खुद को पाइरेसी में शामिल कर लेते हैं। ये

प्रकाशक कुछ विदेशी प्रकाशकों से पुनर्मुद्रण अधिकार खरीदता है और किताबें बेचता रहता है

पुराने स्टॉक को क्लियर करने के नाम पर अनुबंध में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद भी कोई वसूली नहीं की गई।

कई विदेशी प्रकाशक समीक्षा के लिए किताबें भेजते हैं। पायरेट्स को ऐसी किताबों तक पहुँच मिल जाती है और वे बाज़ार में बेचने के लिए जल्दी से जल्दी प्रिंट बना लेते हैं। किताबों की बड़े पैमाने पर फोटोकॉपी के रूप में पायरेसी भारत में काफ़ी प्रचलित है, छात्र पुस्तकालयों से किताबें उधार लेते हैं और फिर उस संस्थान में रखी फोटोकॉपियर से उनकी फोटोकॉपी करवाते हैं जहाँ से किताबें उधार ली जाती हैं। कॉपीराइट के दौरान

कानून सीमित निजी उपयोग जैसे शोध, समीक्षा या आलोचना के लिए साहित्यिक कृतियों की फोटोकॉपी की अनुमति देता है, लेकिन अधिकांश मामलों में कवर पेज सहित पूरी किताब की फोटोकॉपी की जाती है। इस प्रक्रिया में छात्र समुदाय और फोटोकॉपी संचालकों को लाभ होता है, लेकिन प्रकाशकों को भारी नुकसान होता है आय।

ध्वनि रिकॉर्डिंग के मामले में कलाकारों, संगीतकार या रिकॉर्डिंग कंपनी की जानकारी के बिना अलग-अलग वैध कैसेट/सीडी से गाने कॉपी किए जाते हैं। फिर इन्हें अलग दिखने के लिए पैक किया जाता है और बाजार में बेचा जाता है। मूल प्रतियों की नकल हो सकती है। इस प्रकार खरीदारों को गुमराह किया जाता है। संगीत चोरी का तीसरा रूप बूटलेगिंग है, जहां कलाकारों के प्रदर्शन की अनधिकृत रिकॉर्डिंग की जाती है और बाद में पुनरुत्पादित करके बाजार में बेचा जाता है। मई 2006 में बिजनेस सॉफ्टवेयर अलायंस (बीएसए) और नैसकॉम द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत मूल्य के मामले में दुनिया का छठा सबसे बड़ा पायरेट बाजार है, लेकिन मात्रा के मामले में तीसरा है।

सिनेमैटोग्राफिक कार्यों के कॉपीराइट का उल्लंघन दो मुख्य रूपों में होता है, 'वीडियो पाइरेसी' और 'केबल पाइरेसी'। आज इंटरनेट फिल्म पाइरेसी का मुख्य मंच बन गया है। सिनेमैटोग्राफिक फिल्म रिलीज होने के 24 से 36 घंटे के भीतर उसका पाइरेटेड वर्जन इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाता है।

4.3.2.1.5 ध्वनि के संबंध में विशेष प्रावधान

रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों

1984 के संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में एक नया खंड, धारा 52 ए जोड़ा गया।¹²⁵

52ए. [ध्वनि रिकॉर्डिंग]¹²⁶ और वीडियो फिल्मों में शामिल की जाने वाली विशिष्टियां।—

(1) कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के संबंध में [ध्वनि रिकॉर्डिंग]¹²⁷ तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि [ध्वनि रिकॉर्डिंग]¹²⁸ और उसके किसी कंटेनर पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित न हों, अर्थात्:—

(क) ध्वनि रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति का नाम और पता;

(ख) ऐसे कार्य के कॉपीराइट के स्वामी का नाम और पता; और

(ग) इसके प्रथम प्रकाशन का वर्ष।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के संबंध में वीडियो फिल्म तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि प्रदर्शित होने पर वीडियो फिल्म में और वीडियो कैसेट या उसके अन्य कंटेनर पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित न किए जाएं, अर्थात्:-

¹²⁵ 1984 के अधिनियम सं. 65 की धारा 4 द्वारा (8-10-1984 से) अंतःस्थापित।

¹²⁶ 1994 के अधिनियम सं. 38 की धारा 2 द्वारा (10-5-1995 से) "अभिलेख" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹²⁷ पूर्वोक्त

¹²⁸ वही

(क) यदि ऐसा कार्य चलचित्र फिल्म है जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के उपबंधों के अधीन प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है, तो ऐसे कार्य के संबंध में उस अधिनियम की धारा 5क के अधीन फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र की एक प्रति;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसने वीडियो फिल्म बनाई है तथा उसके द्वारा यह घोषणा कि उसने ऐसी वीडियो फिल्म बनाने के लिए ऐसे कार्य के कॉपीराइट के स्वामी से आवश्यक लाइसेंस या सहमति प्राप्त कर ली है; तथा

(ग) ऐसे कार्य के कॉपीराइट के स्वामी का नाम और पता।

ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों अपनी प्रकृति के कारण चोरी के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं।

उन्हें संरक्षण देने के लिए कॉपीराइट अधिनियम में अलग से धारा 52 ए जोड़ी गई है।

किसी भी ऑडियो कैसेट पर प्रदर्शित होने पर, किसी भी ध्वनि रिकॉर्डिंग के साथ निम्नलिखित विवरण देना या कोई अन्य कंटेनर:

- ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माता का नाम और पता;
- उस कार्य (ध्वनि रिकॉर्डिंग) के स्वामी का नाम और पता;
- वह वर्ष जिसमें वह कार्य पहली बार प्रकाशित हुआ।

इसी प्रकार, किसी भी वीडियो फिल्म पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जब किसी भी स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है वीडियो कैसेट या कोई अन्य कंटेनर:

- सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के मामले में, फिल्म बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रमाणीकरण;
- वीडियो फिल्म के निर्माता का नाम और पता तथा लाइसेंस और सहमति का ब्यौरा;
- ऐसे कार्य के स्वामी का नाम और पता।

उपरोक्त प्रावधान इस कंप्यूटर युग में पायरेसी की रोकथाम में सहायक हैं।

4.3.2.1.6 भारत में उल्लंघनकारी प्रतियों का आयात

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 (2) के खंड (iv) में कहा गया है, “किसी कार्य की उल्लंघनकारी प्रतियों का भारत में आयात कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा।” (बशर्ते कि उप-खंड (iv) में कुछ भी आयातक के निजी और घरेलू उपयोग के लिए किसी भी कार्य की एक प्रति के आयात पर लागू नहीं होगा।)¹²⁹

उक्त अधिनियम की धारा 51 में आगे स्पष्ट किया गया है कि, किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य का सिनेमैटोग्राफ फिल्म के रूप में पुनरुत्पादन “उल्लंघनकारी प्रतिलिपि” माना जाएगा।¹³⁰

धारा 2 (एम)¹³¹ के अनुसार 'उल्लंघनकारी प्रतिलिपि' की व्याख्या इस प्रकार है-

“उल्लंघनकारी प्रतिलिपि” का अर्थ है—

- (a) साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य के संबंध में, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के रूप के अलावा उसका पुनरुत्पादन; सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के संबंध में, किसी भी माध्यम पर बनाई गई फिल्म की
- (ii) प्रतिलिपि
किसी भी तरह से;

¹²⁹ 1994 के अधिनियम सं. 38 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित (10-5-1995 से)

¹³⁰ स्पष्टीकरण - भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51;

¹³¹ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957;

- (iii) ध्वनि रिकॉर्डिंग के संबंध में, किसी भी माध्यम से बनाई गई वही ध्वनि रिकॉर्डिंग सम्मिलित करने वाली कोई अन्य रिकॉर्डिंग; किसी कार्यक्रम या प्रदर्शन के संबंध में जिसमें इस
- (चतुर्थ) अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसा प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार या कलाकार का अधिकार विद्यमान है, ऐसे कार्यक्रम या प्रदर्शन की ध्वनि रिकॉर्डिंग या चलचित्र फिल्म, यदि ऐसी पुनरुत्पादन, प्रतिलिपि या ध्वनि रिकॉर्डिंग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बनाई गई है या आयात की गई है;

इस प्रकार, कॉपीराइट का उल्लंघन कॉपीराइट के स्वामी के स्वामित्व वाले और उसके कब्जे वाले निजी डोमेन पर अतिक्रमण है और किसी भी कार्य में कॉपीराइट के स्वामी को कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य के उल्लंघन का अर्थ है।¹³²

4.3.3 कुछ कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होंगे

सिक्के का दूसरा पहलू भी है। निर्माता के अधिकार और हित के बीच संतुलन स्थापित करना समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कॉपीराइट कानून में कुछ अपवाद हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 में इस संबंध में प्रावधान दिए गए हैं:

(1) निम्नलिखित कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे, अर्थात्,—

(क) निजी या व्यक्तिगत उपयोग के प्रयोजनों के लिए किसी भी कार्य (कम्प्यूटर प्रोग्राम को छोड़कर) के साथ निष्पक्ष व्यवहार, जिसमें अनुसंधान, आलोचना या समीक्षा और वर्तमान घटनाओं और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग शामिल है, जिसमें सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान की रिपोर्टिंग भी शामिल है।

स्पष्टीकरण.- इस खंड में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी कार्य का भंडारण, जिसके अंतर्गत किसी ऐसे कम्प्यूटर प्रोग्राम का आनुषंगिक भंडारण भी है, जो स्वयं उक्त प्रयोजनों के लिए उल्लंघनकारी प्रतिलिपि नहीं है, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

(कक) किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम की प्रति के वैध स्वामी द्वारा उस कम्प्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाना या उसे उस प्रति से रूपांतरित करना, ताकि कम्प्यूटर प्रोग्राम का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जा सके जिसके लिए उसे आपूर्ति किया गया था; या हानि, विनाश या क्षति के विरुद्ध केवल अस्थायी संरक्षण के रूप में बैक-अप प्रतियां बनाना;

(कख) किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम के विधिपूर्ण स्वामी द्वारा किसी स्वतंत्र रूप से निर्मित कम्प्यूटर प्रोग्राम की अन्य प्रोग्रामों के साथ अंतर-प्रचालनीयता के संचालन के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई कार्य करना, बशर्ते कि ऐसी सूचना अन्यथा आसानी से उपलब्ध न हो;

(कसी) कम्प्यूटर प्रोग्राम के कामकाज का अवलोकन, अध्ययन या परीक्षण, ताकि उन विचारों और सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जो प्रोग्राम के किसी भी तत्व को रेखांकित करते हैं, जबकि उन कार्यों के लिए आवश्यक कार्य निष्पादित किए जाते हैं जिनके लिए कम्प्यूटर प्रोग्राम की आपूर्ति की गई थी;

¹³² न्यायमूर्ति एस. मुर्तजा फजल अली ने आर . जी. आनंद बनाम डीलक्स फिल्म, एआईआर 1978 एससी 1613 के मामले में फैसला सुनाया।

(कद) गैर-वाणिज्यिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से प्राप्त प्रतिलिपि से कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतिलिपि बनाना या उसका अनुकूलन करना;

(ख) जनता के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचरण या संचार की विशुद्ध रूप से तकनीकी प्रक्रिया में किसी कार्य या प्रदर्शन का क्षणिक या आकस्मिक भंडारण;

(सी) इलेक्ट्रॉनिक लिंक, पहुंच या एकीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से किसी कार्य या प्रदर्शन का क्षणिक या आकस्मिक भंडारण, जहां ऐसे लिंक, पहुंच या एकीकरण को अधिकार धारक द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जब तक कि जिम्मेदार व्यक्ति को पता न हो या उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार न हो कि ऐसा भंडारण उल्लंघनकारी प्रतिलिपि का है: बशर्ते कि यदि ऐसे व्यक्ति को कार्य में कॉपीराइट के स्वामी से लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें शिकायत की गई है कि ऐसा क्षणिक या आकस्मिक भंडारण उल्लंघन है, तो भंडारण के लिए जिम्मेदार ऐसा व्यक्ति इक्कीस दिनों की अवधि के लिए या जब तक वह पहुंच को सुगम बनाने से रोकने के लिए सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ऐसी पहुंच को सुगम बनाने से परहेज करेगा और यदि इक्कीस दिनों की ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं होता है, तो वह ऐसी पहुंच की सुविधा प्रदान करना जारी रख सकता है;

(घ) न्यायिक कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किसी कार्य का पुनरुत्पादन;

(ई) किसी विधानमंडल के सचिवालय द्वारा उस विधानमंडल के सदस्यों के उपयोग के लिए अनन्य रूप से तैयार किए गए किसी कार्य का पुनरुत्पादन या प्रकाशन;

(च) किसी कार्य की प्रमाणित प्रतिलिपि का पुनरुत्पादन, जो कि वर्तमान में लागू किसी कानून के अनुसार बनाई या आपूर्ति की गई हो;

(छ) किसी प्रकाशित साक्षरता या नाट्य कृति से युक्तिसंगत अंशों का सार्वजनिक रूप से वाचन या पुनर्पाठ;

(ज) किसी संग्रह में प्रकाशन, जो मुख्यतः गैर-कॉपीराइट सामग्री से बना हो, जो वास्तविक रूप से शिक्षण उपयोग के लिए अभिप्रेत हो, और जिसका शीर्षक में तथा प्रकाशक द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए किसी विज्ञापन में ऐसा वर्णन हो, प्रकाशित साहित्यिक या नाटकीय कृतियों से लघु अंश, जो स्वयं ऐसे उपयोग के लिए प्रकाशित न हों जिसमें कॉपीराइट विद्यमान हो: बशर्ते कि एक ही लेखक की कृतियों से ऐसे दो से अधिक अंश एक ही प्रकाशक द्वारा पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान प्रकाशित न किए जाएं।

स्पष्टीकरण.- संयुक्त लेखकत्व की किसी रचना की दशा में, इस खंड में रचनाओं के अंशों के संदर्भों में उन अंशों के किसी एक या अधिक लेखकों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से उन लेखकों में से किसी एक या अधिक द्वारा रचनाओं के अंशों के संदर्भ शामिल होंगे;

(i) शिक्षण के दौरान या किसी परीक्षा में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न के भाग के रूप में या ऐसे प्रश्नों के उत्तर में किसी शिक्षक या विद्यार्थी द्वारा किसी कार्य की पुनरुत्पादन;

(जे) किसी शैक्षणिक संस्थान की गतिविधियों के दौरान, संस्थान के कर्मचारियों और छात्रों द्वारा किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कार्य का प्रदर्शन, या किसी चलचित्र का प्रदर्शन

फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग। हालाँकि दर्शक केवल स्टाफ़ और छात्र, माता-पिता और अभिभावक आदि तक ही सीमित हैं।

(ट) किसी आवासीय परिसर (जो होटल या इसी प्रकार का वाणिज्यिक प्रतिष्ठान न हो) में निवासियों के सामान्य उपयोग के लिए बने बंद कमरे या हॉल में या किसी क्लब या इसी प्रकार के संगठन की गतिविधियों के भाग के रूप में, जो लाभ के लिए स्थापित या संचालित न हो, रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक रूप से सुना जाना;

(ठ) किसी शौकिया क्लब या सोसायटी द्वारा साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कार्य का प्रदर्शन, यदि प्रदर्शन भुगतान न करने वाले दर्शकों के लिए या किसी धार्मिक संस्था के लाभ के लिए दिया जाता है;

(ड) किसी समाचार पत्र, पत्रिका या अन्य आवधिक पत्रिका में समसामयिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक विषयों पर किसी लेख का पुनरुत्पादन, जब तक कि ऐसे लेख के लेखक ने ऐसे पुनरुत्पादन का अधिकार स्पष्ट रूप से अपने लिए सुरक्षित न रखा हो;

(ढ) किसी गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा किसी कार्य को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी माध्यम में संरक्षित करने के लिए संग्रहीत करना, यदि पुस्तकालय के पास पहले से ही कार्य की गैर-डिजिटल प्रति मौजूद है;

(ण) किसी पुस्तक (जिसके अंतर्गत पुस्तिका, संगीत पत्र, मानचित्र, चार्ट या योजना है) की तीन से अनधिक प्रतियां किसी गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रभारी व्यक्ति द्वारा या उसके निर्देशन में पुस्तकालय के उपयोग के लिए बनाना, यदि ऐसी पुस्तक भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है;

(त) किसी पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य संस्था में रखी गई किसी अप्रकाशित साहित्यिक, नाट्य या संगीत कृति का अनुसंधान या निजी अध्ययन या प्रकाशन के प्रयोजन के लिए पुनरुत्पादन, जहां जनता की पहुंच हो: परंतु जहां किसी ऐसी कृति के लेखक की या संयुक्त लेखकीय कृति की स्थिति में लेखकों में से किसी की पहचान पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य संस्था को ज्ञात हो, वहां इस खंड के उपबंध केवल तभी लागू होंगे जब ऐसी पुनरुत्पादन रचनाकार की मृत्यु की तारीख से साठ वर्ष से अधिक समय के बाद की गई हो।

(क्यू) किसी आधिकारिक राजपत्र (विधानमंडल के अधिनियम को छोड़कर) में प्रकाशित किसी मामले का पुनरुत्पादन या प्रकाशन, किसी विधानमंडल का कोई अधिनियम इस शर्त के अधीन कि ऐसे अधिनियम को उस पर किसी टिप्पणी के साथ पुनरुत्पादित या प्रकाशित किया जाए या कोई अन्य मूल मामला, सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, आयोग, परिषद, बोर्ड या अन्य समान निकाय की रिपोर्ट यदि ऐसी रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखी गई है, जब तक कि ऐसी रिपोर्ट का पुनरुत्पादन या प्रकाशन सरकार द्वारा निषिद्ध नहीं किया जाता है, किसी विधानमंडल का कोई निर्णय या आदेश

न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य न्यायिक प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई भी अपराध कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसे निर्णय या आदेश का पुनरुत्पादन या प्रकाशन न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य न्यायिक प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध न किया गया हो।

(आर) किसी अधिनियम का किसी भारतीय भाषा में अनुवाद तैयार करना या प्रकाशित करना विधानमंडल और उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का, यदि ऐसे अधिनियम या नियम या आदेश का उस भाषा में कोई अनुवाद सरकार द्वारा पहले से तैयार या प्रकाशित नहीं किया गया है या जहां ऐसे अधिनियम या नियम या आदेश का उस भाषा में अनुवाद सरकार द्वारा पहले से तैयार या प्रकाशित किया गया है, यदि अनुवाद जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है: बशर्ते कि

ऐसे अनुवाद में प्रमुख स्थान पर यह कथन शामिल हो कि अनुवाद को सरकार द्वारा अधिकृत या प्रामाणिक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है;

(ध) वास्तुकला के किसी कार्य की पेंटिंग, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फोटोग्राफ बनाना या प्रकाशित करना या वास्तुकला के किसी कार्य का प्रदर्शन करना;

(टी) धारा 2133 के खंड (सी) के उपखंड (iii) के अंतर्गत आने वाली किसी मूर्ति या अन्य कलात्मक कार्य की पेंटिंग, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फोटोग्राफ का निर्माण या प्रकाशन, यदि ऐसा कार्य किसी सार्वजनिक स्थान या किसी परिसर में स्थायी रूप से स्थित है, जहां जनता की पहुंच है;

(प) किसी सार्वजनिक स्थान या किसी परिसर में स्थायी रूप से स्थित किसी कलात्मक कार्य या किसी अन्य कलात्मक कार्य को सिनेमैटोग्राफ फिल्म में शामिल करना, यदि ऐसा समावेश केवल पृष्ठभूमि के रूप में है या फिल्म में दर्शाए गए मुख्य विषयों से अन्यथा प्रासंगिक है;

(व) किसी कलात्मक कार्य के लेखक द्वारा, जहां ऐसे कार्य का लेखक उसमें कॉपीराइट का स्वामी नहीं है, उस कार्य के उद्देश्य के लिए उसके द्वारा बनाए गए किसी साँचे, ढलाई, रेखाचित्र, योजना, मॉडल या अध्ययन का उपयोग। हालाँकि वह कार्य के मुख्य डिज़ाइन को दोहरा या नकल नहीं कर सकता।

(ब) किसी उपयोगी उपकरण के किसी विशुद्ध कार्यात्मक भाग के औद्योगिक अनुप्रयोग के प्रयोजनों के लिए किसी द्वि-आयामी कलात्मक कार्य, जैसे कि तकनीकी चित्र, से त्रि-आयामी वस्तु का निर्माण;

(x) किसी भवन या संरचना का पुनर्निर्माण, उन वास्तुशिल्पीय रेखाचित्रों या योजनाओं के अनुसार, जिनके संदर्भ में उस भवन या संरचना का मूल रूप से निर्माण किया गया था: बशर्ते कि मूल निर्माण ऐसे रेखाचित्रों और योजनाओं में कॉपीराइट के स्वामी की सहमति या लाइसेंस से किया गया हो;

(म) किसी सिनेमैटोग्राफ फिल्म में रिकार्ड या पुनरुत्पादित किसी साहित्यिक, नाटकीय, कलात्मक या संगीतमय कृति के संबंध में, उसमें कॉपीराइट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसी फिल्म का प्रदर्शन;

(जेड) किसी प्रसारण संगठन द्वारा, किसी कार्य के अपने प्रसारण के लिए अपनी सुविधाओं का उपयोग करते हुए, अल्पकालिक रिकॉर्डिंग बनाना, जिसका प्रसारण करने का अधिकार उसे है; और ऐसी रिकॉर्डिंग को उसके असाधारण दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर अभिलेखीय प्रयोजनों के लिए रखना;

(य) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी वास्तविक धार्मिक समारोह या आधिकारिक समारोह के दौरान किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कृति का प्रदर्शन या ऐसी कृति या ध्वनि रिकॉर्डिंग का जनता तक संप्रेषण;

¹³³ कलात्मक शिल्प कौशल का कोई अन्य कार्य ('कलात्मक कार्य' के अर्थ में आता है); धारा 2 (सी) (iii) भारतीय कॉपीराइट अधिनियम;

(यख) किसी भी कार्य का किसी भी सुलभ प्रारूप में अनुकूलन, पुनरुत्पादन, प्रतियां जारी करना या जनता को संप्रेषित करना, निम्नलिखित द्वारा- (i) किसी भी व्यक्ति द्वारा विकलांग व्यक्तियों को कार्यों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना, जिसमें निजी या व्यक्तिगत उपयोग, शैक्षिक उद्देश्य या अनुसंधान के लिए ऐसे सुलभ प्रारूप को किसी विकलांग व्यक्ति के साथ साझा करना शामिल है; या (ii) किसी भी संगठन द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करना, यदि सामान्य प्रारूप ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्यों का आनंद लेने में बाधा डालता है: बशर्ते कि ऐसे सुलभ प्रारूप में कार्यों की प्रतियां विकलांग व्यक्तियों को गैर-लाभकारी आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन केवल उत्पादन की लागत वसूलने के लिए: आगे यह भी प्रावधान है कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सुलभ प्रारूप में कार्यों की प्रतियां केवल विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाती हैं और व्यवसाय के सामान्य चैनलों में इसके प्रवेश को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण.— इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, "किसी संगठन" में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत संगठन और विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करने वाला संगठन या विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अध्याय 10 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संगठन या विकलांग व्यक्तियों या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या पुस्तकालय या अभिलेखागार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाला संगठन शामिल है;

(यग) किसी साहित्यिक या कलात्मक कार्य की प्रतियों का आयात, जैसे लेबल, कंपनी लोगो या प्रचारात्मक या व्याख्यात्मक सामग्री, जो वैध रूप से आयात किए जा रहे अन्य सामान या उत्पादों के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतमय कृति के अनुवाद या किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतमय या कलात्मक कृति के रूपान्तरण के संबंध में कोई कार्य करने पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे स्वयं उस कृति के संबंध में लागू होते हैं।

उपरोक्त सभी कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं हैं।

4.3.4 उल्लंघन के लिए उपाय

हर अधिकार के लिए कानून के तहत उपाय मौजूद है। कॉपीराइट का मालिक दूसरों पर मुकदमा कर सकता है उसके कॉपीराइट का उल्लंघन। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 नागरिक उपचार प्रदान करता है, कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए आपराधिक उपचार और प्रशासनिक उपचार। निम्नलिखित व्यक्ति अपने कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज कर सकते हैं¹³⁴ -

(a) लेखक और कॉपीराइट के स्वामी

(ii) कॉपीराइट का स्वामी और सह-स्वामी

(iii) कॉपीराइट का समनुदेशिनी

(बच्चों) कार्य का अनुवादक

(v) कार्य का लाइसेंसदाता या लाइसेंसधारी

(vi) कोई भी व्यक्ति जिसे उल्लंघन किए गए कार्य के कारण क्षति हुई हो

(vii) वह व्यक्ति जिसकी बंद हो चुकी प्रतियों/कार्यों या प्लेटों में रुचि हो

निम्नलिखित व्यक्ति कार्यवाही में पक्ष हो सकते हैं:¹³⁵

¹³⁴ बौद्धिक संपदा कानून, डॉ. सीपी सिंह, इलाहाबाद विधि एजेंसी प्रकाशन।

¹³⁵ वही

- (i) कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाला
- (ii) कॉपीराइट का समनुदेशक या समनुदेशिनी
- (iii) व्यक्ति उल्लंघनकारी प्रतियों या प्लेटों को अपने कब्जे में रखता है
- (iv) वह व्यक्ति जो उल्लंघनकारी प्रतियों या प्लेटों का व्यापार करता है
- (v) वह व्यक्ति जो धारा 52 ए के प्रावधानों का उल्लंघन करता है
- (vi) उल्लंघन से संबंधित कंपनी
- (vii) झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति

136

यहाँ यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि कुछ परिस्थितियों में कॉपीराइट का स्वामी कार्यवाही का पक्षकार। संबंधित प्रावधान भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 61 में दिए गए हैं।

61 कहते हैं:

कॉपीराइट के स्वामी का कार्यवाही में पक्षकार होना- (1) किसी अनन्य लाइसेंसधारी द्वारा कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में प्रवर्तित प्रत्येक सिविल वाद या अन्य कार्यवाही में, कॉपीराइट के स्वामी को, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न दे, प्रतिवादी बनाया जाएगा और जहाँ ऐसे स्वामी को प्रतिवादी बनाया जाता है, वहाँ उसे अनन्य लाइसेंसधारी के दावे पर विवाद करने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ किसी अनन्य लाइसेंसधारी द्वारा कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में शुरू किया गया कोई सिविल मुकदमा या अन्य कार्यवाही सफल हो जाती है, वहाँ उसके संबंध में कोई नया मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

कार्रवाई का कारण कॉपीराइट के स्वामी के अनुरोध पर होगा।

इस प्रकार जहाँ कोई मुकदमा अनन्य लाइसेंसधारी द्वारा शुरू किया जाता है, कॉपीराइट का स्वामी कार्यवाही का पक्षकार। और जब अनन्य लाइसेंसधारी द्वारा संस्थित किसी वाद में निर्णय उसके पक्ष में, तो कॉपीराइट के मालिक को नया मुकदमा या अन्य कार्यवाही दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा कार्रवाई के समान कारण का सम्मान।

4.3.4.1 नागरिक उपचार

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम का अध्याय XII कॉपीराइट के उल्लंघन के विरुद्ध दीवानी उपचारों से संबंधित है। कॉपीराइट स्वामी किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है जो कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। कॉपीराइट स्वामी निषेधाज्ञा, क्षतिपूर्ति और लेखा के माध्यम से उपचार पाने का हकदार है।¹³⁷ सिविल उपचार निवारक या प्रतिपूरक हो सकते हैं।

4.3.4.1.1 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी कार्य में कॉपीराइट के उल्लंघन या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के संबंध में अध्याय XII के तहत उत्पन्न होने वाला प्रत्येक वाद या अन्य सिविल कार्यवाही अधिकार क्षेत्र वाले जिला न्यायालय में शुरू की जाएगी।¹³⁸ इस प्रयोजन के लिए, "अधिकार क्षेत्र वाला जिला न्यायालय" में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, एक जिला न्यायालय शामिल होगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, वाद या अन्य कार्यवाही शुरू करने के समय, वाद या अन्य कार्यवाही शुरू करने वाला व्यक्ति या जहाँ एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं,

¹³⁶ 4.3.2.1.5 देखें

¹³⁷ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 55 (1)

¹³⁸ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 62 (1)

उनमें से कोई भी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।¹³⁹

4.3.4.1.2 कॉपीराइट के स्वामी की परिभाषा

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के अध्याय XII के अंतर्गत धारा 54 'कॉपीराइट के स्वामी' की परिभाषा स्पष्ट करती है, जो अपने कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए दूसरों पर मुकदमा कर सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 54 में लिखा है

जैसा:

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "कॉपीराइट का स्वामी" पद में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) एक अनन्य लाइसेंसधारी;

(ख) अनाम या छद्मनाम से प्रकाशित साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य की दशा में, कार्य का प्रकाशक, जब तक लेखक की पहचान उजागर नहीं हो जाती, या संयुक्त लेखकत्व की अनाम कृति या ऐसे नामों से प्रकाशित संयुक्त लेखकत्व की कृति, जिनमें सभी छद्म नाम हैं, की दशा में, लेखकों में से किसी की पहचान लेखक और प्रकाशक द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर दी जाती, या अन्यथा उस लेखक या उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अपील बोर्ड की संतुष्टि के लिए स्थापित नहीं कर दी जाती।

4.3.4.1.3 कार्य के लेखक या प्रकाशक की धारणा

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 55 (2) में प्रावधान है कि साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य से संबंधित उल्लंघन के मामले में, जब तक कि अदालत के समक्ष विपरीत साक्ष्य न हों, कार्य पर लेखक या प्रकाशक का नाम होने पर भी अदालत द्वारा उसे मूल माना जाएगा।

उक्त धारा इस प्रकार है:

"जहां साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य के मामले में, या धारा 13(14) की उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन, एक चलचित्र फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग, उस कार्य के लेखक या प्रकाशक का नाम होने का दावा करने वाला नाम, प्रकाशित कार्य की प्रतियों पर दिखाई देता है, या कलात्मक कार्य के मामले में, उस कार्य पर दिखाई देता है जब इसे बनाया गया था, वह व्यक्ति जिसका नाम इस प्रकार दिखाई देता है या दिखाई दिया, ऐसे कार्य में कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में किसी भी कार्यवाही में, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, यह माना जाएगा कि वह कार्य का लेखक या प्रकाशक है, जैसा भी मामला हो।"

4.3.4.1.4 एंटोन पिलर ऑर्डर

¹³⁹ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 62 (2); विस्तृत जानकारी के लिए देखें यूनिट-3 क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे और शीर्षक के अंतर्गत कॉपीराइट- क्षेत्राधिकार और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम

¹⁴⁰ 13 (3) कॉपीराइट अस्तित्व में नहीं होगा - (क) किसी चलचित्र फिल्म में यदि फिल्म का पर्याप्त भाग किसी अन्य कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन करता है; (ख) किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कार्य के संबंध में बनाई गई किसी [ध्वनि रिकॉर्डिंग] में, यदि ध्वनि रिकॉर्डिंग करते समय ऐसे कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है।

यह एक निवारक राहत है। इसका आविष्कार और प्रयोग पहली बार अंग्रेज प्रतिपादक लॉर्ड डेनिंग ने एंटोन पिलर केजी बनाम मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस लिमिटेड में किया था।¹⁴¹ इसका नाम मामले में वादी के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में, इसे ट्रिप्स के प्रावधान में भी मान्यता मिली है।¹⁴² एंटोन पिलर आदेश एक एकपक्षीय मध्यस्थ आदेश की तरह है। जो प्रतिवादी के परिसर का निरीक्षण करने की अनुमति देता है।

हालाँकि यह एक न्यायसंगत राहत है और इसे केवल दुर्लभ मामलों में ही प्रदान किया जाता है। इस आदेश की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब प्रतिवादी द्वारा प्रासंगिक उल्लंघनकारी दस्तावेजों और लेखों को नष्ट करने का गंभीर खतरा होता है, ताकि न्याय प्रभावित हो या विफल हो जाए।¹⁴³ यह तलाशी वारंट नहीं है। यह केवल अनुमति द्वारा प्रतिवादी के प्रवेश और निरीक्षण को अधिकृत करता है, जिसके अभाव में यह कार्य अतिचार के अपराध के समान होगा।

144

4.3.4.1.5 कॉपीराइट के उल्लंघन के विरुद्ध निषेधाज्ञा

निषेधाज्ञा न्यायालय के आदेश के रूप में एक न्यायसंगत उपाय है जो किसी पक्ष को विशिष्ट कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करता है। यह अधिकांश कॉपीराइट मुकदमों में मांगा जाने वाला मुख्य उपाय है।

प्रतिवादी को ऐसे कार्य जारी रखने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा

उल्लंघन का गठन करता है।¹⁴⁵ यह कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दी गई अंतरिम राहत है। निषेधाज्ञा अस्थायी और स्थायी हो सकती है जो मामले की स्थिति और परिस्थितियों पर निर्भर हो सकती है। रत्न सागर (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम ट्रिसिया पब्लिकेशन और अन्य¹⁴⁶ के मामले में अदालत ने स्थायी निषेधाज्ञा पारित की।

उस मामले में जहां प्रतिवादी यह साबित कर देता है कि उल्लंघन की तिथि पर उसे इसकी जानकारी नहीं थी और उसके पास यह मानने का कोई उचित आधार नहीं था कि कार्य में कॉपीराइट विद्यमान है, वादी उल्लंघन के संबंध में निषेधाज्ञा का हकदार होगा।¹⁴⁷

4.3.4.1.6 प्रतिपूरक नागरिक उपचार

ये प्रकृति में उपचारात्मक हैं और मालिक या खरीदार को मुआवजा प्रदान करते हैं।

कार्य के निर्माता को उल्लंघन के कारण होने वाले वित्तीय/आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए। प्रतिपूरक उपायों में हर्जाना, लाभ का लेखा-जोखा और उल्लंघनकारी प्रतियों का कब्जा/वितरण शामिल है।

कॉपीराइट स्वामी या तो क्षतिपूर्ति या लाभ के विवरण का दावा कर सकता है, दोनों नहीं, क्योंकि इस कानूनी उपाय के पीछे भावना यह है कि वादी को मुआवजा दिया जाना चाहिए और उसे एक ही उल्लंघन किए गए कार्य के लिए दो बार मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। यदि प्रतिवादी के पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि कार्य में कॉपीराइट मौजूद नहीं है, तो वादी उल्लंघनकारी प्रतियों की बिक्री से प्रतिवादी द्वारा अर्जित लाभ के पूरे या हिस्से के लिए एक डिक्री के साथ निषेधाज्ञा के लिए हकदार होगा, जैसा कि अदालत परिस्थितियों में उचित समझे।¹⁴⁸ इसके अलावा लागत

¹⁴¹ (1976) अध्याय 5 (एंटोन पिलर ऑर्डर के रूप में जाना जाता है), डॉ. जे.के. दास द्वारा संदर्भित, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रथम संस्करण, कमल लॉ हाउस, कोलकाता, 2008, पृ.212.

¹⁴² ट्रिप्स समझौता, अनुच्छेद 50 का पैरा 2

¹⁴³ बौद्धिक संपदा अधिकार और कानून, डॉ. जी.बी. रेड्डी; गोगिया लॉ एंजेंसी, हैदराबाद; पृ.159

¹⁴⁴ प्रो. ए.के. कौल, डॉ. वी.के. आहूजा, कॉपीराइट का कानून: गुटेनबर्ग के आविष्कार से इंटरनेट तक; विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001, पृष्ठ 16-17

¹⁴⁵ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 55 (1)

¹⁴⁶ 1996 पीटीसी (16) 597.

¹⁴⁷ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 55 (1)

¹⁴⁸ पूर्वोक्त

कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में किसी भी कार्यवाही में सभी पक्षों का निर्णय न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगा।¹⁴⁹

उल्लंघनकारी प्रतियों को रखने वाले या उनसे निपटने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध स्वामी के अधिकार। किसी ऐसे कार्य की सभी उल्लंघनकारी प्रतियां, जिसमें कॉपीराइट विद्यमान है, तथा ऐसी उल्लंघनकारी प्रतियों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित सभी प्लेटें कॉपीराइट के स्वामी की संपत्ति मानी जाएंगी, जो तदनुसार उनके कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए या उनके रूपांतरण के संबंध में कार्यवाही कर सकता है: परंतु कॉपीराइट का स्वामी किसी उल्लंघनकारी प्रतियों के रूपांतरण के संबंध में किसी उपचार का हकदार नहीं होगा, यदि विरोधी यह साबित कर देता है- (क) कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी और उसके पास यह मानने का कोई उचित आधार नहीं था कि जिस कार्य की ऐसी प्रतियों के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि वे उल्लंघनकारी प्रतियां हैं, उसमें कॉपीराइट विद्यमान है; या (ख) कि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार थे कि ऐसी प्रतियां या प्लेटें किसी कार्य में कॉपीराइट के उल्लंघन में शामिल नहीं हैं।¹⁵⁰

इस प्रकार, जिस कार्य पर कॉपीराइट है, उसकी सभी प्रतियाँ उस कार्य के स्वामी की संपत्ति हैं। उसे सभी न बिकने वाली उल्लंघनकारी प्रतियों और पहले से बिक चुकी सभी प्रतियों की कीमत अपने कब्जे में लेने का अधिकार है।¹⁵¹

4.3.4.1.7 पृथक अधिकारों का संरक्षण

ऐसे मामले में, जहां किसी कार्य में कॉपीराइट से संबंधित अनेक अधिकार, विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व में हों, ऐसे किसी अधिकार का स्वामी, उस अधिकार की सीमा तक, इस अधिनियम द्वारा उपबंधित उपचारों का हकदार होगा और वह किसी अन्य अधिकार के स्वामी को ऐसे वाद, कार्रवाई या कार्यवाही में पक्षकार बनाए बिना, किसी वाद, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही के माध्यम से ऐसे अधिकार को व्यक्तिगत रूप से लागू कर सकेगा।¹⁵²

4.3.4.1.8 निराधार धमकी के मामले में उपाय

कानूनी कार्यवाही

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 60 के अनुसार, जहां कोई व्यक्ति किसी कार्य में कॉपीराइट का स्वामी होने का दावा करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को परिपत्रों, विज्ञापनों या अन्यथा द्वारा कॉपीराइट के कथित उल्लंघन के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही या दायित्व की धमकी देता है, तो उससे व्यथित कोई व्यक्ति, [विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 34 में निहित किसी बात के होते हुए भी], यह घोषणात्मक वाद संस्थित कर सकेगा कि जिस कथित उल्लंघन से धमकी संबंधित थी, वह वास्तव में ऐसी धमकी देने वाले व्यक्ति के किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं था और वह इसका हकदार है-

(क) ऐसी धमकियों को जारी रखने के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करना; तथा

(ख) ऐसी क्षति, यदि कोई हो, वसूल करेगा जो उसे ऐसी धमकियों के कारण हुई हो

¹⁴⁹ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 55 (3)

¹⁵⁰ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 58

¹⁵¹ गोपालदास बनाम जगन्नाथ प्रसाद, एआईआर 1938 एएलएल 266, पृष्ठ 271 देखें; बौद्धिक संपदा अधिकार और कानून, डॉ. जीबी रेड्डी; गोगिया लॉ एजेंसी, हैदराबाद; पृष्ठ 162

¹⁵² भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 56

बशर्ते कि यह धारा उस स्थिति में लागू नहीं होगी, जब ऐसी धमकी देने वाला व्यक्ति समुचित तत्परता के साथ अपने द्वारा दावा किए गए कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करता है और मुकदमा चलाता है।

4.3.4.1.9 निम्नलिखित मामलों में सिविल उपचार उपलब्ध नहीं हैं:

वास्तुकला के कार्य

जहाँ किसी भवन या अन्य संरचना का निर्माण शुरू हो गया है जो किसी अन्य कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या जो पूरा होने पर उल्लंघन करेगा, वहाँ कॉपीराइट का स्वामी ऐसे भवन या संरचना के निर्माण को रोकने या उसे गिराने का आदेश देने के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) के प्रावधान उल्लंघनकारी वास्तुकला कार्य के मामले में लागू नहीं होते हैं।¹⁵³ इसलिए धारा 58 किसी भवन या अन्य संरचना के निर्माण के संबंध में लागू नहीं होगी जो किसी अन्य कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या जो पूरा होने पर उल्लंघन करेगा।¹⁵⁴

4.3.4.2 आपराधिक उपचार

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम का अध्याय XIII कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित अपराधों से संबंधित है। धारा 63 से 70 में इस संबंध में प्रावधान दिए गए हैं।

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 70 में अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय की शक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस धारा के अनुसार - 'मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।'

इसलिए इस अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की शक्ति मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है।

4.3.4.2.1 कॉपीराइट या अन्य उल्लंघन का अपराध

अधिकार- धारा 63

कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है-

(क) किसी कार्य का कॉपीराइट, या

(ख) धारा 53क द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त कोई अन्य अधिकार, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है या कॉपीराइट अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उसे छह महीने से तीन साल तक की सजा और पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

जहां उल्लंघन व्यापार या कारोबार के दौरान लाभ के लिए नहीं किया गया है, वहां न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, छह महीने से कम अवधि के कारावास या पचास हजार रुपए से कम का जुर्माना लगा सकता है।

¹⁵³ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 59 (1)

¹⁵⁴ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 59 (2)

यह भी ध्यान दिया जाता है कि किसी भवन या अन्य संरचना का निर्माण जो किसी अन्य कार्य के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या जिसके पूरा होने पर उल्लंघन होगा, इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा।

पुनः यदि कोई व्यक्ति ऊपर वर्णित किसी अपराध के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और पुनः किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह दूसरी बार और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।¹⁵⁵

बशर्ते कि जहां उल्लंघन व्यापार या कारोबार के दौरान लाभ के लिए नहीं किया गया है, वहां न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, एक वर्ष से कम अवधि के कारावास या एक लाख रुपये से कम का जुर्माना लगा सकेगा: आगे यह भी प्रावधान है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 65) के प्रारंभ से पहले की गई किसी दोषसिद्धि का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।¹⁵⁶

यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि धारा 63 के अंतर्गत वाद केवल कार्य के स्वामी अथवा समनुदेशिनी/लाइसेंसधारी द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।¹⁵⁷

धारा 63 के अंतर्गत अभियोजन के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि कार्य कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो।¹⁵⁸

4.3.4.2.2 जानबूझकर उल्लंघनकारी प्रतियों का उपयोग करना

कंप्यूटर प्रोग्राम

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63बी के अनुसार, कंप्यूटर प्रोग्राम की उल्लंघनकारी कॉपी का जानबूझकर इस्तेमाल करना अपराध है। धारा 63बी इस प्रकार है:

“कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की उल्लंघनकारी प्रतिलिपि का उपयोग कंप्यूटर पर करता है, उसे कम से कम सात दिन के कारावास से, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और कम से कम पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा:

बशर्ते कि जहां कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग लाभ के लिए या व्यापार या कारोबार के क्रम में नहीं किया गया है, वहां न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, कारावास की सजा नहीं दे सकता है और जुर्माना लगा सकता है जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है।”

इस प्रकार कंप्यूटर प्रोग्राम की उल्लंघनकारी कॉपी का जानबूझकर इस्तेमाल करने के मामले में सजा सात दिन से तीन साल तक होगी और जुर्माना 50 हजार से दो लाख रुपये तक होगा।

¹⁵⁵ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 ए

¹⁵⁶ वही.

¹⁵⁷ नवीन चंद्र जैन बनाम यूपी राज्य, 1981 ऑल लॉ जे. 1273; बौद्धिक संपदा कानून डॉ सीपी सिंह द्वारा;

इलाहाबाद लॉ एजेंसी प्रकाशन, पृ. 168

¹⁵⁸ केसी बोकाडिया बनाम दिनेश चंद्र दुबे, (1999) एमपीएलजे 33; बौद्धिक संपदा कानून डॉ सीपी सिंह द्वारा;

इलाहाबाद लॉ एजेंसी प्रकाशन, पृ. 168

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [94]

कम्प्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग किसी लाभ के लिए या व्यापार या कारोबार के दौरान नहीं किया जाता है तो न्यायालय बिना किसी कारावास के केवल 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

4.3.4.2.3 उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्लेटों का कब्जा

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 65 के अनुसार, उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के उद्देश्य से प्लेटों का कब्जा एक अपराध है और इस अपराध के लिए दो साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है, जो न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। उक्त अधिनियम की धारा 65 इस प्रकार है-

'कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी ऐसे कार्य की उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के उद्देश्य से कोई प्लेट बनाता है, या अपने कब्जे में रखता है, जिसमें कॉपीराइट विद्यमान है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।'

इसके अलावा धारा 66 उल्लंघनकारी प्रतियों या प्लेटों के उल्लंघनकारी प्रतियों के निर्माण के उद्देश्य से निपटान का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार - 'इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय, चाहे कथित अपराधी को दोषी ठहराया गया हो या नहीं, आदेश दे सकता है कि कथित अपराधी के कब्जे में मौजूद कृति की सभी प्रतियां या सभी प्लेटें, जो उसे उल्लंघनकारी प्रतियां या उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के उद्देश्य से प्लेटें प्रतीत होती हैं, कॉपीराइट के स्वामी को सौंप दी जाएं या ऐसी प्रतियों या प्लेटों के निपटान के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

इस प्रकार उपरोक्त मामले में न्यायालय ऐसी उल्लंघनकारी प्रतियों, या उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के उद्देश्य से प्लेटों को कॉपीराइट के स्वामी को सौंपने का आदेश दे सकता है।

धारा 66 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध अपीलें- धारा 66 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उस न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसमें आदेश देने वाले न्यायालय से सामान्यतया अपीलें होती हैं और ऐसा अपीलीय न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि अपील का निपटारा होने तक आदेश के निष्पादन को रोक दिया जाए।¹⁵⁹

4.3.4.2.4 रजिस्टर आदि में गलत प्रविष्टियां करना, गलत प्रविष्टियां प्रस्तुत करना या निविदा देना

उक्त अधिनियम की धारा 67 में रजिस्टर आदि में झूठी प्रविष्टियां करने, झूठी प्रविष्टियां प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 67 के अनुसार-

“कोई भी व्यक्ति जो,—

(क) इस अधिनियम के अधीन रखे गए कॉपीराइट रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टि करेगा या कराएगा, या

(ख) ऐसा लेख बनाएगा या बनवाएगा जो ऐसे रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की नकल होने का मिथ्या तात्पर्य रखता हो, या (ग) ऐसी किसी प्रविष्टि या लेख को साक्ष्य के रूप में पेश करेगा या पेश करवाएगा, यह जानते हुए कि वह मिथ्या है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत दंड एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा।

¹⁵⁹ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 71

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [95]

4.3.4.2.5 किसी उद्देश्य से गलत बयान देना

किसी अधिकारी या अधिकारी को धोखा देना या प्रभावित करना

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 68 किसी अधिकारी या अधिकारी को धोखा देने या प्रभावित करने के उद्देश्य से गलत बयान देने पर दंड का प्रावधान करती है। धारा 68 इस प्रकार है-

“कोई भी व्यक्ति जो,—

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के निष्पादन में किसी प्राधिकारी या अधिकारी को धोखा देने की दृष्टि से अभिनेता

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन किसी विषय के संबंध में किसी बात के किए जाने या न किए जाने को उपाप्त करने या प्रभावित करने की दृष्टि से, यह जानते हुए कि वह मिथ्या है, कोई मिथ्या कथन या अभ्यावेदन करेगा, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

इसलिए धारा 68 के अंतर्गत भी एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

4.3.4.2.6 धारा 52ए का उल्लंघन

धारा 52ए ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों के प्रकाशन के मामले में उनमें शामिल किए जाने वाले विवरणों के बारे में विशेष प्रावधान करती है।¹⁶⁰ धारा 68ए धारा 52ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार-

“कोई भी व्यक्ति जो धारा 52ए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ध्वनि रिकॉर्डिंग या वीडियो फिल्म प्रकाशित करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।”

चूंकि ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्में अपनी प्रकृति के कारण चोरी के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कॉपीराइट अधिनियम में अलग से धारा 52 ए जोड़ी गई। इसका उल्लंघन ऐसा करने पर तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

4.3.4.2.7 कंपनियों द्वारा अपराध

ऐसे मामले में जहां कोई कंपनी अर्थात् कोई भी निगमित संस्था और जिसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है, इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करती है, धारा 69 इस संबंध में प्रावधान देती है।

धारा 69 कहती है-

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कंपनी भी ऐसे अपराध का दोषी समझी जाएगी और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगी:

¹⁶⁰ 4.3.2.1.5 ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों के संबंध में विशेष प्रावधान देखें

¹⁶¹ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 69 का स्पष्टीकरण

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दंडित किया जा सकेगा।

यहां फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म में भागीदार से है।¹⁶²

इस प्रकार किसी कंपनी द्वारा भारतीय संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया कोई भी अपराध कॉपीराइट अधिनियम के तहत निम्नलिखित दंडनीय हो सकते हैं:

1. वह व्यक्ति जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी है
2. कंपनी
3. निदेशक
4. प्रबंधक
5. सचिव
6. अन्य अधिकारी

जिसकी ओर से अपराध किया गया है उसकी सहमति या मिलीभगत से या उसकी ओर से किसी लापरवाही के कारण।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 'फर्म' शब्द भी 'कंपनी' के अंतर्गत आता है।¹⁶³

4.3.4.2.8 तकनीकी उपायों और सुरक्षा का संरक्षण

अधिकार संरक्षण प्रबंधन सूचना

कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में दो नई धाराएं - 65ए और 65बी शामिल की गई हैं, जो प्रौद्योगिकीय उपायों के लिए संरक्षण तथा सूचना प्रबंधन के अधिकार के लिए संरक्षण प्रदान करती हैं।¹⁶⁴

टीपीएम तकनीकी सुरक्षा उपाय हैं जो डिजिटल प्रारूप में संरक्षित कार्य की कई बार नकल करने से रोकते हैं। आरएमआई को आम तौर पर संरक्षित कार्य पर लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य के स्वामी का लेबल हमेशा कार्य में अंतर्निहित रहे।¹⁶⁵

¹⁶² वही मोनार्बेन

¹⁶³ के.व.भाई शाह एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2004) 7 एसएससी 15; बौद्धिक संपदा

डॉ. सीपी सिंह द्वारा कानून; इलाहाबाद लॉ एजेंसी प्रकाशन। पृ. 173

¹⁶⁴ विस्तृत जानकारी के लिए देखें 2.3.6 इंटरनेट पाइरेसी से सुरक्षा; यूनिट 2- इंटरनेट में कॉपीराइट

¹⁶⁵ विस्तृत जानकारी के लिए देखें 2.3.3.2 तकनीकी सुरक्षा उपाय और अधिकार प्रबंधन सूचना (टीपीएम/आरएमआई); इकाई 2- इंटरनेट में कॉपीराइट

4.3.4.2.9 उल्लंघनकारी प्रतियों को जब्त करने की पुलिस की शक्ति, धारा 63 का उल्लंघन

धारा 64 पुलिस को उल्लंघनकारी प्रतियों को जब्त करने का अधिकार देती है। उक्त धारा का प्रावधान इस प्रकार है:

“(1) कोई भी पुलिस अधिकारी, जो उपनिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी कार्य में कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में धारा 63 के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने की संभावना है, तो वह कार्य की सभी प्रतियां और कार्य की उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई सभी प्लेटों को, जहां कहीं भी पाया जाए, बिना वारंट के जब्त कर सकेगा और इस प्रकार जब्त की गई सभी प्रतियां और प्लेटें यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएंगी।

(2) कोई व्यक्ति, जिसका उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किसी कृति की प्रतियों या प्लेटों में हित है, ऐसी अभिग्रहण के पन्द्रह दिन के भीतर मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा कि ऐसी प्रतियां या प्लेटें उसे वापस कर दी जाएं और मजिस्ट्रेट, आवेदक और शिकायतकर्ता को सुनने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात, जो आवश्यक हो, आवेदन पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे।

इस प्रकार भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान पुलिस अधिकारी को शक्ति प्रदान करते हैं, जो उप निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, वह बिना वारंट के कार्य की सभी उल्लंघनकारी प्रतियों और कार्य की उल्लंघनकारी प्रतियों को बनाने के उद्देश्य से उपयोग की गई सभी प्लेटों को जब्त कर सकता है। इसलिए उल्लंघन गतिविधियों की निरंतरता यानी निरंतर अपराध को रोकें। और फिर उचित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। प्रावधान आगे कहता है कि जब्त की गई सामग्री में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी जब्त की गई पंद्रह दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट को ऐसी सामग्री वापस करने के लिए आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट, आवेदक और शिकायतकर्ता को सुनने और आवश्यक हो सकने वाली आगे की जांच करने के बाद, आवेदन पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह उचित समझे।¹⁶⁶

4.3.4.3 प्रशासनिक उपाय

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 6 में कुछ विवादों के बारे में प्रावधान किया गया है जिनका निर्णय अपील बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस धारा के अनुसार-

“यदि कोई प्रश्न उठता है-

(क) क्या कोई कार्य प्रकाशित हुआ है या अध्याय V/167 के प्रयोजनों के लिए कोई कार्य किस तारीख को प्रकाशित हुआ था, या

(ख) क्या किसी अन्य देश में किसी कृति के लिए कॉपीराइट की अवधि इस अधिनियम के अधीन उस कृति के संबंध में उपबंधित अवधि से कम है, तो उसे धारा 11 के अधीन गठित अपील बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा:

¹⁶⁶ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 66 देखें।

¹⁶⁷ अध्याय 5 के अंतर्गत कॉपीराइट की अवधि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [98]

परन्तु यदि अपील बोर्ड की राय में धारा 3168 में निर्दिष्ट प्रतियां जारी करना या जनता को संसूचना देना महत्वहीन प्रकृति का था तो उसे उस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रकाशन नहीं समझा जाएगा।

यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि अपील बोर्ड सामान्यतः इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष संस्थित किसी कार्यवाही की सुनवाई उस क्षेत्र में करेगा¹⁶⁹ जिसमें कार्यवाही संस्थित करने के समय कार्यवाही संस्थित करने वाला व्यक्ति वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।¹⁷⁰

अपीलीय बोर्ड कॉपीराइट के हस्तांतरण से संबंधित किसी भी विवाद में अपना निर्णय देगा।

यदि कोई समनुदेशी उसे सौंपे गए अधिकारों का पर्याप्त प्रयोग करने में असफल रहता है, और ऐसी असफलता समनुदेशक के किसी कार्य या चूक के कारण नहीं है, तो अपील बोर्ड समनुदेशक से शिकायत प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे समनुदेशन को रद्द कर सकता है।¹⁷¹

पुनः, "यदि किसी कॉपीराइट के हस्तांतरण के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अपील बोर्ड, पीड़ित पक्ष से शिकायत प्राप्त होने पर और आवश्यक समझे जाने वाले जांच के पश्चात, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे, जिसमें देय किसी रॉयल्टी की वसूली का आदेश भी शामिल है: बशर्ते कि अपील बोर्ड इस उपधारा के अंतर्गत हस्तांतरण को रद्द करने के लिए कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगा, जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि हस्तांतरण की शर्तें हस्तांतरणकर्ता के लिए कठोर हैं, यदि हस्तांतरणकर्ता लेखक भी है: आगे यह भी प्रावधान है कि, इस उपधारा के अंतर्गत हस्तांतरण के रद्द करने के लिए आवेदन के निपटान तक, अपील बोर्ड हस्तांतरण की शर्तों और नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जिसमें सौंपे गए अधिकारों के उपभोग के लिए भुगतान किए जाने वाले किसी भी प्रतिफल सहित हस्तांतरण की शर्तें शामिल हैं: यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा के अंतर्गत हस्तांतरण के रद्द करने का कोई आदेश ऐसे हस्तांतरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाएगा।"¹⁷²

4.3.4.4 अपीलीय उपचार

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के अध्याय VIV के अंतर्गत धारा 71 से 73 में मजिस्ट्रेट के कुछ आदेशों के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान दिए गए हैं।

4.3.4.4.1 मजिस्ट्रेट के कुछ आदेशों के विरुद्ध अपील -

धारा 71

धारा 71 मजिस्ट्रेट के कुछ आदेशों के खिलाफ अपील के बारे में प्रावधान करती है।

धारा इस प्रकार है—

'धारा 64 की उपधारा (2) या धारा 66 के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उस न्यायालय में अपील कर सकता है, जिसमें उस न्यायालय से अपील की जाती है।

¹⁶⁸ धारा 3 में प्रकाशन का अर्थ दिया गया है- "इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रकाशन" का अर्थ है किसी रचना को प्रकाशित करना। प्रतियां जारी करके या जनता तक कार्य का संचार करके जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।"

¹⁶⁹ इस उपधारा में "क्षेत्र" का तात्पर्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 15 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है; भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 12 का स्पष्टीकरण।

¹⁷⁰ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 12 देखें; अपील बोर्ड की शक्तियां और प्रक्रिया। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा

¹⁷¹ 19ए (1)

¹⁷² भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 19ए (2)

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [99]

आदेश को सामान्यतः निरस्त किया जा सकता है, और ऐसा अपीलीय न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि अपील के निपटारे तक आदेश के निष्पादन को रोक दिया जाए।”

इस प्रकार कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
ऐसे आदेश पारित करने के 30 दिनों के भीतर।

4.3.4.4.2 रजिस्ट्रार के आदेशों के खिलाफ अपील

कॉपीराइट और अपील बोर्ड - धारा 72

धारा 72 में कॉपीराइट रजिस्ट्रार और अपीलीय बोर्ड के आदेशों के खिलाफ अपील के प्रावधान दिए गए हैं। यह धारा कहती है-

“(1) कॉपीराइट रजिस्ट्रार के किसी अंतिम निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश या निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर अपील बोर्ड में अपील कर सकता है।

(2) अपील बोर्ड के किसी अंतिम निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन अपील में किया गया निर्णय या आदेश नहीं है, ऐसे निर्णय या आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर उस उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में अपीलकर्ता वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है:

परन्तु धारा 6 के अधीन अपील बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन अपील के लिए उपबंधित तीन मास की अवधि की गणना करते समय, जिस निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, उसके आदेश या अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्रदान करने में लिया गया समय निकाल दिया जाएगा।

इस प्रकार धारा 72 में आदेश के अंतिम निर्णय के विरुद्ध अपील के संबंध में प्रावधान प्रदान किए गए।

कॉपीराइट रजिस्ट्रार और अपीलीय बोर्ड। उच्च न्यायालय धारा 72.173 के तहत उसके समक्ष की गई अपीलों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकता है।

4.3.4.5 कोई व्यक्ति दीवानी और फौजदारी दोनों तरह का अपराध कर सकता है

एक साथ उपाय

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कॉपीराइट के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति पर एक ही समय में सिविल और आपराधिक उपचार लेने पर प्रतिबंध लगाता हो।¹⁷⁴

4.4 सारांश

कॉपीराइट कानून रचनात्मकता और मौलिकता को सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी नया आविष्कार बहुत सारा पैसा और समय। सफल आविष्कार के बाद कॉपीराइट ने उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए अपने काम पर निर्भर करता है। जिसका आनंद वह सीमित समय तक ले सकता है और अपने पूरे जीवन भर ले सकता है कुछ मामलों में, जैसे साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्य। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 'उल्लंघन' के बारे में कहती है। कॉपीराइट का उल्लंघन उन परिस्थितियों में होता है जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के बिना कोई कार्य करता है या

¹⁷³ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 73.

¹⁷⁴ बौद्धिक संपदा कानून, डॉ. सीपी सिंह; इलाहाबाद विधि एजेंसी प्रकाशन, पृ. 173

कॉपीराइट रजिस्ट्रार, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कॉपीराइट के अनन्य अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं।

कॉपीराइट स्वामी। उल्लंघन के सामान्य रूप हैं:

1. किसी भी भौतिक रूप में कार्य का पुनरुत्पादन और प्रकाशन;
2. जनता तक कार्य का संचार;
3. किसी भी माध्यम से जनता के समक्ष कार्य का प्रदर्शन;
4. कार्य की बिक्री या किराये पर देना;
5. कार्य में अनुकूलन और अनुवाद करना।

आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स¹⁷⁵ के ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी

कॉपीराइट के उल्लंघन का निर्णय लेने के सिद्धांत:

1. जिस तरह से काम के लेखक अपने विचार व्यक्त करते हैं;
2. किसी विचार पर कोई कॉपीराइट नहीं है;
3. कॉपीराइट कार्य से पर्याप्त समानताएं;
4. मूल कार्य की प्रतिलिपि प्रतीत होती है;
5. एक ही विषय पर अलग-अलग प्रस्तुति कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है;
6. यदि समानताएं पूर्णतः आकस्मिक हैं तो कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं होगा;
7. चोरी का स्पष्ट रूप से सिद्ध कृत्य;
8. किसी फिल्म या नाटक में दर्शकों द्वारा मूल की प्रतिलिपि की समग्र छाप।

सृजनकर्ता के अधिकार और समाज के हित के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं:

कॉपीराइट कानून में अपवाद, जो समाज की जरूरतों को पूरा करते हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 इस संबंध में अपवाद निर्धारित करती है। निष्पक्ष व्यवहार, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाना या उनका अनुकूलन करना, वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग, न्यायिक कार्यवाही और विधायी उद्देश्यों के संबंध में पुनरुत्पादन या प्रमाणित प्रतियां बनाना, उद्धरणों को पढ़ना या सुनाना, शैक्षिक संस्थानों के उपयोग के लिए प्रकाशन, शिक्षण और शिक्षा के दौरान शिक्षक या छात्रों द्वारा पुनरुत्पादन, शैक्षिक संस्थानों से संबंधित गतिविधियों के दौरान या किसी शौकिया क्लब या समाज द्वारा प्रदर्शन, कुछ परिस्थितियों में और संलग्न कमरे में ध्वनि रिकॉर्डिंग करना और उसका उपयोग करना, आदि। ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों में कॉपीराइट की नाजुक प्रकृति के कारण कॉपीराइट अधिनियम में 1984 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 52 ए के तहत विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए सिविल, आपराधिक, प्रशासनिक और अपीलीय उपचार प्रदान किए गए हैं। इन उपचारों को नीचे दी गई तालिका-1 से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है और आसानी से समझा जा सकता है:

प्रकृति का प्रतिकार	अधिनियम का प्रावधान	उपाय/दंड	क्षेत्राधिकार
सिविल उपाय -एस: अध्याय बारहवीं	धारा 54. की परिभाषा 'कॉपीराइट का स्वामी' धारा 55. सिविल उपचार कॉपीराइट का उल्लंघन	निषेधाज्ञा, क्षति, लेखा और अन्यथा	अनुभाग 62. क्षेत्राधिकार अदालत ऊपर इसके अंतर्गत उठने वाले मामले अध्याय-

¹⁷⁵ एआईआर 1978 एससी 1613 (1627)। बौद्धिक संपदा अधिकार और कानून, डॉ. जीबी रेड्डी; गोगिया लॉ एजेंसी, हैदराबाद; पृ.146

<p>(अनुभाग -एस 54 टीओ 62)</p>	<p>धारा 56. संरक्षण पृथक अधिकार (किसी भी कार्य का स्वामित्व अलग-अलग व्यक्तियों के पास हो) धारा 57. लेखक के विशेष अधिकार धारा 58. उल्लंघनकारी प्रतियों को रखने वाले या उनसे निपटने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध स्वामी के अधिकार धारा 59. वास्तुकला के कार्यों के मामले में उपचार पर प्रतिबंध धारा 60. विधिक कार्यवाही की निराधार धमकी के मामले में उपाय धारा 61. स्वामी कार्यवाही में पक्षकार बनने के लिए कॉपीराइट</p>	<p>हर्जाना सभी उल्लंघनकारी प्रतियों और ऐसी उल्लंघनकारी प्रतियों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त या आशयित सभी प्लेटों के कब्जे की वसूली, निषेधाज्ञा या हर्जाना या दोनों</p>	<p>जिला अदालत अधिकार क्षेत्र होना।</p>
<p>क्रिमिना एल उपाय एल- अध्याय तेरहवें (अनुभाग -एस 63 टीओ 70)</p>	<p>धारा 63. अपराध इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त कॉपीराइट या अन्य अधिकारों का उल्लंघन धारा 63-ए. दूसरी और बाद की सज़ाओं पर बढ़ी हुई सज़ा धारा 63-बी. कंप्यूटर की उल्लंघनकारी कॉपी का जानबूझकर इस्तेमाल करना program' धारा 64. उल्लंघनकारी प्रतियों/प्लेटों को जब्त करने की पुलिस की शक्ति धारा 65. उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के उद्देश्य से प्लेटों का कब्ज़ा धारा 65ए. तकनीकी उपाय धारा 65बी. संरक्षण अधिकार प्रबंध संबंधी जानकारी धारा 66. उल्लंघनकारी प्रतियों या प्लेटों का निपटान</p>	<p>6 माह से 3 वर्ष तक कारावास तथा 50 हजार से 2 लाख रुपये तक जुर्माना 1 से 3 वर्ष तक कारावास और 1 लाख से 2 लाख तक जुर्माना 7 दिन से तीन साल तक की कैद और 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना दो वर्ष तक का कारावास और जुर्माना ऊपर की तरह ऊपर के समान और भी उपलब्ध नागरिक उपचार न्यायालय द्वारा कॉपीराइट के स्वामी को दिया गया आदेश या उसके संबंध में उचित समझा गया आदेश</p>	<p>अनुभाग 70. अपराधों का संज्ञान.- मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी से निम्नतर कोई न्यायालय अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा</p>

	<p>उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने का उद्देश्य</p> <p>धारा 67. रजिस्टर आदि में झूठी प्रविष्टियां करना, झूठी प्रविष्टियां प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करना</p> <p>धारा 68. किसी प्राधिकारी या अधिकारी को धोखा देने या प्रभावित करने के उद्देश्य से झूठे बयान देना</p> <p>धारा 68ए. धारा 52ए के उल्लंघन के लिए जुर्माना</p> <p>धारा 69. कंपनियों द्वारा अपराध</p>	<p>ऐसी प्रतियों या प्लेटों का निपटान</p> <p>एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों</p> <p>ऊपर की तरह</p> <p>तीन साल तक की कैद और जुर्माना</p> <p>तदनुसार कार्यवाही की गई और दंडित किया गया</p>	
<p>निवेदन- देर उपाय- तों अध्याय चौदह (खंड- एनएस 71 टीओ 73)</p>	<p>धारा 71. मजिस्ट्रेट के कुछ आदेशों के विरुद्ध अपील</p> <p>धारा 72. कॉपीराइट रजिस्ट्रार और अपीलीय बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपील</p> <p>धारा 73. प्रक्रिया अपील</p>	<p>न्यायालय अपील के निपटारे तक आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश दे सकता है</p> <p>अपीलीय बोर्ड और उच्च न्यायालय में क्रमशः अपील</p>	<p>वह न्यायालय जिसमें अपील की जाती है अदालत आदेश बनाना</p> <p>आमतौर पर झूठ बोलना</p> <p>उच्च न्यायालय इस संबंध में नियम बना सकता है।</p> <p>धारा के तहत की गई अपीलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया</p> <p>72.</p>
<p>एडमिन- स्ट्रेटिव- इ उपाय- तों</p>	<p>धारा 6. कुछ विवादों का निर्णय अपील बोर्ड द्वारा किया जाएगा</p> <p>धारा 19ए. कॉपीराइट के हस्तांतरण के संबंध में विवाद</p>	<p>ऐसे असाइनमेंट को रद्द किया जा सकता है और/या देय किसी भी रॉयल्टी की वसूली की जा सकती है</p>	<p>अपील तख्ता गठित इस अनुभाग के अंतर्गत कॉपीराइट का 11 कानून</p>

तालिका नंबर एक

4.5 शब्दावली

1. सक्षम प्राधिकारी: सक्षम प्राधिकारी का अर्थ है किसी भी देश की किसी भी सरकार का कोई राष्ट्रीय या स्थानीय एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्री, मंत्रालय अधिकारी, संसद या सार्वजनिक या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) जिसका इस समझौते या यूरोपीय आयोग, प्रथम दृष्टया न्यायालय और यूरोपीय न्यायालय सहित पक्षों द्वारा परिकल्पित किसी भी गतिविधि पर अधिकार क्षेत्र हो।
176

2. धारा 51 (1) (एए): निम्नलिखित कार्य अनुच्छेद 2013 के उल्लंघन नहीं माने जाएंगे।

कॉपीराइट, अर्थात्,—

किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम की प्रतिलिपि के वैध स्वामी द्वारा, ऐसी प्रतिलिपि से, उसकी प्रतिलिपि बनाना या कम्प्यूटर प्रोग्राम का अनुकूलन करना—

- (a) कम्प्यूटर प्रोग्राम को उस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाने के लिए जिसके लिए उसे आपूर्ति किया गया था; या केवल उस उद्देश्य के लिए कम्प्यूटर
- (ii) प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए हानि, विनाश या क्षति के विरुद्ध अस्थायी संरक्षण के रूप में बैक-अप प्रतियां बनाने के लिए जिसके लिए उसे आपूर्ति किया गया था;

3. अनुकूलन: "अनुकूलन" का अर्थ है, (i) एक नाटकीय कार्य के संबंध में, कार्य को एक गैर-नाटकीय कार्य में बदलना; (ii) एक साहित्यिक कार्य या एक कलात्मक कार्य के संबंध में, सार्वजनिक रूप से या अन्यथा प्रदर्शन के माध्यम से कार्य को एक नाटकीय कार्य में बदलना; (iii) एक साहित्यिक या नाटकीय कार्य के संबंध में, कार्य का कोई संक्षिप्तीकरण या कार्य का कोई संस्करण जिसमें कहानी या क्रिया को पूरी तरह या मुख्य रूप से चित्रों के माध्यम से किसी पुस्तक में या समाचार पत्र, पत्रिका या इसी तरह के आवधिक में पुनरुत्पादन के लिए उपयुक्त रूप में व्यक्त किया जाता है; (iv) एक संगीत कार्य के संबंध में, कार्य की कोई व्यवस्था या प्रतिलेखन; 4 [और] 4 [(v) किसी भी कार्य के संबंध में, ऐसे कार्य का कोई उपयोग जिसमें इसकी पुनर्व्यवस्था या परिवर्तन शामिल है; 177

4. कॉपीराइट का हस्तांतरण¹⁷⁸: भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में यह प्रावधान है कि कॉपीराइट का स्वामी सीमित अवधि के लिए या कॉपीराइट की पूरी अवधि के लिए कुछ शर्तों और नियमों पर संपूर्ण कॉपीराइट का हस्तांतरण कर सकता है या अधिकारों का आंशिक हस्तांतरण कर सकता है। हस्तांतरण, जो अनुबंध की प्रकृति का है, लिखित रूप में होगा।

कॉपीराइट का हस्तांतरण तभी वैध है जब वह लिखित रूप में हो।¹⁷⁹

5. ट्रिप्स समझौता, अनुच्छेद 50 का पैरा 2: अनुच्छेद 50:2 के अनुसार न्यायिक प्राधिकारियों के पास "इनाउडिटा अल्टेरा पार्ट" (दूसरे पक्ष की सुनवाई के बाहर) अनंतिम उपाय अपनाने की शक्ति होनी चाहिए, जहां देरी से अपूरणीय क्षति हो सकती है।

इसका मतलब यह है कि आईपीआर धारक को तत्काल आदेश प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उल्लंघनकारी तरीके से काम करने वाले कथित पक्ष को सूचित किया जा सके या नहीं और उसे सुनवाई का अवसर दिया जा सके। इस स्थिति में, प्रभावित पक्ष को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए, और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और उठाए गए कदमों पर आपत्ति जतानी चाहिए।¹⁸⁰

¹⁷⁶ <https://www.lawinsider.com/dictionary/competent-authority>

¹⁷⁷ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (ए)

¹⁷⁸ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 18 और 19

¹⁷⁹ के.ए. वेणुगोपाल शेट्टी बनाम डॉ. सूर्यकांत यू. कामथ, एआईआर 1992, केईआर 11

¹⁸⁰ http://unctad.org/en/Docs/edmmisc232add18_en.pdf

4.6 एसएक्यूएस

8. लघु उत्तरीय प्रश्न

(vii) कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की कौन सी धारा कॉपीराइट के स्वामी को अधिकार देती है

लिखित लाइसेंस द्वारा अधिकार में रुचि?

(आठ) संगीतमय ध्वनि रिकॉर्डिंग में कई अधिकार धारक होते हैं। क्या प्रत्येक अधिकार धारक को लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है?

(ix) किसी संगीत कृति के संबंध में कॉपीराइट का प्रथम स्वामी कौन है? (x) क्या आयातक के निजी और घरेलू उपयोग के लिए

किसी कृति की एक प्रति का आयात करना उल्लंघन माना जाएगा? (xi) धारा 52 ए का क्या महत्व है? (xii) एक केबल ऑपरेटर को एक सिनेमैटोग्राफ

फिल्म प्रसारित की गई, जिसे जनता के

किसी भी सदस्य ने नहीं देखा।

देखें. क्या यह अभी भी जनता के लिए एक संचार है? (xiii)

कॉपीराइट उल्लंघन के अपराध के अंतर्गत दूसरी और बाद की सजा पर क्या दंड है?

(xiv) कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार किसके पास है? (xv) क्या कोई व्यक्ति सिविल और आपराधिक उपचार एक साथ प्राप्त कर सकता है?

9. रिक्त स्थान भरें

(चौदह) कॉपीराइट अधिनियम के विशेष प्रावधान लेखक की सत्यनिष्ठा के अधिकार के साथ-साथ पितृत्व के अधिकार को भी अक्षुण्ण रखते हैं और इस प्रकार लेखक की मृत्यु के बाद भी उसके सम्मान की रक्षा करते हैं।

(xv) यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई संबोधन या भाषण दिया है, तो ऐसा -----

----- कॉपीराइट का प्रथम स्वामी होगा।

(xvi) सिनेमैटोग्राफिक कार्यों के कॉपीराइट का उल्लंघन दो मुख्य रूपों में होता है,

अर्थात् ----- और -----.

(सत्रह) किसी कार्य की सभी प्रतियां, जिनमें कॉपीराइट विद्यमान है, उस कार्य के स्वामी की हैं।

(अठारह) धारा 71 मजिस्ट्रेट के कुछ आदेशों के विरुद्ध ----- का प्रावधान करती है।

(उन्नीस) कॉपीराइट के हस्तांतरण के संबंध में किसी भी विवाद में ----- अपना निर्णय देगा।

(xx) ----- पुलिस को उल्लंघनकारी प्रतियां जब्त करने की शक्ति देता है।

10. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न

(i) एक लेखक के पास एक ही कार्य में अनेक अधिकार होते हैं। (सत्य/असत्य)

(ii) परीक्षा के लिए तैयार प्रश्नपत्र कॉपीराइट संरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(सत्य/असत्य)

(iii) कॉपीराइट के माध्यम से रचनात्मकता को पुरस्कृत करना तथा सृजन पर विशेष अधिकार देना

अधिक सृजन करने तथा दूसरों को सृजन के लिए प्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है। (सत्य/असत्य)

(iv) भारत विभिन्न क्षेत्रों में समुद्री डकैती का केंद्र बन गया है। (सत्य/असत्य)

(v) साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य से संबंधित उल्लंघन के मामले में, यदि कार्य पर लेखक या प्रकाशक का नाम दिखाई देता है, तो

न्यायालय द्वारा उसे मूल नहीं माना जाएगा। (सत्य/असत्य)

(vi) भारतीय कॉपीराइट अधिनियम का अध्याय XII कॉपीराइट उल्लंघन के विरुद्ध दीवानी उपचार से संबंधित है।

कॉपीराइट का उल्लंघन. (सत्य/असत्य)

(vii) उप निरीक्षक स्तर का कोई भी पुलिस अधिकारी, यदि वह संतुष्ट हो कि किसी कार्य में कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में धारा 63 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह बिना वारंट के उल्लंघनकारी सभी सामग्री को जब्त कर सकता है। (सत्य/असत्य),

4.7 संदर्भ

1. <http://copyright.gov.in/documents/handbook.html>
2. ट्रिप्स समझौता
3. बौद्धिक संपदा अधिकार और कानून, डॉ. जीबी रेड्डी, गोगिया लॉ एजेंसी, हैदराबाद
4. बौद्धिक संपदा कानून, डॉ. सीपी सिंह; इलाहाबाद विधि एजेंसी प्रकाशन
5. http://unctad.org/en/Docs/edmmisc232add18_en.pdf
6. <http://www.copyright.gov.in/Documents/CopyrightRules1957.pdf>
7. <https://www.lawinsider.com/dictionary/competent-authority>

4.8 सुझाए गए पठन सामग्री

1. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957
2. बौद्धिक संपदा अधिकार और कानून, डॉ. जीबी रेड्डी, गोगिया लॉ एजेंसी, हैदराबाद
3. बौद्धिक संपदा कानून, डॉ. सीपी सिंह; इलाहाबाद विधि एजेंसी प्रकाशन
4. ट्रिप्स समझौता 5. <http://copyright.gov.in/documents/handbook.html>

4.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. कॉपीराइट के स्वामी को कौन-कौन से अनन्य अधिकार प्राप्त हैं? संक्षेप में समझाइए।
2. कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत कॉपीराइट के उल्लंघन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें।
3. किसी रचना के लेखक को कौन से नैतिक अधिकार दिए गए हैं?
4. उन कार्यों का वर्णन करें जो जनता से संचार के अर्थ में आते हैं और कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं।
5. ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों के संबंध में विशेष प्रावधान क्या हैं?
क्या इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है?
6. भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी और अच्छी स्वदेशी पुस्तकों की चोरी प्रचलित है और मौसमी प्रकृति के हैं। टिप्पणी करें।
7. भारत में उल्लंघनकारी प्रतियों के आयात के संबंध में क्या प्रावधान हैं?
8. कौन से कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे?
9. वास्तुकला के कार्यों के मामले में सिविल उपचार उपलब्ध नहीं हैं। टिप्पणी करें।
10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें:
(*) निवारक नागरिक उपचार
(ii) क्षतिपूर्ति नागरिक उपचार

(iii) एंटोन स्तम्भ आदेश (iv)

पृथक अधिकारों का संरक्षण (v)

अपीलीय उपचार (vi) प्रशासनिक

उपचार

(vii) धारा 63 के अपराध के अंतर्गत उल्लंघनकारी प्रतियों को जब्त करने की पुलिस की शक्ति

(viii) धारा- 65ए और 65बी

11. क्या कॉपीराइट का स्वामी कार्यवाही में पक्षकार हो सकता है? संबंधित प्रावधान बताइए।

12. भारतीय दंड संहिता के तहत किसी कृति के स्वामी के लिए उपलब्ध अपराधिक उपचार क्या हैं?

कॉपीराइट अधिनियम?

13. यदि कोई फर्म भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो क्या उसका अपराध माना जाएगा?

क्या कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसा करना दंडनीय है?

4.10 उत्तर

एसएक्यूएस

1. (i) धारा 30; 4.3.2.1.1 देखें; (ii) हां; 4.3.2.1.1 देखें; (iii) संगीतकार; 4.3.2.1.1 देखें; (iv) हां; 4.3.2.1 देखें; (v) ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान किए गए ; धारा 4.3.2.1.5 देखें; (vi) हां; 4.3.2.1.3 देखें;

(vii) 1 से 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना; 4.3.4.2.1 देखें; (viii)

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट; 4.3.4.2 देखें; 4.3.4.5 देखें;

(ix)हां;

2. (i) धारा 57; देखें 4.3.2.1.2.2; 'वीडियो पाइरेसी', (ii) अन्य व्यक्ति; 4.3.2.1.1 देखें; (iii) 'केबल पाइरेसी'; देखें 4.3.2.1.4; (iv) संपत्ति; देखें 4.3.4.1.6; (v) अपील; देखें 4.3.4.4.1; (vii) (vi) अपील बोर्ड; 4.3.4.3 देखें;

धारा 64; 4.3.4.2.9 देखें;

3. (i) सत्य; देखें 4.3.2.1.2.1; (ii) असत्य; देखें 4.3.1; (iii) सत्य; देखें 4.3.1; (iv) सत्य; देखें 4.3.2.1.4; (v) असत्य; देखें 4.3.4.1.3; (vi) सत्य; देखें 4.3.4.1; (vii) सत्य; देखें 4.3.4.2.9;

अंतिम प्रश्न और आधुनिक प्रश्न

1. 4.3.2.1.2 देखें;

2. 4.3.2.1 देखें;

3. 4.3.2.1.2.2 देखें;

4. 4.3.2.1.3 देखें;

5. 4.3.2.1.5 और 4.3.4.2.6 देखें ;

6. 4.3.2.1.4 देखें;

7. 4.3.2.1.6 देखें;

8. 4.3.3 देखें;

9. 4.3.4.1.9 देखें;

10. (i) 4.3.4.1 देखें (ii) 4.3.4.1 देखें (iii) 4.3.4.1.4 देखें (iv) 4.3.4.1.7 देखें (v) 4.3.4.4 देखें

(vi) 4.3.4.3 देखें (vii) 4.3.4.2.9 देखें (viii) 4.3.4.2.8 देखें 11. 4.3.4 देखें;

12. 4.3.4.2 देखें;

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [107]

13. 4.3.4.2.7 देखें;

इकाई-5

पेटेंट को समझना

संरचना

5.1. परिचय

5.2. उद्देश्य

5.3. विषय

5.3.1. पेटेंट का अर्थ

5.3.2. 'पेटेंट' शब्द की उत्पत्ति

5.3.3. पेटेंट की आवश्यकताएं

5.3.3.1. नया आविष्कार

5.3.3.2. आविष्कारक कदम

5.3.3.3. औद्योगिक अनुप्रयोग

5.3.4. भारतीय पेटेंट कानून

5.3.5. उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट

5.3.6. आविष्कार जो पेटेंट योग्य नहीं हैं

5.3.7. पेटेंट नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी

5.3.8. पेटेंट कार्यालय और उसकी शाखाएँ

5.3.9. पेटेंट प्रक्रिया

5.3.9.1. पेटेंट आवेदन दाखिल करना

5.3.9.2. पेटेंट आवेदक

5.3.9.1.2. आविष्कार की एकता

5.3.9.1.3. दाखिल करने का स्थान

5.3.9.1.4. दाखिल करने की भाषा और प्रारूप 5.3.9.1.5. आवेदन का

प्रारूप 5.3.9.1.6. अनंतिम और पूर्ण विनिर्देश

5.3.9.1.7. प्राथमिकता तिथि

5.3.9.2. पेटेंट आवेदन की जांच

5.3.9.3. पेटेंट आवेदन का प्रकाशन

5.3.9.4. अनुदान-पूर्व विरोध

5.3.9.5. पेटेंट अनुदान और प्रकाशन

5.3.10. पेटेंटधारक के अधिकार

5.4. सारांश

5.5.एसएक्यूएस

5.6. संदर्भ

5.7. सुझाए गए पठन सामग्री

5.8. अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

5.1. परिचय

बौद्धिक संपदा की अवधारणा के रूप में पेटेंट ज्ञान आधारित उद्योगों के लिए एक संसाधन है। यह पहलू दुनिया भर में अच्छी तरह से पहचाना जाता है। पेटेंट कानून का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक भलाई के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देना है। यह आविष्कारकों को सीमित समय के लिए उनके आविष्कारों पर विशेष अधिकार प्रदान करके इस उद्देश्य को प्राप्त करता है। आविष्कारकों को विशेष अधिकार प्रदान करके, कानून उन्हें और निवेशकों को अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पेटेंट किसी विचार के लिए नहीं दिया जाता है, चाहे वह कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, बल्कि इसे लागू करने के नए, उपयोगी और आविष्कारशील तरीके के लिए दिया जाता है। पेटेंट एक पुरस्कार है जो विचार को शामिल करने वाले बौद्धिक इनपुट को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।

5.2. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- पेटेंट का अर्थ जानें।
- पेटेंट की अनिवार्यता को समझें।
- उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट का निर्धारण
- पेटेंट योग्य आविष्कारों की विषयवस्तु का पता लगाएं।
- पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया और पेटेंटधारक के अधिकारों को समझना।

5.3 विषय

5.3.1.पेटेंट का अर्थ

पेटेंट एक एकाधिकार अधिकार है जो पेटेंट कार्यालय द्वारा आविष्कारक को सीमित अवधि के लिए अपने आविष्कार का उपयोग करने के लिए दिया जाता है। इस अवधि के दौरान आविष्कारक को अपने आविष्कार का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने से किसी और को बाहर रखने का अधिकार है। आविष्कारक के अनन्य अधिकारों का उपयोग आविष्कारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आविष्कारक की पूर्व अनुमति या प्राधिकरण के साथ किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को पेटेंट दिया जाता है उसे पेटेंटधारक के रूप में जाना जाता है। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 (1) (एम) के अनुसार 'पेटेंट' का अर्थ इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी आविष्कार के लिए पेटेंट है।

5.3.2. 'पेटेंट' शब्द की उत्पत्ति

'पेटेंट' शब्द की उत्पत्ति "लेटर पेटेंट" शब्द से हुई है। "लेटर पेटेंट" का मतलब बंद पत्रों से अलग खुले पत्र थे। ये इंग्लैंड के राजा की महान मुहर के तहत क्राउन द्वारा अपने सभी नागरिकों को संबोधित किए जाने वाले दस्तावेज थे, जिसमें क्राउन राज्य में एक या अधिक व्यक्तियों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता था। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में कला, प्रक्रिया, निर्माण की विधि या तरीके, मशीनरी, उपकरण और अन्य पदार्थों के क्षेत्र में नए आविष्कार बढ़ रहे थे, जो निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए गए थे और आविष्कारक इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि उनके द्वारा किए गए आविष्कारों का किसी और द्वारा नकल करके या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई विधियों को अपनाकर उल्लंघन न किया जाए। आविष्कारकों के हितों की रक्षा के लिए, तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 को अधिनियमित किया।

5.3.3. पेटेंट की आवश्यकताएं

पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, पेटेंट योग्य होने के लिए किसी आविष्कार का नया होना आवश्यक है। या नवीन, इसमें आविष्कारी कदम शामिल है और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए।

5.3.3.1. नया आविष्कार

'नया आविष्कार' का अर्थ है कोई ऐसा आविष्कार या तकनीक जिसका किसी दस्तावेज़ में प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है या जिसका उपयोग देश में या दुनिया में कहीं और पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तिथि से पहले नहीं किया गया है। कोई आविष्कार तभी पेटेंट योग्य होता है जब वह पूर्व कला के प्रकाश में नया या नवीन हो, या पूर्व कला द्वारा पूर्वानुमानित न हो। पूर्व कला में आविष्कार से संबंधित सभी जानकारी और ज्ञान शामिल हैं जो पेटेंट आवेदन की तिथि पर उपलब्ध थे।

यदि कोई आविष्कार किसी दस्तावेज़ में प्रकाशित हो या विश्व में कहीं भी उपयोग किया जाए, तो उसे पूर्व कला या सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा माना जाएगा, और इसलिए उसे नवीन नहीं माना जाएगा।

यदि कोई आविष्कार नया है, तो यह पता लगाने के लिए आगे की जांच की जानी चाहिए कि क्या यह "पर्याप्त रूप से नया" है, जो कि कला में सामान्य कौशल वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं है।

नवीनता या आविष्कारशील कदम की आवश्यकताओं के परीक्षण के लिए कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक नहीं हैं। नवीनता और आविष्कारशील कदम के मानक देश-दर-देश और समय-समय पर भिन्न होते हैं। ट्रिप्स समझौते में नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए परिभाषा की कमी को देखते हुए, इन अवधारणाओं को परिभाषित करने का काम सदस्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों पर छोड़ दिया गया है।

5.3.3.2. आविष्कारक कदम

पेटेंट अधिनियम के तहत आविष्कारक कदम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "आविष्कार की वह विशेषता जिसमें मौजूदा ज्ञान की तुलना में तकनीकी उन्नति शामिल है या जिसका आर्थिक महत्व है या दोनों हैं और जो आविष्कार को कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट बनाता है।" आविष्कार उस कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं होना चाहिए जिससे वह आविष्कार संबंधित है।

5.3.3.3. औद्योगिक अनुप्रयोग

आविष्कार नया और अस्पष्ट होने के अलावा उपयोगी भी होना चाहिए। एक आविष्कार जो नया और अस्पष्ट है लेकिन जिसे मानव जाति के किसी भी लाभकारी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। हालाँकि, कुछ देशों में इतने उपयोगी आविष्कारों को 'उपयोगिता मॉडल' के रूप में संरक्षित किया जाता है। लेकिन भारत में उस अवधारणा को वैधानिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। आविष्कार अवश्य ही उपयोगी होना चाहिए।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [111]

औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम। इसका मतलब है कि आविष्कार उद्योग में बनाया या इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आविष्कार जो औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम नहीं है, वह भारत में पेटेंट योग्य नहीं है।

5.3.4. भारतीय पेटेंट कानून

पेटेंट पर वर्तमान कानून पेटेंट अधिनियम, 1970 है। यह 20 अप्रैल, 1972 को लागू हुआ। पेटेंट अधिनियम, 1970 को 1999 में पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे 1 जनवरी, 1995 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। संशोधित अधिनियम में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि-रसायनों के क्षेत्र में पेटेंट उत्पादों के लिए आवेदन दाखिल करने का प्रावधान किया गया था। हालाँकि, ऐसे आवेदनों की जाँच 31 दिसंबर, 2004 के बाद ही की गई थी।

पेटेंट अधिनियम, 1970 में दूसरा संशोधन पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1970 के माध्यम से किया गया था।

यह संशोधन अधिनियम 20 मई, 2002 को पेटेंट नियम, 1972 के स्थान पर नए पेटेंट नियम, 2003 की शुरुआत के साथ लागू हुआ।

पेटेंट अधिनियम, 1970 में तीसरा संशोधन पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के माध्यम से 1 जनवरी, 2005 से लागू किया गया था। इस अध्यादेश को बाद में पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे 1 जनवरी, 2005 से लागू किया गया।

भारतीय पेटेंट अधिनियम में किए गए प्रमुख परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों के प्रति भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक थे। नए पेटेंट अधिनियम (पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005) ने भारत में एक मजबूत पेटेंट प्रणाली बनाई है। कुल मिलाकर वर्तमान अधिनियम ने पेटेंटिंग के दायरे को बढ़ाया है और पेटेंटधारक को कड़े सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। नया अधिनियम प्रौद्योगिकी संचालित बाजार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

5.3.5. उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट

पेटेंट किसी ऐसे आविष्कार के लिए दिया जाता है जो उत्पाद या प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन ऐसा उत्पाद या प्रक्रिया नई होनी चाहिए, इसमें आविष्कारक कदम शामिल होने चाहिए और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए। पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 से पहले, भारत में खाद्य, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में केवल प्रक्रिया पेटेंट दिए जाते थे। पदार्थों के संबंध में कोई उत्पाद पेटेंट नहीं दिया गया था। थॉमसन ब्रांट बनाम पेटेंट नियंत्रक मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि 'निर्माण की प्रक्रिया' निर्माण द्वारा उत्पादित पदार्थ से स्वतंत्र है। निर्माण की प्रक्रिया की अपनी एक विशेष पहचान होती है, जो निर्माण के उत्पाद से जुड़ी नहीं होती।

5.3.6. आविष्कार जो पेटेंट योग्य नहीं हैं

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 4 में निम्नलिखित वस्तुओं की सूची दी गई है जो भारत में पेटेंट योग्य नहीं हैं।

1. ऐसा आविष्कार जो तुच्छ हो या जो सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत कुछ दावा करता हो प्राकृतिक कानून.
2. ऐसा आविष्कार जिसका उपयोग नैतिकता के विपरीत हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या जो मानव, पशु या पौधे के जीवन या स्वास्थ्य या पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता हो।

3. मात्र एक वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज या एक अमूर्त सिद्धांत का निर्माण या प्रकृति में पाए जाने वाले किसी भी जीवित वस्तु या निर्जीव पदार्थ की खोज।
4. किसी ज्ञात पदार्थ के किसी नए गुण या नए उपयोग की खोज मात्र या किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण का उपयोग मात्र, जब तक कि ऐसे ज्ञात पदार्थ के परिणामस्वरूप कोई नया उत्पाद न बने या कम से कम एक नया अभिकारक काम में न आए।
5. मात्र मिश्रण से प्राप्त पदार्थ जिसके परिणामस्वरूप केवल समग्र गुण होते हैं
उसके घटकों या ऐसे पदार्थ के उत्पादन की प्रक्रिया का विवरण।
6. ज्ञात उपकरणों की कार्यप्रणाली की मात्र व्यवस्था, पुनर्व्यवस्था या दोहराव
एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक ज्ञात तरीके से।
7. विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान लागू परीक्षण की एक विधि या प्रक्रिया, जिससे मशीन, उपकरण या अन्य उपकरण अधिक कुशल बन जाते हैं, या विनिर्माण के सुधार या नियंत्रण के लिए विद्यमान मशीन, उपकरण या अन्य उपकरण के सुधार या पुनरुद्धार के लिए।
8. कृषि या बागवानी की एक विधि।
9. मनुष्यों के औषधीय, शल्य चिकित्सा, रोगहर, रोगनिरोधी या अन्य उपचार के लिए कोई प्रक्रिया या पशुओं के समान उपचार के लिए कोई प्रक्रिया जिससे उन्हें रोग मुक्त किया जा सके या उनके या उनके उत्पादों के आर्थिक मूल्य में वृद्धि की जा सके।
10. सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सम्पूर्ण पौधे और प्राणी या उनका कोई भाग, किन्तु इसके अंतर्गत बीज, किस्में और प्रजातियाँ तथा पौधों और प्राणियों के उत्पादन या प्रवर्धन के लिए अनिवार्यतः जैविक प्रक्रियाएँ भी हैं।
11. एक गणितीय या व्यावसायिक विधि या एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम।
12. कोई साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य या कोई भी अन्य सौंदर्यात्मक रचना
सिनेमैटोग्राफिक कार्य और टेलीविजन निर्माण सहित;
13. मानसिक कार्य करने की मात्र योजना या नियम या विधि या खेल खेलने की विधि;
14. सूचना का प्रस्तुतीकरण;
15. एकीकृत सर्किट की स्थलाकृति;
16. ऐसा आविष्कार जो वस्तुतः परम्परागत ज्ञान है या जो परम्परागत रूप से ज्ञात घटकों या घटकों के ज्ञात गुणों का एकत्रीकरण या दोहराव है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा से संबंधित किसी आविष्कार के संबंध में कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया जाएगा।

5.3.7. पेटेंट नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 3 के तहत नियुक्त पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक को पेटेंट नियंत्रक होना चाहिए। केंद्र सरकार जितने परीक्षक और अन्य अधिकारी उचित समझे, उन्हें नियुक्त कर सकती है। ऐसे अधिकारियों को नियंत्रक द्वारा निर्धारित कार्यों का निर्वहन करना होगा और उनके अधीक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना होगा। नियंत्रक किसी अधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को लिखित आदेश द्वारा और दर्ज किए जाने वाले कारणों से वापस ले सकता है और ऐसे मामले को शुरू से या जिस चरण में इसे वापस लिया गया था, उस चरण से खुद ही निपटा सकता है। वह मामले को किसी अन्य अधिकारी को हस्तांतरित भी कर सकता है और ऐसे अधिकारी को मामले की शुरुआत से या जिस चरण में इसे वापस लिया गया था, उस चरण से जांच करने का निर्देश दे सकता है।

5.3.8. पेटेंट कार्यालय और उसकी शाखाएँ

पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कोलकाता में है। केंद्र सरकार ने मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई में पेटेंट कार्यालय की शाखाएँ भी स्थापित की हैं। पेटेंट सूचना प्रणाली का कार्यालय नागपुर में है। पेटेंट कार्यालय की अपनी मुहर होती है।

5.3.9. पेटेंट प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति पेटेंट कार्यालय में पेटेंट आवेदन दाखिल करके भारत में पेटेंट प्राप्त कर सकता है। पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

1. पेटेंट आवेदन दाखिल करना।
2. आवेदन की जांच
3. पेटेंट आवेदन का प्रकाशन
4. अनुदान-पूर्व विरोध और प्रतिनिधित्व
5. पेटेंट अनुदान और प्रकाशन; और
6. अनुदान के बाद विरोध.

5.3.9.1. पेटेंट आवेदन दाखिल करना

5.3.9.1.1. पेटेंट आवेदक

भारत में, पेटेंट आवेदन किसी प्राकृतिक और/या कानूनी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है। आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है:

- क. सच्चा और पहला आविष्कारक;
- ख. आविष्कारक का समनुदेशिनी; या ग.
आविष्कारक का कानूनी प्रतिनिधि।

कोई भी व्यक्ति जो किसी आविष्कार का सच्चा आविष्कारक होने का दावा करता है, वह पेटेंट आवेदन दाखिल कर सकता है। सच्चा और पहला आविष्कारक का मतलब है वह व्यक्ति जो आविष्कार की कल्पना करता है। कोई व्यक्ति जो किसी आविष्कार को वित्तपोषित करता है लेकिन आविष्कार की कल्पना करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है, उसे आविष्कारक नहीं माना जा सकता। लेकिन उसे किसी कर्मचारी के नियोक्ता से अलग माना जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रोजगार के तहत और रोजगार के दौरान कुछ आविष्कार करता है तो नियोक्ता को आविष्कार का आविष्कारक माना जाएगा और वह पेटेंट कार्यालय में पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है।

आविष्कार का एक असाइनी भी पेटेंट आवेदन दायर कर सकता है, यदि वास्तविक और पहला आविष्कारक असाइनी को आविष्कार सौंपता है। असाइनी कोई कंपनी, फर्म या कोई अन्य कानूनी व्यक्ति हो सकता है। पेटेंट आवेदन दाखिल करते समय असाइनी को आवेदन दाखिल करने के अपने अधिकार को साबित करने के लिए आविष्कारक द्वारा निष्पादित असाइनमेंट डीड को पेटेंट कार्यालय में जमा करना होगा।

मृत आविष्कारक का कानूनी प्रतिनिधि भी पेटेंट आवेदन दायर कर सकता है।

इसके अलावा, यदि आविष्कार के एक से अधिक आविष्कारक या समनुदेशिनी हों तो पेटेंट आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया जा सकता है।

5.3.9.1.2. आविष्कार की एकता

पेटेंट आवेदन केवल एक आविष्कार या किसी एकल आविष्कारात्मक अवधारणा से संबंधित आविष्कारों के समूह के लिए दायर किया जा सकता है। यदि पेटेंट आवेदन में एक से अधिक आविष्कार या संबंधित हैं

एक से अधिक आविष्कारों से संबंधित या एक से अधिक आविष्कारात्मक अवधारणा से संबंधित है, तो प्रत्येक आविष्कार या आविष्कारात्मक अवधारणा के संबंध में अलग-अलग आवेदन दायर करने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि A पेन और पेन होल्डर से संबंधित पेटेंट आवेदन दायर करता है, तो A को दो अलग-अलग आवेदन दायर करने होंगे क्योंकि पेन और पेन होल्डर दो अलग-अलग आविष्कार हैं। हालाँकि, यदि A पेन और पेन बनाने की प्रक्रिया से संबंधित पेटेंट आवेदन दायर करता है, तो A को अलग-अलग आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पेन और पेन बनाने की प्रक्रिया एक ही आविष्कारात्मक अवधारणा से संबंधित है।

5.3.9.1.3. दाखिल करने का स्थान

पेटेंट आवेदन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्थित किसी भी उपयुक्त पेटेंट कार्यालय में दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक पेटेंट कार्यालय का अपना क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होता है।

पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए उपयुक्त पेटेंट कार्यालय उस क्षेत्र पर आधारित होता है जिसमें:

(क) आवेदक या पेटेंट के लिए संयुक्त आवेदकों के मामले में प्रथम उल्लिखित आवेदक, सामान्यतः

निवास करता है या उसका अधिवास है या उसका व्यवसाय का स्थान है या वह स्थान है जहां से आविष्कार किया गया था वास्तव में उत्पन्न हुआ; या

(ख) पेटेंट के लिए आवेदक या कार्यवाही में पक्षकार यदि उसके पास कोई व्यवसाय स्थान या निवास स्थान नहीं है

भारत में, ऐसे आवेदक या पक्ष द्वारा तामील के लिए दिया गया पता स्थित है; और

अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के संबंध में एक बार निर्धारित उपयुक्त कार्यालय को सामान्यतः नहीं बदला जाएगा।

5.3.9.1.4. फाइलिंग की भाषा और प्रारूप

पेटेंट आवेदन और संबंधित दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में दाखिल किए जाने चाहिए, जब तक कि नियंत्रक अन्य भाषाओं में दाखिल करने की अनुमति न दे। ऐसे दस्तावेज गहरे अमिट स्याही से बड़े और सुपाठ्य अक्षरों में लिखे, टाइप किए, लिथोग्राफ किए या मुद्रित होने चाहिए।

5.3.9.1.5. आवेदन का प्रारूप

आवेदन सीधे भारतीय पेटेंट कार्यालय में या पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत राष्ट्रीय चरण के आवेदन के रूप में या किसी अन्य देश में प्रथम आवेदन दाखिल करने के बाद कन्वेंशन आवेदन के रूप में दाखिल किया जा सकता है, जिसे पेटेंट अधिनियम के तहत कन्वेंशन देश के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कन्वेंशन आवेदन एक पेटेंट आवेदन है जिसे कन्वेंशन देश में पहले दाखिल किए जाने के बाद भारत में पेटेंट कार्यालय में दाखिल किया जाता है। कन्वेंशन देश वह देश होता है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या द्विपक्षीय संधि, कन्वेंशन या व्यवस्था पर हस्ताक्षरकर्ता या पक्षकार होता है, जिस पर भारत भी हस्ताक्षरकर्ता या पक्षकार होता है और जो भारत में पेटेंट के लिए आवेदकों या भारत के नागरिकों को पेटेंट प्रदान करने और पेटेंट अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अपने नागरिकों या अपने सदस्य देशों के नागरिकों को दिए जाने वाले समान विशेषाधिकार प्रदान करता है।

पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत पेटेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवेदन एक ऐसा आवेदन है जो भारत को नामित करता है और पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय चरण के पूरा होने के बाद भारतीय पेटेंट कार्यालय में दायर किया जाता है। इसके अलावा, पीसीटी आवेदन के एक भाग के रूप में दायर विनिर्देश को भारत में दायर एक पूर्ण विनिर्देश के रूप में माना जाएगा। पीसीटी राष्ट्रीय चरण आवेदन दाखिल करने की तिथि पीसीटी आवेदन की दाखिल करने की तिथि या प्राथमिकता होगी। भारतीय पेटेंट

कार्यालय पीसीटी राष्ट्रीय चरण आवेदन की जांच पीसीटी आवेदन की प्राथमिकता तिथि से 31 महीने के बाद ही शुरू करेगा।

5.3.9.1.6. अनंतिम और पूर्ण विनिर्देश

विनिर्देशन बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् विवरण और दावा। विवरण आविष्कार का खुलासा करता है जबकि दावा एकाधिकार अधिकारों के दायरे को चिह्नित करता है जो पेटेंट दिए जाने की स्थिति में पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रदान किए जाने की संभावना है। पेटेंट के लिए आवेदन के साथ एक अनंतिम या पूर्ण विनिर्देशन होना चाहिए। जहां पेटेंट के लिए आवेदन के साथ एक अनंतिम विनिर्देशन है, वहां आवेदन दाखिल करने की तारीख से 12 महीने के भीतर एक पूर्ण विनिर्देशन दाखिल किया जाना चाहिए। यदि पूर्ण विनिर्देशन दाखिल नहीं किया जाता है, तो आवेदन को छोड़ दिया गया माना जाएगा। अनंतिम विनिर्देशन दाखिल करने का उद्देश्य प्राथमिकता तिथि तय करना है। अनंतिम विनिर्देशन और पूर्ण विनिर्देशन दाखिल करने की अवधि के बीच, आविष्कारक आगे अनुसंधान कर सकता है और अपने आविष्कार में सुधार कर सकता है। इंपीरियल केमिकल लिमिटेड के आवेदन में यह कहा गया था कि एक अनंतिम विनिर्देशन में आविष्कार की सामान्य प्रकृति, इसके आवेदन के क्षेत्र और प्रत्याशित परिणाम का केवल विवरण होना चाहिए।

5.3.9.1.7. प्राथमिकता तिथि

प्राथमिकता तिथि वह पहली फाइलिंग तिथि है, जो पेटेंट कार्यालय द्वारा किसी आवेदन को आवंटित की जाती है। प्राथमिकता तिथि किसी आविष्कार की नवीनता और गैर-स्पष्टता का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण तिथि है जो पेटेंट आवेदन का हिस्सा बनती है। पूर्ण विनिर्देशन के प्रत्येक दावे की एक प्राथमिकता तिथि होगी। यदि अनंतिम प्रमाणन के बाद पूर्ण विनिर्देशन दायर किया जाता है, तो पूर्ण विनिर्देशन में दावे की प्राथमिकता तिथि अनंतिम विनिर्देशन के साथ आवेदन दाखिल करने की तिथि होगी, जिसमें दावे की विषय-वस्तु शामिल होती है।

5.3.9.2. पेटेंट आवेदन की जांच

पेटेंट आवेदन दाखिल होने के बाद, पेटेंट कार्यालय पेटेंट अधिनियम और नियमों के तहत पेटेंट अनुदान के लिए आवेदन की पात्रता की जांच करेगा। जांच की प्रक्रिया जांच के अनुरोध से शुरू होती है और जांच और फिर आवेदन के अनुदान या अस्वीकृति तक आगे बढ़ती है। पेटेंट आवेदन की जांच नियंत्रक द्वारा पेटेंट परीक्षक के साथ समन्वय में की जाती है। जांच के लिए अनुरोध प्राप्त करने के बाद, नियंत्रक आवेदन को प्रकाशन की तारीख या आवेदन प्राप्त करने की तारीख से आम तौर पर एक महीने के भीतर जांच के लिए संदर्भित करता है, आवेदन की समीक्षा करेगा और इसके संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षक आवेदन की समीक्षा करेगा और निर्णय देगा।

निम्नलिखित की रिपोर्ट:

1. क्या आवेदन का प्रारूप और विनिर्देशन, नियम एवं शर्तों के अनुरूप हैं?
पेटेंट अधिनियम और नियमों की आवश्यकताएं;
2. क्या आविष्कार जो पेटेंट आवेदन का हिस्सा है, वह विषय-वस्तु, औद्योगिक प्रयोज्यता, नवीनता, आविष्कारात्मक कदम और विनिर्देशन जैसी पेटेंट योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करता है, और

3. क्या आवेदन किसी अन्य आवश्यकता जैसे आविष्कार की एकता की पुष्टि करता है

अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित अन्य प्रावधान।

परीक्षक को नियंत्रक द्वारा संदर्भित तिथि से एक से तीन महीने के भीतर नियंत्रक को परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। नियंत्रक रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और परीक्षक से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर नियंत्रक को परीक्षक की परीक्षा रिपोर्ट का निपटान करेगा। नियंत्रक को परीक्षक की रिपोर्ट गोपनीय होती है और सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुली नहीं होती है। परीक्षक की पहली रिपोर्ट नियंत्रक द्वारा पेटेंट आवेदक को भेजी जाएगी और इसे पहली परीक्षा रिपोर्ट (FER) कहा जाता है।

एफईआर प्राप्त करने के बाद, पेटेंट आवेदक को नियंत्रक को आश्वस्त करना होगा और आवेदन की तिथि से बारह महीने के भीतर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा। एफईआर आवेदक के अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। यदि एफईआर अनुकूल है, तो पेटेंट आवेदन को नियंत्रक द्वारा अनुमति दी जाएगी और अनुदान दिया जाएगा। हालांकि, यदि एफईआर प्रतिकूल है, तो आपत्तियों का सार रिपोर्ट में बताया जाएगा और आवेदक को सूचित किया जाएगा। एक प्रतिकूल रिपोर्ट में दो स्तरों पर आपत्तियां शामिल हो सकती हैं, अर्थात् आवेदन या विनिर्देश या शुल्क के प्रारूप से संबंधित औपचारिक आपत्तियां, और अधिनियम के तहत पेटेंट योग्यता आवश्यकताओं या किसी अन्य आवश्यकताओं से संबंधित वास्तविक आपत्तियां। नियंत्रक आवेदक को आपत्तियों को दूर करने के लिए आवेदन में संशोधन करने की आवश्यकता कर सकता है। आवेदक आपत्तियों का विरोध भी कर सकता है।

वह आपत्तियों को स्वीकार न करने के कारण बताते हुए जांच रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया लिखकर ऐसा कर सकता है। आवेदक जांच रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों को समझने के लिए सुनवाई का अनुरोध भी कर सकता है। आवेदक आवेदन दाखिल करने के बाद और पेटेंट दिए जाने से पहले किसी भी समय आवेदन वापस भी ले सकता है।

5.3.9.3 पेटेंट आवेदन का प्रकाशन

पेटेंट कार्यालय में दायर पेटेंट आवेदन को प्रकाशित होने तक गुप्त रखा जाएगा।

आवेदन प्राथमिकता तिथि या आवेदन दाखिल करने की तिथि से अठारह महीने की समाप्ति पर प्रकाशित किया जाता है, जो भी पहले हो। नियंत्रक आम तौर पर 18 महीने की समाप्ति के एक महीने के भीतर आवेदन प्रकाशित करता है। यदि कोई आवेदक 18 महीने की अवधि से पहले अपना आवेदन प्रकाशित करना चाहता है, तो वह नियंत्रक को जल्दी प्रकाशन के लिए आवेदन कर सकता है और नियंत्रक आम तौर पर ऐसे आवेदन की तारीख से एक महीने के भीतर आवेदन प्रकाशित करेगा।

पेटेंट आवेदन प्रकाशित नहीं किया जाता है यदि,

1. आवेदन के संबंध में गोपनीयता निर्देश जारी किए जाते हैं क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित है।
ऊर्जा या रक्षा प्रयोजनों के लिए;
2. आवेदन को त्याग दिया गया है; या,
3. आवेदन को प्राथमिकता या दाखिल तिथि से अठारह महीने की समाप्ति से तीन महीने पहले वापस ले लिया गया हो।

आवेदन के प्रकाशन में निम्नलिखित शामिल है

1. आवेदन की तिथि;
2. आवेदन संख्या;
3. आवेदक का नाम और पता; और
4. सार.

आवेदन के प्रकाशन पर:

पेटेंट कार्यालय आवेदन के विनिर्देश और चित्र को शुल्क लेकर जनता के लिए उपलब्ध कराएगा, और,

यदि आवेदन में जमा राशि शामिल है, तो डिपॉजिटरी संस्था आवेदन में उल्लिखित जैविक सामग्री को जनता के लिए उपलब्ध कराएगी।

पेटेंट आवेदक के अधिकार पेटेंट आवेदन के प्रकाशन की तारीख से शुरू होते हैं। हालाँकि, उल्लंघन का मुकदमा पेटेंट मिलने के बाद ही दायर किया जा सकता है।

5.3.9.4. अनुदान-पूर्व विरोध

पेटेंट प्रदान करने के लिए विरोध पेटेंट प्रदान करने से पहले या बाद में दायर किया जा सकता है। पेटेंट दिए जाने से पहले दायर किए गए विरोध को प्री-ग्रांट विरोध कहा जाता है और पेटेंट दिए जाने के बाद दायर किए गए विरोध को पोस्ट-ग्रांट विरोध कहा जाता है। पेटेंट आवेदन प्रकाशित होने के बाद, कोई भी व्यक्ति आविष्कार पर पेटेंट दिए जाने के खिलाफ नियंत्रक के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर कर सकता है जो आवेदन का हिस्सा है। पेटेंट नियमों के अनुसार, पेटेंट कार्यालय प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर पेटेंट नहीं दे सकता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दायर करने के लिए न्यूनतम समय प्रकाशन की तारीख से छह महीने है।

निम्नलिखित आधारों पर अभ्यावेदन दायर किया जा सकता है:

1. पेटेंट के लिए आवेदक ने गलत तरीके से आविष्कार प्राप्त किया।
2. पेटेंट आवेदन का हिस्सा बनने वाले आविष्कार में नवीनता और/या आविष्कारशीलता का अभाव है कदम।
3. पेटेंट पेटेंट योग्य विषय वस्तु नहीं है।
4. विनिर्देश में पर्याप्त प्रकटीकरण का अभाव है या सक्षम नहीं है।
5. आवेदक ने आवेदन से संबंधित गलत जानकारी रोकी या बताई। पेटेंट कार्यालय।
6. किसी कन्वेंशन देश में प्रथम आवेदन की तिथि से 12 माह के भीतर कन्वेंशन आवेदन दायर नहीं किया गया हो।
7. पूर्ण विनिर्देशन स्रोत का खुलासा नहीं करता है या गलत उल्लेख करता है आविष्कार के लिए प्रयुक्त जैविक सामग्री की भौगोलिक उत्पत्ति।
8. आविष्कार विश्व में कहीं भी पारंपरिक ज्ञान का हिस्सा है।

विरोध के लिए आवेदन उस पेटेंट कार्यालय में दाखिल किया जाना चाहिए, जहां आवेदन दाखिल किया गया है। इसमें आवेदन के समर्थन में एक बयान और कोई भी मौजूदा सबूत शामिल होना चाहिए।

5.3.9.5. पेटेंट अनुदान और प्रकाशन

यदि आवेदन पेटेंट अधिनियम और नियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो आवेदन को अनुदान के लिए उचित माना जाता है। अनुदान के लिए आवेदन स्वीकृत किया जाएगा और पेटेंट अनुदान की तारीख रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। पेटेंट अनुदान प्रमाणपत्र आवेदक या एजेंट को कॉम्पैक्ट डिस्क में पूर्ण विनिर्देश के अंतिम संस्करण के साथ भेजा जाएगा।

स्वीकृत पेटेंट को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और यह सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। स्वीकृत पेटेंट की तिथि पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तिथि होगी।

परीक्षक या नियंत्रक द्वारा की गई जांच पेटेंट की वैधता की गारंटी नहीं देती है।

5.3.9.6. अनुदान के बाद विरोध

पेटेंट अनुदान के प्रकाशन के बाद और ऐसे प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा अनुदान-पश्चात विरोध दायर किया जा सकता है। अनुदान-पूर्व प्रतिनिधित्व के लिए निर्दिष्ट किसी भी आधार पर अनुदान-पश्चात विरोध दायर किया जा सकता है।

5.3.3. पेटेंटधारक के अधिकार

पेटेंट से पेटेंटधारक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं:

जहां पेटेंट का विषय-वस्तु कोई उत्पाद है, वहां पेटेंटधारक की सहमति के बिना तीसरे पक्ष को भारत में उस उत्पाद को बनाने, उपयोग करने, बिक्री के लिए पेश करने, बेचने या उन प्रयोजनों के लिए आयात करने से रोकने का विशेष अधिकार;

जहां पेटेंट का विषय-वस्तु एक प्रक्रिया है, वहां तीसरे पक्ष को भारत में उस प्रक्रिया द्वारा सीधे प्राप्त उत्पाद का उपयोग करने, बिक्री के लिए पेश करने, बेचने या उन प्रयोजनों के लिए आयात करने से रोकने का विशेष अधिकार।

अधिनियम के अंतर्गत पेटेंटधारक को प्रदान किये गये अधिकार इस प्रकार हैं:

- (i) पेटेंट का दोहन करने के लिए,
- (ii) किसी अन्य को पेटेंट का लाइसेंस देना,
- (iii) पेटेंट को किसी अन्य को सौंपना,
- (iv) पेटेंट वापस करना,
- (v) पेटेंट के उल्लंघन के लिए मुकदमा करना।

5.4. सारांश

पेटेंट एक एकाधिकार अधिकार है जो किसी आविष्कारक को सीमित अवधि के लिए अपने आविष्कार का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के लिए दिया जाता है। भारत में, यह अवधि बीस वर्ष की होती है। पेटेंट किसी ऐसे आविष्कार के लिए दिया जाता है जो या तो उत्पाद हो या प्रक्रिया, लेकिन ऐसा उत्पाद या प्रक्रिया नई होनी चाहिए, उसमें आविष्कारक कदम शामिल होने चाहिए और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए। पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 से पहले, भारत में खाद्य, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में केवल प्रक्रिया पेटेंट दिए जाते थे। पेटेंट कार्यालय पेटेंटधारक को इस आधार पर कुछ अधिकार प्रदान करता है कि पेटेंट उत्पाद है या प्रक्रिया।

5.5.एसएक्यूएस

1 लघु उत्तरीय प्रश्न

- क. 'प्राथमिकता तिथि' से आपका क्या तात्पर्य है?
- ख. पेटेंटधारक के अधिकार क्या हैं?
2. रिक्त स्थान भरें

क. किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा पेटेंट अनुदान के प्रकाशन के बाद और ऐसे प्रकाशन की तारीख से के भीतर अनुदान-पश्चात विरोध दायर किया जा सकता है।

ख. आवेदन पत्र प्राथमिकता तिथि या आवेदन दाखिल करने की तिथि सेकी समाप्ति पर प्रकाशित किया जाता है, जो भी पहले हो।

3. सत्य या असत्य

क. स्वीकृत पेटेंट की तारीख पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख होगी।

ख. प्रकृति में पाए जाने वाले किसी नए पदार्थ की खोज के लिए पेटेंट नहीं दिया जा सकता।

5.6. संदर्भ

बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानून: वी.के. आहूजा (लेक्सिस नेक्सिस, 2009)

बौद्धिक संपदा से संबंधित कानून: डॉ. बीएल वढेरा (यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग)

कं, 2011)

5.7. सुझाए गए पठन सामग्री

भारतीय पेटेंट कानून और प्रैक्टिस, कल्याण सी. कंकनाला द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012।

एनएस गोपालकृष्णन और टीजी अगिथा द्वारा बौद्धिक संपदा के सिद्धांत।

5.8. अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

क. उन विषय-वस्तु पर चर्चा करें जो गैर-पेटेंट योग्य हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है भारतीय पेटेंट कानून.

ख. भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया का वर्णन करें।

जवाब

1. क. 5.3.9.1.7 देखें

ख. 5.3.3 देखें.

2. क. एक वर्ष 3. क.

बी. अठारह महीने

सत्य

ख. सत्य

अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

क. 5.3.6 देखें.

ख. 5.3.9 देखें.

यूनिट 6

पेटेंट कानून का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ

6.1. परिचय

6.2. उद्देश्य

6.3. विषय

6.3.1. अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट

6.3.2. पारंपरिक पेटेंट प्रणाली

6.3.3. पेटेंट का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण

6.3.4. अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ग्रंथ

6.3.4.1. औद्योगिक संपत्ति पर पेरिस कन्वेंशन

6.3.4.1.1 राष्ट्रीय उपचार

6.3.4.1.2. प्राथमिकता का अधिकार

6.3.4.1.3. सामान्य नियम

6.3.4.2. पेटेंट कन्वेंशन संधि (पीसीटी)

6.3.4.2.1. पीसीटी का इतिहास

6.3.4.2.2. पीसीटी के मुख्य उद्देश्य

6.3.4.2.3. पीसीटी: पेटेंट फाइलिंग सिस्टम

6.3.4.2.4. अंतर्राष्ट्रीय आवेदन का प्रभाव

6.3.4.2.5. अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोगों का मानकीकरण

6.3.4.2.6. पेटेंट सहयोग संधि के साथ संबंध

6.3.4.3. यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन

6.3.4.3.1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

6.3.4.3.2. यूरोपीय पेटेंट की प्रकृति और उद्देश्य

सम्मेलन

6.3.4.3.3. गैर-अनुबंधित राज्यों के साथ सहयोग समझौते: विस्तार और सत्यापन समझौते

6.3.4.3.4. कानूनी प्रकृति और सामग्री

6.3.4.3.5. यूरोपीय पेटेंट की अवधि

6.3.4.3.6. पेटेंट सहयोग संधि के साथ संबंध

6.3.4.3.7. मूल पेटेंट कानून

6.3.4.4. यात्राओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौता

6.3.4.4.1. ट्रिप्स के तहत पेटेंट संरक्षण

6.3.4.4.2. यात्रा समझौता और भारतीय यात्रा नियम में संशोधन

पेटेंट अधिनियम 1970

6.4. सारांश

6.5. एसएक्यूएस

6.6. संदर्भ

6.7. सुझाए गए पठन सामग्री

6.8. अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

6.1. परिचय

पेटेंट, पेटेंटधारक के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके कई आयाम हैं। कुछ आयाम ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से हैं। ये पेटेंट की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन आयामों को हर देश में अलग-अलग तरीकों से और अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय समझौतों के द्वारा माना जाता है। वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय कानून का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में अपनाए गए पेटेंट कानूनों में सामंजस्य और एकरूपता लाना है। फिर भी, पेटेंट की वास्तविक सुरक्षा धरेलू स्तर पर ही होनी चाहिए क्योंकि देशों की अपने पेटेंट कानून को संरक्षित करने में गहरी दिलचस्पी होती है।

6.2. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- आविष्कारों के अंतरराष्ट्रीय संरक्षण के बारे में समझें।
- पेटेंट के अंतरराष्ट्रीय संरक्षण के महत्व का पता लगाएं
- महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधियों के बारे में जानें।
- महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय के उद्देश्यों और विषय-वस्तु का निर्धारण करना सम्मेलनों.
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया को समझना।

6.3. विषय

6.3.1. अंतरराष्ट्रीय पेटेंट

पेटेंट केवल एक देश या क्षेत्र में किसी आविष्कार की सुरक्षा करता है। अंतरराष्ट्रीय या विश्वव्यापी पेटेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। विश्वव्यापी पेटेंट मौजूद नहीं है। प्रत्येक देश का अपना पेटेंट कानून होता है, जो उस देश में पेटेंट के आवेदन और अनुदान को नियंत्रित करता है।

अंतरराष्ट्रीय पेटेंट कानून विभिन्न देशों में पेटेंट प्राप्त करना आसान बना सकता है।

6.3.2. पारंपरिक पेटेंट प्रणाली

पारंपरिक पेटेंट प्रणाली में प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग पेटेंट आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पेटेंट सुरक्षा मांगी जाती है। हालाँकि, यह क्षेत्रीय पेटेंट प्रणालियों जैसे कि अफ्रीकी बौद्धिक संपदा संगठन (AIPO) प्रणाली, अफ्रीकी क्षेत्रीय औद्योगिक संपदा संगठन (ARIPO) और यूरोपीय पेटेंट प्रणाली के कुछ अपवादों के अधीन है। पारंपरिक प्रणाली के तहत, जिस पेटेंट कार्यालय में आवेदन दाखिल किया जाता है, उसे अपने पास दाखिल किए गए प्रत्येक आवेदन की औपचारिक जांच करनी होती है। पेटेंट कार्यालय आविष्कार की पेटेंट योग्यता निर्धारित करता है। पारंपरिक राष्ट्रीय पेटेंट प्रणाली और क्षेत्रीय पेटेंट प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक क्षेत्रीय पेटेंट कई राज्यों के लिए एक पेटेंट कार्यालय द्वारा दिया जाता है।

6.3.3. पेटेंट का अंतरराष्ट्रीय संरक्षण

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [122]

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) पेटेंट के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की प्रणालियों का प्रबंधन करता है। यह कई देशों में एक साथ IP संरक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की प्रणाली एक आविष्कारक को एक ही भाषा में एक ही आवेदन दाखिल करने और एक ही आवेदन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाती है। ये प्रणालियाँ प्रक्रिया को आसान बनाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त करने की लागत को कम करती हैं। पेटेंट कन्वेंशन संधि ऐसी ही एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कई देशों में पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है।

6.3.4. अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ग्रंथ

मुख्य संधियाँ जो पेटेंट के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण को सुगम बनाने का प्रयास करती हैं, वे हैं:

1. औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए 1883 का पेरिस कन्वेंशन
2. 1970 की पेटेंट सहयोग संधि
3. यूरोपीय पेटेंट अनुदान पर कन्वेंशन (ईपीसी) 1973।
4. बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स) 1994।
5. पेटेंट कानून संधि (पीएलटी) 2000

6.3.4.1. औद्योगिक संपत्ति पर पेरिस कन्वेंशन

औद्योगिक संपत्ति पर पेरिस कन्वेंशन पेटेंट के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। चौदह अनुबंध करने वाले राज्यों, जिन्हें कन्वेंशन देश भी कहा जाता है, ने वर्ष 1883 में औद्योगिक संपत्ति पर पेरिस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके मसौदे में कई सम्मेलनों के माध्यम से संशोधन किया गया है जो ब्रुसेल्स (14 दिसंबर, 1990), वाशिंगटन (2 जून, 1911), द हेग (6 नवंबर, 1925), लंदन (2 जून, 1934), लिस्बन (31 अक्टूबर, 1958 और स्टॉकहोम (14 जुलाई, 1967) में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, 2 अक्टूबर, 1979 को इसमें संशोधन भी हुआ। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि औद्योगिक संपत्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय साधन वैश्विक स्तर पर बौद्धिक कार्यों की सुरक्षा के लिए पहला समझौता था। कन्वेंशन सभी राज्यों के लिए खुला है। अनुसमर्थन या परिग्रहण के उपकरण डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशक के पास जमा किए जाने चाहिए। भारत पेरिस कन्वेंशन का सदस्य है, जिसने वर्ष 1998 में इसे स्वीकार किया था। जनवरी 2019 तक, कन्वेंशन इसमें 177 संविदाकारी सदस्य देश शामिल हैं, जो इसे विश्व भर में सर्वाधिक व्यापक रूप से अपनाई गई संधियों में से एक बनाता है।

पेरिस कन्वेंशन औद्योगिक संपत्ति पर लागू होता है। औद्योगिक संपत्ति में पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, सेवा चिह्न, भौगोलिक संकेत और अनुचित प्रतिस्पर्धा की रोकथाम शामिल है। कन्वेंशन के मूल प्रावधान तीन मुख्य श्रेणियों में आते हैं: राष्ट्रीय उपचार, प्राथमिकता का अधिकार, सामान्य नियम। भारतीय पेटेंट कानून पेरिस कन्वेंशन में दिए गए राष्ट्रीय उपचार, प्राथमिकता अधिकार आदि से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप है।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [123]

6.3.4.1.1 राष्ट्रीय उपचार

पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में राष्ट्रीय उपचार की बात कही गई है।

सिद्धांत। इसके अनुसार, कन्वेंशन के सदस्य देश अन्य सदस्य देशों के नागरिकों की औद्योगिक संपत्ति को उसी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे जैसे वे अपने नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। हालाँकि, सदस्य देश को पेटेंट के आवेदक पर समान प्रक्रिया या अधिकार क्षेत्र लागू करने या प्रशासित करने का अधिकार है।

कन्वेंशन का अनुच्छेद 3 अन्य देशों के नागरिकों को उक्त राष्ट्रीय उपचार की सुविधा प्रदान करता है। इसमें प्रावधान है कि गैर-अनुबंधित राज्यों के नागरिक भी कन्वेंशन के तहत राष्ट्रीय उपचार के हकदार हैं, यदि वे कन्वेंशन में शामिल देशों में से किसी एक के क्षेत्र में निवास करते हैं या उनके पास वास्तविक और प्रभावी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है।

6.3.4.1.2. प्राथमिकता का अधिकार

कन्वेंशन पेटेंट (और उपयोगिता मॉडल जहां वे मौजूद हैं), चिह्नों और औद्योगिक डिजाइनों के मामले में प्राथमिकता के अधिकार के लिए प्रावधान करता है। कन्वेंशन का अनुच्छेद 4 किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बारह महीने की प्राथमिकता अवधि तय करता है जिसने अन्य देशों में उसी पेटेंट के संरक्षण के लिए आवेदन दायर करने के उद्देश्य से सदस्य देशों में से किसी एक में पेटेंट आदि के लिए आवेदन दायर किया है। इन बाद के आवेदनों को इस तरह माना जाएगा जैसे कि वे पहले आवेदन के समान दिन दायर किए गए थे। दूसरे शब्दों में, उन्हें उसी आविष्कार या औद्योगिक डिजाइन के लिए उक्त समयावधि के दौरान दूसरों द्वारा दायर किए गए आवेदनों पर प्राथमिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 4 आगे यह प्रावधान करता है कि पेटेंट का अनुदान "इस आधार पर कम या अमान्य नहीं किया जाएगा कि पेटेंट उत्पाद या पेटेंट प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त उत्पाद की बिक्री घरेलू कानून के परिणामस्वरूप प्रतिबंधों या सीमाओं के अधीन है।

6.3.4.1.3. सामान्य नियम

कन्वेंशन में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका सभी अनुबंधित राज्यों को पालन करना होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं:

एक ही आविष्कार के लिए विभिन्न संविदाकारी राज्यों में दिए गए पेटेंट एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।

अन्य, एक संविदाकारी राज्य में पेटेंट प्रदान करने से अन्य संविदाकारी राज्यों को पेटेंट प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, किसी भी संविदाकारी राज्य में पेटेंट को इस आधार पर अस्वीकार, निरस्त या समाप्त नहीं किया जा सकता है कि इसे किसी अन्य संविदाकारी राज्य में अस्वीकार या निरस्त या समाप्त कर दिया गया है।

आविष्कारक को पेटेंट में इस तरह नामित होने का अधिकार है।

किसी पेटेंट को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, तथा पेटेंट को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है कि पेटेंट प्राप्त उत्पाद की बिक्री, या पेटेंट प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त उत्पाद की बिक्री, घरेलू कानून के परिणामस्वरूप प्रतिबंधों या सीमाओं के अधीन है।

प्रत्येक संविदाकारी राज्य, जो पेटेंट द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों के परिणामस्वरूप होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने हेतु विधायी उपाय करता है, ऐसा केवल कुछ शर्तों के अधीन ही कर सकता है।

पेटेंट किए गए आविष्कार के काम न करने या अपर्याप्त रूप से काम करने के आधार पर एक अनिवार्य लाइसेंस (पेटेंट के मालिक द्वारा नहीं बल्कि संबंधित राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दिया गया लाइसेंस), पेटेंट के अनुदान से तीन साल के बाद दायर अनुरोध के अनुसार ही दिया जा सकता है।

पेटेंट की वैधता की अवधि पेटेंट की प्राप्ति की तिथि से चार वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा यदि पेटेंटधारक अपनी निष्क्रियता को उचित ठहराने के लिए वैध कारण देता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, पेटेंट जब्ती का प्रावधान नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां अनिवार्य लाइसेंस का अनुदान दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता। बाद के मामले में, पेटेंट जब्ती की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन केवल पहले अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान से दो साल की समाप्ति के बाद।

6.3.4.2. पेटेंट कन्वेंशन संधि (पीसीटी)

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के पूर्ववर्ती, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि ब्यूरो (BIRPI) ने 1967 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार किया था। इसे विशेषज्ञों की समिति द्वारा संशोधित किया गया और 1970 में वाशिंगटन में इस पर हस्ताक्षर किए गए। "पेटेंट सहयोग संधि" के रूप में जानी जाने वाली यह संधि 24 जनवरी, 1978 को लागू हुई और 1 जून, 1978 को लागू हुई। शुरुआत में इस पर 18 अनुबंध करने वाले देशों ने हस्ताक्षर किए थे और वर्तमान में इसके 152 सदस्य हैं। भारत ने भी वर्ष 1998 में अपना परिग्रहण पत्र जमा कर दिया है और 7 दिसंबर 1998 को इसका अनुबंध करने वाला देश बन गया है।

पेटेंट सहयोग संधि को सदस्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने, खोज करने, जांच करने और अन्य तकनीकी सेवाओं के संबंध में सदस्यों के बीच सहयोग लाने के लिए अपनाया गया था। पेटेंट सहयोग संधि कई देशों में पेटेंट प्राप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग प्रक्रिया प्रदान करती है। यह एक सदस्य राज्य में एक आवेदक को पेटेंट आवेदन दाखिल करने और आवेदन में निर्दिष्ट सभी देशों में पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के अनुदान के लिए प्रावधान नहीं करता है, बल्कि केवल एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाता है और आवेदक को पेरिस संघ के किसी भी देश में उसके पक्ष में पेटेंट प्राप्त करने में मदद करता है जिसे नामित कार्यालय कहा जाता है।

जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पेटेंट सहयोग संधि अंतरराष्ट्रीय पेटेंट सहयोग के लिए एक समझौता है।

पेटेंट के क्षेत्र में सहयोग। इसे इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह काफी हद तक पेटेंट आवेदनों की फाइलिंग, खोज और जांच और उसमें निहित तकनीकी जानकारी के प्रसार के संबंध में युक्तिकरण और सहयोग के लिए एक संधि है। यह ध्यान दिया जाता है कि पीसीटी "अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट" के अनुदान के लिए प्रावधान नहीं करता है। पेटेंट देने का कार्य और जिम्मेदारी विशेष रूप से उन देशों के पेटेंट कार्यालयों के हाथों में रहती है जहां संरक्षण की मांग की जाती है। पीसीटी प्रणाली एक पेटेंट फाइलिंग प्रणाली है और इसे पेटेंट देने वाली प्रणाली के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए।

उल्लेखनीय रूप से, PCT पेरिस कन्वेंशन का पूरक है। वास्तव में, यह पेरिस कन्वेंशन के तहत एक विशेष समझौता है जो केवल उन राज्यों के लिए खुला है जो पेरिस कन्वेंशन के भी पक्ष हैं।

6.3.4.2.1. पीसीटी का इतिहास

पारंपरिक प्रणाली में शामिल कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए, 1967 में BIRPI द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार किया गया और विशेषज्ञों की एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

आगामी वर्षों में, कई बैठकों में संशोधित मसौदे तैयार किये गये और जून 1970 में वाशिंगटन में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन में पेटेंट सहयोग संधि नामक संधि को अपनाया गया।

6.3.4.2.2.पीसीटी के मुख्य उद्देश्य

पीसीटी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- (क) पेटेंट के लिए आवेदन करने के तरीकों को सरल तथा अधिक प्रभावी और किफायती बनाना
कई देशों में आविष्कारों के लिए संरक्षण;
- (ख) उन प्रणालियों से छुटकारा पाना जिनके लिए पेटेंट के लिए कई आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होती थी
कई देशों में एक ही आविष्कार और इस अंत के लिए-
- (क) एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करना जो आवेदक द्वारा उल्लिखित सदस्य देशों में पेटेंट प्रदान करने के उद्देश्य से एक ही कार्यालय में एक ही भाषा में एक ही आवेदन के माध्यम से फाइलिंग को सक्षम बनाती है;
- (ii) एकल पेटेंट कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आवेदन की औपचारिक जांच की व्यवस्था करना;
- (iii) प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय आवेदन की अंतर्राष्ट्रीय जांच करना जिसके परिणामस्वरूप एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसकी प्रति आवेदक को प्रकाशन से पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी;
- (चतुर्थ) खोज रिपोर्ट सहित अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के केंद्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन की व्यवस्था करना; तथा
- (वी) नामित कार्यालय को यह विचार करने का अवसर प्रदान करना कि क्या पेटेंट प्रदान किया जाना चाहिए; और यदि हां, तो आविष्कार किस हद तक पेटेंट योग्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करता है।
- (ग) इन सदस्य देशों को बढ़े हुए कार्यभार से निपटने में सहायता करना, क्योंकि जब तक आवेदन किसी निर्दिष्ट कार्यालय में पहुंचता है, तब तक प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा उसके स्वरूप की जांच कर ली जाती है।
- (घ) उद्योगों और अन्य इच्छुक क्षेत्रों द्वारा आविष्कारों से संबंधित तकनीकी जानकारी तक पहुंच को सुगम और त्वरित बनाना तथा विकासशील देशों को प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता करना।

6.3.4.2.3.पेटेंट फाइलिंग सिस्टम

पीसीटी संविदाकारी राज्य का कोई भी नागरिक या निवासी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दायर कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय आवेदन अधिकांश मामलों में राष्ट्रीय कार्यालय में दाखिल किए जा सकते हैं, जो पीसीटी प्राप्त करने वाले कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। पीसीटी और हरारे प्रोटोकॉल, यूरेशियन पेटेंट कन्वेंशन या यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों के नागरिक और निवासी आम तौर पर क्रमशः एआरआईपीओ कार्यालय, यूरेशियन पेटेंट कार्यालय या यूरोपीय पेटेंट कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने का विकल्प भी रखते हैं। ओएपीआई देशों और कुछ अन्य विकासशील देशों के नागरिकों और निवासियों को डब्ल्यूआईपीओ के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के साथ अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करना चाहिए, जो उनके लिए प्राप्त करने वाले कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा,

अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो सभी पीसीटी अनुबंधित राज्यों के नागरिकों और निवासियों की इच्छा पर एक प्राप्ति कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

जब कोई PCT आवेदन दायर किया जाता है, तो उसे "अंतर्राष्ट्रीय खोज" के अधीन किया जाता है। यह खोज एक अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (ISA) द्वारा की जाती है। खोज के परिणामस्वरूप एक अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (ISR) तैयार होती है और इसमें प्रकाशित दस्तावेजों का विवरण होता है जो दावा किए गए आविष्कार की पेटेंट योग्यता पर प्रभाव डालते हैं। ISA पेटेंट योग्यता पर एक लिखित राय भी तैयार करता है।

अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट और लिखित राय आईएसए द्वारा आवेदक को भेजी जाती है। इस दौरान आवेदक अपना आवेदन वापस लेने का फैसला कर सकता है, अगर उक्त रिपोर्ट में दी गई राय के कारण पेटेंट दिए जाने की संभावना कम हो। अगर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट वापस नहीं ली जाती है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया जाता है।

पीसीटी के अंतर्गत प्रक्रिया से आवेदक, पेटेंट कार्यालय और आम जनता को बहुत लाभ होगा।

6.3.4.2.4. अंतर्राष्ट्रीय आवेदन का प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय आवेदन, अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग तिथि के अनुसार, उन पीसीटी अनुबंधित राज्यों में राष्ट्रीय आवेदन के समान प्रभावी होता है, जिन्हें आवेदक अपने आवेदन में राष्ट्रीय पेटेंट के लिए नामित करता है। इसका उन पीसीटी अनुबंधित राज्यों में क्षेत्रीय पेटेंट आवेदन के समान प्रभाव होता है, जो क्षेत्रीय पेटेंट संधि के पक्षकार हैं, बशर्ते कि वे क्षेत्रीय पेटेंट के लिए नामित हों।

6.3.4.2.5. अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोगों का मानकीकरण

पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए कुछ मानक निर्धारित करता है। इन मानकों के अनुसार तैयार किया गया अंतरराष्ट्रीय आवेदन, जहां तक आवेदन के प्रारूप और विषय-वस्तु का संबंध है, सभी पीसीटी अनुबंधित राज्यों को स्वीकार्य होगा, और बदलती राष्ट्रीय या क्षेत्रीय आवश्यकताओं (और उससे जुड़ी लागत) के कारण बाद में कोई संशोधन आवश्यक नहीं होगा। कोई भी राष्ट्रीय कानून अंतरराष्ट्रीय आवेदन के प्रारूप या विषय-वस्तु से संबंधित आवश्यकताओं के अनुपालन की मांग नहीं कर सकता है जो पीसीटी द्वारा प्रदान की गई आवश्यकताओं से अलग या अतिरिक्त हो।

6.3.4.3. यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन

यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन (ईपीसी) को यूरोपीय पेटेंट के अनुदान पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 अक्टूबर 1973 को लागू हुआ। यह यूरोपीय पेटेंट संगठन की स्थापना करने वाली एक बहुपक्षीय संधि है जो एक स्वायत्त कानूनी प्रणाली प्रदान करती है जिसके अनुसार यूरोपीय पेटेंट प्रदान किए जाते हैं। यूरोपीय पेटेंट शब्द का उपयोग यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के तहत दिए गए पेटेंट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, एक यूरोपीय पेटेंट एकात्मक अधिकार नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से स्वतंत्र राष्ट्रीय-प्रवर्तनीय, राष्ट्रीय-प्रतिसंहरणीय पेटेंट का एक समूह है।

ईपीसी यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के समक्ष एकल, सुसंगत प्रक्रिया के माध्यम से यूरोपीय पेटेंट प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। एक भाषा में एकल पेटेंट आवेदन म्यूनिख में यूरोपीय पेटेंट कार्यालय में हेग में इसकी शाखा में, बर्लिन में इसके उप-कार्यालय में या किसी अनुबंधकारी राज्य के राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय में दायर किया जा सकता है, यदि राज्य का राष्ट्रीय कानून इसकी अनुमति देता है।

6.3.4.3.1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1978 से पहले, यूरोप के कई देशों में पेटेंट सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते समय दो महत्वपूर्ण समस्याएँ सामने आ रही थीं। पहली समस्या थी प्रत्येक देश में एक अलग पेटेंट आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता, जिसके बाद प्रत्येक देश में अलग-अलग अनुदान प्रक्रिया होती थी, और दूसरी समस्या थी आवेदन के पाठ को कई अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करने की आवश्यकता। वास्तव में यूरोपीय देशों में अलग-अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है और उनमें से प्रत्येक भाषा में अनुवाद तैयार करने में काफी खर्च होता है। जबकि यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन अनुवाद की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है (चूंकि किसी दिए गए ईपीसी अनुबंधित राज्य में पेटेंट को मान्य करने के लिए अनुदान के बाद अनुवाद की आवश्यकता हो सकती है), यह अभियोजन को एक भाषा में केंद्रीकृत करता है और अनुदान के समय तक अनुवाद की लागत को स्थगित करता है।

6.3.4.3.2. यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन की प्रकृति और उद्देश्य

एकल आवेदन के आधार पर पेटेंट प्रदान करने के लिए एक एकल यूरोपीय प्रक्रिया स्थापित की गई है। इसने अनुबंधित राज्यों में आविष्कारों के लिए आसान, सस्ता और मजबूत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मूल पेटेंट कानून का एक समान निकाय बनाया। प्रत्येक अनुबंधित राज्य में जिसके लिए इसे प्रदान किया जाता है, एक यूरोपीय पेटेंट अपने स्वामी को वही अधिकार देता है जो उस राज्य में दिए गए राष्ट्रीय पेटेंट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यदि इसका विषय-वस्तु एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया द्वारा सीधे प्राप्त उत्पादों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यूरोपीय पेटेंट के किसी भी उल्लंघन से राष्ट्रीय कानून द्वारा निपटा जाता है।

प्रकाशित यूरोपीय पेटेंट आवेदन अनंतिम सुरक्षा प्रदान करता है जो किसी प्रकाशित राष्ट्रीय आवेदन के लिए अनुबंध करने वाले राज्य द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से कम नहीं है। इसमें कम से कम गलत उल्लंघन की स्थिति में उचित मुआवजे का अधिकार शामिल होना चाहिए। यूरोपीय पेटेंट की मानक अवधि दाखिल करने की तारीख से बीस वर्ष है। बशर्ते कि वार्षिक नवीनीकरण शुल्क का विधिवत भुगतान किया जाए, पेटेंट अधिकतम अवधि के लिए प्रभावी रहते हैं। यूरोपीय पेटेंट कुछ ऐसे देशों में भी प्रभावी हो सकते हैं जिन्होंने EPC (विस्तार और सत्यापन राज्य) में प्रवेश नहीं किया है।

6.3.4.3.3. गैर-अनुबंधित राज्यों के साथ सहयोग समझौते: विस्तार और सत्यापन समझौते

ई.पी.सी. के इतिहास में, कुछ गैर-अनुबंधित राज्यों ने यूरोपीय पेटेंट संगठन के साथ सहयोग समझौते किए हैं, जिन्हें विस्तार या सत्यापन समझौते के रूप में जाना जाता है। ये राज्य तब "विस्तार राज्य" या "सत्यापन राज्य" बन गए, जिसका अर्थ है कि ई.पी.ओ. द्वारा दिए गए यूरोपीय पेटेंट को अतिरिक्त शुल्क के भुगतान और कुछ औपचारिकताओं को पूरा करके उन देशों तक बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि ई.पी.ओ. अनुबंधित राज्यों में होता है, इन राज्यों में मान्य/विस्तारित यूरोपीय पेटेंट को दिए गए अधिकार उन राज्यों में राष्ट्रीय पेटेंट के समान ही हैं।

6.3.4.3.4. कानूनी प्रकृति और सामग्री

यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन **औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 के अर्थ के भीतर एक विशेष समझौता है।** 1883 और पेटेंट सहयोग संधि के अनुच्छेद 45, पैराग्राफ 1 के अर्थ के भीतर एक क्षेत्रीय पेटेंट संधि वर्तमान में ई.पी.सी. सभी 38 देशों में केन्द्रीय रूप से लागू करने योग्य पेटेंट प्रदान करने में सहायक नहीं है।

6.3.4.3.5. यूरोपीय पेटेंट की अवधि

ई.पी.सी. सभी न्यायक्षेत्रों को यूरोपीय पेटेंट के लिए एक निश्चित अवधि देने की आवश्यकता रखता है। दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष की अवधि। दाखिल करने की तिथि यूरोपीय पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने की वास्तविक तिथि या पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की तिथि है। ईपीओ को नामित करना। दाखिल करने की तारीख जरूरी नहीं कि प्राथमिकता तिथि हो, जो एक वर्ष पहले तक हो सकता है। किसी स्वीकृत यूरोपीय पेटेंट की अवधि राष्ट्रीय कानून के तहत बढ़ाई जा सकती है, यदि राष्ट्रीय कानून विपणन-पूर्व विनियामक अनुमोदन की भरपाई के लिए अवधि विस्तार प्रदान करता है।

6.3.4.3.6. पेटेंट सहयोग संधि से संबंध

यूरोपीय पेटेंट आवेदन, पेटेंट सहयोग संधि के तहत एक अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने के परिणामस्वरूप हो सकता है (पीसीटी), यानी पीसीटी आवेदन दाखिल करना, और फिर "यूरोपीय क्षेत्रीय चरण" में प्रवेश करना, यानी अंतरराष्ट्रीय से यूरोपीय प्रक्रियात्मक चरणों में संक्रमण। इसलिए यूरोपीय पेटेंट आवेदन को "यूरो-पीसीटी आवेदन" कहा जाता है और ईपीओ को एक नामित या निर्वाचित कार्यालय के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है। ईपीसी और पीसीटी के प्रावधानों के बीच संघर्ष के मामले में, पीसीटी और उसके विनियमन के प्रावधान ईपीसी के प्रावधानों पर प्रबल होते हैं।

6.3.4.4. ट्रिप्स समझौता

बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा प्रशासित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों के नागरिकों पर लागू बौद्धिक संपदा (आईपी) विनियमन के कई रूपों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार से संबंधित मामलों से निपटता है।

राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियम। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बनने वाले देश, इनका पालन करने का वचन देते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए किए गए समझौते से जुड़े 18 विशिष्ट समझौतों के लिए। वे नहीं कर सकते कुछ समझौतों में पक्ष बनना चुनते हैं लेकिन अन्य में नहीं।

इन समझौतों में से बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू (ट्रिप्स)

माना जाता है कि इसका विश्व व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ट्रिप्स समझौते में

बौद्धिक संपदा के लगभग सभी रूपों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए वैश्विक न्यूनतम मानक

संपत्ति अधिकार (आईपीआर)। इस समझौते में अब सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर, अपने कानूनों को आईपीआर संरक्षण के न्यूनतम मानकों के अनुकूल बनाना। इसके अलावा, ट्रिप्स समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विस्तृत दायित्व भी प्रस्तुत किए गए।

संपत्ति के अधिकार.

6.3.4.4.1. ट्रिप्स के तहत पेटेंट संरक्षण

ट्रिप्स समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है किसी भी आविष्कार के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि, जिसमें शामिल हैं

दवा उत्पाद या प्रक्रिया। ट्रिप्स समझौते से पहले, पेटेंट अवधि थी

कई देशों में यह अवधि काफी कम है। उदाहरण के लिए, विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में

कुछ विकासशील देशों में पेटेंट की अवधि 15 से 17 वर्ष तक होती है, जबकि कुछ विकासशील देशों में पेटेंट की अवधि 15 से 17 वर्ष तक होती है।

देशों में पेटेंट 5 से 7 साल की छोटी अवधि के लिए दिए गए। ट्रिप्स समझौते में यह भी कहा गया कि

देशों को सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और उत्पादों दोनों के लिए पेटेंट संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है

प्रौद्योगिकी का.

ट्रिप्स से पहले, कई देश केवल प्रक्रिया पेटेंट प्रदान करते थे, उत्पाद पेटेंट नहीं। उत्पाद पेटेंट उत्पाद की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि प्रक्रिया पेटेंट प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया के संबंध में सुरक्षा प्रदान करते हैं विनिर्माण की विधि। प्रक्रिया पेटेंट के लिए संरक्षण विनिर्माण को नहीं रोकेगा पेटेंट उत्पादों का रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रक्रिया द्वारा निर्माण, जहां एक अलग प्रक्रिया या जो विधि आविष्कृत (और पेटेंट) की गई है, उसका उपयोग किया जाता है। ट्रिप्स समझौता आईपीआर से संबंधित कई मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक भी निर्धारित करता है।

6.3.4.4.2. ट्रिप्स समझौता और भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन

भारत ने 1995 में अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने इस उम्मीद के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि ट्रिप्स व्यवस्था के परिणामस्वरूप बौद्धिक संपदा के मानकों में अंतर के रूप में मौजूद बाधाओं को दूर करके सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी जानकारी का मुक्त प्रवाह होगा।

1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत पहले की भारतीय पेटेंट व्यवस्था ट्रिप्स समझौते से कई मायनों में भिन्न थी। पेटेंट अधिनियम ने बुनियादी जरूरतों से जुड़े क्षेत्रों में पेटेंट धारकों के अधिकारों को काफी हद तक सीमित कर दिया था। पेटेंट अधिनियम 1970 को अपनाना एक लंबी विधायी प्रक्रिया और स्वास्थ्य और खाद्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पेटेंट के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर आधारित था। इसलिए भारत को अपने पेटेंट कानून में काफी बदलाव करना पड़ा। ट्रिप्स प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए भारत ने पेटेंट अधिनियम 1970 में तीन बार संशोधन किया। पेटेंट कानून में पहले दो संशोधन 1999 और 2002 में हुए थे, मुख्य रूप से 'अनन्य विपणन अधिकार' (ईएमआर) जैसे मुद्दों को समायोजित करने और पेटेंट सुरक्षा को क्रमशः 20 साल के लिए बढ़ाने के लिए। 2005 में, पेटेंट अधिनियम 1970 में तीसरी बार संशोधन किया गया। इस संशोधन के तुरंत बाद वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक समुदाय गहन बहस के लिए तैयार हो गए।

ट्रिप्स अनुच्छेद 27.1 में कहा गया है, "किसी भी आविष्कार के लिए पेटेंट उपलब्ध होगा, चाहे वह उत्पाद हो या प्रक्रिया, सभी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, बशर्ते कि वे नए हों, उनमें कोई आविष्कारक कदम शामिल हो और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हों।" यह प्रावधान सदस्य देशों को प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में उत्पाद और प्रक्रिया पेटेंट प्रदान करने के लिए बाध्य करता है और पेटेंट योग्यता के लिए तीन मानदंड निर्धारित करता है, नवीनता, आविष्कारक कदम और औद्योगिक प्रयोज्यता। वर्तमान अधिनियम ट्रिप्स आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करता है।

6.4. सारांश

पेटेंट पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून में कुछ संधियाँ और समझौते शामिल हैं। इनमें से प्रमुख हैं औद्योगिक संपत्ति पर पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट कन्वेंशन संधि (पीसीटी), यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन, ट्रिप्स पर डब्ल्यूटीओ-समझौता। इन संधियों के अलावा कई अन्य संधियाँ, सम्मेलन और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते मौजूद हैं, जो दूसरे देशों में पेटेंट की रक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों में सामंजस्य और एकरूपता लाना है। भारत औद्योगिक संपत्ति पर पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट कन्वेंशन संधि (पीसीटी) और ट्रिप्स पर डब्ल्यूटीओ-समझौते का अनुबंध करने वाला पक्ष है, जो इसमें पारित आवश्यकताओं और प्रस्तावों को पूरा करता है और घरेलू कानून को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप लाने का प्रयास करता है।

6.5. एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न

अ. औद्योगिक संपत्ति पर पेरिस कन्वेंशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

ख. पीसीटी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

2. रिक्त स्थान भरें

क. भारत ट्रिप्स समझौते का एक पक्ष बन गया।

ख. यूरोपीय पेटेंट की अवधि यूरोपीय पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से है।

3. सत्य या असत्य

क. पीसीटी "अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट" प्रदान करने का प्रावधान नहीं करता है।

(ख) पेरिस कन्वेंशन के अनुसार, कन्वेंशन के सदस्य देश अन्य सदस्य देशों के नागरिकों की औद्योगिक संपत्ति को उसी प्रकार संरक्षण प्रदान करेंगे, जिस प्रकार वे अपने नागरिकों की संपत्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं।

6.6. संदर्भ

<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html

<https://www.wipo.int/pct/en/>

https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

भारतीय पेटेंट कानून और प्रैक्टिस, कल्याण सी. कंकनाला एट अल., ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012.

6.7. सुझाए गए पठन सामग्री

बौद्धिक संपदा अधिकार का परिचय: जेपी मिश्रा, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2005।

बौद्धिक संपदा कानून: वीजे तारापोरेवाला (थॉमसन रॉयटर्स, नई दिल्ली, 2013)।

6.7. अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

क. डब्ल्यूटीओ-ट्रिप्स समझौते के तहत पेटेंट संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें और इसके अनुसार भारतीय पेटेंट कानून में संशोधनों पर भी चर्चा करें।

ख. पेटेंट से संबंधित औद्योगिक संपत्ति पर पेरिस कन्वेंशन के उद्देश्यों और विषय-वस्तु पर व्याख्यात्मक नोट लिखें।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [131]

जवाब

1. क. 6.3.4.1 देखें. ख. 6.3.4.2.2 देखें.

2. अप्रैल 1994 बी. 20 वर्ष

3. क. सत्य ख. झूठा

अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

ग. 6.3.4.4.1. और 6.3.4.4.2 देखें।

घ. 6.3.4.1 देखें.

यूनिट-7

कंप्यूटर से संबंधित मामलों में भारतीयों की स्थिति पेटेंट

7.1. परिचय

7.2. उद्देश्य

7.3. विषय

7.3.1. कम्प्यूटर से संबंधित आविष्कार

7.3.2. मजबूत आईपी संरक्षण की आवश्यकता

7.3.3. सॉफ्टवेयर पेटेंट का अर्थ

7.3.4. सॉफ्टवेयर पेटेंट का प्रारंभिक उदाहरण

7.3.5. कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षण

7.3.6. पेटेंट कानून के तहत संरक्षण

7.3.7. सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के लिए कॉपीराइट सुरक्षा और पेटेंट सुरक्षा के बीच अंतर

7.3.7.1. विभिन्न विषय-वस्तु

7.3.7.2. पेटेंट या कॉपीराइट का अधिकार कौन दावा कर सकता है

7.3.7.3. प्रदत्त अधिकार

7.3.7.4. अवधि

7.3.8. अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत सॉफ्टवेयर पेटेंट

7.3.8.1. यात्राएं

7.3.8.2. यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के तहत सॉफ्टवेयर पेटेंट

7.3.9. अन्य देशों में सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग

7.3.10. भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग पर कानून

7.3.10.1. पेटेंट अधिनियम की धारा 3(के)

7.3.10.2. सॉफ्टवेयर पेटेंट प्राप्त करने की आवश्यकता

7.3.10.3. सीआरआई दिशानिर्देश

7.3.10.4. भारतीय मामला कानून

7.3.11. सॉफ्टवेयर पेटेंट के गुण और दोष

7.4. सारांश

7.5. एसएक्यूएस

7.6. संदर्भ

7.7. सुझाए गए पठन सामग्री

7.8. अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

7.1. परिचय

कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों की सुरक्षा आईपीआर के क्षेत्र में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्रामों का बढ़ता आर्थिक महत्व सॉफ्टवेयर पेटेंट को और अधिक जटिल बनाता है। भारत में कंप्यूटर से संबंधित आविष्कार कॉपीराइट कानून और पेटेंट कानून के तहत संरक्षित हैं। कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों की सुरक्षा तब तक अस्पष्ट रही, जब तक कि पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक ने कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों की जांच पर अपने दिशानिर्देश जारी नहीं किए। हाल ही में इन दिशानिर्देशों का एक नया संस्करण प्रकाशित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर पेटेंट के बहिष्कार की पुष्टि करता है और कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों के लिए पेटेंट अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए नवीनता, औद्योगिक कदम और उपयोगिता के पारंपरिक परीक्षण की भी आवश्यकता है। पेटेंट कानून ऐसा होना चाहिए जो विशेष रूप से इंटरनेट युग और वैश्विक युग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे उद्योगों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम चुनौतियों का सामना कर सके।

7.2. उद्देश्य

यह इकाई आपको निम्नलिखित समझने में सक्षम बनाएगी:

- सॉफ्टवेयर पेटेंट का अर्थ ○ सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग पर भारतीय पेटेंट कानून
- सॉफ्टवेयर पेटेंट के लिए दिशानिर्देश
- सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग के गुण और दोष

7.3. विषय

7.3.1. कंप्यूटर से संबंधित आविष्कार

कंप्यूटर से संबंधित आविष्कार (CRI) को कंप्यूटर-कार्यान्वित आविष्कार (CII) भी कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य प्रोग्राम करने योग्य उपकरण का उपयोग शामिल है, जहाँ एक या अधिक सुविधाएँ पूरी तरह या आंशिक रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। CRI और CII उन्हें प्रदान की जाने वाली बौद्धिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय कानून के तहत इन्हें कॉपीराइट के साथ-साथ पेटेंट कानून द्वारा भी संरक्षित किया गया है।

7.3.2. मजबूत आईपी संरक्षण की आवश्यकता

डिजिटल तकनीक में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का बहुत महत्व है। आजकल लगभग सभी आर्थिक क्षेत्र सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग ने भारत में भी आर्थिक विकास को सुगम बनाया है। सॉफ्टवेयर उद्योग भारत के सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग है। परिणामस्वरूप, यह बौद्धिक संपदा कानूनों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। इसके अलावा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उन्नति के साथ-साथ कंप्यूटिंग और संचार में बड़े निवेश के साथ इंटरनेट वाणिज्य के एक नए माध्यम के रूप में उभरा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर, सामान्य रूप से बौद्धिक संपदा और विशेष रूप से पेटेंट की बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ गई है। संयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों के विशाल आर्थिक विकास और उपयोग ने उन्हें प्रदान की जाने वाली बौद्धिक संपदा सुरक्षा के बारे में पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है।

सॉफ्टवेयर उद्योग का योगदान भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा है। हालांकि भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग ने अतीत में बहुत कम नई और मूल्यवान बौद्धिक संपदा बनाई है, लेकिन वैश्विक दुनिया में इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास तब तक निरर्थक हैं जब तक सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व को महसूस नहीं किया जाता। आईटी उद्योग का विकास बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्राप्ति और प्रभावी सुरक्षा पर निर्भर करता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय करना सरकार के लिए अनिवार्य है। यह नए और प्रभावी कानून लाकर किया जा सकता है जो बदले में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करेंगे।

7.3.3. सॉफ्टवेयर पेटेंट का अर्थ

"सॉफ्टवेयर" शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है और सॉफ्टवेयर उद्योग भी इसकी कोई विशिष्ट परिभाषा देने में विफल रहे हैं। लेकिन इसका उपयोग मूल रूप से सभी विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम मूल रूप से "एप्लिकेशन प्रोग्राम" और "ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम" में विभाजित होते हैं। एप्लिकेशन प्रोग्राम कंप्यूटर के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर एक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर से संबंधित उपकरणों को संचालित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए किया जाता है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार पेटेंट किसी नए उत्पाद या प्रक्रिया को दिया जाता है जो अभिनव हो और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम हो। इसी तरह 'सॉफ्टवेयर पेटेंट' एक ऐसा शब्द है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से पहचाने जाने वाले कंप्यूटर के किसी भी प्रदर्शन को दिया जाता है।

सॉफ्टवेयर पेटेंट से तात्पर्य ऐसे उत्पादों या प्रक्रियाओं पर दिए जाने वाले अनुदान से भी है, जिनमें इच्छित परिणाम उत्पन्न करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

पेटेंट कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कंप्यूटर प्रोग्राम "जैसे कि" पेटेंट योग्यता क्षेत्र से वर्जित हैं। हालांकि, अगर उन्हें किसी मशीन या प्रक्रिया में एकीकृत किया जाता है जो पेटेंट योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करती है यानी नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक अनुप्रयोग, तो कंप्यूटर को संचालित करने की परिणामी प्रणाली या प्रक्रिया को पेटेंट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है यदि उसमें तकनीकी चरित्र है।

7.3.4. सॉफ्टवेयर पेटेंट का प्रारंभिक उदाहरण

21 मई 1962 को एक ब्रिटिश पेटेंट आवेदन दायर किया गया जिसका शीर्षक था "रैखिक प्रोग्रामिंग के स्वचालित समाधान के लिए व्यवस्थित एक कंप्यूटर। यह आविष्कार सरलतम एल्गोरिदम के लिए कुशल मेमोरी प्रबंधन से संबंधित था, और यह विशुद्ध रूप से सॉफ्टवेयर साधन हो सकता है। पेटेंट 17 अगस्त, 1966 को प्रदान किया गया था और शायद यह विश्व स्तर पर दिए गए पहले सॉफ्टवेयर पेटेंट में से एक था।

7.3.5. कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षण

भारत में सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट पंजीकरण का अधिक उपयोग किया जाता है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(O) के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को साहित्यिक कार्य के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इसलिए, सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट सुरक्षा अधिक उपयुक्त है।

साहित्यिक कार्य के विवरण में कंप्यूटर प्रोग्राम शामिल हैं। इस प्रकार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के तहत साहित्यिक कार्य के रूप में संरक्षित हैं। कॉपीराइट अधिनियम 1957 कंप्यूटर को इस प्रकार परिभाषित करता है कि इसमें 'कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या समान उपकरण शामिल है जिसमें

सूचना प्रसंस्करण क्षमताएँ। अधिनियम में 'कम्प्यूटर प्रोग्राम' को शब्दों, कोडों, योजनाओं या किसी अन्य रूप में व्यक्त निर्देशों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें मशीन-पठनीय माध्यम भी शामिल है, जो कम्प्यूटर को कोई विशेष कार्य करने या कोई विशेष परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि कम्प्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत 'साहित्यिक कार्य' के रूप में संरक्षित है। यह स्पष्ट है कि कम्प्यूटर शब्द का अर्थ है और इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं जो इसमें दी गई जानकारी को संसाधित करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार, एक सेल फोन एक कम्प्यूटर है जिसे अन्य कार्यों के अलावा डिजिटल ऑडियो सिग्नल प्राप्त करने, इसे एनालॉग ऑडियो सिग्नल में बदलने और वायरलेस तकनीक द्वारा बाहरी रूप से डिजिटल रूप में एनालॉग ऑडियो सिग्नल भेजने के लिए प्रोग्राम किया गया है।

हालाँकि, भारत में कॉपीराइट कानून केवल विशिष्ट कोड की सुरक्षा करते हैं और उस कोड के पीछे के विचार को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। स्रोत कोड के अलावा, कम्प्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त पहलुओं को कम्प्यूटर प्रोग्राम के ग्राफिक्स, ध्वनि और उपस्थिति के लिए उचित कॉपीराइट दायर करके संरक्षित किया जा सकता है।

भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट समान कार्यक्षमता और विचार वाले किसी भिन्न कोड के निर्माण पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए पेटेंट प्राप्त करके संरक्षित किया जाता है।

प्रभावी रूप से, कम्प्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉपीराइट संरक्षण कम्प्यूटर प्रोग्राम की संरचना और डिजाइन सहित अनधिकृत नकल और उल्लंघन को रोकता है।

कार्यक्रम.

7.3.6. पेटेंट कानून के तहत संरक्षण

चूंकि कॉपीराइट संरक्षण केवल विचार की अभिव्यक्ति तक ही सीमित है, स्वयं विचार तक नहीं।

स्रोत कोड, ऑब्जेक्ट कोड और स्क्रीन डिस्प्ले को "लुक एंड फील" सिद्धांत के रूप में संरक्षण दिया गया।

पेटेंट सिस्टम के माध्यम से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा का मुख्य लाभ पेटेंट कानूनों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की ताकत और व्यापक क्षेत्र है। पेटेंट का मालिक अन्य सभी को पेटेंट किए गए आविष्कार को बनाने, उपयोग करने या बेचने से रोक सकता है। पेटेंट सुरक्षा उस आविष्कार के पीछे मूल अंतर्निहित तकनीकी विचार या सिद्धांत की रक्षा करती है। चूंकि दुनिया में सामान्य प्रवृत्ति यह है कि दुनिया के 128 देशों में से आधे से अधिक देश कम्प्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट सुरक्षा दे रहे हैं, इससे यह संकेत मिलता है कि पेटेंट सुरक्षा कम्प्यूटर प्रोग्राम को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रोग्रामर.

7.3.7. सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के लिए कॉपीराइट संरक्षण और पेटेंट संरक्षण के बीच अंतर

एक कम्प्यूटर प्रोग्राम में प्रोग्राम टेक्स्ट और व्यवहार दोनों होते हैं और इसलिए इसमें शाब्दिक यानी प्रोग्राम का स्रोत और ऑब्जेक्ट कोड - निर्देशों का सेट जो सुनिश्चित करता है कि कम्प्यूटर हार्डवेयर कुछ निश्चित कार्य करता है और गैर-शाब्दिक तत्व जैसे घटक एल्गोरिदम, संरचना या कम्प्यूटर प्रोग्राम का नुक्कड़ और अनुभव। औसत कम्प्यूटर उपयोगकर्ता का शाब्दिक तत्वों से बहुत कम या कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से वह इस बात में रुचि रखता है कि वह स्क्रीन पर क्या देखेगा यानी प्रोग्राम का लुक और फील या यूजर इंटरफेस, जो बदले में यह निर्धारित करता है कि प्रोग्राम का उपयोग करना कितना आसान है और यह इसकी लोकप्रियता और बाद की व्यावसायिक सफलता से दृढ़ता से संबंधित होगा। इस प्रकार प्रोग्राम का मूल्य उसके व्यवहार में निहित है। कॉपीराइट केवल शाब्दिक प्रतिलिपि की रक्षा करता है। इसका मतलब है कि गैर-शाब्दिक तत्वों को संरक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अधिक संबंधित हैं।

अभिव्यक्ति से ज़्यादा विचार को महत्व दिया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम अन्य साहित्यिक कृतियों के लिए अपवाद है क्योंकि यह कंप्यूटर कोड नहीं बल्कि प्रोग्राम के पीछे का विचार है जो इसे मूल्यवान बनाता है। हार्ड-टेक दुनिया में, साहित्यिक कृति यानी स्रोत या ऑब्जेक्ट कोड के पाठ की वास्तव में नकल किए बिना कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम की नकल या अनुकरण कर सकता है और उल्लंघन की कार्रवाई से बच सकता है जिससे पारंपरिक परीक्षण दुर्लभ, अपूर्ण और निरर्थक हो जाते हैं। इस प्रकार प्रोग्राम के मूल्यवान पहलू जैसे कि प्रोग्राम के संचालन के दौरान उत्पन्न उपयोगी व्यवहार और इस व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार औद्योगिक डिज़ाइन तेजी से नकल के लिए असुरक्षित हैं। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो यह सॉफ्टवेयर विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन को कमजोर कर देगा।

परंपरागत रूप से, सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित किया जाता रहा है क्योंकि कोड साहित्यिक कार्य के विवरण के लिए आसानी से फिट बैठता है। बर्न कन्वेंशन के तहत सॉफ्टवेयर को साहित्यिक कार्यों के रूप में संरक्षित किया गया था और कोई भी लिखा गया सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से कॉपीराइट द्वारा संरक्षित होता है। जबकि सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग हाल ही में यूएसए, जापान और यूरोप जैसे देशों में उभरी है।

7.3.7.1. विभिन्न विषय-वस्तु

कंप्यूटर प्रोग्राम, नाटकीय कार्य, संगीत, कलात्मक कार्य, ध्वनि रिकॉर्डिंग और सिनेमैटोग्राफिक कार्य सहित मूल साहित्यिक कार्य कॉपीराइट का विषय हैं।

कॉपीराइट सुरक्षा केवल विचार की अभिव्यक्ति तक ही सीमित है, न कि विचार तक। उदाहरण के लिए, दो अलग-अलग कंप्यूटर भाषाओं में लिखे गए अंकों को जोड़ने वाला प्रोग्राम एक विचार की दो अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ होंगी। इसके अलावा स्वतंत्र कार्य भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करते हैं।

जबकि पेटेंट केवल नए और उपयोगी आविष्कार के लिए दिए जाते हैं जिसमें आविष्कारशील कदम शामिल होते हैं। उन्हें निर्माण की विधि या तरीके, मशीनों, उपकरणों या निर्माण द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं या पदार्थों पर प्रदान किया जाता है। सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग के प्रति खैरा वैश्विक स्तर पर संदेहपूर्ण है।

7.3.7.2. पेटेंट या कॉपीराइट का अधिकार कौन दावा कर सकता है?

कॉपीराइट संरक्षण के तहत आम तौर पर लेखक कॉपीराइट का स्वामी होता है। जबकि पेटेंट पहले आवेदन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

7.3.7.3. प्रदत्त अधिकार

कॉपीराइट द्वारा प्रदत्त अधिकारों में सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने, प्रतियां जारी करने, प्रदर्शन करने, कार्य को अनुकूलित करने और अनुवाद करने का विशेष अधिकार शामिल है। हालाँकि, यदि जनता के लिए ऐसे अधिकारों का उचित उपयोग उपलब्ध है, तो इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। उचित उपयोग में शैक्षणिक उद्देश्य, निजी उद्देश्य और गैर-वाणिज्यिक मनोरंजन आदि के लिए उपयोग शामिल है।

दूसरी ओर, पेटेंट अधिकार एक एकाधिकार अधिकार है जो पेटेंटधारक को दिया जाता है। इसमें दूसरों को बनाने, उपयोग करने, बिक्री के लिए पेश करने आदि से रोकने का अधिकार शामिल है। पेटेंट अधिकार के तहत सुरक्षा कॉपीराइट से अधिक मजबूत है। कई पेटेंट आवेदन बहुत छोटे और विशिष्ट एल्गोरिदम या कई कार्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली तकनीकों को कवर करते हैं।

7.3.7.4. अवधि

इन दोनों अधिकारों को दिए जाने की अवधि में अंतर है। कॉपीराइट आम तौर पर लेखक की मृत्यु के बाद साठ साल की अवधि के लिए दिया जाता है जबकि पेटेंट केवल लेखक की मृत्यु के बाद साठ साल की अवधि के लिए दिया जाता है।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [137]

बीस वर्ष की अवधि के लिए। ट्रिप्स समझौते में प्रावधान है कि उत्पाद पेटेंट के लिए यह अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए और प्रक्रिया के लिए यह 15 वर्ष होनी चाहिए।

7.3.8. अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत सॉफ्टवेयर पेटेंट

सॉफ्टवेयर पेटेंट निम्नलिखित महत्वपूर्ण संधि के अधीन हैं

- i) ट्रिप्स
- ii) यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन

7.3.8.1. यात्राएं

ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद 27 1994 का ट्रिप्स समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए है। ट्रिप्स के अनुच्छेद 27(1) में कहा गया है कि: "... किसी भी आविष्कार के लिए पेटेंट उपलब्ध होगा, चाहे वह उत्पाद हो या प्रक्रिया, सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के लिए, बशर्ते कि वे नए हों, उनमें कोई आविष्कारक कदम शामिल हो और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हों।"

विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद भारत ट्रिप्स समझौते का अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 27 में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के सभी "आविष्कारों (प्रक्रिया या अंतिम उत्पाद)" को पेटेंट प्रदान किया जाए जो नए और उपयोगी हों; वे स्पष्ट या तुच्छ नहीं होने चाहिए। इस प्रकार, ट्रिप्स कंप्यूटर प्रोग्राम पर पेटेंट देने से नहीं रोकता है।

ट्रिप्स के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि स्रोत कोड और ऑब्जेक्ट कोड को बर्न कन्वेंशन 1971 के तहत साहित्यिक कार्य के रूप में संरक्षित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर की सुरक्षा का विवाद कॉपीराइट या पेटेंट सुरक्षा के मुद्दों पर उठता है। ट्रिप्स समझौते में ऑब्जेक्ट कोड और स्रोत कोड के कॉपीराइट संरक्षण का उल्लेख है। सॉफ्टवेयर और साहित्यिक कार्य के बीच बुनियादी अंतर के कारण कॉपीराइट संरक्षण के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करना मुश्किल है। सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट सुरक्षा का विरोध व्यवहार कोड के द्वंद्व के कारण किया जाता है और कंप्यूटर प्रोग्राम का वास्तविक मूल्य ऑब्जेक्ट कोड के बजाय स्रोत कोड में निहित है। इस प्रकार, शुद्ध सॉफ्टवेयर या इसके तकनीकी अनुप्रयोग या भौतिक अभिव्यक्ति के लिए पेटेंट संरक्षण के बारे में प्रश्न अनुत्तरित रहता है।

7.3.8.2. यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के तहत सॉफ्टवेयर पेटेंट

1970 के दशक के अंत में यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के अस्तित्व में आने के बाद से सॉफ्टवेयर से जुड़े आविष्कारों के लिए कई पेटेंट जारी किए गए थे। अनुच्छेद 52 ईपीसी कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को पेटेंट योग्यता से बाहर रखता है, इस सीमा तक कि पेटेंट आवेदन कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित है। कंप्यूटर द्वारा कार्यान्वित आविष्कार जो केवल एक गैर-स्पष्ट तकनीकी योगदान देता है या एक तकनीकी समस्या को हल करता है, पेटेंट योग्य है।

7.3.9. अन्य देशों में सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग

अन्य देशों में सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग की स्थिति संदेहास्पद है। अमेरिका और जापान में सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग आम हो गई है। अमेरिका में कुछ ऐतिहासिक मामलों के कारण सॉफ्टवेयर की पेटेंटिंग की शुरुआत हुई है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एल्गोरिदम को पेटेंट नहीं कराया जा सकता, लेकिन उनका उपयोग करने वाले उपकरणों को पेटेंट कराया जा सकता है। सॉफ्टवेयर पेटेंट अब अमेरिका में लागू किए जा सकते हैं। जापान में भी सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है।

7.3.10. भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग पर कानून

भारत में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित हैं क्योंकि ये प्रोग्राम साहित्यिक कार्य की श्रेणी में आते हैं। भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है।

भारत में पेटेंट के बारे में विस्तृत जानकारी, जिसमें शामिल है कि क्या पेटेंट कराया जा सकता है और क्या नहीं, पेटेंट प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश, पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया, पंजीकृत पेटेंट की अवधि आदि।

7.3.10.1. पेटेंट अधिनियम की धारा 3(के)

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 (के) निम्नलिखित आविष्कारों को पेटेंट योग्यता से बाहर रखती है: गणितीय या व्यावसायिक विधि; कंप्यूटर प्रोग्राम स्वयं (स्वयं द्वारा); या एल्गोरिदम।

धारा 3(के) के तहत कंप्यूटर प्रोग्राम की पेटेंट योग्यता के बारे में भ्रमित करने वाली बात 'पर से' वाक्यांश का उपयोग है। कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रत्यय "पर से" जोड़ने का विधायी इरादा पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 को पेश करते समय संयुक्त संसदीय समिति द्वारा व्यक्त निम्नलिखित दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है:

"नए प्रस्तावित खंड (के) में "स्वयं" शब्द शामिल किए गए हैं। यह परिवर्तन इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि कभी-कभी कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ अन्य चीजें शामिल हो सकती हैं, जो उसके सहायक हों या उस पर विकसित हों। यहाँ इरादा उन्हें पेटेंट देने से मना करना नहीं है, अगर वे आविष्कार हैं। हालाँकि, कंप्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट देने का इरादा नहीं है। इस संशोधन का उद्देश्य उद्देश्य को स्पष्ट करना है।

इसलिए, पेटेंट कार्यालय भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंट के लिए अधिकांश पेटेंट आवेदनों को खारिज कर रहा है, भले ही उनमें नवाचार की अधिकता हो।

7.3.10.2. सॉफ्टवेयर पेटेंट प्राप्त करने की आवश्यकता

हालाँकि, पेटेंट ऑफिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मैनुअल में कहा गया है कि सभी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इनोवेशन भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3(के) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए, भारत में कुछ प्रकार के सॉफ्टवेयर पेटेंट योग्य हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक सफल पेटेंट आवेदन करने के लिए, मुख्य बात यह है कि सॉफ्टवेयर के लिए पेटेंट प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित न करें। आवेदन का ध्यान उस उत्पाद के लिए पेटेंट प्राप्त करने पर होना चाहिए जिसमें सॉफ्टवेयर एक आवश्यक भूमिका निभाता है - सॉफ्टवेयर की पेटेंट सुरक्षा को उत्पाद के पेटेंट का एक हिस्सा बनाना।

भारत में पेटेंट प्राप्त करने के लिए किसी आविष्कार को चार मानदंडों को पूरा करना होगा:

1. नवीनता:- "नया आविष्कार" से तात्पर्य किसी ऐसे आविष्कार या प्रौद्योगिकी से है, जिसका किसी दस्तावेज में प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है या जिसका उपयोग देश में या विश्व में अन्यत्र पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तिथि से पहले नहीं किया गया है, अर्थात् विषय-वस्तु सार्वजनिक डोमेन में नहीं आई है या यह अत्याधुनिक तकनीक का हिस्सा नहीं है।
2. आविष्कारात्मक कदम:- "आविष्कारात्मक कदम" से तात्पर्य किसी आविष्कार की ऐसी विशेषता से है जिसमें विद्यमान ज्ञान की तुलना में तकनीकी उन्नति शामिल है या जिसका आर्थिक महत्व है या दोनों हैं और जो आविष्कार को कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं बनाता है।
3. औद्योगिक प्रयोज्यता:- किसी आविष्कार के संबंध में "औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम" का अर्थ है कि आविष्कार किसी उद्योग में बनाया या उपयोग किया जा सकता है।

4. सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पेटेंट योग्यता बहिष्करण:- गणितीय व्यवसाय

विधि कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम प्रति।

कंप्यूटर से संबंधित नवाचारों, सॉफ्टवेयर और मोबाइल अनुप्रयोगों का दावा करने वाले पेटेंट आवेदनों को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, यदि पेटेंट दावों को ऐसे आविष्कारों के अभिनव पहलुओं की रक्षा के लिए तैयार किया जाता है। विशेष रूप से, अभिनव पहलुओं में आविष्कारशील प्रक्रिया / विधियों के साथ-साथ आविष्कारशील उपकरण / प्रणाली (हार्डवेयर घटक) शामिल हो सकते हैं।

7.3.10.3.सीआरआई दिशानिर्देश

2015 तक भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंट देने के मुद्दे पर चारों पेटेंट कार्यालयों के बीच एकरूपता नहीं थी। इस तथ्य को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) ने याहू बनाम नियंत्रक और रेडिफ मामले में भी नोट किया था। कंप्यूटर संबंधी आविष्कारों (सीआरआई) पर पेटेंट के मुद्दे पर किसी दिशा-निर्देश के अभाव में, यह पाया गया कि जहां कुछ पेटेंट कार्यालयों ने सॉफ्टवेयर पेटेंट देने से इनकार कर दिया, वहीं अन्य सॉफ्टवेयर पर पेटेंट देने के इच्छुक थे। भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंट देने से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए पेटेंट नियंत्रक ने 2015 में सबसे पहले सीआरआई से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए। इन्हें सीआरआई दिशा-निर्देश 2015 के नाम से जाना जाता है।

2015 के दिशानिर्देशों के तहत, भारत में पेटेंट कार्यालयों को व्यवसाय पद्धति पेटेंट जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जबकि कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ शर्तों को पूरा करने पर पेटेंट योग्य हो सकते थे।

सीआरआई दिशानिर्देश 2015 की भारत में नागरिक समाज द्वारा आलोचना की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि 2015 के दिशानिर्देश भारत में स्टार्ट-अप द्वारा किए जाने वाले नवाचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे; उन्होंने तर्क दिया कि 2015 के दिशानिर्देश पेटेंट अधिनियम की धारा 3(के) का उल्लंघन करते हैं, जो स्पष्ट रूप से सॉफ्टवेयर पेटेंट पर प्रतिबंध लगाता है।

इसके कारण दिसंबर 2015 में 2015 के दिशा-निर्देशों को वापस लेना पड़ा और उसके बाद फरवरी 2016 में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए। 2016 के दिशा-निर्देशों ने पहले की स्थिति को इस हद तक बदल दिया कि कंप्यूटर प्रोग्राम पर भी पेटेंट तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि आविष्कारक यह न दिखा दे कि आविष्कार में कंप्यूटर प्रोग्राम "एक नए हार्डवेयर के साथ" शामिल है (जिसे 'नए हार्डवेयर की आवश्यकता' भी कहा जाता है)। 2016 के दिशा-निर्देशों के तहत व्यावसायिक तरीके गैर-पेटेंट योग्य बने हुए हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षक का ध्यान आविष्कार के अंतर्निहित तत्व पर होना चाहिए, न कि उस विशेष रूप पर जिसमें उसका दावा किया गया है। दावों की उचित व्याख्या की जानी चाहिए और दावे के वास्तविक योगदान की पहचान की जानी चाहिए, और यदि योगदान केवल गणितीय विधि, व्यावसायिक विधि या एल्गोरिथ्म में निहित है, तो दावों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों के मामले में निम्नलिखित परीक्षण लागू होगा

1. यदि दावे नए हार्डवेयर के साथ संयोजन में हैं, तो परीक्षक को अन्य कदम उठाने चाहिए;
2. यदि योगदान केवल कंप्यूटर प्रोग्राम में निहित है, तो दावे को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए; और
3. यदि योगदान कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ-साथ हार्डवेयर दोनों में निहित है, तो परीक्षक को पेटेंट योग्यता निर्धारित करने के लिए नवीनता, उपयोगिता और आविष्कारशील कदम जैसे अन्य चरणों पर आगे बढ़ना चाहिए।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [140]

2016 के दिशा-निर्देशों के तहत व्यवसाय पद्धतियाँ गैर-पेटेंट योग्य बनी हुई हैं। जबकि 2016 के दिशा-निर्देशों ने भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग से संबंधित कानूनी अस्पष्टता को दूर कर दिया, हाल के रुझान से संकेत मिलता है कि सॉफ्टवेयर पेटेंट (विशेष रूप से व्यवसाय पद्धति पेटेंट) भारतीय पेटेंट कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से दिए जाते हैं। 2017 में भारत में चार व्यवसाय पद्धति पेटेंट दिए गए हैं।

दिशा-निर्देश जारी करने की श्रृंखला में भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने एक बार फिर कंप्यूटर संबंधी आविष्कार (सीआरआई) की जांच के लिए दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार किया है और 30 जून 2017 को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मूल रूप से, 2017 के दिशा-निर्देश 2016 के दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं, 2016 के दिशा-निर्देशों में जो परीक्षण प्रस्तावित किया गया था, उसमें नवीनतम को हटा दिया गया है। संशोधित दिशा-निर्देश सीआरआई की पेटेंट योग्यता पर कोई विशिष्ट परीक्षण, संकेतक या निर्धारक स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-पेटेंट योग्य और पेटेंट योग्य दावों पर उदाहरणात्मक उदाहरण भी हटा दिए गए हैं। तदनुसार यह माना जा सकता है कि पेटेंट परीक्षक को आविष्कार के अंतर्निहित सार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उस विशेष रूप पर जिसमें इसका दावा किया गया है।

7.3.10.4. भारतीय केस लॉ

भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंट मामलों से संबंधित कई मामले सामने आए हैं, और पेटेंट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं:

इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाम पेटेंट्स के महानियंत्रक, "ए कैओस थ्योरेटिकल एक्सपोज़िशन वैल्यू कैलकुलेशन सिस्टम" नामक आविष्कार के लिए एक मामला था, जिसमें पेटेंट कार्यालय द्वारा इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था कि प्रस्तावित प्रणाली गणितीय सूत्रों की श्रेणी में आती है, भले ही इससे तकनीकी प्रभाव पड़े। आविष्कार ने गणितीय विधि का दावा किया था ताकि यह निर्धारित और मूल्यांकन किया जा सके कि क्या यह गणितीय है।

समय संकेत.

याहू बनाम पेटेंट नियंत्रक और रेंडिफ डॉट कॉम इंडिया लिमिटेड, एक ऐसा मामला था जिसमें धारा 3(के) पर विस्तार से चर्चा की गई थी, और पेटेंट आवेदन को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सन्निकटित व्यवसाय मॉडल के कारण खारिज कर दिया गया था। यह निहित था कि तकनीकी नवाचारों के रूप में प्रच्छन्न व्यवसाय मॉडल भारत में दिए जा रहे पेटेंट के मानदंडों को पूरा नहीं करेगा।

इस मामले में, पेटेंट दावों में याहू के व्यवसाय से संबंधित खोज शब्दों को लक्षित करने वाले सॉफ्टवेयर टूल की विशेषताएं शामिल थीं। तदनुसार, आईपीएबी ने निष्कर्ष निकाला कि तकनीकी प्रगति

याहू द्वारा प्रस्तावित पेटेंट केवल व्यापार करने का एक तरीका था, भले ही यह व्यापार करने का तकनीकी रूप से बेहतर तरीका था और इसलिए पेटेंट अधिनियम की धारा 3(के) के प्रावधानों के अनुसार इसे पेटेंट नहीं कराया जा सकता।

एक्सचेंजर ग्लोबल सर्विस जीएमबीएच बनाम पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक मामले में, भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3(के) के प्रावधानों के तहत पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट पंजीकरण के लिए पेटेंट आवेदन को शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, पेटेंट आवेदक ने आईपीएबी के समक्ष अपील की, और नियंत्रक के निर्णय के अनुसार, यह माना गया कि दावा किया गया तत्काल आविष्कार सही नहीं है।

सॉफ्टवेयर के मामले में, लेकिन एक ऐसी प्रणाली का दावा किया गया है जिसमें वेब सेवाओं और सॉफ्टवेयर में सुधार हो रहा है। तदनुसार, यह माना गया कि चूँकि आविष्कार धारा 3(के) अर्थात् सॉफ्टवेयर के मामले में श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए संबंधित आपत्ति को माफ कर दिया गया और पेटेंट प्रदान किया गया।

एनरकॉन इंडिया लिमिटेड बनाम एलॉयस वोबेन, जर्मनी में एक आविष्कार प्रस्तुत किया गया था जिसमें पवन टरबाइन को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित चरण थे जो कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर थे। बोर्ड ने फैसला किया कि यह केवल एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या नियमों या एल्गोरिदम जैसी प्रक्रिया का एक सेट नहीं था और इसलिए इसकी पेटेंट योग्यता पर आपत्ति नहीं की जा सकती। पेटेंट आवेदन को मंजूरी दे दी गई।

7.3.11. सॉफ्टवेयर पेटेंट के गुण और दोष

गुण	अवगुण
सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग से विचार की सुरक्षा होती है और इसका उपयोग केवल पेटेंटधारक की अनुमति के आधार पर ही किया जा सकता है।	सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट जैसे अन्य वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है क्योंकि इसे साहित्यिक कार्य माना जा सकता है, और पेटेंट बनाए रखना एक महंगा मामला है।
रॉयल्टी से लेकर लाइसेंस शुल्क तक नए प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।	सॉफ्टवेयर के छोटे चक्र पेटेंट को पुराना और/या अप्रचलित बनाकर बेकार बना देंगे।
इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और अधिक लोगों को इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।	दीर्घकालिक संरक्षण से विकास पर भारी अंकुश लगेगा।
कम्पनियों की सौदेबाजी क्षमता में सुधार होगा।	इससे बेकार पेटेंटों में वृद्धि होगी और पेटेंट कार्यालयों के संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा।

7.4. सारांश

भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंट देना संभव है। कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित नवाचारों के लिए दायर किए गए पेटेंट ऐसे नवाचारों की नवीन और आविष्कारशील विशेषताओं को प्रतिस्पर्धियों द्वारा कॉपी किए जाने से बचाते हैं। भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंट मोबाइल एप्लीकेशन में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और/या सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर संयोजन के लिए दिया जाता है।

हालाँकि, भारत में पेटेंट कानून सॉफ्टवेयर के लिए पेटेंट सुरक्षा की अनुमति नहीं देता है, जिसके तहत कंप्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट कराना प्रतिबंधित है। यह प्रावधान भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है, जो गैर-पेटेंट योग्य आविष्कारों से संबंधित है।

कंप्यूटर पठनीय माध्यम या कंप्यूटर प्रोग्राम उत्पादों के पेटेंट दावों के मामले में, भारतीय पेटेंट कार्यालय ऐसे पेटेंट दावों को कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में वर्गीकृत करता है, और इसलिए ऐसे दावों को भारतीय पेटेंट कानूनों के अनुसार पेटेंट नहीं किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर पेटेंट / कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों (सीआरआई) की जांच के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रकाशित भारतीय पेटेंट कानूनों और दिशानिर्देशों के प्रकाश में, भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंट के लिए आवेदन किया जा सकता है।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाओं के संयोजन का एक संयोजन, जो नवीन, आविष्कारशील है और औद्योगिक अनुप्रयोगों से युक्त है।

7.5.एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न

क. सी.आर.आई. दिशानिर्देशों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

ख. सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग से आप क्या समझते हैं?

2. रिक्त स्थान भरें

क. कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कोके प्रावधानों के तहत संरक्षित किया जाता है
कॉपीराइट अधिनियम 1957.

ख. व्यावसायिक पद्धतियाँ भारतीय पेटेंट कानून के अंतर्गत हैं।

3.सत्य या असत्य

a. धारा 3 (के), पेटेंट अधिनियम, 1970 'कंप्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट से बाहर रखता है
पेटेंट योग्यता.

ख. भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंट के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विशेषताओं के संयोजन के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, जो नवीन,
आविष्कारशील हैं और जिनमें औद्योगिक अनुप्रयोग हैं।

7.6. संदर्भ

भारतीय पेटेंट कानून और प्रैक्टिस, कल्याण सी. कंकनाला एट अल., ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012.

बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानून, वी.के. आहूजा, लेक्सिस नेक्सिस नागपुर, 2009

7.7. सुझाए गए पठन सामग्री

बौद्धिक संपदा अधिकार का परिचय: जेपी मिश्रा, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2005।

बौद्धिक संपदा कानून: वीजे तारापोरेवाला (थॉमसन रॉयटर्स, नई दिल्ली, 2013)।

7.8. अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

क. भारत में सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग कानून पर विस्तार से चर्चा करें।

ख. सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के लिए कॉपीराइट संरक्षण और पेटेंट संरक्षण के बीच अंतर पर व्याख्यात्मक नोट लिखें।

जवाब

1. क. 7.3.10.3 देखें.

ख. 7.3.3 देखें.

2. क. साहित्यिक कार्य

ख. गैर-पेटेंट योग्य

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [143]

3. क. सत्य

ख. सच

अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

क. 7.3.10 देखें.

ख. 7.3.7 देखें.

यूनिट -8

इंटरनेट में ट्रेडमार्क

संरचना

10.1. परिचय

10.2. उद्देश्य

10.3. विषय

10.3.1. डोमेन नाम

10.3.2. इंटरनेट पर पते के रूप में डोमेन नाम

10.3.3. DNS पारंपरिक डाक प्रणाली के समान है

10.3.3.1. एसएलडीएस और टीएलडीएस

10.3.4. आईसीएनएन

10.3.5.1. ट्रेडमार्क के रूप में डोमेन नाम

10.3.5.2. ट्रेडमार्क को डोमेन नाम के रूप में मानने में समस्याएँ

10.3.6. डोमेन नाम का पंजीकरण

10.3.7. डोमेन नाम विवाद

10.3.8. डोमेन नाम विवाद के प्रकार

10.3.8.1. साइबरस्क्वाटिंग विवाद

10.3.8.2. प्रतिस्पर्धी विवाद

10.3.8.3. विवादों को टालना

10.3.8.4. पैरोडी विवाद

10.3.9. डोमेन नाम विवाद समाधान

10.3.10. उल्लंघन का प्रभाव

10.3.11. डोमेन नामों की सुरक्षा के लिए कानून का अभाव

10.3.12. डोमेन नामों पर उल्लंघन कानून की प्रयोज्यता

10.3.13. डोमेन नामों पर 'पासिंग ऑफ' का अनुप्रयोग

10.3.14. न्यायिक दृष्टिकोण

10.4. सारांश

10.5. एसएक्यूएस

10.6. संदर्भ

10.7. सुझाए गए पठन सामग्री

10.8. अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न

10.1. परिचय

वर्तमान विश्व व्यापार और व्यापार गतिविधियों के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन देख रहा है। यह मुख्य रूप से वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट के कारण है। आजकल ट्रेडमार्क का उपयोग केवल वस्तुओं या सेवाओं की पहचान के लिए उत्पादों पर ही नहीं किया जाता है, बल्कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए भी इंटरनेट पर किया जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें इंटरनेट पर इस्तेमाल किए जा रहे ट्रेडमार्क को समान सुरक्षा की आवश्यकता है। इंटरनेट के व्यापक उपयोग और विस्तार के परिणामस्वरूप इंटरनेट पर ट्रेडमार्क के अनुचित या अनधिकृत उपयोग में भी वृद्धि हुई है। इसलिए, यह समय की मांग है कि हमारे कानून को विशेष रूप से इंटरनेट के युग में वाणिज्यिक और व्यापार गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाया जाए। हालाँकि, ई-कॉमर्स अपने अंतर्राष्ट्रीय चरित्र और संबंधित जटिलताओं के कारण ट्रेडमार्क की सुरक्षा में बहुत कठिनाइयाँ पैदा करता है।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- o डोमेन नाम और डोमेन नाम विवादों का अर्थ जानें।
- o ट्रेडमार्क और डोमेन नाम के बीच संबंध निर्धारित करें। o इंटरनेट और डोमेन पर ट्रेडमार्क को प्रदान की गई सुरक्षा को समझें
names.
- o डोमेन नामों पर ट्रेडमार्क कानून की प्रयोज्यता को समझना।

10.3. विषय

10.3.1. डोमेन नाम

'डोमेन नाम' एक ऐसा नाम या पहचान है जो इंटरनेट पर एक रजिस्ट्रार को दूसरे से अलग करता है। एक उद्यम, अपने डोमेन नाम को पंजीकृत करके, इंटरनेट पर एक अनूठी पहचान प्राप्त करता है जो ई-कॉमर्स की दुनिया में उसी उद्देश्य को पूरा करता है जो व्यापार और वाणिज्य की दुनिया में एक ट्रेडमार्क द्वारा पूरा किया जाता है। डोमेन नाम संख्याएँ नहीं हैं, बल्कि कई नाम या उनके संक्षिप्त रूप एक साथ संयुक्त हैं। उदाहरण के लिए 'google.com' का अर्थ है एक व्यावसायिक उद्यम जो व्यवसाय के संक्षिप्त नाम 'google' का उपयोग करता है। इंटरनेट सभी क्षेत्रों से परे सभी उपयोगकर्ताओं को सार्वभौमिक पहुँच की अनुमति देता है। इस प्रकार, यह एक डोमेन नाम को विश्वव्यापी विशिष्टता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि कोई भी दो डोमेन नाम एक जैसे नहीं हो सकते।

इंटरनेट सिस्टम के अंतर्गत एक इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) होता है जो सिस्टम से जुड़े हर कंप्यूटर या सर्वर को एक संख्यात्मक पता आवंटित करता है। IP पता याद रखना आसान नहीं होता, इसलिए डोमेन नाम की ज़रूरत होती है।

10.3.2. इंटरनेट पर पते के रूप में डोमेन नाम

'डोमेन नाम' इंटरनेट पर एक पता है। इंटरनेट डोमेन नाम प्रणाली (DNS) आभासी दुनिया का पता व्यवस्था है। यह एक वितरित डेटाबेस पर निर्मित एक पदानुक्रमित नामकरण प्रणाली है। यह प्रणाली डोमेन नामों को IP पतों में बदल देती है और इंटरनेट संसाधनों और उपयोगकर्ताओं के समूहों को डोमेन नाम असाइन करना संभव बनाती है। यह लोगों को इंटरनेट पर एक का पता लगाने की अनुमति देता है। DNS मुख्य रूप से उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर किसी व्यापारी को नेविगेट करने में सुविधा प्रदान करता है। यह दो घटकों अर्थात् डोमेन नाम और उसके संगत की सहायता से ऐसा करता है

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [146]

इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर। डोमेन नाम कंप्यूटर का एक मानव-अनुकूल पता होता है जो आमतौर पर ऐसे रूप में होता है जिसे याद रखना या पहचानना आसान होता है। IP नंबर एक अद्वितीय अंतर्निहित संख्यात्मक पता होता है जैसे कि 192.91.247.53 जो डोमेन नाम www.wipo.net के लिए संगत IP नंबर है। इन उपयोगकर्ता-अनुकूल पतों को आमतौर पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो संख्यात्मक इंटरनेट नेटवर्क एड्रेस (INA) या इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर (IP नंबर) का प्रतिनिधित्व करते हैं या उससे जुड़े होते हैं।

10.3.3. पारंपरिक डाक प्रणाली के समान DNS

DNS या INA सिस्टम पारंपरिक डाक प्रणाली की तरह काम करता है। जहाँ पारंपरिक पते में घर का नंबर, सड़क, शहर और राज्य शामिल होता है, वहीं INA में भी होस्टनाम, सब-डोमेन, सेकंड-लेवल डोमेन (SLD) और टॉप-लेवल डोमेन (TLD) जैसे समान तत्व होते हैं।

10.3.3.1. एस.एल.डी. और टी.एल.डी.

INA को SLD और TLD डोमेन में विभाजित किया जाता है, विशिष्ट डोमेन को सेकंड लेवल डोमेन या SLD कहा जाता है, और सामान्य डोमेन जिसमें SLD रहते हैं उन्हें टॉप-लेवल डोमेन या TLD कहा जाता है। उदाहरण के लिए, INA 'www.uttaranchaluniversity.com' में http होस्टनाम है, 'www' सब-डोमेन है, 'uttaranchaluniversity' SLD है और 'com' TLD है।

सात नए TLD को शामिल किए जाने से पहले ही दो प्रकार के TLD का उपयोग किया जा रहा था। ये थे जेनेरिक और कंट्री कोड TLD (ccTLD)।

जेनेरिक टीएलडी (जीटीएलडी) हैं

.com- व्यावसायिक उपयोग के लिए

.edu.- शैक्षणिक संस्थानों के लिए

.org- विविध और गैर-लाभकारी संगठन के लिए

.net- नेटवर्किंग प्रदाताओं के लिए

.gov- सरकारी संगठनों के लिए

.int- अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन के लिए

.mil- रक्षा के लिए

देश कोड टीएलडी (ccTLD) का एक उदाहरण '.in' है जिसका प्रयोग भारत के संबंध में किया जाता है।

10.3.4. आईसीएनएन

डोमेन नाम प्रणाली (DNS) का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबरर्स (ICANN) द्वारा विनियमित किया जाता है। ICANN एक गैर-लाभकारी संगठन है जो डोमेन नाम पंजीकरण की देखरेख करता है। यह सभी पतों, DNS प्रबंधन और रूट सर्वर सिस्टम प्रबंधन कार्यों के लिए स्थान आवंटन को नियंत्रित करता है। ICANN को निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है, जिसमें इसके अध्यक्ष, नौ बड़े निदेशक और दुनिया भर के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के वोट के अनुसार चुने गए नौ निदेशक शामिल हैं। यह ट्रेडमार्क मालिकों से अपने पंजीकरण को सालाना नवीनीकृत करने और एजेंसी को दुरुपयोग की तत्काल रिपोर्ट करने का आग्रह करता है।

10.3.5. ट्रेडमार्क और डोमेन नाम के बीच संबंध

परंपरागत रूप से, डोमेन नाम को इंटरनेट पर व्यापारी का केवल एक पता माना जाता था, लेकिन वर्तमान में यह व्यापारियों द्वारा खुद को, अपने उत्पादों और अपनी गतिविधियों को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानक संचार का हिस्सा बन गया है। डोमेन नाम की मूल भूमिका निस्संदेह इंटरनेट पर कंप्यूटरों के लिए एक पता प्रदान करना था। लेकिन इंटरनेट संचार के एक मात्र साधन से विकसित होकर व्यावसायिक गतिविधि करने का एक तरीका बन गया है।

इंटरनेट पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ, डोमेन नाम का उपयोग व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में भी किया जाता है।

10.3.5.1. ट्रेडमार्क के रूप में डोमेन नाम

डोमेन नाम इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ट्रेडमार्क है। डोमेन नाम की स्थिति के बारे में शैक्षणिक स्तर पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत में न्यायालयों का मानना है कि डोमेन नाम वही कार्य करता है जो ट्रेडमार्क करता है। सत्यम इन्फोवे लिमिटेड बनाम सिफोनेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 2 (1) (जेडबी) में 'ट्रेड मार्क' की परिभाषा और ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 2 (1) (एम) में 'मार्क' का विश्लेषण करने के बाद माना कि वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में एक विशिष्ट चिह्न एक ट्रेड मार्क है। इस प्रकार, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि डोमेन नाम न केवल इंटरनेट संचार के लिए एक पते के रूप में कार्य करता है, बल्कि विशिष्ट इंटरनेट साइट की पहचान भी करता है।

10.3.5.2. ट्रेडमार्क को डोमेन नाम के रूप में मानने में समस्याएँ

इंटरनेट डोमेन नाम पंजीकरण 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होता है। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडमार्क का स्वामी है, उसे अपने ट्रेडमार्क को डोमेन नाम के रूप में पंजीकृत करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, यदि यह पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पंजीकृत किया गया है। ट्रेडमार्क कानून विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं पर एक ही चिह्न के समवर्ती उपयोग की अनुमति देता है, बशर्ते कि भ्रम की कोई संभावना न हो। वर्तमान IDN पंजीकरण प्रणाली के तहत यह संभव नहीं है। इसके अलावा, ट्रेडमार्क के विपरीत वर्तमान इंटरनेट तकनीक कैपिटलाइज़ेशन, स्टाइल्ड फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट के उपयोग के माध्यम से डोमेन नामों को अलग करना संभव नहीं बनाती है।

10.3.6. डोमेन नाम का पंजीकरण

डोमेन नाम का पंजीकरण एक प्रशासनिक कार्य है। इसमें डोमेन नाम रजिस्ट्री से अनुरोध, शुल्क का भुगतान और आवंटन शामिल है, यदि इंटरनेट पर समान डोमेन नाम वाला कोई पूर्व उपयोगकर्ता नहीं है। वह संगठन जो आईपी पते के आवंटन और संबंधित मुद्दों की निगरानी करता है, उसे इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबरर्स (ICANN) के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने कई एजेंसियों को शीर्ष स्तरीय डोमेन के प्रशासन को अधिकृत किया है। अपना खुद का डोमेन नाम पंजीकृत करने के इच्छुक व्यापारी को उस एजेंसी के प्रशासक से संपर्क करना चाहिए जो संबंधित शीर्ष स्तरीय डोमेन से संबंधित है। प्रशासक अनुरोधित डोमेन नाम को मंजूरी देगा बशर्ते कि यह पहले से इंटरनेट पर मौजूद न हो। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, किसी भी दो उद्यमों को एक ही डोमेन नाम नहीं सौंपा जा सकता है।

भारत में, डोमेन नामों के प्रशासन के लिए ICANN द्वारा अधिकृत एजेंसी मुंबई स्थित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र है।

10.3.7. डोमेन नाम विवाद

डोमेन नामों के संबंध में विभिन्न प्रकार के विवाद होते हैं। सबसे आम डोमेन नाम विवाद तब होता है जब पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान डोमेन नाम किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन द्वारा पंजीकृत किया जाता है जो ट्रेडमार्क का वास्तविक स्वामी नहीं होता है। जिस आसानी से कोई व्यक्ति या संगठन इंटरनेट पर डोमेन नाम पंजीकृत करता है, वह ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क या नामों के अनधिकृत उपयोग का मुख्य कारण है।

ICANN के अनुसार डोमेन नाम के पंजीकरण के लिए इच्छुक प्रत्येक आवेदक को डोमेन नाम से संबंधित किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई किसी भी शिकायत के मामले में अनिवार्य प्रशासनिक कार्यवाही के लिए सहमत होने का वचन देना होगा। ये कार्यवाही www.icann.org/undrp/approved-providers.htm पर सूचीबद्ध प्रशासनिक विवाद समाधान सेवा प्रदाताओं में से किसी एक के समक्ष आयोजित की जाएगी।

10.3.8. डोमेन नाम विवाद के प्रकार

डोमेन नाम विवाद जटिल होते हैं क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग कारणों से अलग-अलग प्रकार के डोमेन नाम पंजीकृत करते हैं। इन विवादों के इर्द-गिर्द उचित कानूनी ढांचे को समझने के लिए, डोमेन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के प्रकारों को वर्गीकृत करना उपयोगी है

names.

10.3.8.1. साइबरस्क्वार्टिंग विवाद

जब भी किसी अन्य व्यक्ति का ट्रेडमार्क या व्यापार नाम किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत किया जाता है, तो उसे ट्रेडमार्क या व्यापार नाम के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

किसी अज्ञात व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के डोमेन नाम को अपने डोमेन नाम के रूप में उपयोग करना, इसे साइबर-स्क्वार्टिंग कहा जाता है। साइबर स्क्वार्टिंग का अर्थ है डोमेन नाम का अनधिकृत पंजीकरण या उपयोग। जहां एक ट्रेडमार्क धारक अपने डोमेन नाम की उपेक्षा करता है या उसे पंजीकृत नहीं करता है, साइबर स्क्वैटर उनके नाम चुरा लेते हैं और इसे बुरे विश्वास में पंजीकृत कर लेते हैं। यह किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाने वाला सबसे आम अपराध है और ऐसे अपराधी को साइबर स्क्वैटर कहा जाता है। साइबर स्क्वैटिंग में ऐसे विज्ञापनदाता भी शामिल हैं जो जाने-माने डोमेन नामों की नकल करते हैं। कभी-कभी साइबर स्क्वैटर किसी प्रसिद्ध नाम या ट्रेड मार्क को डोमेन नाम के रूप में इस इरादे से पंजीकृत करते हैं कि वे इस तरह के मार्क का अनुचित तरीके से उपयोग करें या लाभ प्राप्त करें या इसे वास्तविक व्यापारी को उच्च कीमतों पर बेच दें। साइबर स्क्वैटिंग को डोमेन स्क्वैटिंग के रूप में भी जाना जाता है।

हालाँकि, कुछ मामलों में, साइबरस्क्वैटिंग अवैध नहीं है और पूरी तरह से वैध है। किसी शब्द को बिना किसी दुर्भावना के या भविष्य में इसका उपयोग करने के उद्देश्य से डोमेन नाम के रूप में पंजीकृत करना अवैध नहीं है।

10.3.8.2. प्रतिस्पर्धी विवाद

डोमेन नाम विवादों के दूसरे प्रकार में प्रतिस्पर्धियों द्वारा पंजीकरण शामिल है, जिन्हें कभी-कभी 'प्री-एम्पशन विवाद' कहा जाता है। इन स्थितियों में लोग ऐसे डोमेन नाम पंजीकृत करते हैं जिनमें उनके प्रतिस्पर्धियों की कंपनी का नाम या ट्रेडमार्क शामिल होता है। आम तौर पर ऐसा या तो प्रतिस्पर्धी को डोमेन नाम का उपयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। आम तौर पर, अदालतें इन विवादों को ट्रेडमार्क उल्लंघन और अनुचित प्रतिस्पर्धा कानून के तहत सुलझाती हैं।

10.3.8.3. विवादों को दबाना

डोमेन नाम विवादों के तीसरे प्रकार में किसी और के ट्रेडमार्क की प्रसिद्धि और साख को 'हथियाने' के इरादे से डोमेन नाम का पंजीकरण शामिल है। इन स्थितियों में, एक कंपनी अपने प्रतिस्पर्धी का डोमेन नाम पंजीकृत करती है और फिर अपनी खुद की कंपनी की वेबसाइट के डोमेन नाम को लिंक करती है। इस तरह प्रतिस्पर्धी की तलाश करने वाले उपभोक्ता आएंगे

न्यायालय आमतौर पर इन विवादों को अनुचित प्रतिस्पर्धा, ट्रेडमार्क उल्लंघन और कमजोरीकरण कानून के तहत सुलझाते हैं।

10.3.8.4. पैरोडी विवाद

डोमेन नाम विवादों के चौथे प्रकार में पैरोडी शामिल है। इन स्थितियों में, कोई व्यक्ति किसी कंपनी के नाम और ट्रेडमार्क से मिलता-जुलता डोमेन नाम पंजीकृत करता है और फिर उसका उपयोग किसी वेबसाइट के संबंध में करता है जिसमें टिप्पणी शामिल होती है या उसके बारे में कोई राजनीतिक या व्यंग्यात्मक बयान होता है। इस अभ्यास की वैधता संदिग्ध है।

10.3.9. डोमेन नाम विवाद समाधान

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ऐसे उपाय अपनाने का प्रयास करता है जिससे दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। WIPO ट्रेडमार्क के मुकाबले डोमेन नाम के इस्तेमाल को विनियमित करने के उद्देश्य से कुछ मानदंड निर्धारित करता है। इन मानदंडों को ICANN अपनी यूनिफॉर्म डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन पॉलिसी के तहत अपनाता है।

डोमेन नामों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए नीति को यूनिफॉर्म डोमेन नाम विवाद समाधान नीति के रूप में जाना जाता है। यह अक्टूबर, 1999 को प्रभावी हुई। ऐसी किसी भी प्रशासनिक कार्यवाही में, शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि निम्नलिखित तीन तत्व मौजूद हैं:

- (i) प्रतिवादी का डोमेन नाम उस ट्रेडमार्क या सेवा चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है जिस पर शिकायतकर्ता के अधिकार हैं; प्रतिवादी के पास डोमेन के संबंध में कोई अधिकार या वैध हित नहीं है
- (ii) नाम;
- (iii) प्रतिवादी का डोमेन नाम पंजीकृत किया गया है और उसका गलत उपयोग किया जा रहा है
आस्था।

10.3.10. उल्लंघन का प्रभाव

आवेदक के पक्ष में पंजीकृत डोमेन नाम को ऊपर उल्लिखित तीन शर्तों की संतुष्टि पर रद्द या हस्तांतरित किया जा सकता है। यह साबित करने का भार कि तीन तत्व मौजूद हैं, शिकायतकर्ता पर है। प्रशासनिक पैनल का निर्णय आवेदक के डोमेन नाम को रद्द करने या शिकायतकर्ता को उक्त डोमेन नाम के हस्तांतरण तक सीमित है।

प्रशासनिक पैनल द्वारा कोई अन्य राहत नहीं दी जा सकती। ICANN पंजीकृत डोमेन नाम को रद्द, स्थानांतरित या उसमें परिवर्तन करता है, जब (a) पंजीकरणकर्ता स्वयं अनुरोध करता है, (b) न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के आदेश के तहत ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता होती है और (c) जब प्रशासनिक पैनल द्वारा आदेश पारित किया जाता है।

10.3.11. डोमेन नामों की सुरक्षा के लिए कानून का अभाव

भारत में, ऐसा कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है जो डोमेन नामों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए स्पष्ट रूप से संदर्भित करता हो। डोमेन नामों में ट्रेडमार्क के उपयोग की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 अतिरिक्त क्षेत्रीय नहीं है, इसलिए यह डोमेन नामों की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि डोमेन नामों को पासिंग ऑफ से संबंधित कानूनों के तहत यथासंभव कानूनी रूप से संरक्षित किया जाता है। भारत में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि डोमेन नामों को ट्रेडमार्क के समान ही संरक्षित किया जाना चाहिए।

10.3.12. डोमेन नामों पर उल्लंघन कानून की प्रयोज्यता

भारत में न्यायालयों ने बार-बार ट्रेडमार्क के उल्लंघन से संबंधित कानून को इंटरनेट पर डोमेन नाम विवादों पर लागू किया है। ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों और सिद्धांतों को न्यायपालिका द्वारा ट्रेडमार्क या डोमेन नाम विवादों के विभिन्न मुद्दों का निर्धारण करते समय लागू किया गया है। कभी-कभी यह दावा करने वालों द्वारा तर्क दिया जाता है कि डोमेन नाम केवल इंटरनेट पर एक पता है और ICANN के साथ डोमेन नाम का पंजीकरण किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार या ट्रेडमार्क अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है जो संचार को प्राधिकरण के सर्वर के माध्यम से मालिक के कंप्यूटर तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि डोमेन नाम का पंजीकरण किसी कंपनी के पंजीकरण के समान है, लेकिन कोई बौद्धिक संपदा या ट्रेडमार्क अधिकार प्रदान नहीं करता है।

10.3.13. डोमेन नामों पर 'पासिंग ऑफ' का अनुप्रयोग

वाक्यांश 'पासिंग ऑफ' का अर्थ है पास करना अर्थात् अपने माल को दूसरे का बताकर बेचना। इसके अलावा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पासिंग ऑफ का मामला प्रतिवादी को ट्रेड मार्क या ट्रेड नाम और अब डोमेन नाम का उपयोग करके वादी के रूप में अपने माल या सेवाओं को जनता को पास करने से रोकने और रोकने के लिए शुरू किया गया है। यह कार्रवाई न केवल वादी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बल्कि जनता के हितों की रक्षा के लिए भी शुरू की गई थी। पासिंग ऑफ की कार्रवाई में सफल होने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रतिवादी ने अपने माल को बेचा होगा या अपनी सेवाओं को इस तरह से पेश किया होगा कि यह जनता को धोखा देता हो या यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा देने की संभावना हो कि प्रतिवादी का माल या सेवा वादी की है। कार्रवाई का अधिकार ट्रेड मार्क के मालिक या उस व्यक्ति को उपलब्ध है जो किसी शब्द या नाम का आविष्कार करता है और उसका उपयोग करता है। ट्रेड मार्क से संबंधित मानदंडों और नियमों को डोमेन नामों पर भी लागू किया गया है।

10.3.14. न्यायिक दृष्टिकोण

आजकल, इंटरनेट पर ट्रेडमार्क विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। न्यायालयों ने डोमेन नाम विवादों के लिए लगातार पासिंग ऑफ से संबंधित कानून को लागू किया है। सत्यम बनाम सिफिनेट के एक ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत रूप में निर्धारित किया था कि ट्रेडमार्क कानून इंटरनेट पर लागू होगा और उसी पर अतिक्रमण करने वालों की दलीलों को खारिज कर दिया गया था। यह भी माना गया कि पूर्व उपयोगकर्ता को प्रतिवादी को उस सद्भावना को कम करने से रोकने का अधिकार था जो उसने नाम के संबंध में बनाई हो सकती है। अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए थे कि वह पूर्व उपयोगकर्ता था और जनता ने अपीलकर्ता के साथ ट्रेड नाम SIFY को जोड़ा था।

ब्रिटिश टेलीकम्यूनिकेशन बनाम वन इन ए मिलियन के प्रसिद्ध मामले में, जहां प्रतिवादी ने कई प्रसिद्ध नामों के लिए डोमेन नाम पंजीकरण प्राप्त किया था, जिसमें वादी संगठन की साख थी, इसे अपील की अदालत ने प्रतिवादी की ओर से कार्रवाई योग्य गलत बयानी का कार्य माना था।

याहू इंक . बनाम आकाश अरोड़ा मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को 'याहू इंडिया डॉट कॉम' डोमेन नाम का उपयोग करने से रोक दिया था, क्योंकि यह नाम वादी, एक अमेरिकी कंपनी के सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क 'याहू' के साथ भ्रामक रूप से मिलता-जुलता था।

इस संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण मामला रेडिफ कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारत सरकार का है। साइबरबूथ और एक अन्य, जहां वादी के पास इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रसिद्ध डोमेन नाम 'रेडिफ' था, और प्रतिवादी ने भी डोमेन नाम के रूप में 'रेडिफ' पंजीकृत कराया था।

समान सेवाओं के संबंध में। अदालत ने प्रतिवादी को उसके डोमेन नाम का उपयोग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा दी।

2.4. सारांश

ट्रेडमार्क का उपयोग इंटरनेट पर डोमेन नाम के रूप में किया जाता है। दुनिया भर में डोमेन नाम के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली एर्जेसी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (ICANN) है। ICANN एक गैर-लाभकारी संगठन है जो डोमेन नाम पंजीकरण की देखरेख करता है। डोमेन नाम इंटरनेट पर व्यापारी का केवल एक पता नहीं है, बल्कि यह ट्रेडमार्क के समान कार्य करता है। डोमेन नाम विवाद के विभिन्न प्रकार हैं जैसे साइबर स्क्वैटर विवाद, 'पार्सिंग ऑफ' विवाद और पैरोडी विवाद। डोमेन नाम विवादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'यूनिफ़ॉर्म डोमेन नेम्स विवाद समाधान नीति' नामक नीति द्वारा हल किया जाता है। ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित कानून और 'पार्सिंग ऑफ' की सामान्य कानूनी कार्रवाई के सिद्धांतों को भारत में न्यायालयों द्वारा डोमेन नाम विवादों के निपटारे में लागू किया जाता है।

आजकल इंटरनेट कई कार्यों के लिए एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है और कई लोग कई गतिविधियों के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। इंटरनेट गतिविधियों में इस वृद्धि के कारण व्यापारी भी इसे अपनी व्यावसायिक रणनीतियों के विस्तार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए भी गुंजाइश बनाता है जो डोमेन नाम के रूप में लोकप्रिय नामों को चुराकर और पंजीकृत करके अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। बदलते परिदृश्य और बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों या व्यापार गतिविधियों के साथ कानूनी प्रावधानों को बनाए रखना ज़रूरी है।

2.5 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न.

क. डोमेन नाम से आप क्या समझते हैं?

ख. ट्रेड मार्क और डोमेन नाम के बीच संबंध पर चर्चा करें।

2. रिक्त स्थान भरें

a. डोमेन नाम प्रणाली (DNS) का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण किसके द्वारा विनियमित होता है?

_____.

बी। डोमेन नामों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए नीति को कहा जाता है

_____.

3. सत्य या असत्य

a. साइबरस्क्वार्टिंग का अर्थ है डोमेन नाम का अनधिकृत पंजीकरण या उपयोग।

ख. डोमेन नाम इंटरनेट में उपयोग किया जाने वाला एक ट्रेडमार्क है।

2.6 संदर्भ

बौद्धिक संपदा अधिकार का परिचय: जेपी मिश्रा

भारत में ट्रेडमार्क कानून: अश्विनी कुमार बंसल

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [152]

<https://www.wipo.int>

<http://www.ipindia.nic.in/trade-marks>

2.8 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

क. भारत में डोमेन नामों के लिए उपलब्ध सुरक्षा पर चर्चा करें।

ख. डोमेन नाम विवाद से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें।

उत्तर:

एसएक्यू

1. क. 10.3.1 देखें.

ख. 10.3.5 देखें.

2. क. इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबरर्स (आईसीएएनएन)।

ख. एकसमान डोमेन नाम विवाद समाधान नीति।

3. क. सत्य

ख. सत्य

अंतिम प्रश्न और उत्तर

क. 10.3.11, 10.3.12, 10.3.13 और 10.3.14 देखें।

ख. 10.3.8 देखें.

इकाई-9

ट्रेडमार्क को समझना

संरचना

8.1 परिचय

8.2 उद्देश्य

8.3 विषय

8.3.1 ट्रेडमार्क का अर्थ

8.3.2 कार्य

8.3.3 ट्रेडमार्क कानून की आवश्यकता

8.3.4 ट्रेडमार्क की उत्पत्ति

8.3.5 ट्रेडमार्क का अंतर्राष्ट्रीय कानून

8.3.6 विधायी इतिहास

8.3.6.1 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1940 से पहले ट्रेडमार्क का संरक्षण

8.3.6.2 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1940 का अधिनियमन

8.3.6.3 व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 का अधिनियमन

8.3.7 ट्रेडमार्क की अनिवार्यताएं

8.3.8 कुछ अन्य चिह्न

8.3.8.1 सेवा चिह्न

8.3.8.2 उत्पाद चिह्न

8.3.8.3 प्रमाणन ट्रेडमार्क

8.3.8.4 सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क

8.3.8.5 भ्रामक रूप से समान कार्य

8.3.9 अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों से अलग ट्रेडमार्क

8.4 सारांश

8.5 एसएक्यूएस

8.6 संदर्भ

8.7 सुझाए गए पठन सामग्री

8.8 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल उत्तर

8.1 परिचय एवं

8.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- ट्रेडमार्क को परिभाषित करें
- ट्रेड मार्क का कार्य जानें
- ट्रेडमार्क कानून की आवश्यकता को समझें
- ट्रेडमार्क पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करें
- ट्रेडमार्क कानून के विकास का वर्णन करें
- ट्रेड मार्क की अनिवार्यताएं जानें
- कुछ अन्य चिह्नों को समझें
- ट्रेडमार्क को बौद्धिक संपदा अधिकारों के अन्य रूपों से अलग करना

8.3 विषय

8.3.1 ट्रेड मार्क का अर्थ

(i) अर्थ

अपने भौतिक रूप में ट्रेडमार्क एक प्रतीक है। यह एक दृश्य प्रतीक है जो एक उद्यम के सामान या सेवाओं को दूसरों से अलग करता है। वे उत्पाद विभेदन का प्रमुख स्रोत हैं। यह एक टिकट, लेबल हो सकता है जिसे लेख पर चिपकाया जा सकता है। यह एक डिज़ाइन, नाम, शब्द, अक्षर, हस्ताक्षर, अंक या विभिन्न आकृतियों और रंगों में इनका कोई भी संयोजन हो सकता है।

इस प्रकार, ट्रेडमार्क एक शब्द, वाक्यांश, डिज़ाइन, ध्वनि, गंध, रंग, उत्पाद, विन्यास, संख्या, उनके संयोजन, एक उपकरण या वाणिज्य के लेखों पर लागू लेबल के रूप में एक दृश्य प्रतीक है, जो एक वस्तु या सेवा को अन्य से अलग करने में सक्षम है।

ट्रेडमार्क उपभोक्ताओं के मन पर एक छाप या छवि छोड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उनमें यह विश्वास उत्पन्न होता है कि यह वास्तविक है और इसकी गुणवत्ता अच्छी है।

ट्रेडमार्क को उपभोक्ताओं के लिए किसी उत्पाद को व्यक्तिगत बनाने के लिए उसके स्रोत का संकेत देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उपभोक्ता को वास्तविक निर्माता के बारे में बताना चाहिए। यह पर्याप्त है कि उपभोक्ता उद्यम पर भरोसा कर सकता है, भले ही वह उसे न जानता हो।

कोई व्यक्ति जो किसी विशेष ट्रेडमार्क के तहत अपना उत्पाद बेचता है, उसे उन वस्तुओं के संबंध में उस चिह्न के उपयोग का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। ट्रेडमार्क को एक ऐसी संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है जो कानून द्वारा संरक्षित है, न कि केवल एक छवि या प्रतीक। ट्रेडमार्क नामक इस संपत्ति को सरकार द्वारा स्थापित ट्रेडमार्क रजिस्टर में पंजीकृत करके संरक्षित किया जा सकता है।

अपंजीकृत ट्रेडमार्क को पारिंग ऑफ के विरुद्ध भी सुरक्षा उपलब्ध है। ट्रेडमार्क में निहित संपत्ति अमूर्त चीजों पर अमूर्त संपत्ति है। कई मामलों में ब्रांड मूल्य किसी कंपनी की भौतिक संपत्तियों के मूल्य से अधिक होता है।

इस प्रकार की संपत्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है तथा उल्लंघन और चोरी से सुरक्षित रखी जा सकती है।

ट्रेडमार्क की कानूनी अवधारणा को निम्नलिखित परिभाषा के संदर्भ में समझा जा सकता है:

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 2(1)(जेडबी) के तहत ट्रेडमार्क।

8.3.2 कार्य

ट्रेडमार्क का कार्य कानूनी शिक्षाविदों के बीच निरंतर अटकलों और बहस का विषय है। इसे अक्सर ट्रेडमार्क वैधता और उल्लंघन के सवाल का आकलन करने में निर्णायक कारक कहा जाता है।

कानूनी लेखकों ने सुझाव दिया है कि ट्रेडमार्क कई कार्य करते हैं जिनमें उत्पाद की पहचान, भौतिक स्रोत की पहचान, गुणवत्ता की गारंटी और विज्ञापन कार्य शामिल हैं।

ट्रेडमार्क उस व्यक्ति को बताता है जो खरीदने वाला है कि उसे क्या प्रस्तुत किया जा रहा है और उस उत्पाद का स्रोत क्या है या उसने पहले भी उसी स्रोत से आने वाली किसी चीज़ के बारे में सुना है।

यह खरीदार को उस वस्तु के निर्माण और गुणवत्ता के बारे में संतोषजनक आश्वासन देता है जिसे वह खरीद रहा है। उत्पाद की साख उसके ट्रेडमार्क के माध्यम से भी परिलक्षित होती है। ट्रेडमार्क का उपयोग न केवल यह दर्शाने के लिए किया जा सकता है कि माल किसी विशेष निर्माता का है, बल्कि उस निर्माता का माल किसी विशेष प्रकार या गुणवत्ता का है। इस प्रकार, एक व्यापारी एक ट्रेडमार्क द्वारा अपनी सर्वोत्तम गुणवत्ता, दूसरे ट्रेडमार्क द्वारा अपनी दूसरी गुणवत्ता और इसी तरह आगे भी दर्शा सकता है।

ट्रेडमार्क के कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (i) मूल के संकेतक के रूप में ट्रेडमार्क - ट्रेडमार्क उत्पाद और उसके मूल की पहचान करता है। खरीदार को उत्पाद के बारे में उसके ट्रेडमार्क के माध्यम से पता चलता है। ये चिह्न सुरक्षा के हकदार हैं क्योंकि वे उस व्यापार स्रोत के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं जहाँ से माल या सेवाएँ आती हैं। ट्रेडमार्क माल की उत्पत्ति के स्रोत की पहचान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। उदाहरण के लिए व्यापार नाम 'वीडियोकॉन' भारत की वीडियोकॉन कंपनी द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को दर्शाता है।
- (ii) यह माल की स्थापित गुणवत्ता की गारंटी देता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट 'कोलगेट' की गुणवत्ता अच्छी तरह से स्थापित है। 'कोलगेट' टूथपेस्ट खरीदने वाले को इसकी गुणवत्ता का भरोसा होता है। इसके अन्य उदाहरण 'ब्रुक बॉन्ड' और 'ताज महल' भी हैं। 'ब्रुक बॉन्ड टी' के लेबल वाले पैक में बेची जाने वाली चाय की गुणवत्ता समान होगी। लेकिन यह 'ताज महल' के लेबल वाले पैक से अलग होगी।

हालांकि गुणवत्ता की यह गारंटी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। लेकिन ट्रेडमार्क स्वामी के हित में यह है कि वह उन वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखे जिन पर यह चिह्न लागू होता है, यदि उन्हें सुधारना संभव न हो तो।

- (iii) यह उत्पाद के विज्ञापन का एक साधन है। हर कंपनी जो अपने उत्पाद को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना चाहती है, उसे अपने उत्पाद को एक ट्रेड नाम देना पड़ता है और फिर उसका ब्रांड मूल्य बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, 'लक्स' साबुन का एक लोकप्रिय नाम है।

(iv) ट्रेडमार्क जनता के मन में उत्पाद की छवि बनाता है। उदाहरण के लिए, ट्रेड नाम 'पारले' कंपनी द्वारा बेची जाने वाली मिठाइयों और बिस्कुटों की गुणवत्ता के बारे में जनता में एक धारणा और छवि बनाता है।

(v) ट्रेडमार्क किसी विशेष उत्पाद के मूल स्रोत को अन्य समान उत्पादों से अलग पहचान कर जनता को भ्रम और धोखे से बचाता है।

(vi) ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क स्वामी के व्यापार और व्यवसाय के साथ-साथ उसकी साख की भी रक्षा करता है जो उनके ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ है।

ट्रेडमार्क उन उत्पादों या सेवाओं के लिए प्रतिष्ठा बनाने में बुनियादी तत्व हैं जिनसे वे जुड़े हुए हैं। सद्भावना बनाना ट्रेडमार्क का मूल कार्य है।

गुडविल का निर्माण सामान खरीदते समय खरीदार के व्यवहार को प्रभावित करके किया जाता है। जब तक गुडविल के निर्माण का यह कार्य किया जाता है, तब तक कोई भी ट्रेडमार्क अपने लिए एक परिसंपत्ति होगा।

मालिक।

8.3.3 ट्रेडमार्क कानून की आवश्यकता

वस्तुओं से जुड़े चिह्नों ने अपने इर्द-गिर्द प्रतिष्ठा और सद्भावना अर्जित की। विशिष्ट कानून के अभाव के कारण सामान्य कानून चिह्नों को पंजीकृत नहीं किया जा सका। सामान्य कानून चिह्न के स्वामी को अपने चिह्न को उल्लंघन या पासिंग ऑफ से बचाने के लिए सामान्य कानून कार्यवाही शुरू करनी पड़ती थी। ऐसी कार्यवाही हर बार उल्लंघन होने पर शुरू करनी पड़ती थी। ऐसी कार्यवाही केवल तभी शुरू की जा सकती थी जब उल्लंघन हुआ हो और इसमें समय लगता था। इस प्रकार व्यापार चिह्नों पर एक विशेष कानून की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

8.3.4 ट्रेड मार्क्स की उत्पत्ति

मानव समाज कई तरह से चिह्नों, प्रतीकों या चिह्नों का उपयोग करता रहा है। पहले के समय में भी कुछ चिह्नों, नाम टैग, मवेशियों के ब्रांड आदि का उपयोग वस्तुओं, संपत्ति और अन्य वस्तुओं के स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया जाता था। वस्तुओं पर इस्तेमाल किए जाने वाले चिह्नों का इस्तेमाल इस शब्द के वर्तमान अर्थ में इस्तेमाल होने से कई शताब्दियों पहले शुरू हुआ था। भारत और अन्य जगहों पर ब्रांडिंग का एक लंबा इतिहास रहा है।

(i) प्रारंभिक इतिहास

दुनिया भर के प्राचीन लोग वस्तुओं की पहचान करने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए चिह्नों का इस्तेमाल करते थे, उन्हीं कारणों से जो आज ट्रेडमार्क के इस्तेमाल में सहायक हैं। सबसे पहले चिह्न संभवतः जानवरों पर निशान लगाने से बने थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन किसका मालिक है। चूँकि शुरुआती वाणिज्य तत्काल इलाके तक ही सीमित था, इसलिए बहुत कम व्यापारियों को अपने उत्पादों पर चिह्नों की ज़रूरत थी। जैसे-जैसे वाणिज्य विकसित हुआ, चिह्नों ने कई तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करना शुरू कर दिया। चिह्नों के इस्तेमाल के पीछे का उद्देश्य इन सभी समयों में अपनी प्रकृति और दायरे में बदलता रहा है।

4000 ईसा पूर्व में बनी मिस्र की इमारतों पर खदानों के निशान और पत्थर काटने वालों के चिह्न दिखाई देते हैं। प्राचीन मिस्र जैसे स्थानों से कलाकृतियाँ मिलीं जिन पर विभिन्न प्रतीक उकेरे गए थे। ग्रीक और रोमन काल से बचे अवशेषों में कुम्हारों के निशान दिखाई दिए, जिनका उपयोग किसी विशेष बर्तन के निर्माता की पहचान करने के लिए किया जाता था।

ट्रेडमार्क संबंधी ग्रंथों में आमतौर पर बताया जाता है कि रोमन साम्राज्य में तलवारें बनाने वाले लोहारों को ट्रेडमार्क के पहले उपयोगकर्ता के रूप में माना जाता है। मेसोपोटामिया और मिस्र की ईंटों और टाइलों पर सम्राट या इसके निर्माण के समय सत्ता में रहने वाले व्यक्ति के नाम का संकेत देने वाले शिलालेख थे। प्राचीन काल में चिह्नों का उपयोग किया जाता था, वे मध्यकाल में प्रचलन में थे, और आधुनिक युग में भी उनका उपयोग किया जाता है।

10वीं शताब्दी के दौरान, एक चिह्न को व्यापारी का चिह्न कहा जाता था। इन चिह्नों को एक प्रकार के मालिकाना चिह्न के रूप में माना जा सकता है, जिसका उपयोग अनिवार्य रूप से माल के स्वामित्व अधिकारों को साबित करने के लिए किया जाता था। तेरहवीं शताब्दी में अंग्रेजों ने एक निश्चित कंपनी से दूसरे में उत्पादों की नकल से बचने के लिए नियम बनाए।

चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी में व्यापारियों और शिल्प संघों के नाटकीय उदय के दौरान, ट्रेडमार्क जैसे प्रतीक और लोगो इन फर्मों की पहचान के रूप में सामने आने लगे।

कानूनी विद्वानों ने एंग्लो-अमेरिकन संदर्भ में ट्रेडमार्क कानून की उत्पत्ति का पता गिल्ड सिस्टम से उत्पन्न मध्ययुगीन इंग्लैंड से लगाया है। एंग्लो इंडियन ट्रेडमार्क कानून का पता बेकर्स मार्किंग लॉ के साथ 1266 ई. में लगाया गया है। इसके तहत बेकर्स को अपनी बेची जाने वाली रोटी पर निशान लगाने होते थे, जिससे बेकर की पहचान होती थी। बिक्री के लिए पेश की गई बिना मुहर वाली रोटी जब्त कर ली जाती थी और उल्लंघन करने वाले बेकर को भारी हर्जाना देना पड़ता था। ब्रेड और बीयर का कानून ट्रेडमार्क के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। गिल्ड सिस्टम में आज के ट्रेडमार्क कानून के कई बीज समाहित हैं। हालांकि ट्रेडमार्क की सुरक्षा अपेक्षाकृत बाद में विकसित हुई है।

(ii) भारत में ट्रेडमार्क की उत्पत्ति

भारतीय संदर्भ में प्राचीन काल से लेकर आज तक ट्रेडमार्क के कई उदाहरण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अलग-अलग मुहरों का उपयोग और विकास देखा गया। विभिन्न मुहरों और कलाकृतियों पर निशान पाए गए या अलग-अलग जगहों से खुदाई की गई। आगे सिंधु घाटी संस्कृतियों में मिट्टी के बर्तनों के निशान और खदान के निशान पाए गए। इन खदान के निशानों से इमारतों में इस्तेमाल किए गए पत्थर के स्रोत का पता चलता था और पत्थर काटने वालों के निशान से श्रमिकों को मजदूरी के अपने दावों को साबित करने में मदद मिलती थी। प्राचीन भारत में भारतीय व्यापारियों ने कुछ विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। वे विदेशों में तत्कालीन ढाका (अब बांग्लादेश में) के कपड़े जैसी वस्तुओं की आपूर्ति करते थे। विदेशियों को ये बहुत पसंद आते थे और वे कहते थे कि यह वस्तु इंड्र द्वारा बनाई गई है या इंड्र से आई है।

चूंकि भारतीय चिह्नों के सामान अपनी गुणवत्ता में सर्वोच्च थे और कोई भी अन्य व्यक्ति उनकी नकल नहीं कर सकता था। इसलिए, भारतीय अपने सामान के लिए किसी ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम के लिए नहीं आते थे। यही स्थिति भारत में मुस्लिम काल के दौरान भी रही। लेकिन जब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और देश के बड़े हिस्से पर शासन करना शुरू कर दिया। बड़े व्यापारियों और निजी और साथ ही कॉर्पोरेट ने बाजार में अपने उत्पादों पर अपना चिह्न स्थापित किया। उन्होंने ब्रांड नाम, शैली या डिज़ाइन को अपने स्वयं के निर्दिष्ट ब्रांड नाम के तहत बेचा या इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारी को उनके ब्रांड नाम, शैली या डिज़ाइन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह व्यवहार में ट्रेडमार्क कानून की उत्पत्ति थी।

और बाद में ट्रेडमार्क कानून पर क्रमिक अधिनियमों के रूप में विकसित हुआ।

औद्योगिक क्रांति और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण, संरक्षण की आवश्यकता ट्रेडमार्क का उपयोग और अधिक बढ़ गया। ऐसा मुख्य रूप से उनके धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग की आशंका के कारण हुआ।

8.3.5 ट्रेड मार्क्स का अंतर्राष्ट्रीय कानून

ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 15 से 21 ट्रेडमार्क संरक्षण से संबंधित हैं।

8.3.6 विधायी इतिहास

चूँकि पहले के समय में बाज़ारों का बहुत विकास नहीं हुआ था और व्यापारी या सौदागर बहुत कम थे और नकल और अन्य अनुचित व्यापार व्यवहार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसलिए, संरक्षण की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। जनसंचार माध्यमों के विकास के साथ चिह्नों की अवधारणा में कई बदलाव हुए।

कुछ साल बाद इंग्लैंड में चांसरी अदालतों ने ट्रेडमार्क की अवधारणाओं को और परिष्कृत किया, उन्हें संपत्ति माना। इन अदालतों ने माना कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने सामान पर ट्रेडमार्क लगाने से उस चिह्न पर अधिकार प्राप्त होता है। नतीजतन, अदालतों ने किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ति की तरह ट्रेडमार्क के कब्जे और आनंद को संरक्षण देना शुरू कर दिया।

यूके ट्रेडमार्क पंजीकरण अधिनियम पहला ट्रेडमार्क कानून था जो 1875 में अस्तित्व में आया। इसने पहली बार इंग्लैंड में ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रदान किया।

1858 में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश राज को हस्तांतरित कर दिया गया और चिह्नों के उपयोग पर एकाधिकार तथा दूसरों द्वारा नकल को प्रतिबंधित करने की मांगें धीरे-धीरे जोर पकड़ती गईं।

1877 में बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन ने अंग्रेजी ट्रेडमार्क पंजीकरण अधिनियम 1875 की तर्ज पर ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए प्रावधान बनाने की पहली मांग की। भारत सरकार ने 1879 में एक विधेयक पेश किया जिसे एक समिति को भेज दिया गया।

इस बात पर मतभेद था कि इंग्लैंड में पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क को भारत में नए सिरे से पंजीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

8.3.6.1 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1940 से पहले ट्रेडमार्क का संरक्षण

भारतीय ट्रेडमार्क कानून की जड़ें यूनाइटेड किंगडम की सामान्य कानून प्रणाली में पाई जाती हैं। वैधानिक कानून की अनुपस्थिति में ट्रेडमार्क को केवल सामान्य कानून संरक्षण ही उपलब्ध था। यदि किसी के ट्रेडमार्क को किसी अन्य व्यापारी द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था, तो वह व्यक्ति मुकदमा दायर कर सकता था।

बाद में आम कानून अदालतों में धोखाधड़ी के लिए कार्रवाई की गई। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में, आम कानून अदालतों और चांसरी अदालतों का अधिकार क्षेत्र विभाजित था। ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे चांसरी अदालतों में दायर किए गए थे, जिन्होंने इन मुकदमों को धोखाधड़ी की कार्रवाई माना। वादी के लिए निषेधाज्ञा का दावा करने के लिए धोखाधड़ी के इरादे का सबूत ज़रूरी था।

जब चांसरी कोर्ट - इक्विटी कोर्ट अस्तित्व में आया, तो इसने किसी विशेष चिह्न या प्रतीक के उपयोग के माध्यम से प्रतिष्ठा या सद्भावना विकसित करने वाले व्यापारी की रक्षा के लिए 'पासिंग ऑफ' की कार्रवाई का इस्तेमाल किया। यह 1838 में था कि धोखे की कार्रवाई आधुनिक समय की पासिंग ऑफ कार्रवाई में विकसित हुई। 1880 में एक नया विधेयक पेश किया गया और फिर से राय विभाजित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 1879 का मूल विधेयक बहाल कर दिया गया। परिणामस्वरूप भारत की ब्रिटिश सरकार

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [159]

भारतीय व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1889 को अधिनियमित करना पड़ा। हालाँकि, यह अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता नहीं था।

8.3.6.2 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1940 का अधिनियमन

बीसवीं सदी की शुरुआत में इस विषय पर कानून बनाने की मांग फिर से शुरू हुई।

भारतीय व्यापारिक जनता की यह तीव्र इच्छा थी कि ट्रेडमार्क विषय पर एक सम्पूर्ण संहिता होनी चाहिए।

मांग ने जोर पकड़ा और अंततः केंद्र सरकार को एक अधिनियम पारित करने की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1937 में एक ज्ञापन तैयार किया गया जिसे सभी स्थानीय सरकारों और वाणिज्यिक निकायों को राय के लिए भेजा गया। राय को विचार और रिपोर्ट के लिए श्री आर.के. नेहरू के पास भेजा गया। उन्होंने तदनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1937 में

सितंबर, 1939 को वाणिज्य और उद्योग के लिए भारत सरकार के तत्कालीन कार्यकारी पार्षद सर ए. राम स्वामी मुदलियार ने ट्रेडमार्क विधेयक पेश किया। इसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 11 मार्च 1940 को गवर्नर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम एक समेकित अधिनियम था और इसका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के साथ ट्रेडमार्क की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना था।

8.3.6.3 व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 का अधिनियमन

1940 का ट्रेडमार्क अधिनियम 1938 के अंग्रेजी अधिनियम के आधार पर बनाया गया था। इसके बाद, 1941 और 1943 में दो संशोधन अधिनियम पारित किए गए, जिनका उद्देश्य 1940 के अधिनियम में कुछ दोषों को दूर करना था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और बाद में विकसित हुई परिस्थितियों तथा वाणिज्यिक उद्यमों के तेजी से विकास के बाद, अधिनियम में बदलाव आवश्यक महसूस किए गए। ट्रेडमार्क को अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई।

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1940 में किए गए व्यापक संशोधनों और भारतीय व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1889 में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए, नए अधिनियम की आवश्यकता थी। व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1889, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1940 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के संबंधित प्रावधानों से संबंधित कानून को समेकित करना उचित समझा गया था। इसका परिणाम व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 पारित होना था, जो 25 नवंबर, 1959 को लागू हुआ।

8.3.6.4 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 का अधिनियमन

व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 में व्यापक संशोधनों को देखते हुए, आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए उक्त अधिनियम को निरस्त करना और पुनः अधिनियमित करना उचित समझा गया। ट्रेडमार्क विधेयक, 1999 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 30 दिसंबर, 1999 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम ने ट्रेडमार्क से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित किया है और खाद्य पदार्थों और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा का प्रावधान किया है। अधिनियम का एक उद्देश्य धोखाधड़ी वाले चिह्नों के उपयोग की रोकथाम करना है।

8.3.7 ट्रेड मार्क की अनिवार्यताएं

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में दी गई 'ट्रेडमार्क' की परिभाषा बहुत व्यापक है। वास्तव में ट्रेडमार्क किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में इस्तेमाल किया जाने वाला एक दृश्य प्रतीक है जो उस वस्तु या सेवा और चिह्न का उपयोग करने वाले व्यक्ति के बीच किसी प्रकार के संबंध को इंगित करता है। इसे वैधानिक परिभाषा के दायरे में लाने के लिए ट्रेडमार्क को निम्नलिखित आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

- (a) यह ऐसा चिह्न होना चाहिए जो एक उपकरण, ब्रांड, शीर्षक, लेबल, टिकट, नाम या नाम का संक्षिप्त रूप, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर या अंक, माल का आकार, पैकेजिंग या रंगों का संयोजन या इनका कोई संयोजन हो।
 - (ii) इसे ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकने में सक्षम होना चाहिए। ग्राफिकल प्रतिनिधित्व का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा के लिए ट्रेडमार्क का कागज़ के रूप में प्रस्तुतीकरण।
 - (iii) उसे एक व्यक्ति की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य व्यक्तियों से अलग करने में सक्षम होना चाहिए।
- (बदल) इसका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में किया जाना चाहिए या उपयोग करने का प्रस्ताव होना चाहिए।
- (v) उपयोग चिह्न के मुद्रित या अन्य दृश्य प्रतिनिधित्व का होना चाहिए।
 - (vi) उपयोग का उद्देश्य यह दर्शाना या दर्शाना होना चाहिए कि व्यापार के दौरान वस्तुओं या सेवाओं तथा किसी ऐसे व्यक्ति के बीच संबंध है, जिसके पास चिह्न का उपयोग करने का अधिकार है, चाहे वह स्वामी के रूप में हो या अनुमत उपयोगकर्ता के रूप में, जैसा भी मामला हो। यह आवश्यक नहीं है कि चिह्न का उपयोग करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान बताए।

8.3.8 कुछ अन्य चिह्न

8.3.8.1 सेवा चिह्न

आधुनिक व्यापार में, उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की वस्तुओं और विविध सेवाओं के विशाल विकल्प का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे चिह्नों की भी आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं जैसे बीमा कंपनियों, केयर रेंटल फर्मों, एयरलाइंस आदि के बीच अंतर करने में मदद करें। ये चिह्न जो इन सेवाओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं, अनिवार्य रूप से वस्तुओं के लिए ट्रेडमार्क द्वारा समान कार्य करते हैं। सेवा चिह्न एक ट्रेडमार्क है, लेकिन इसका उपयोग एक व्यक्ति की सेवाओं को दूसरों की सेवाओं से पहचानने और अलग करने और सेवाओं के स्रोत को इंगित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, एयरटेल, यूपी रोडवेज, दूरदर्शन, हॉलिडे इन, एयर इंडिया, आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध सेवा प्रदाता हैं। रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के शीर्षक, चरित्र के नाम और अन्य विशिष्ट विशेषताएं सेवा चिह्नों के रूप में पंजीकृत हो सकती हैं।

8.3.8.2 सामूहिक चिह्न

सामूहिक चिह्न का अर्थ है एक ट्रेडमार्क जो व्यक्तियों के एक संघ के सदस्यों के माल या सेवाओं को अलग करता है जो साझेदारी नहीं है जो चिह्न का स्वामी है और दूसरों के माल या सेवाओं से अलग है। चिह्न का स्वामी संघ है।

साझेदारी फर्म उन व्यक्तियों के संघ की श्रेणी में नहीं आती है जो सामूहिक चिह्न रख सकते हैं। सामूहिक चिह्नों का प्राथमिक उद्देश्य उत्पाद या सेवाओं की विशेषताओं को दूसरों से अलग करना है। ट्रेडमार्क किसी व्यक्ति के होते हैं लेकिन सामूहिक चिह्न साझेदारी फर्म के अलावा अन्य व्यक्तियों के संघ के होते हैं। उदाहरण के लिए बजाज, गोदरेज आदि। सामूहिक चिह्न का उपयोग आम तौर पर किसके द्वारा किया जा सकता है

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [161]

संगठन के रूप में, लेकिन इसका उपयोग इसके सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। पंजीकरण के संबंध में, एक सामूहिक चिह्न पंजीकृत नहीं किया जाता है यदि यह निर्णायक होने या जनता के लिए भ्रम पैदा करने की संभावना है।

8.3.8.2 उत्पाद चिह्न

इस तरह के ट्रेडमार्क में कोई भी शब्द, नाम, प्रतीक या उपकरण, रंग, योजना या ग्राफिकल प्रस्तुति शामिल होती है जो किसी व्यक्ति के सामान को पहचानने और अलग करने के लिए होती है, जिसमें एक अद्वितीय उत्पाद भी शामिल है जो दूसरों द्वारा निर्मित या बेचा जाता है। यह सामान के स्रोत को इंगित करता है, भले ही वह स्रोत अज्ञात हो।

8.3.8.3 प्रमाणन ट्रेड मार्क्स

प्रमाणन ट्रेडमार्क समाज में बहुत उपयोगी उद्देश्य पूरा करते हैं। लेकिन ये चिह्न बहुत लोकप्रिय नहीं हैं, क्योंकि ये व्यापारियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते, बल्कि ये उपभोक्ताओं के लाभ के लिए होते हैं।

भारत में ऊनी वस्तुओं के संबंध में वूलमार्क और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रमाणन चिह्नों के संबंध में एगमार्क। निर्दिष्ट उत्पादों पर प्रमाणन चिह्न की उपस्थिति उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता या विशेषताओं के बारे में आश्वस्त करती है। इसका कार्य यह इंगित करना नहीं है कि माल की कुछ विशेषताओं के अनुसार चिह्न के स्वामी द्वारा माल को प्रमाणित किया गया है। इसमें भौगोलिक उत्पत्ति, सामग्री आदि शामिल हो सकते हैं।

प्रमाणन चिह्न शब्द के तकनीकी अर्थ में एक चिह्न है, इसलिए 'चिह्न' की परिभाषा इस पर लागू होती है। पंजीकरण के उद्देश्य से इसे ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि ट्रेडमार्क की परिभाषा में प्रमाणपत्र चिह्न शामिल है, इसलिए उल्लंघन का दायरा प्रमाणन चिह्न को भी कवर करता है।

8.3.8.4 सुप्रसिद्ध ट्रेड मार्क

सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क शब्द का प्रयोग पहली बार ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में किया गया है तथा इसे उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(जेडजी) में परिभाषित किया गया है। सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क वह सामान्य ट्रेडमार्क है जो सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क का स्वरूप प्राप्त कर सकता है। जब उपभोक्ता जनता किसी वस्तु या सेवा पर ट्रेडमार्क देखकर उसे किसी अन्य वस्तु या सेवा पर पहले से उपयोग किए गए ट्रेडमार्क से जोड़ती है, तो ऐसे ट्रेडमार्क को सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क माना जाता है। मारुति, ज़ेरॉक्स, लक्स, कोलगेट सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क के कुछ उदाहरण हैं।

ट्रिप्स के अनुच्छेद 16(2) की नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय कानून की परिभाषा को अपनाया गया है।

8.3.8.5 भ्रामक रूप से समान कार्य

“भ्रामक रूप से समान” अभिव्यक्ति का अर्थ है वह जो दूसरे चिह्न से इतना मिलता-जुलता हो कि धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना हो। भ्रामकता का निर्धारण करने के लिए मानदंड अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

कानून में निर्धारित किया गया है। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत मामलों का फैसला करते समय अधिकारियों का महत्व बहुत अधिक नहीं होता।

8.3.9 ट्रेडमार्क को अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों से अलग किया गया

पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क औद्योगिक संपत्ति हैं क्योंकि इनका उपयोग किसी प्रकार के उद्योग या व्यवसाय में किया जाता है। इन्हें बौद्धिक संपदा के रूप में उपयुक्त रूप से कहा जाता है। बौद्धिक संपदा ने हाल के दिनों में दुनिया भर में एक नया मूल्य और महत्व प्राप्त किया है। संक्षेप में परिभाषित करें तो, "बौद्धिक संपदा मानव बुद्धि या मन का एक उत्पाद है। इस संपत्ति को खरीदा या बेचा जा सकता है, किराए पर लिया जा सकता है या लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। इस संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिए गए अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है।"

बौद्धिक संपदा अधिकार बौद्धिक पूंजी से मूल्य निकालने के लिए उपकरण प्रदान करता है। इसे लोगों को उनके मन की रचनाओं पर दिया गया अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है।

पेटेंट स्वामी को सीमित अवधि के लिए पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया को बनाने, बेचने या उपयोग करने का एकाधिकार अधिकार होता है।

इसी तरह पंजीकृत डिज़ाइन के स्वामी को सीमित अवधि के लिए डिज़ाइन लागू करने का एकाधिकार अधिकार होता है। कॉपीराइट में, जिस कार्य पर कॉपीराइट होता है, उसके लेखक को एक निश्चित अवधि के लिए विशेष अधिकार दिया जाता है।

दूसरी ओर, किसी व्यापारी द्वारा चुना गया ट्रेडमार्क आवश्यक रूप से आविष्कारशील कौशल या बौद्धिक श्रम का परिणाम नहीं होता है। ट्रेडमार्क के स्वामी को विशेष वस्तुओं के संबंध में इसका उपयोग करने का स्थायी अधिकार प्राप्त होता है।

यह अधिकार अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के विपरीत आजीवन और शाश्वत है। ट्रेडमार्क अधिकार और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच यही बुनियादी अंतर है। ट्रेडमार्क अपने असाइनमेंट के संबंध में भी पेटेंट और कॉपीराइट से अलग है। पेटेंट या कॉपीराइट के विपरीत, जहां आविष्कार या काम में ही संपत्ति के अधिकार होते हैं।

बौद्धिक संपदा के रूप में ट्रेडमार्क स्वामित्व के हस्तांतरण के अधीन है। हालाँकि, मूल रूप से, ट्रेडमार्क का एकमात्र कार्य स्रोत की पहचान करना माना जाता था। सद्भावना और ट्रेडमार्क को अविभाज्य माना जाता था और इसलिए सद्भावना के बिना ट्रेडमार्क का असाइनमेंट व्यवहार्य नहीं माना जाता था। हालाँकि, ट्रेडमार्क के कार्य के संबंध में दृष्टिकोण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इसकी स्थिति सद्भावना के प्रतीक से बदलकर सद्भावना के निर्माण के सबसे प्रभावी एजेंट के रूप में बदल गई। अंततः, यह अपने आप में एक अच्छा बन गया।

8.4 सारांश

ट्रेडमार्क व्यापार, वाणिज्य और संभोग में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वास्तव में, ट्रेडमार्क वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ा एक प्रतीक है, जो उन्हें समान विवरण वाली अन्य वस्तुओं या सेवाओं से अलग करता है। ट्रेडमार्क की उत्पत्ति का पता वस्तुओं के प्रचलन की शुरुआत से लगाया जा सकता है। मानव जाति और धर्म के इतिहास में, औद्योगिक क्रांति और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण, ट्रेडमार्क की सुरक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ गई और साथ ही

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [163]

उनके धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग की आशंका के लिए। मूल रूप से, ट्रेडमार्क चार प्रकार के होते हैं, अर्थात् माल के लिए ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, सामूहिक चिह्न और प्रमाणन चिह्न। रंगीन चिह्न, त्रि-आयामी चिह्न और श्रव्य चिह्न जैसे कुछ चिह्न वर्तमान समय के बाजारों में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ट्रेडमार्क विभिन्न कार्य करते हैं जैसे उत्पाद और उसके मूल की पहचान, यह माल की स्थापित गुणवत्ता की गारंटी देता है, विज्ञापन का साधन है और उत्पाद या सेवा को अलग करके जनता को भ्रम और धोखे से बचाता है।

8.5 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न.

क. ट्रेड मार्क को परिभाषित करें।

ख. ट्रेड मार्क के कार्य क्या हैं?

2. रिक्त स्थान भरें

a. व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958, कब लागू हुआ b. ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा _____ में परिभाषित किया गया है।

3. सत्य या असत्य

क. बौद्धिक संपदा के रूप में ट्रेडमार्क स्वामित्व के हस्तांतरण के अधीन है।

ख. सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क शब्द का प्रयोग पहली बार ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में किया गया है।

8.6 संदर्भ

ट्रेड मार्क्स से संबंधित कानून- उल्लंघन और संबद्ध पहलू, रजित शर्मा (रीगल) द्वारा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016)

8.7 सुझाए गए पठन सामग्री

बौद्धिक संपदा अधिकार BLWadehra द्वारा

बौद्धिक संपदा अधिकार, पी. नारायणन

8.8 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

क. विभिन्न प्रकार के ट्रेड मार्क पर चर्चा करें।

ख. ट्रेडमार्क कानून के विकास की व्याख्या करें।

उत्तर:

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [164]

एसएक्यू

1. लघु उत्तरीय प्रश्न.

क. 8.3.1 देखें

बी. 8.3.2 देखें

2. रिक्त स्थान भरें

क. 25 नवंबर, 1959. ख. 2(1)

(जेडबी)

3. सत्य या असत्य

सच्चा

ख. सत्य

अंतिम प्रश्न और उत्तर

क. 8.3.8 देखें

बी. 8.3.6 देखें

यूनिट-10

भारत में ट्रेडमार्क कानून

संरचना

9.1 परिचय

9.2 उद्देश्य

9.3 विषय

9.3.1 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 का अधिनियमन

9.3.2 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की मुख्य विशेषताएं

9.3.3 भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण

9.3.3.1 पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें

9.3.3.2 पंजीकरण से इनकार करने के पूर्ण आधार

9.3.3.3 पंजीकरण से इनकार करने के सापेक्ष आधार

9.3.3.4 पंजीकरण की प्रक्रिया

9.3.4 ट्रेडमार्क का उल्लंघन

9.3.5 पासिंग ऑफ

9.3.6 ट्रेडमार्क कमजोरीकरण

9.4 सारांश

9.5 एसएक्यूएस

9.6 संदर्भ

9.7 सुझाए गए पठन सामग्री

9.8 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल उत्तर

9.1 परिचय

भारत के ट्रेडमार्क कानून की जड़ें यूनाइटेड किंगडम की सामान्य कानून प्रणाली में पाई जाती हैं। यूके ट्रेडमार्क पंजीकरण अधिनियम यूके में पहला ट्रेडमार्क कानून था जो 1875 में अस्तित्व में आया था। इसने पहली बार इंग्लैंड में ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रदान किया। 1875 के बाद, यूके में 1905 का अधिनियम लागू किया गया जिसे निरस्त कर दिया गया और 1938 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान में ट्रेडमार्क पर कानून यूनाइटेड किंगडम में ट्रेडमार्क अधिनियम, 1994 द्वारा शासित है। वैधानिक कानून की अनुपस्थिति में ट्रेडमार्क को केवल सामान्य कानून संरक्षण ही उपलब्ध था। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1940 भारत में ट्रेडमार्क के विषय पर पहला पूर्ण कोड था। हालाँकि, 1889 में, भारतीय व्यापारिक चिह्न अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन यह अपने आप में एक पूर्ण कोड नहीं था। 1940 के अधिनियम को दोहराया गया और व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें ट्रेडमार्क अधिनियम, 1940, भारतीय व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1889 और इसमें निहित कुछ ट्रेडमार्क प्रावधानों को समेकित किया गया।

आईपीसी, सीआरपीसी, विशिष्ट राहत अधिनियम और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 की जगह लेता है और ट्रेडमार्क पर कानून को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं के बराबर लाने का एक समेकित प्रयास है। यह 'ट्रेडमार्क' को "एक चिह्न के रूप में परिभाषित करता है जिसे ग्राफिक रूप से दर्शाया जा सकता है और एक व्यक्ति के सामान या सेवाओं को दूसरों से अलग करने में सक्षम है।" ऐसे कई चिह्न हैं जो ट्रेडमार्क के रूप में काम कर सकते हैं।

इनमें शब्द, अक्षर और अंक, उपकरण, शीर्षक, नाम, रंगीन चिह्न, श्रव्य संकेत, त्रि-आयामी संकेत आदि शामिल हो सकते हैं। मूलतः ट्रेडमार्क चार प्रकार के होते हैं, अर्थात् उत्पाद चिह्न, सेवा चिह्न, सामूहिक चिह्न और प्रमाणन चिह्न।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के अधिनियमन की पृष्ठभूमि को समझें
- ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें
- भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण के बारे में जानें • ट्रेडमार्क के उल्लंघन की व्याख्या करें
- पासिंग ऑफ का वर्णन करें
- ट्रेड मार्क कमजोरीकरण के बारे में जानें
- ट्रेड मार्क को पासिंग ऑफ और ट्रेड मार्क डाइल्यूशन से अलग करना

9.3 विषय

9.3.1 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 का अधिनियमन

व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 में व्यापक संशोधनों को देखते हुए, आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए उक्त अधिनियम को निरस्त करना और पुनः अधिनियमित करना उचित समझा गया। ट्रेडमार्क विधेयक, 1999 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 30 दिसंबर, 1999 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम ने ट्रेडमार्क से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित किया है और खाद्य पदार्थों और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा का प्रावधान किया है। अधिनियम का एक उद्देश्य धोखाधड़ी वाले चिह्नों के उपयोग की रोकथाम करना है।

9.3.2 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की मुख्य विशेषताएं

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999, व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 का स्थान लेता है।

यह अधिनियम कानून को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के समकक्ष लाने का एक समेकित प्रयास है।

- (1) पहली बार, यह अधिनियम सेवा चिह्नों की भी सुरक्षा करना चाहता है। जिन सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत किया जा सकता है, उनमें विज्ञापन और व्यवसाय, बीमा और वित्त, निर्माण और मरम्मत, परिवहन और भंडारण, बोर्डिंग और लॉजिंग, शिक्षा और मनोरंजन शामिल हैं।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [167]

- (2) ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 ट्रेडमार्क की परिभाषा के दायरे का विस्तार करता है, जिसमें ग्राफिक प्रतिनिधित्व, आकार, पैकेजिंग और रंगों का संयोजन शामिल है तथा इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है।
- (3) अन्य शब्दों जैसे "चिह्न", "सामूहिक चिह्न", "माल", "पंजीकृत ट्रेडमार्क", "अनुमत उपयोग" का दायरा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप विस्तारित किया गया है।
- (4) अपीलीय न्यायालय के गठन से न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र भी प्रभावित होता है।
न्यायाधिकरण.
- (5) अधिनियम भाग ए और बी पंजीकरण की पुरानी प्रणाली को हटाकर ट्रेडमार्क के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रावधान करता है।
- (6) इसमें एक से अधिक वर्गों में पंजीकरण के लिए एक ही आवेदन की अनुमति प्रदान की गई है तथा पंजीकरण एवं नवीकरण की अवधि को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है।
- (7) अधिनियम में वस्तुओं और सेवाओं के मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण का भी प्रावधान है।
- (8) ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को वस्तुओं के वर्गीकरण में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं और सेवाएं.
- (9) ट्रेडमार्क कानून के दायरे को "उल्लंघन" की परिभाषा में विस्तारित किया गया है।
इस अधिनियम में उल्लंघन की परिभाषा में न केवल भ्रामक रूप से समान, बल्कि समान चिह्न, समान वस्तुएं और यहां तक कि उन वस्तुओं को भी शामिल किया गया है जो उन वस्तुओं से समान नहीं हैं जिनके लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत है।
- (10) इस अधिनियम के तहत ट्रेडमार्क का उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध है। पुलिस उन मामलों में कार्रवाई कर सकती है जहां उल्लंघन होने की संभावना है।

9.3.3 भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण

ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए पहली बार व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 में प्रावधान किए गए थे। पहले से उपयोग में आने वाले ट्रेडमार्क और साथ ही उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क भी पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जा सकते थे। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत ट्रेडमार्क और सेवा चिह्नों के व्यापक पंजीकरण का प्रावधान किया गया है।

व्यापार में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी चिह्न पंजीकृत नहीं हैं। वे पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकते हैं। ट्रेडमार्क कानून व्यापार और कारोबार में प्रयुक्त सभी चिह्नों के पंजीकरण का प्रावधान नहीं करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, पंजीकरण कहलाती है। केवल वे चिह्न ही पंजीकृत किए जा सकते हैं जो कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में पंजीकरण योग्य चिह्नों की श्रेणियों या चिह्न के पंजीकरण के लिए अपेक्षित शर्तों को परिभाषित नहीं किया गया है। यह केवल यह परिभाषित करता है कि कौन से चिह्न पंजीकरण योग्य नहीं हैं। धारा 9 के तहत इनकार करने के लिए ये पूर्ण आधार हैं और पंजीकरण के लिए ट्रेडमार्क के इनकार के सापेक्ष आधार हैं। पंजीकरण ट्रेडमार्क के स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

जबकि, पंजीकरण न होने की स्थिति में ट्रेडमार्क के उपयोगकर्ता को पूर्व उपयोग और पासिंग ऑफ को स्थापित करना होगा।

ट्रेडमार्क का पंजीकरण अधिनियम की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे ट्रेडमार्क का उपयोगकर्ता जो पंजीकृत नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति को इसके अनधिकृत उपयोग से रोक सकता है और हर्जाना वसूल सकता है। लेकिन ऐसे उपयोगकर्ता को अपना मामला साबित करने और यहां तक कि अपना बचाव करने के लिए बहुत सारे और पर्याप्त सबूत देने होंगे। पंजीकृत ट्रेडमार्क के मामले में ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी के स्वामित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। ट्रेडमार्क का पंजीकरण ट्रेडमार्क की वैधता का प्रथम दृष्टया सबूत है। ट्रेडमार्क का पंजीकरण स्वामी को उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में ट्रेडमार्क का उपयोग करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है जिनके संबंध में ट्रेडमार्क पंजीकृत है। यह उन वस्तुओं के संबंध में राहत प्राप्त करने का विशेष अधिकार भी प्रदान करता है जिनके संबंध में ट्रेडमार्क पंजीकृत है और अधिनियम में दिए गए तरीके से ट्रेडमार्क के उल्लंघन के संबंध में राहत प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

9.3.3.1 पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें

किसी चिह्न की पंजीकरण योग्यता के लिए बुनियादी योग्यता ट्रेडमार्क की परिभाषा में ही निहित है। पहली आवश्यकता यह है कि कोई चिह्न ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के अर्थ में ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क की परिभाषा से निम्नलिखित शर्तें उभर कर आती हैं। ट्रेडमार्क होना चाहिए:

(a) एक व्यक्ति की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य व्यक्तियों से अलग करने में सक्षम।

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 2(1) (जेडबी) में ट्रेडमार्क की परिभाषा में शब्दों की उपस्थिति से विशिष्ट चरित्र उभरता है। "एक व्यक्ति के सामान को दूसरों के सामान से अलग करने में सक्षम..."

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में 'विशिष्ट चरित्र' शब्द को 1958 अधिनियम में 'विशिष्टता' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 यह भी मानता है कि विशिष्ट चरित्र अंतर्निहित या अर्जित हो सकता है। विशिष्टता को ट्रेडमार्क में कुछ गुणवत्ता के रूप में समझा गया है जो इस तरह से चिह्नित वस्तुओं को अन्य उत्पादों या वस्तुओं से अलग बनाती है। यह अंतर्निहित हो सकता है या समय के साथ अर्जित किया जा सकता है।

(ii) दूसरे, चिह्न को ग्राफिक रूप में प्रदर्शित किया जा सकने योग्य होना चाहिए।

9.3.3.2 पंजीकरण से इनकार करने के पूर्ण आधार

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जो ट्रेडमार्क के पंजीकरण को अस्वीकार करते हैं। इन आधारों को पूर्ण आधार कहा जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत इनका प्रावधान किया गया है। ये निम्नलिखित हैं:

(a) ऐसे ट्रेडमार्क जो किसी विशिष्ट चरित्र से रहित हों, अर्थात् एक व्यक्ति के सामान या सेवाओं को दूसरे से अलग करने में सक्षम न हों, पंजीकरण योग्य नहीं हैं।

(ii) ट्रेडमार्क जो प्रकार, गुणवत्ता और मात्रा दर्शाता है, वह भी पंजीकरण योग्य नहीं है।

(iii) ऐसे ट्रेडमार्क जिनमें ऐसे चिह्न या संकेत शामिल हों जो वर्तमान भाषा में प्रचलित हो गए हैं, वे भी पंजीकरण योग्य नहीं हैं।

हालांकि, किसी ट्रेडमार्क का पंजीकरण अस्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आवेदन की तिथि से पहले, उसने उपयोग के परिणामस्वरूप विशिष्ट चरित्र प्राप्त कर लिया हो या यदि वह पहले से ही एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क हो।

(iv) कोई चिह्न तब भी पंजीकृत नहीं किया जाएगा यदि वह ऐसी प्रकृति का हो जो जनता को धोखा देने वाला हो या भ्रम पैदा करने वाला हो या जिसमें कोई ऐसी बात हो जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हों या जो निंदनीय हो या जिसमें कुछ अश्लील बातें हों।

(v) यदि चिह्न प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत प्रतिबंधित है तो उसे पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

पूर्ण आधार विशिष्टता के प्रति अंतर्निहित आपत्तियों और कुछ जनहित आपत्तियों से संबंधित हैं।

(vi) कोई चिह्न उस स्थिति में भी ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब उसमें केवल वस्तुओं के ऐसे आकार शामिल हों, जो स्वयं वस्तुओं की प्रकृति के कारण उत्पन्न हुए हों, या वस्तुओं के ऐसे आकार हों, जो तकनीकी परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों, या ऐसे आकार हों, जो वस्तुओं को पर्याप्त मूल्य प्रदान करते हों।

9.3.3.3 पंजीकरण से इनकार करने के सापेक्ष आधार

किसी ट्रेडमार्क का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, यदि वह किसी पूर्ववर्ती ट्रेडमार्क के समरूप है, या यदि वह किसी पूर्ववर्ती ट्रेडमार्क के समान है तथा समान वस्तुओं और सेवाओं को कवर करता है, जिससे जनता के मन में भ्रम पैदा होता है।

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 11 पंजीकरण से इनकार करने के लिए सापेक्ष आधार प्रदान करती है। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी ट्रेडमार्क में पहले से मौजूद किसी प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के साथ समानता या पहचान है, लेकिन इसे किसी अन्य श्रेणी के सामान पर लागू करने की कोशिश की जाती है, तो भी इसे पंजीकृत नहीं किया जाएगा। क्योंकि यह किसी प्रसिद्ध ब्रांड का अनुचित लाभ उठाने या पहले से मौजूद प्रसिद्ध ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है।

यदि कोई ट्रेडमार्क किसी कानून का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से किसी अपंजीकृत ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए पासिंग ऑफ कानून या कॉपीराइट कानून का, तो उसे पंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणियों के चिह्न भी पंजीकृत नहीं किए जा सकते हैं:

(i) एक शब्द जो किसी एकल रासायनिक तत्व या एकल रासायनिक यौगिक का सामान्यतः प्रयुक्त और स्वीकृत नाम है; तथा

(ii) कोई भौगोलिक नाम या उपनाम या व्यक्तिगत नाम या कोई सामान्य संक्षिप्त नाम या भारत में किसी संप्रदाय, जाति या जनजाति का नाम।

अधिनियम में ईमानदार, समवर्ती उपयोग के मामले में एक से अधिक स्वामियों के लिए एक ही या समान ट्रेडमार्क के पंजीकरण का प्रावधान है, यदि रजिस्ट्रार की राय में विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना उचित हो।

जहां ट्रेडमार्क का स्वामी यह दावा करता है कि उसे ट्रेडमार्क के किसी भाग के अनन्य उपयोग का अधिकार है, वहां वह संपूर्ण ट्रेडमार्क और उसके भाग को अलग-अलग ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन कर सकता है।

9.3.3.4 पंजीकरण की प्रक्रिया

भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के रखरखाव के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित किया गया है। पेटेंट और डिजाइन के महानियंत्रक भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार में सभी पंजीकृत ट्रेडमार्क का रिकॉर्ड होता है, जिसमें मालिकों और उपयोगकर्ताओं के नाम, पते और विवरण, असाइनमेंट और ट्रांसमिशन शामिल होते हैं। इसमें शर्तें और सीमाएँ और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के नाम भी शामिल होते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो किसी ट्रेडमार्क का स्वामी होने का दावा करता है, वह इसके पंजीकरण के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर सकता है। ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए ट्रेडमार्क का स्वामी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति, फर्म के भागीदार, निगम, किसी सरकारी विभाग, ट्रस्ट या संयुक्त आवेदक के नाम पर आवेदन किया जा सकता है। ट्रेडमार्क का उपयोग जिन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में किया जाना है, उनका नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(i) आवेदन

जो व्यक्ति अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए ट्रेडमार्क का स्वामी होने का दावा करता है और इसे पंजीकृत करने का इच्छुक है, उसे निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार को लिखित रूप में आवेदन करना होगा। विभिन्न श्रेणियों के सामान और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए एक ही आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए देय शुल्क आवेदन के साथ निर्धारित रूप से संलग्न होना चाहिए। ऐसा प्रत्येक आवेदन उस ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के कार्यालय में दायर किया जाना है जिसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आवेदक का मुख्य व्यवसाय स्थान स्थित है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, रजिस्ट्रार आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या इसे पूर्ण रूप से या संशोधनों, संशोधनों, शर्तों या सीमाओं के अधीन स्वीकार कर सकता है। किसी आवेदन के अस्वीकार या सशर्त स्वीकृति के मामले में, रजिस्ट्रार ऐसे अस्वीकार या सशर्त स्वीकृति के आधारों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(ii) आवेदन का विज्ञापन

जहां ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, चाहे पूर्ण रूप से या शर्तों के अधीन। रजिस्ट्रार यथाशीघ्र स्वीकृति के पश्चात आवेदन को निर्धारित तरीके से विज्ञापित करवाएगा।

(iii) विरोध और पंजीकरण

कोई भी व्यक्ति विज्ञापन की तिथि से तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रार को पंजीकरण के विरोध में लिखित रूप में नोटिस दे सकता है। रजिस्ट्रार विरोध के लिए आवेदन करने की अवधि को एक महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता है। रजिस्ट्रार द्वारा विरोध के नोटिस की एक प्रति आवेदक को प्रति-बयान दाखिल करने के लिए दी जाती है। रजिस्ट्रार दोनों पक्षों को उचित सुनवाई देते हुए, यदि आवश्यक हो या उनके संबंधित विचारों पर विचार करने के बाद इस मुद्दे पर निर्णय लेता है।

जब पंजीकरण की प्रक्रिया, जिसमें विरोध, यदि कोई हो, शामिल है, संतोषजनक रूप से पूरी हो जाती है, तो रजिस्ट्रार को आवेदन की तिथि से चिह्न को पंजीकृत करने का अधिकार होता है। ट्रेडमार्क के पंजीकरण के बाद, रजिस्ट्रार आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र जारी करता है। ट्रेडमार्क का पंजीकरण दस वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन निर्धारित नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर इसे अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

9.3.4 ट्रेड मार्क का उल्लंघन

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में 'उल्लंघन' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि अधिनियम उन परिस्थितियों और स्थितियों की व्याख्या करता है जिनके अंतर्गत किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया जाता है।

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन सी बातें उल्लंघन मानी जाएंगी या कौन से कार्य ट्रेडमार्क का उल्लंघन माने जाएंगे।

ट्रेडमार्क का उल्लंघन ट्रेडमार्क के पंजीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करने में निहित है। कभी-कभी अधिकार पूर्ण होते हैं और कभी-कभी वे रजिस्टर में विधिवत दर्ज प्रतिबंधात्मक शर्तों और सीमाओं के अधीन होते हैं। मूल रूप से, ट्रेडमार्क के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं:

(*) व्यक्ति को ऐसे चिह्न का उपयोग करना चाहिए जो पंजीकृत ट्रेडमार्क के समरूप हो या भ्रामक रूप से समान हो।

(ii) जिन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में इसका उपयोग किया जाता है, वे पंजीकरण के अंतर्गत आनी चाहिए।

(iii) चिह्न का उपयोग व्यापार के दौरान उस क्षेत्र में किया जाना चाहिए जो इसके अंतर्गत आता हो।
पंजीकरण।

(iv) उपयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि इसे अवैध उपयोग के रूप में लिया जा सके।
ट्रेडमार्क.

(v) प्रतिवादी अनुमत उपयोगकर्ता नहीं होना चाहिए जिसमें पंजीकृत उपयोगकर्ता और दोनों शामिल हैं
अपंजीकृत उपयोगकर्ता.

यदि उपयोग से उपभोक्ता के मन में भ्रम या धोखा पैदा होने की संभावना है या ट्रेडमार्क के साथ इसका संबंध होने की संभावना है, तो यह उल्लंघन है। वे सामान या सेवाएँ जो समान सामान या सेवाओं का हिस्सा होंगी, वे न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या पर निर्भर करती हैं। ट्रेडमार्क की तुलना के संबंध में एक साथ तुलना करना अनुचित है। चिह्नों की समानता उन्हें अलग-अलग देखकर निर्धारित की जानी चाहिए।

न्यायालय वस्तुओं की प्रकृति, व्यापार चैनलों और जनता द्वारा संबद्धता की संभावना के संबंध में वस्तुओं या सेवाओं की समानता निर्धारित करते हैं। 'समान वस्तुओं' का दायरा 'समान या समान वर्णन' वाली वस्तुओं की तुलना में काफी बड़ा है। 'समान' शब्द में असमान या भिन्न वस्तुओं को छोड़कर स्थानापन्न वस्तुओं सहित अन्य सभी वस्तुएं शामिल होंगी। यह निर्धारित करना कठिन है कि समानता कब समाप्त होती है और असमानता कब शुरू होती है। व्यापार के दौरान समान या भ्रामक रूप से समान चिह्नों का उपयोग उल्लंघन का कारण बन सकता है। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में "भ्रामक रूप से समान" शब्द को एक चिह्न के रूप में परिभाषित किया गया है यदि यह किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क से इतना मिलता-जुलता है कि धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है। धोखे या भ्रम के कारण होने वाला उल्लंघन वस्तुओं के संबंध में धोखे या भ्रम, व्यापार की उत्पत्ति के संबंध में धोखे या भ्रम या व्यापार संबंध के संबंध में धोखे या भ्रम के रूप में उत्पन्न हो सकता है। स्थिति के लिए वास्तविक धोखे या भ्रम की आवश्यकता नहीं होती है। चिह्नों की समानता का न्याय करते समय, न्यायालय कभी-कभी चिह्न के विचार पर जोर देते हैं। अर्थात्, वे चिह्न के विवरण पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि उससे व्यक्त होने वाले सामान्य विचार पर देते हैं।

कुछ वस्तुओं से लेकर समान वस्तुओं तक तथा यहां तक कि सुप्रसिद्ध चिह्नों के संबंध में असमान वस्तुओं तक उल्लंघन के संबंध में ट्रेडमार्क के अधिकार का विस्तार कानून को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं के समतुल्य लाने का एक प्रयास है। प्रतिष्ठित ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा पर व्यापार करना उल्लंघन माना जाता है।

पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए मुकदमा ऐसे जिला या उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए जिसके पास ऐसे मुकदमों पर विचार करने का मूल अधिकार क्षेत्र हो। ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि उल्लंघन की तारीख से तीन वर्ष है। जहां उल्लंघन जारी है, वहां हर बार उल्लंघन होने पर कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न होगा।

घटित होना।

उल्लंघन कार्रवाई एक वैधानिक अधिकार है जो पंजीकरण की वैधता पर निर्भर करता है और अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य प्रतिबंधों और सीमाओं के अधीन है। जहां प्रतिवादी का ट्रेडमार्क वादी के चिह्न के समान है, वहां न्यायालय यह जांच नहीं करेगा कि क्या उल्लंघन ऐसा है जिससे भ्रम पैदा होने की संभावना है। भ्रम की संभावना के बारे में परीक्षण उल्लंघन कार्रवाई में चिह्नों की समानता से उत्पन्न होता है।

ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मामले में उपाय उपलब्ध कराए जाते हैं। ये उपाय मार्क के पंजीकृत स्वामी या उपयोगकर्ता द्वारा उठाए गए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदान किए जाते हैं। पंजीकृत ट्रेडमार्क के मामले में ट्रेडमार्क कानून कुछ उपाय प्रदान करता है। उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर करके कानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय प्राप्त कर सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उपलब्ध नागरिक उपाय कमोबेश किसी अन्य प्रकार की संपत्ति के उल्लंघन के लिए उपलब्ध उपायों के समान हैं।

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में उन राहतों को निर्दिष्ट किया गया है जो न्यायालय उल्लंघन के मामले में दे सकता है। राहतों में शामिल हैं:

(ए) निषेधादेश, जो ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन हो सकता है जिन्हें न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझे।

(ख) क्षति या लाभ का लेखा;

(सी) उल्लंघनकारी लेबलों को नष्ट करने या मिटाने के लिए सौंपना।

वादी को किसी एक राहत या सभी राहतों का दावा करने का विकल्प दिया जाता है और अदालत राहत प्रदान कर सकती है। किसी निश्चित मामले में उन सभी या उनमें से किसी एक या अधिक का चुनाव कई कारकों पर निर्भर करता है।

अस्थायी निषेधाज्ञा की राहत निम्नलिखित में से किसी भी मामले के लिए एकपक्षीय रूप से भी दी जा सकती है:

(i) दस्तावेजों की खोज के लिए।

(ii) माल या दस्तावेज या पर्याप्त साक्ष्य को संरक्षित करने के लिए;

(iii) प्रतिवादी को ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए, जो वादी की क्षतिपूर्ति, लागत या किसी अन्य आर्थिक उपचार को वसूलने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो अंततः वादी को प्रदान किया जा सकता है।

इसके अलावा, अधिनियम में यह प्रावधान है कि न्यायालय क्षतिपूर्ति के रूप में राहत प्रदान नहीं करेगा। निम्नलिखित स्थितियों में नाममात्र की क्षति या लाभ के कारण को छोड़कर:

1) प्रमाणन या सामूहिक चिह्न के उल्लंघन के मामले में; या

2) यदि उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी निम्नलिखित मामलों के लिए अदालत को संतुष्ट करता है। जिस समय उसने चिह्न का उपयोग शुरू किया, वह इस बात से अनभिज्ञ था कि वादी

ऐसे चिह्न का पंजीकृत उपयोगकर्ता और जब उसे ट्रेडमार्क में वादी के अधिकार के अस्तित्व और प्रकृति के बारे में पता चला तो उसने ट्रेडमार्क का उपयोग करना बंद कर दिया। उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में ट्रेडमार्क का उपयोग जिसके संबंध में इसे पंजीकृत किया गया था।

क) निषेधाज्ञा

पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन को रोकने में निषेधाज्ञा सबसे प्रभावी उपाय है। यह न्यायालय का विशिष्ट आदेश है, जिसमें प्रतिवादी को उल्लंघन के कार्य से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है। यह किसी व्यक्ति को दूसरे द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा और साख को भुनाने से रोकने के लिए उचित उपाय है। निषेधाज्ञा के आदेश में एकतरफा निषेधाज्ञा या दस्तावेजों की खोज, या उल्लंघनकारी वस्तुओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्यों को संरक्षित करने के लिए कोई अंतरिम आदेश शामिल हो सकता है। इसमें प्रतिवादी को अपनी संपत्तियों का निपटान या उससे निपटने से रोकने का आदेश भी शामिल हो सकता है, जो वादी की क्षतिपूर्ति, लागत या अन्य आर्थिक उपचारों को वसूलने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, जो अंततः वादी को दिए जा सकते हैं।

ख) हर्जाना

हर्जाना ट्रेडमार्क के पंजीकृत स्वामी या उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराया जाने वाला एक अन्य प्रकार का उपाय है। हर्जाना स्वामी या उपयोगकर्ता को अनधिकृत उपयोग के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से दिया जाता है। प्रतिवादी द्वारा वादी को पहुँचाई गई कानूनी चोट या नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना दिया जा सकता है। न्यायालय कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हर्जाने की राशि तय करता है। ये चिह्न की प्रतिष्ठा, स्वामी का व्यवसाय और उल्लंघन की अवधि आदि हो सकते हैं। यह न्यायालय द्वारा वादी को दिया जाने वाला हर्जाना है, भले ही वादी को वास्तव में कितना भी नुकसान हुआ हो।

ग) लाभ का लेखा

न्यायालय दंड के उपाय के रूप में लाभ के साथ-साथ हर्जाना भी दे सकता है। यह जुर्माना उल्लंघनकर्ता पर स्वामी या उपयोगकर्ता के प्राधिकरण के बिना चिह्न का उपयोग करने के लिए लगाया जाता है। न्यायालय अनधिकृत उपयोग के कारण उल्लंघनकर्ता द्वारा प्राप्त वास्तविक लाभ को मापने के लिए लाभ के खाते प्रदान कर सकता है। ट्रेडमार्क के उल्लंघन या पासिंग ऑफ के लिए उपाय वही हैं, जो ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत प्रदान किए गए हैं। भारत में, ट्रेडमार्क उल्लंघन में हर्जाने से जुड़े सिद्धांत अभी भी विकसित हो रहे हैं और भारतीय न्यायालय लगातार नई व्याख्याओं को अपना रहे हैं और विकसित कर रहे हैं।

9.3.5 पासिंग ऑफ

पंजीकृत ट्रेडमार्क की तरह, अपंजीकृत ट्रेडमार्क भी चिह्न के धारक या मालिक की संपत्ति है। यह पासिंग ऑफ़ की सामान्य कानूनी कार्रवाई द्वारा संरक्षित है। पासिंग ऑफ़ कार्रवाई के लिए ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रासंगिक नहीं है। यह चिह्न के उपयोग से अर्जित सद्भावना संपत्ति पर आधारित है। पासिंग ऑफ़ कार्रवाई के मामले में प्रतिवादी के सामान वादी के सामान के समान होने की आवश्यकता नहीं है, वे संबद्ध या भिन्न भी हो सकते हैं। हालांकि, प्रसिद्ध ट्रेडमार्क पर आधारित उल्लंघन के दावे में तब भी उल्लंघन हो सकता है जब ट्रेडमार्क का उपयोग विभिन्न सामानों के लिए किया जाता है। दुर्गा दत्त शर्मा बनाम एनपी लैबोरेटरीज (एआईआर 1965 एससी 980.) मामले में उल्लंघन कार्रवाई और पासिंग ऑफ़ के बीच अंतर बताया गया है।

पासिंग ऑफ के लिए कार्रवाई एक सामान्य कानूनी उपाय है, जो कि मूल रूप से छल के लिए कार्रवाई है, अर्थात् किसी व्यक्ति द्वारा अपने माल को दूसरे के माल के रूप में पास करना। लेकिन उल्लंघन के लिए कार्रवाई का सार यह नहीं है। उल्लंघन के लिए कार्रवाई एक वैधानिक उपाय है जो पंजीकृत ट्रेडमार्क के पंजीकृत स्वामी को ट्रेडमार्क का उपयोग करने के अनन्य अधिकार की पुष्टि के लिए प्रदान किया जाता है।

पासिंग ऑफ कार्रवाई का मूल अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने माल को दूसरे के माल के रूप में प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है। पासिंग ऑफ के टोट के तीन मूल तत्व हैं प्रतिष्ठा या सद्भावना, गलत बयानी या धोखा और क्षति। इन्हें कभी-कभी "शास्त्रीय त्रिमूर्ति" के रूप में संदर्भित किया जाता है। पासिंग ऑफ के लिए कार्रवाई में साबित करने वाला पहला कारक संबंधित उत्पाद या सेवा के संबंध में सद्भावना है। दूसरा कारक जो वादी को साबित करना होगा वह प्रतिवादी द्वारा जनता के सामने गलत बयानी है। यह उस चिह्न का उपयोग करके किया जा सकता है जो वादी के चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान या रंग-बिरंगी नकल है। गलत बयानी ट्रेडमार्क की कुछ विशेषताओं का उपयोग करके भी की जा सकती है जिसके द्वारा वादी के सामान को उपभोक्ता जनता के बीच जाना जाता है।

यह तय करने में कि क्या प्रतिवादी का गलत बयान भ्रामक है, अदालत कई कारकों को ध्यान में रख सकती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) दावेदार के चिह्न के साथ जनता के जुड़ाव की ताकत,
- (ii) प्रतिवादी के चिह्न की समानता,
- (iii) दावेदार और प्रतिवादी के व्यवसाय के क्षेत्रों की निकटता,
- (चतुर्थ) बाजार की विशेषताएं,
- (वी) प्रतिवादी का इरादा,
- (vi) क्या प्रतिवादी ने अस्वीकरण किया है या पैरोडी या व्यंग्य का प्रयास किया है।

तीसरा तत्व जिसे दावेदार को पासिंग ऑफ कार्रवाई को कायम रखने के लिए साबित करना होगा, वह यह है कि प्रतिवादी के गलत बयान के परिणामस्वरूप उसे नुकसान हुआ है या होने की संभावना है। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 पासिंग ऑफ के सामान्य कानून के तहत अधिकारों और उपायों को प्रभावित नहीं करता है। 'पासिंग ऑफ' शब्द को ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे उक्त अधिनियम की धारा 27(2), 134(1)(सी) और धारा 135 में संदर्भित किया गया है। अधिनियम पासिंग ऑफ के संबंध में सभी अधिकारों और उपायों को सुरक्षित रखता है और विशेष रूप से घोषित करता है कि इस अधिनियम में कुछ भी इसके संबंध में अधिकारों और उपायों को प्रभावित नहीं करेगा।

पासिंग ऑफ की अवधारणा मूल रूप से टोट का एक रूप है जिसमें समय बीतने और न्यायिक व्याख्याओं के कारण कई बदलाव हुए हैं। पहले यह एक व्यक्ति के सामान को दूसरे व्यक्ति के सामान के रूप में दर्शाने तक सीमित था। बाद में, इसे व्यापार और सेवाओं में विस्तारित किया गया। इसके बाद, इसे व्यवसायों और गैर-व्यापारिक गतिविधियों तक आगे बढ़ाया गया।

आज इसे अनुचित व्यापार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के कई रूपों में लागू किया जाता है, जहाँ एक व्यक्ति की गतिविधियाँ किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की गतिविधियों से जुड़ी सद्भावना को नुकसान या चोट पहुँचाती हैं। पासिंग ऑफ कार्रवाई का उद्देश्य सद्भावना की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि खरीदारों का शोषण न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कैडिला में "पासिंग ऑफ" को परिभाषित किया है

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [175]

हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एआईआर 2001 एससी 1952) को अनुचित व्यापार प्रतिस्पर्धा या कार्रवाई योग्य अनुचित व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति धोखे से उस प्रतिष्ठा का आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसे दूसरे ने किसी विशेष व्यापार या व्यवसाय में अपने लिए स्थापित किया है। इस कार्रवाई को छल के लिए की गई कार्रवाई माना जाता है।

पासिंग ऑफ कई तरह का होता है। व्यापार की तकनीक में हर रोज सुधार के साथ, पासिंग ऑफ के अनगिनत प्रकार सामने आ सकते हैं। पासिंग ऑफ के कानून की स्थापना व्यापारियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। कानून की यह शाखा लगातार विस्तारित हो रही है।

व्यापार में बदलते रुझान और वैश्वीकरण के प्रभाव ने ट्रेडमार्क संरक्षण को अपनी पारंपरिक सीमाओं से परे विस्तारित करने पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। इस प्रवृत्ति का मौलिक उदाहरण ट्रेडमार्क कमजोर पड़ने की अवधारणा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ट्रेडमार्क कमजोर पड़ना एक ट्रेडमार्क कानून की अवधारणा है जो किसी प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के मालिक को दूसरों को उस चिह्न का उपयोग करने से रोकने का अधिकार देता है जिससे उसकी विशिष्टता कम हो जाए। कमजोर पड़ना ट्रेडमार्क उल्लंघन का एक आधार है जो केवल प्रसिद्ध ट्रेडमार्क पर लागू होता है। कमजोर पड़ने से सुरक्षा ट्रेडमार्क के ऐसे उपयोग तक फैली हुई है जो उपभोक्ताओं को भ्रमित नहीं करते हैं। इसके बजाय, कमजोर पड़ने से सुरक्षा कानून का उद्देश्य पर्याप्त रूप से मजबूत ट्रेडमार्क को किसी विशेष उत्पाद के साथ जनता के दिमाग में अपने विलक्षण जुड़ाव को खोने से बचाना है। कमजोर पड़ने को कभी-कभी दो संबंधित अवधारणाओं में विभाजित किया जाता है: धुंधलापन

9.3.6 ट्रेड मार्क कमजोरीकरण

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में 'कमजोरीकरण' शब्द का उल्लेख नहीं है। यह उल्लंघन के इस रूप के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। फिर भी, धारा 29(4) की पूरी संरचना पहले के चिह्न से अलग है क्योंकि 'भ्रम की संभावना' परीक्षण जो ट्रेडमार्क कानून का आवश्यक आधार है, उस तरह के उल्लंघन के संबंध में शामिल नहीं है जिसकी इसमें कल्पना की गई है।

ट्रेडमार्क कमजोरीकरण और ट्रेडमार्क उल्लंघन के बीच अंतर किया जाता है।

उल्लंघन तब होता है जब ट्रेडमार्क स्वामी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस चिह्न का उपयोग इस तरह से करता है जिससे भ्रम पैदा होता है जबकि ग्राहक का भ्रम ट्रेडमार्क कमजोर पड़ने में एक आवश्यक तत्व नहीं है। ट्रेडमार्क का कमजोर पड़ना तब होता है जब ट्रेडमार्क का उपयोग समान वस्तुओं या असमान वस्तुओं पर उपयोग किए जाने के बावजूद चिह्नों की विशिष्टता को कम करता है और उपभोक्ताओं के मन में भ्रम पैदा करने के बावजूद भी।

भारतीय कानून के तहत संरक्षण प्रसिद्ध और पंजीकृत ट्रेडमार्क के लिए है, जिसमें भ्रम की आवश्यकता नहीं है और तब भी जब उपयोग असमान वस्तुओं पर किया जाता है। यह अन्य प्रावधानों से काफी अलग है, जिसमें उल्लंघन के लिए भ्रम को एक आवश्यक घटक के रूप में आवश्यक माना जाता है। यह प्रसिद्ध ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए उल्लंघन का एक विस्तार है।

9.4 निष्कर्ष

भारतीय ट्रेडमार्क कानून की जड़ें यूनाइटेड किंगडम की सामान्य कानून प्रणाली में पाई जाती हैं। वैधानिक कानून की अनुपस्थिति में ट्रेडमार्क को केवल सामान्य कानून संरक्षण ही उपलब्ध था। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1940 ट्रेडमार्क के विषय पर पहला पूर्ण कोड था। हालाँकि, 1889 में भारतीय व्यापारिक चिह्न अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन यह अपने आप में एक पूर्ण कोड नहीं था। 1940 के अधिनियम को व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [176]

अधिनियम, 1958 ने ट्रेडमार्क अधिनियम, 1940, भारतीय व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1889 और आईपीसी, सीआरपीसी और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम में निहित कुछ ट्रेडमार्क प्रावधानों को समेकित किया। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 का स्थान लेता है। वर्तमान अधिनियम कानून को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के बराबर लाने का एक समेकित प्रयास है।

9.5 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न.

क. ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें।

ख. ट्रेडमार्क कमजोरीकरण क्या है?

2. रिक्त स्थान भरें

a. ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

ख. ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा _____ ट्रेडमार्क के पंजीकरण से इनकार करने के लिए पूर्ण आधार प्रदान करती है।

3. सत्य या असत्य

क. ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 का एक उद्देश्य धोखाधड़ी वाले चिह्नों के उपयोग की रोकथाम है।

ख. अपंजीकृत ट्रेडमार्क को पार्सिंग ऑफ की सामान्य कानूनी कार्रवाई द्वारा संरक्षित किया जाता है।

9.6 संदर्भ

ट्रेड मार्क्स से संबंधित कानून- उल्लंघन और संबद्ध पहलू, रजित शर्मा (रीगल) द्वारा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016)

9.7 सुझाए गए पठन सामग्री

बौद्धिक संपदा अधिकार BLWadehra द्वारा

बौद्धिक संपदा अधिकार, पी. नारायणन

9.8 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

क. भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण पर चर्चा करें।

ख. ट्रेडमार्क के उल्लंघन और इसके विरुद्ध उपलब्ध उपायों की व्याख्या करें।

उत्तर:

एसएक्यू

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [177]

1. लघु उत्तरीय प्रश्न.

अ. 9.3.2 देखें

बी. 9.3.6 देखें

2. रिक्त स्थान भरें

30 दिसंबर 1999

बी. 9(नौ)

3. सत्य या असत्य

सच्चा

ख. सत्य

अंतिम प्रश्न और उत्तर

क. 9.3.3 देखें

बी. 9.3.4 देखें

इकाई: 11

डोमेन नाम पंजीकरण

- 11.1 परिचय
- 11.2 डोमेन नाम पंजीकरण के उद्देश्य
- 11.3 डोमेन नाम पंजीकरण
- 11.4 इंटरनेट निगम को सौंपे गए नाम और नंबर
- 11.5 सारांश
- 11.6 शब्दावली
- 11.7 एसएक्यूएस
- 11.8 संदर्भ
- 11.9 सुझाए गए पठन सामग्री
- 11.10 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न

11.1 परिचय

जैसा कि मैं सोचता हूँ कि यह तकनीक-अनुकूल दुनिया मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसके परिणाम क्रान्तिकारी हैं क्योंकि पूरी दुनिया इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से हमारे बेडरूम में है। हम इंटरनेट तकनीक की उपयोगिता देख रहे हैं क्योंकि बिस्तर पर जाने से पहले लोग अपने ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और वेबसाइटों को सर्वश्रेष्ठ शॉपिंग ऑफ़र के लिए चेक करना नहीं भूलते हैं और दुनिया भर के अपने रिश्तेदारों से चैट करते हैं। ये वेबसाइटें जिनका हम कई उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं, उनके उपयोगकर्ता-अनुकूल पते हैं जो हमें इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर और लोगों को जोड़ने में मदद करते हैं। ये पते उपयोग करने और याद रखने में आसान हैं जैसे कि facebook.com और ऐसा पता उन वेबसाइटों का डोमेन नाम है जिनका उपयोग हम लोगों को जोड़ने के लिए करते हैं।

इसलिए, डोमेन नाम किसी वेबसाइट का पता होता है। चूंकि इनका इस्तेमाल करना और याद रखना आसान है, इसलिए डोमेन नाम व्यवसाय की पहचान बन गए हैं और यहां तक कि ये खुद के लिए ट्रेडमार्क भी बन गए हैं जैसे कि gmail.com, yahoo.com, amazon.com, flipkart.com और sony.com.

इसलिए, डोमेन नाम एक पहचान लिंक है जो इंटरनेट के भीतर प्रशासनिक स्वायत्तता, अधिकार या नियंत्रण के दायरे को परिभाषित करता है। ये डोमेन नाम डोमेन नाम प्रणाली यानी DNS के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करके बनाए जाते हैं। DNS में पंजीकृत कोई भी नाम एक डोमेन नाम है। डोमेन नाम विभिन्न नेटवर्किंग उद्देश्यों और एप्लिकेशन-विशिष्ट नामकरण और पते के उद्देश्य से उपयोग किए जाने के लिए हैं।

डोमेन नाम किसी कंपनी के इंटरनेट प्रोटोकॉल को ट्रेडमार्क के रूप में दर्शाते हैं, चाहे वे पंजीकृत हों या अपंजीकृत, या कंपनी से जुड़े शब्द और वाक्यांश।

डोमेन उपयोगकर्ता अनुकूल: डोमेन नाम अमूर्त संपत्ति के संदर्भ में एक निजी क्षेत्र है जो इस तरह के तकनीकी प्रयासों पर स्वामित्व प्रदान करता है और इसके मालिक की अनुमति के बिना किसी को भी दूसरे के अधिकार में अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है।

इस इकाई में हम इंटरनेट के उद्देश्य के लिए डोमेन नामों के पंजीकरण का विश्लेषण करेंगे।

वे सेवाएँ जिनका हम दिन-प्रतिदिन लाभ उठाते हैं।

11.2 डोमेन नाम पंजीकरण का उद्देश्य:

इस इकाई के अध्ययन से छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि डोमेन नाम इंटरनेट संसाधनों, जैसे कंप्यूटर, नेटवर्क और सेवाओं की पहचान करने के लिए काम करते हैं, एक टेक्स्ट-आधारित लेबल के साथ जो इंटरनेट प्रोटोकॉल में उपयोग किए जाने वाले संख्यात्मक पत्तों की तुलना में याद रखना आसान है। एक डोमेन नाम ऐसे संसाधनों या व्यक्तिगत उदाहरणों के पूरे संग्रह का प्रतिनिधित्व कर सकता है। व्यक्तिगत इंटरनेट होस्ट कंप्यूटर होस्ट पहचानकर्ता के रूप में डोमेन नामों का उपयोग करते हैं, जिन्हें होस्ट नाम भी कहा जाता है। होस्ट नाम शब्द का उपयोग डोमेन नाम प्रणाली में लीफ लेबल के लिए भी किया जाता है, आमतौर पर बिना किसी अतिरिक्त अधीनस्थ डोमेन नाम स्थान के। होस्ट नाम इंटरनेट संसाधनों जैसे वेब साइट्स (जैसे, en.wikipedia.org) के लिए यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) में एक घटक के रूप में दिखाई देते हैं।

डोमेन नाम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को आसानी से पहचाने जाने योग्य नाम प्रदान करना है। संख्यात्मक रूप से संबोधित इंटरनेट संसाधन।

11.3 डोमेन नाम पंजीकरण

डोमेन नाम ट्रेडमार्क के रूप में किसी कंपनी के इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करते हैं पंजीकृत या अपंजीकृत, या कंपनी से जुड़े शब्द और वाक्यांश।

डोमेन नाम का उपयोग करने का अधिकार डोमेन नाम रजिस्ट्रार द्वारा दिया जाता है, जो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबरर्स (ICANN) द्वारा मान्यता प्राप्त है, यह संगठन इंटरनेट के नाम और संख्या प्रणालियों की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है। ICANN के अलावा, प्रत्येक शीर्ष-स्तरीय डोमेन (TLD) को एक रजिस्ट्री संचालित करने वाले प्रशासनिक संगठन द्वारा तकनीकी रूप से बनाए रखा और सेवा दी जाती है। एक रजिस्ट्री उस TLD के भीतर पंजीकृत नामों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है जिसे वह प्रशासित करती है। रजिस्ट्री संबंधित TLD में नाम निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत प्रत्येक डोमेन नाम रजिस्ट्रार से पंजीकरण जानकारी प्राप्त करती है और एक विशेष सेवा, WHOIS का उपयोग करके जानकारी प्रकाशित करती है

शिष्टाचार।

पहला वाणिज्यिक इंटरनेट डोमेन नाम, TLD com में, 15 मार्च 1985 को कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स स्थित कंप्यूटर सिस्टम फर्म सिम्बॉलिक्स इंक. द्वारा symbolics.com नाम से पंजीकृत किया गया था।

11.4 इंटरनेट निगम को सौंपे गए नाम और नंबर

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [180]

इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर (ICANN) की स्थापना अक्टूबर 1998 में हुई थी। यह एक गैर-लाभकारी निजी क्षेत्र का निगम है, जिसका गठन इंटरनेट के व्यावसायिक तकनीकी और शैक्षणिक समुदायों के बोर्ड गठबंधन द्वारा किया गया है।

सभी डोमेन नाम विवाद ICANN यूनिफॉर्म डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन पॉलिसी (UDRP) के अधीन हैं, जिसे 24 अक्टूबर 1999 को अनुमोदित किया गया था और 1 दिसंबर 1999 को पेश किया गया था।

यह एक त्वरित और सस्ती मध्यस्थता प्रक्रिया प्रदान करता है और विवादित डोमेन नाम को रद्द करने या स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ICANN के तहत काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा पहले ही काफी संख्या में मामले भेजे और निपटाए जा चुके हैं।

ccTLD का प्रशासन संबंधित विशिष्ट देश पर छोड़ दिया जाता है। उदाहरण- .in (भारतीय) ccTLD के भीतर डोमेन नामों का प्रशासन NCST (नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी) 2004 द्वारा देखा जाता है। IANA (इंटरनेट असाइन्ड नेम्स एंड नंबर) TLD कोड द्वारा रूट-ज़ोन हू इज़ इन्फॉर्मेशन इंडेक्स प्रदान करता है। यह इंडेक्स इस ccTLD वाले सभी देशों को सूचीबद्ध करता है। जैसे Yahoo.com और Yahoo.co.in

11.4 नियामक ढांचा:

विनियामक ढांचा दो गुना है। इसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है

1. समान विवाद समाधान नीति (यूडीआरपी)
2. भारतीय विवाद समाधान नीति (आईएनडीआरपी)

1. यूडीआरपी सिद्धांत:

विभिन्न न्यायक्षेत्रों में पारंपरिक मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण, UDRP को पेश किया गया और अंततः ICANN द्वारा अनुमोदित किया गया। इसे 24.oct.1999 को पेश किया गया था। UDRP को सभी gTLD में ICANN-मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार द्वारा अपनाया गया है। UDRP रजिस्ट्रार और उसके ग्राहक के बीच एक नीति है और इसे सभी ICANN-मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार के लिए पंजीकरण समझौते में शामिल किया गया है। डोमेन नाम के प्रत्येक रजिस्ट्रार को gTLD डोमेन नाम के पंजीकरण के लिए नियम और शर्तों के विवाद खंड से सहमत होना पड़ता है। इसलिए, एक बार जब शिकायतकर्ता कार्यवाही शुरू कर देता है, तो रजिस्ट्रार को ऐसी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत होना चाहिए।

यूडीआरपी का पैराग्राफ 3 आईसीएएनएन को डोमेन नाम पंजीकरण को रद्द करने, स्थानांतरित करने या अन्यथा परिवर्तन करने की अनुमति देता है, यदि उन्हें सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण से ऐसा आदेश प्राप्त होता है, जिसमें ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसलिए, कोई व्यक्ति पारंपरिक मुकदमेबाजी का विकल्प भी चुन सकता है, डोमेन नाम के हस्तांतरण के लिए आदेश प्राप्त कर सकता है और फिर डोमेन नाम के हस्तांतरण के लिए यूडीआरपी के पैराग्राफ 3 के तहत आईसीएएनएन से संपर्क कर सकता है।

नियम 4(ए) - ट्रेडमार्क स्वामी को यह दिखाना होगा-

1. प्रतिवादी का डोमेन नाम किसी ट्रेडमार्क या सेवा चिह्न के समरूप या भ्रामक रूप से समान है।

2. प्रतिवादी का डोमेन नाम के संबंध में कोई अधिकार या वैध हित नहीं है।
 3. प्रतिवादी का डोमेन नाम पंजीकृत किया गया है और उसका गलत उपयोग किया जा रहा है।
2. आईएनडीआरपी सिद्धांतः

.IN रजिस्ट्री ने INDRP तैयार किया है। यह नीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दिशा-निर्देशों और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुरूप है। यह नीति .in इंटरनेट डोमेन नाम के पंजीकरण और उपयोग से उत्पन्न होने वाले रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता के बीच विवाद को हल करने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करती है। INDRP प्रक्रिया नियम बताते हैं कि शिकायत कैसे दर्ज की जाए, शिकायत का जवाब कैसे दिया जाए, शुल्क, संचार, अन्य प्रक्रियाएं आदि। INDRP का पैरा 4, UDRP के पैरा 4 (a) से काफी मिलता-जुलता है और शिकायत दर्ज करने के लिए समान आवश्यक आधार बनाता है। पैरा 6, INDRP = पैरा 4(b), UDRP - बुरा विश्वास

11.5 डोमेन नाम और भारतीय कानून

डोमेन नाम, हालांकि ICANN की आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप से पंजीकृत है, फिर भी यह ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के अधीन है यदि कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक साबित कर देता है कि उसके पास अधिनियम से निकलने वाले 'अधिकार' हैं। नियम 2 नियम 4 (के) के साथ है जो पार्टियों को सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष आंदोलन करने का अधिकार देता है, भले ही ICANN द्वारा इसके विपरीत घोषणा या निर्णय लिया गया हो।

इस प्रकार, सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले भारतीय न्यायालय का विपरीत निर्णय प्रभावी होगा।
आईसीएनएन का निर्णय।

अधिकार और दायित्व: ट्रेडमार्क के तहत न्यायनिर्णित किए जाने वाले अधिकार और दायित्व
अधिनियम, 1999 को निम्नलिखित समूहों के अंतर्गत उप-विभाजित किया जा सकता है:

□ उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व □ पासिंग

ऑफ़ के लिए उत्तरदायित्व

टीएमए अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत अपंजीकृत ट्रेडमार्क के मामले में केवल पासिंग ऑफ़ उपाय उपलब्ध है।

□ नागरिक दायित्व और आपराधिक दायित्व (धारा 106-109, 114, 120, 140, 151)

□ आपराधिक दायित्व

□ धारा 103 टीएमए- झूठे ट्रेडमार्क, व्यापार विवरण आदि लागू करने पर जुर्माना।

□ धारा 104- माल बेचने या सेवाएं प्रदान करने के लिए जुर्माना

गलत ट्रेडमार्क या गलत व्यापार विवरण लागू किया गया है

11.6 सारांशः

डोमेन नाम का उपयोग करने का अधिकार डोमेन नाम रजिस्ट्रार द्वारा दिया जाता है, जो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबरर्स (ICANN) द्वारा मान्यता प्राप्त है, यह संगठन इंटरनेट के नाम और संख्या प्रणालियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

ICANN के अलावा, प्रत्येक शीर्ष-स्तरीय डोमेन (TLD) को एक रजिस्ट्री संचालित करने वाले प्रशासनिक संगठन द्वारा तकनीकी रूप से बनाए रखा और सेवा दी जाती है। एक रजिस्ट्री उस TLD के भीतर पंजीकृत नामों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है जिसे वह प्रशासित करती है। रजिस्ट्री संबंधित TLD में नाम निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत प्रत्येक डोमेन नाम रजिस्ट्रार से पंजीकरण जानकारी प्राप्त करती है और एक विशेष सेवा, WHOIS का उपयोग करके जानकारी प्रकाशित करती है

शिष्टाचार।

शब्दावली:

1. आईसीएनएन - इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबरर्स।
2. यूडीआरपी- समान विवाद समाधान नीति 3. डीएनएस- डोमेन नाम प्रणाली
4. टीएलडी- शीर्ष स्तरीय डोमेन

11.7 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न:-

क) डोमेन नाम क्या दर्शाता है?

i)

आईपी ii) देश

ख) डीएनएस क्या है?

i) डोमेन नाम प्रणाली

ii) निष्क्रिय नार्को सिस्टम

2. रिक्त स्थान भरें:

a) सभी डोमेन नाम विवाद के अधीन हैं।

ख) एक रजिस्ट्री पंजीकृत नामों के को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है
TLD के भीतर यह प्रशासित है

3. सत्य और असत्य:

a) इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबरर्स (ICANN) की स्थापना की गई थी
अक्टूबर 1998.

(i) सत्य, (ii) असत्य

b) DNS में पंजीकृत कोई भी नाम डोमेन नाम है।

(i) सत्य, (ii) असत्य

11.8 संदर्भ

1. <https://www.domainindia.org/>
2. <https://www.hostindia.net/domains.php>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name
4. www.wipo.int/amc/en/domains/decisions.htm

11.9 सुझाए गए पठन सामग्री

1. ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999

2. डब्ल्यूआईपीओ दिशानिर्देश

11.10 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न

1. डोमेन नाम के पंजीकरण की प्रक्रिया समझाइए।

2. ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के तहत विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करें।

SAQS उत्तर:

1. a(i) b) (i) 2.

a) ICANN b) डेटाबेस 3. (a) सत्य

(b) सत्य टर्मिनल प्रश्नों के उत्तर

(a)11.3 (b) ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999

इकाई-12

डोमेन नाम विवाद और डब्ल्यूआईपीओ बनाम.

डेटाबेस

12.1 परिचय

12.2 उद्देश्य

12.3 डोमेन नाम प्रणाली और के बीच इंटरफ़ेस

बौद्धिक संपदा: डब्ल्यूआईपीओ प्रक्रिया

12.4 डब्ल्यूआईपीओ प्रक्रिया की क्रियाविधि

12.5 सारांश

12.6 शब्दावली

12.7 अपनी प्रगति जाँचने के लिए उत्तर/SAQ के संभावित उत्तर

12.8 संदर्भ/ग्रंथसूची

12.9 सुझाए गए पठन सामग्री

12.10 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न

12.1 परिचय

अब डोमेन नाम रखना एक स्मार्ट व्यावसायिक निर्णय बन गया है। पंजीकृत डोमेन नाम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेब पर कंपनी की साइट का पता लगाने में सक्षम बनाता है। कंपनी के डोमेन नाम "TLDs" नामक किसी भी संख्या में "शीर्ष स्तरीय डोमेन" में पंजीकृत हो सकते हैं। जेनेरिक शीर्ष स्तरीय डोमेन ("gTLDs") चुने जा सकते हैं, जैसे .com, .net, .org, .info आदि या हम आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद विशेष और प्रतिबंधित शीर्ष स्तरीय डोमेन से भी चुनाव कर सकते हैं जैसे हवाई यात्रा और परिवहन व्यवसायों के लिए .aero, या वाणिज्यिक उद्यमों के लिए .biz।

इसके अलावा हम अपने डोमेन नामों को "देश कोड शीर्ष स्तरीय डोमेन" ("सीसीटीएलडी") के अंतर्गत पंजीकृत भी कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, बुल्गारिया के लिए .bg, चीन के लिए .cn, स्विट्जरलैंड के लिए .ch।

WIPO मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र ने दिसंबर 1999 में यूनिफॉर्म डोमेन नेम विवाद समाधान नीति (UDRP) में डोमेन नाम विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करना शुरू किया। केंद्र की सेवाओं में जेनेरिक टॉप-लेवल डोमेन (gTLD) के लिए दूसरे स्तर के डोमेन नाम विवादों का प्रबंधन करना शामिल है, जिस पर UDRP लागू है। यह केंद्र WIPO द्वारा शुरू किए गए, ICANN-अनिवार्य UDRP के तहत विवाद समाधान सेवा प्रदाता में अग्रणी है। केंद्र व्यक्तिगत gTLD रजिस्ट्री द्वारा अपनाई गई कई विशिष्ट नीतियों के तहत विवादों का प्रबंधन भी करता है।

12.2 उद्देश्य: इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

डब्ल्यूआईपीओ मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र की स्थापना निम्नलिखित कार्य करने के लिए की गई है:

1. इंटरनेट डोमेन नाम विवादों को हल करने के लिए समय-कुशल तंत्र।

2. इंटरनेट डोमेन नाम विवादों को हल करने के लिए लागत-कुशल तंत्र।

3. न्यायालयीन मुकदमेबाजी की आवश्यकता के बिना।

4. यह सेवा डब्ल्यूआईपीओ द्वारा शुरू की गई समान डोमेन नाम विवाद समाधान नीति (यूडीआरपी) को भी शामिल करने पर केंद्रित है, जिसके तहत

डब्ल्यूआईपीओ केंद्र ने 39,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

12.3 डोमेन नाम प्रणाली और के बीच इंटरफ़ेस

बौद्धिक संपदा: डब्ल्यूआईपीओ प्रक्रिया

DNS के प्रबंधन से संबंधित चर्चाओं और परामर्शों के ताने-बाने में एक सुसंगत सूत्र इंटरनेट पर पते के रूप में डोमेन नामों और बौद्धिक संपदा या, अधिक विशेष रूप से, ट्रेडमार्क और पहचान के अन्य मान्यता प्राप्त अधिकारों के बीच का इंटरफ़ेस रहा है, जैसा कि वे इंटरनेट के आगमन से पहले दुनिया में मौजूद थे। यह सभी के लिए स्पष्ट हो गया है कि एक ओर, मानव-अनुकूल रूप में इंटरनेट पर पते जो अर्थ और पहचान की शक्ति रखते हैं और दूसरी ओर, वास्तविक दुनिया में पहचान के मान्यता प्राप्त अधिकार, जिसमें ट्रेडमार्क और व्यावसायिक पहचान के अन्य अधिकार, व्यक्तित्व अधिकारों का विकासशील क्षेत्र, चाहे वे वास्तविक या काल्पनिक पात्रों से जुड़े हों, और भौगोलिक संकेत शामिल हैं, के बीच अनजाने में काफी तनाव पैदा हो गया है। एक प्रणाली - DNS - काफी हद तक निजी तौर पर प्रशासित है और पंजीकरण को जन्म देती है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक उपस्थिति होती है, जो दुनिया में कहीं से भी सुलभ होती है।

दूसरी प्रणाली - बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली - सार्वजनिक रूप से क्षेत्रीय आधार पर प्रशासित होती है और ऐसे अधिकारों को जन्म देती है, जिनका प्रयोग केवल संबंधित क्षेत्र के भीतर ही किया जा सकता है।

इस संबंध में, डीएनएस और बौद्धिक संपदा प्रणाली का प्रतिच्छेदन एक बड़ी घटना का एक उदाहरण मात्र है: एक वैश्विक माध्यम का प्रतिच्छेदन जिसमें यातायात सीमाओं के संज्ञान के बिना प्रसारित होता है, ऐतिहासिक, प्रादेशिक आधारित प्रणालियों के साथ जो क्षेत्र के संप्रभु प्राधिकरण से निकलती हैं।

दोनों प्रणालियों की प्रकृति के बीच मौजूद तनाव को कई शिकारी और परजीवी प्रथाओं द्वारा और बढ़ा दिया गया है, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा उन उद्देश्यों के बीच संबंध की कमी का फायदा उठाने के लिए अपनाया गया है जिनके लिए DNS को डिज़ाइन किया गया था और जिनके लिए बौद्धिक सुरक्षा मौजूद है। इन प्रथाओं में जानबूझकर, बुरे विश्वास के साथ जाने-माने और अन्य ट्रेडमार्क के डोमेन नामों के रूप में पंजीकरण शामिल है, ताकि उन चिह्नों के मालिकों को डोमेन नाम बेचे जा सकें, या बस उन चिह्नों से जुड़ी प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाया जा सके।

IAHC की सिफारिशों में डोमेन नाम और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच मौजूद तनाव पर ध्यान दिया गया और दोनों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए डिज़ाइन की गई विशिष्ट प्रक्रियाओं को शामिल किया गया। संयुक्त राज्य सरकार के श्वेत पत्र ने अपनी विशिष्ट सिफारिशों को DNS के प्रबंधन की वांछनीय विशेषताओं और उस प्रबंधन को नए निगम में स्थानांतरित करने तक सीमित रखा। बौद्धिक संपदा के संबंध में, श्वेत पत्र में निम्नलिखित अंश शामिल थे:

"अमेरिकी सरकार विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) से एक संतुलित और पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग करेगी, जिसमें ट्रेडमार्क धारकों और इंटरनेट समुदाय के उन सदस्यों की भागीदारी शामिल है जो ट्रेडमार्क धारक नहीं हैं, ताकि (1) ट्रेडमार्क समस्याओं के समाधान के लिए एक समान दृष्टिकोण हेतु सिफारिशें विकसित की जा सकें।

साइबर पाइरेसी से जुड़े ट्रेडमार्क/डोमेन नाम विवाद (वैध प्रतिस्पर्धी अधिकारों वाले ट्रेडमार्क धारकों के बीच संघर्ष के विपरीत), (2) जेनेरिक शीर्ष स्तरीय डोमेन में प्रसिद्ध ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए एक प्रक्रिया की सिफारिश करें, और (3) स्वतंत्र संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर प्रभावों का मूल्यांकन करें, जैसे कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की नेशनल रिसर्च काउंसिल, नए gTLDs और ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा धारकों पर संबंधित विवाद समाधान प्रक्रियाओं को जोड़ने के लिए। इन निष्कर्षों और सिफारिशों को रजिस्ट्री और रजिस्ट्रार नीति के विकास और नए gTLDs के निर्माण और परिचय के साथ संयोजन में नए निगम के बोर्ड को विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्वेत पत्र के प्रकाशन के बाद से, डब्ल्यूआईपीओ को अपने सदस्य देशों से श्वेत पत्र में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के संचालन के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है, तथा उसने इसे अपना लिया है।

12.4 डब्ल्यूआईपीओ प्रक्रिया की क्रियाविधि

डब्ल्यूआईपीओ इंटरनेट डोमेन नाम प्रक्रिया में तीन चरण शामिल थे।

पहला चरण WIPO प्रक्रिया में संबोधित किए जाने वाले मुद्दों, उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रक्रिया के समय सारिणी पर आम सहमति प्राप्त करने से संबंधित था। इस उद्देश्य के लिए 8 जुलाई, 1998 को टिप्पणियों के लिए अनुरोध (WIPO RFC-1) जारी किया गया था, जिसमें 24 अगस्त, 1998 तक टिप्पणियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि थी। WIPO RFC-1 ने प्रक्रिया के लिए संदर्भ की शर्तों के रूप में श्वेत पत्र में उल्लिखित तीन मुद्दों का विवरण दिया, अर्थात्, समान विवाद समाधान प्रक्रियाएँ, प्रसिद्ध चिह्नों की सुरक्षा के लिए एक तंत्र और नए gTLDs को जोड़ने से बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन। इसने संदर्भ की एक और शर्त जोड़ी, जिसे WIPO ने संदर्भ में उपयुक्त माना, अर्थात्, DNS के प्रशासन में विवाद निवारण या अभ्यास जो डोमेन नामों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। WIPO RFC-1 के जवाब में साठ-छह सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, पेशेवर संघों, निगमों और व्यक्तियों ने टिप्पणियाँ प्रदान कीं।

WIPO प्रक्रिया के दूसरे चरण में WIPO RFC-1 पर प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद परिभाषित मुद्दों पर टिप्पणियाँ माँगना और परामर्श करना शामिल था। इस उद्देश्य से, टिप्पणियों के लिए दूसरा अनुरोध (WIPO RFC-2) 16 सितंबर, 1998 को जारी किया गया था, जिसमें 6 नवंबर, 1998 तक टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी। WIPO RFC-2 के जवाब में बहत्तर सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, व्यावसायिक संघों, निगमों और व्यक्तियों ने टिप्पणियाँ प्रदान कीं। दूसरे चरण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा विचाराधीन मुद्दों पर चर्चा करने और टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का आयोजन था। उन क्षेत्रीय परामर्श बैठकों में कुल 848 व्यक्ति शामिल हुए

WIPO प्रक्रिया के तीसरे चरण में 23 दिसंबर, 1998 को अंतरिम रिपोर्ट का प्रकाशन शामिल था, जिसमें अंतरिम सिफारिशें शामिल थीं, जिन्हें टिप्पणियों के लिए तीसरे अनुरोध (WIPO RFC-3) के रूप में टिप्पणियों के लिए खोला गया था। टिप्पणियों के लिए अवधि के समापन की तिथि, 19 मार्च, 1999 तक, 196 सरकारें, अंतर-सरकारी

संगठनों, व्यावसायिक संघों, निगमों और व्यक्तियों ने WIPO RFC-3 के जवाब में टिप्पणियाँ प्रदान की थीं। इसके अलावा, अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा करने और टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का दूसरा दौर आयोजित किया गया था। क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के दूसरे दौर में कुल 416 लोगों ने भाग लिया।

रूपात्मकता

इस प्रक्रिया के संचालन में, डब्ल्यूआईपीओ ने इच्छुक पक्षों की व्यापकतम अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी से भागीदारी प्राप्त करने के लिए तीन तौर-तरीकों का उपयोग किया है:

(i) WIPO ने WIPO प्रक्रिया से संबंधित संचार के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में एक वेबसाइट (<http://wipo2.wipo.int>) स्थापित की। WIPO प्रक्रिया से संबंधित सूचना और दस्तावेजों के प्रकाशन के अलावा, वेबसाइट में इच्छुक व्यक्तियों के लिए WIPO प्रक्रिया में विकास से संबंधित संचार प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने की सुविधा थी। इस सुविधा के तहत 74 देशों के लगभग 1,358 व्यक्तियों या संगठनों ने पंजीकरण कराया। वेबसाइट में जारी किए गए तीन टिप्पणियों के अनुरोधों (WIPO RFC-1, RFC-2 और RFC-3) के जवाब में प्राप्त सभी टिप्पणियों का पाठ भी शामिल था। इसने आगे एक खुली सूची सर्वर चर्चा मंच की स्थापना की। सूची, जिसे मॉडरेट नहीं किया गया था, का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को WIPO प्रक्रिया के संबंध में उठने वाले प्रश्नों की व्यापक संभव सीमा पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करने की अनुमति देना था। सूची सर्वर में योगदान को औपचारिक रूप से RFC के जवाब में टिप्पणियों के रूप में नहीं माना जाता था। इस रिपोर्ट की तिथि पर सूची सर्वर के ग्राहकों की संख्या 42 थी।

(ii) चूंकि इंटरनेट एक वैश्विक माध्यम है, लेकिन इस तक पहुंच सार्वभौमिक नहीं है, इसलिए डब्ल्यूआईपीओ ने अपने द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिप्पणी अनुरोध को कागज के रूप में प्रकाशित किया और इन्हें अपने प्रत्येक सदस्य राज्यों की सरकारों और औद्योगिक संपत्ति कार्यालयों के साथ-साथ प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को भेजा, जिसे डब्ल्यूआईपीओ के साथ पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी गई थी।

(iii) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डब्ल्यूआईपीओ ने दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों के साथ इंटरनेट और कागज-आधारित परामर्श को पूरक बनाने की भी मांग की है।

सिफारिशों के निर्माण में मार्गदर्शक सिद्धांत

डब्ल्यूआईपीओ प्रक्रिया

रिपोर्ट के शेष भाग में, डब्ल्यूआईपीओ प्रक्रिया में विचार किए गए मुद्दों और उन मुद्दों के संबंध में की गई सिफारिशों पर आगे बढ़ने से पहले, उन पद्धतिगत सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाना चाहिए जिन्होंने सिफारिशों के निर्माण को निर्देशित किया है। ऐसे पाँच सिद्धांत हैं।

इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति तथा इसके उपयोग के विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, WIPO ने एक ऐसी प्रक्रिया तैयार करने का प्रयास किया है जो अंतर्राष्ट्रीय हो तथा जिसमें इंटरनेट के उपयोग तथा भविष्य के विकास में रुचि रखने वाले सभी क्षेत्रों की भागीदारी हो।

यद्यपि डब्ल्यूआईपीओ का अधिदेश बौद्धिक संपदा संरक्षण से संबंधित है, यह माना जाता है कि बौद्धिक संपदा को बहुक्रियाशील वैश्विक माध्यम के संदर्भ में पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है।

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [188]

यह भी माना जाता है कि इस WIPO प्रक्रिया का लक्ष्य बौद्धिक संपदा के नए अधिकार बनाना नहीं है, न ही साइबरस्पेस में बौद्धिक संपदा को अन्यत्र मौजूद बौद्धिक संपदा की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। बल्कि, इसका लक्ष्य इंटरनेट के नए, बहु-न्यायालयीय और अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम तथा इंटरनेट पर यातायात को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार DNS के संदर्भ में बौद्धिक संपदा संरक्षण के मौजूदा, बहुपक्षीय रूप से सहमत मानकों को उचित और पर्याप्त अभिव्यक्ति देना है। WIPO प्रक्रिया ऐसी प्रक्रियाओं को खोजने का प्रयास करती है जो बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहमत नीतियों और नियमों की अनजाने में कमी या निराशा से बचेंगी।

इसके विपरीत, इसका यह उद्देश्य नहीं है कि बौद्धिक संपदा के सहमत मानकों को उचित और पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के परिणामस्वरूप अन्य सहमत अधिकारों, जैसे कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में गारंटीकृत अधिकारों, के आनंद में कमी आए या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

इंटरनेट का केंद्रीय महत्व और उपयोगकर्ताओं के तेजी से बढ़ते समूह के विविध हितों की सेवा करने की इसकी क्षमता मौलिक है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर विचार किया गया है कि WIPO प्रक्रिया की सिफारिशें व्यावहारिक हों और डोमेन नाम पंजीकरण प्राधिकरणों के उच्च-मात्रा और स्वचालित संचालन पर अनुचित प्रतिबंध लगाकर इंटरनेट की कार्यक्षमता में हस्तक्षेप न करें।

इंटरनेट के विस्तार और विकास के पीछे की प्रौद्योगिकियों की गतिशील प्रकृति को भी मान्यता दी गई है। WIPO प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी था कि

ये सिफारिशें किसी भी तरह से इंटरनेट के भविष्य के तकनीकी विकास को प्रभावित नहीं करती हैं।

डब्ल्यूआईपीओ अनुशंसाओं का दायरा: उनकी प्रासंगिकता

सीसीटीएलडीएस

WIPO अंतरिम रिपोर्ट में, साथ ही ऊपर दिए गए पैराग्राफ 6, 7 और 8 में, "खुले" TLD (चाहे gTLD हों या ccTLD), के बीच अंतर किया गया है, जिसमें उन व्यक्तियों या संस्थाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो उनमें पंजीकरण कर सकते हैं, और "प्रतिबंधित" TLD, जिसमें केवल कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति या संस्थाएँ, जैसे कि संबंधित क्षेत्र में निवास, डोमेन नाम पंजीकृत कर सकते हैं। अंतरिम रिपोर्ट में, यह भी सुझाव दिया गया था कि, जबकि WIPO प्रक्रिया की सिफारिशें gTLD तक सीमित थीं, वे संभावित रूप से सभी खुले TLD पर लागू थीं जिनमें डोमेन नाम बिना किसी प्रतिबंध के पंजीकृत किए जा सकते हैं और जिनमें डोमेन नाम खरीदे और बेचे जा सकते हैं।

"खुले" और "प्रतिबंधित" TLD के बीच किए गए अंतर पर की गई टिप्पणियाँ विभाजित थीं। कुछ पक्ष इस अंतर के पक्ष में थे और उन्होंने इसे gTLD और ccTLD के बीच कार्यात्मक समानताओं को इंगित करने के साधन के रूप में सहायक माना और, परिणामस्वरूप, डोमेन नामों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच इंटरफेस के संबंध में आने वाली समस्याओं की समानता। अन्य लोगों ने ccTLD में पंजीकरण पर लागू होने वाली विभिन्न स्थितियों के कारण इस अंतर को ढीला और परिभाषात्मक सटीकता की कमी वाला माना। इसके अलावा, कुछ पक्षों ने इस अंतर को खतरनाक माना, क्योंकि इसका उपयोग समस्याओं के समाधान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

डोमेन नाम और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच इंटरफेस और सीसीटीएलडी के संचालन को सीमित करने के साधन के रूप में। प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, इस भेद के उद्देश्य और उपयोगिता पर हमारे विचार आगामी पैराग्राफ में दिए गए हैं।

"खुले" और "प्रतिबंधित" TLD के बीच अंतर का उद्देश्य वैश्विक माध्यम के रूप में इंटरनेट की मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषता की ओर ध्यान आकर्षित करना था। डोमेन नाम पंजीकरण, चाहे gTLD में हो या ccTLD में, वैश्विक उपस्थिति को जन्म देता है। डोमेन नाम और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच इंटरफेस से निपटने में आने वाली कई कठिनाइयाँ इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्रीय रूप से आधारित होते हैं और उन्हें केवल उस क्षेत्र के भीतर ही लागू किया जा सकता है जिसके लिए उन्हें प्रदान किया जाता है। एक देश में पंजीकृत डोमेन नाम (लेकिन जरूरी नहीं कि) किसी अन्य देश में गतिविधियों के लिए आधार बन सकता है जिसमें विधायी रूप से स्वीकृत प्रणाली के तहत प्रदान किया गया क्षेत्रीय रूप से सीमित बौद्धिक संपदा अधिकार मौजूद है। डोमेन नाम उपभोक्ता को भ्रमित और धोखा दे सकता है (लेकिन जरूरी नहीं कि) और क्षेत्रीय रूप से सीमित बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन कर सकता है (लेकिन जरूरी नहीं कि)। परिणामस्वरूप, किसी अन्य क्षेत्राधिकार में डोमेन नाम पंजीकरण के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के कारण मान्यता प्राप्त प्रादेशिक रूप से सीमित बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन खतरे में पड़ सकता है, जिससे बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, इसका आकलन करने और उल्लंघनकारी गतिविधियों के विरुद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

जहाँ प्रतिबंध उन व्यक्तियों या संस्थाओं पर लागू होते हैं जो TLD में पंजीकरण कर सकते हैं, वे प्रतिबंध डोमेन नाम और क्षेत्रीय रूप से आधारित बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच तनाव को कम करने के साधन प्रदान कर सकते हैं (लेकिन जरूरी नहीं है)। उदाहरण के लिए, यदि लागू किए जाने वाले प्रतिबंधों में से एक उस क्षेत्र में निवास है जिससे ccTLD संबंधित है, तो डोमेन नाम द्वारा उल्लंघन किए जाने वाले किसी भी प्रासंगिक बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रवर्तन को अधिकार क्षेत्र से कनेक्शन द्वारा सुगम बनाया जा सकता है, और इस प्रकार कानूनी प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है, जिसे निवास का प्रतिबंध लागू करता है। या, उदाहरण के लिए, यदि TLD पर लागू प्रतिबंध TLD में पंजीकरण करने वाली संस्था के प्रकार को सावधानीपूर्वक परिभाषित करता है, जैसे कि .int में यह आवश्यकता कि पंजीकरणकर्ता एक अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, तो यह प्रतिबंध डोमेन नाम और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने के लिए काम कर सकता है, क्योंकि यह वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए डोमेन में पंजीकरण करने की संभावना को हटा देता है। हम अनुशंसा नहीं करते हैं कि TLD के संबंध में प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन केवल इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि प्रतिबंध डोमेन नाम और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच संबंधों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

जहाँ TLD में पंजीकरण पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है, वहाँ डोमेन नाम और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है। कार्यात्मक रूप से, ऐसे मामले में, चाहे TLD gTLD हो या ccTLD, डोमेन नामों के पंजीकरण डोमेन नामों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच इंटरफेस के बारे में समान प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। "खुले" और "प्रतिबंधित" TLD के बीच अंतर करने का हमारा उद्देश्य केवल इस तथ्य को उजागर करना था कि अप्रतिबंधित डोमेन में डोमेन नाम और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच उत्पन्न होने वाली समस्याएँ समान हैं।

इन समस्याओं की समानता को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकलता है कि डोमेन नाम और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच आने वाली समस्याओं का कोई भी व्यापक समाधान सबसे प्रभावी होगा यदि इसे इस तरह से लागू किया जाए कि इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति और डोमेन नाम पंजीकरण द्वारा दी गई वैश्विक उपस्थिति को मान्यता दी जाए। कर पनाहगाह की अवधारणा सर्वविदित है। ccTLD को इस तरह से संचालित किया जा सकता है कि यह बौद्धिक संपदा चोरी का पनाहगाह बन जाए; यानी, इसे बौद्धिक संपदा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की मान्यता प्राप्त प्रणाली के बाहर प्रशासित किया जा सकता है और इस तरह, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लेनदेन लागत में वृद्धि हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली की दक्षता कम हो सकती है।

WIPO यह मानता है कि इस रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें केवल gTLD पर लागू करने के लिए हैं। यह इंटरनेट की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को भी पहचानता है और वर्तमान रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को ccTLD के उन प्रशासकों के विचारार्थ भी प्रस्तुत करता है जो डोमेन नाम पंजीकरण द्वारा दी गई वैश्विक उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी का संज्ञान लेना चाहते हैं। ccTLD के कुछ प्रशासकों के विशिष्ट अनुरोध के जवाब में, अनुलग्नक VIII में विस्तृत मार्गदर्शन शामिल है, जिस पर WIPO वर्तमान रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को ccTLD के लिए संभावित रूप से उपयोगी मानता है, ताकि डोमेन नामों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच इंटरफेस से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का एक व्यापक और कुशल समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यह स्पष्ट रूप से ccTLD के प्रशासकों पर निर्भर करता है कि वे उन सिफारिशों में से किसी को अपनाना चाहते हैं या नहीं।

12.5 सारांश:

WIPO ने WIPO प्रक्रिया से संबंधित संचार के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में एक वेबसाइट (<http://wipo2.wipo.int>) स्थापित की। WIPO प्रक्रिया से संबंधित सूचना और दस्तावेजों के प्रकाशन के अलावा, वेबसाइट में इच्छुक व्यक्तियों के लिए WIPO प्रक्रिया में विकास से संबंधित संचार प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने की सुविधा थी। इस सुविधा के तहत 74 देशों के लगभग 1,358 व्यक्तियों या संगठनों ने पंजीकरण कराया। वेबसाइट में जारी किए गए तीन टिप्पणियों के अनुरोधों (WIPO RFC-1, RFC-2 और RFC-3) के जवाब में प्राप्त सभी टिप्पणियों का पाठ भी शामिल था। इसने आगे एक खुली सूची सर्वर चर्चा मंच की स्थापना की। सूची, जिसे मॉडरेट नहीं किया गया था, का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को WIPO प्रक्रिया के संबंध में उठने वाले प्रश्नों की व्यापक संभव सीमा पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करने की अनुमति देना था। सूची सर्वर में योगदान को औपचारिक रूप से RFC के जवाब में टिप्पणियों के रूप में नहीं माना जाता था। इस रिपोर्ट की तिथि पर सूची सर्वर के ग्राहकों की संख्या 42 थी।

(ii) चूंकि इंटरनेट एक वैश्विक माध्यम है, लेकिन इस तक पहुंच सार्वभौमिक नहीं है, इसलिए डब्ल्यूआईपीओ ने अपने द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिप्पणी अनुरोध को कागज के रूप में प्रकाशित किया और इन्हें अपने प्रत्येक सदस्य राज्यों की सरकारों और औद्योगिक संपत्ति कार्यालयों के साथ-साथ प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को भेजा, जिसे डब्ल्यूआईपीओ के साथ पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी गई थी।

(iii) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डब्ल्यूआईपीओ ने दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों के साथ इंटरनेट और कागज-आधारित परामर्श को पूरक बनाने की भी मांग की है।

12.6 शब्दावली

1. WIPO- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
2. टीएलडी - शीर्ष स्तरीय डोमेन

12.7 एसएक्यूएस

1. डब्ल्यूआईपीओ का क्या अर्थ है?
2. टीडीएल क्या है?

2. रिक्त स्थान भरें:

a) डब्ल्यूआईपीओ इंटरनेट डोमेन नाम प्रक्रिया में चरण शामिल थे।

ख) डब्ल्यूआईपीओ मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र की स्थापना इंटरनेट डोमेन नाम विवादों को हल करने के लिए तंत्र प्रदान करने के लिए की गई है

3. सत्य और असत्य:

1. डब्ल्यूआईपीओ ने प्राथमिक रूप से अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में एक वेबसाइट स्थापित की डब्ल्यूआईपीओ प्रक्रिया से संबंधित संचार के लिए वाहन।

(अ)सत्य, (ब) असत्य

2. कंपनी के डोमेन नाम किसी भी संख्या में "शीर्ष" डोमेन में पंजीकृत हो सकते हैं। स्तरीय डोमेन" को "टीएलडी" कहा जाता है।

(अ)सत्य, (ब) असत्य

12.8 संदर्भ/ग्रंथ सूची

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/>

<http://www.wipo.int/amc/en/center/bibliography/>

12.9 सुझाए गए पठन

WIPO मध्यस्थता द्वारा WIPO UDRP डोमेन नाम पैनल निर्णयों का संग्रह
मध्यस्थता केंद्र (लेखक)

12.10 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न

क) डोमेन नाम विवादों को सुलझाने में डब्ल्यूआईपीओ द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया क्या है?

(ख) इंटरनेट संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में डब्ल्यूआईपीओ की शक्तियों, कार्यों और अधिकार क्षेत्र पर चर्चा करें।

SAQS उत्तर:

1. (क) विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन (ख) शीर्ष स्तरीय डोमेन
2. (ए) तीन (बी) लागत-कुशल 3. (ए) सत्य (बी)

सत्य

टर्मिनल प्रश्नों के उत्तर

(बी)12.4 (बी) 11.12.4-12.6

इकाई-13

डेटाबेस की सुरक्षा

- 13.1 परिचय
- 13.2 उद्देश्य
- 13.3 डेटाबेस की सुरक्षा
- 13.4 डेटाबेस का अर्थ
- 13.5 डेटाबेस सुरक्षा की आवश्यकता
- 13.6 कॉपीराइट कानून और डेटाबेस निर्देश
- 13.7 डेटाबेस की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास
- 13.8 डेटाबेस निर्देश
- 13.9 सारांश
- 13.10 शब्दावली
- 13.11 एसएक्यूएस
- 13.12 संदर्भ/ग्रंथसूची
- 13.13 सुझाए गए पठन सामग्री
- 13.14 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न
- 13.15 उत्तर

13.1 परिचय

डेटाबेस सुरक्षा डेटाबेस की सुरक्षा के लिए सूचना सुरक्षा नियंत्रण की व्यापक श्रेणी के उपयोग से संबंधित है और संभावित रूप से इसमें डेटा, डेटाबेस अनुप्रयोग या संग्रहीत फ़ंक्शन, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सर्वर और संबंधित नेटवर्क लिंक शामिल हैं जो उनकी गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता के साथ समझौता किए बिना काम करते हैं। इसमें तकनीकी, प्रक्रियात्मक/प्रशासनिक और भौतिक जैसे विभिन्न प्रकार या श्रेणियों के नियंत्रण शामिल हैं। डेटाबेस सुरक्षा कंप्यूटर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के व्यापक दायरे में एक विशेष विषय है।

13.2 उद्देश्य:

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी आसानी से सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए तंत्र को सक्रिय बनाने के पीछे के वास्तविक उद्देश्य की जांच कर सकेंगे, जो सुनिश्चित करने की पहली आवश्यकता है:

1. अधिकृत डेटाबेस उपयोगकर्ताओं, डेटाबेस प्रशासकों, या नेटवर्क/सिस्टम प्रबंधकों, या अनधिकृत उपयोगकर्ताओं या हैकर्स द्वारा अनधिकृत या अनपेक्षित गतिविधि या दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा।
2. अमान्य डेटा या कमांड की प्रविष्टि, डेटाबेस या सिस्टम प्रशासन प्रक्रियाओं में गलतियों, तोड़फोड़/आपराधिक क्षति आदि के कारण होने वाले डेटा भ्रष्टाचार और/या हानि के विरुद्ध सुरक्षा।

3. अनधिकृत पहुंच जैसी घटनाओं को जन्म देने वाले मैलवेयर संक्रमणों से सुरक्षा।
4. डेटाबेस और संबंधित प्रोग्रामों और प्रणालियों में डिज़ाइन दोषों और प्रोग्रामिंग बगों के विरुद्ध सुरक्षा, जो विभिन्न सुरक्षा कमजोरियाँ पैदा करते हैं।

13.3 डेटाबेस की सुरक्षा

फ़ायरवॉल और नेटवर्क-आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियों जैसे नेटवर्क सुरक्षा उपायों के माध्यम से डेटाबेस को हैकर्स के खिलाफ़ काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा गया है। जबकि नेटवर्क सुरक्षा नियंत्रण इस संबंध में मूल्यवान बने हुए हैं, डेटाबेस सिस्टम को सुरक्षित करना और उनके भीतर मौजूद प्रोग्राम/फ़ंक्शन और डेटा, यकीनन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि नेटवर्क तेजी से व्यापक पहुँच के लिए खुल रहे हैं, विशेष रूप से इंटरनेट से पहुँच। इसके अलावा, सिस्टम, प्रोग्राम, फ़ंक्शन और डेटा एक्सेस नियंत्रण, संबंधित उपयोगकर्ता पहचान, प्रमाणीकरण और अधिकार प्रबंधन फ़ंक्शन के साथ, हमेशा अधिकृत उपयोगकर्ताओं और प्रशासकों की गतिविधियों को सीमित करने और कुछ मामलों में लॉग करने के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। दूसरे शब्दों में, ये डेटाबेस सुरक्षा के पूरक दृष्टिकोण हैं, जो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर दोनों तरह से काम करते हैं।

13.4 डेटाबेस का अर्थ

डेटाबेस एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। अपने सबसे सामान्य रूप में, यह स्वतंत्र घटकों का एक संग्रह है, जैसे कि सूचना, डेटा या कार्य के टुकड़े, जो व्यवस्थित या विधिवत तरीके से व्यवस्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से व्यक्तिगत रूप से सुलभ होते हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में डेटाबेस या कंप्यूटर डेटाबेस शब्द से जुड़े कोई विशिष्ट अर्थ नहीं हैं। डेटाबेस सहित संकलन को साहित्यिक कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है।

हालाँकि, कॉपीराइट, डिज़ाइन और पेटेंट अधिनियम, 1988 (सीडीपीए) (यूके अधिनियम) डेटाबेस को इस प्रकार परिभाषित करता है:

स्वतंत्र कार्यों, डेटा या अन्य सामग्रियों का संग्रह जो:

- (ए) व्यवस्थित या विधिवत तरीके से व्यवस्थित हैं; और
- (बी) इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से व्यक्तिगत रूप से सुलभ हैं।

अमेरिकी कॉपीराइट कार्यालय ने कहा है कि "कॉपीराइट कानून की शब्दावली में, डेटाबेस एक संकलन है:

पहले से मौजूद सामग्रियों या डेटा के संग्रह और संयोजन से बना कार्य...।"

इसके अलावा, डेटाबेस को डेटाबेस के कानूनी संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश के अनुच्छेद 1(2) में स्वतंत्र कार्यों, डेटा या अन्य सामग्रियों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें व्यवस्थित या विधिवत तरीके से व्यवस्थित किया गया है और जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से व्यक्तिगत रूप से एक्सेस किया जा सकता है। डेटाबेस विनियमों में एक समान परिभाषा निहित है। इस परिभाषा में महत्वपूर्ण तत्व "स्वतंत्र कार्यों, डेटा या अन्य सामग्रियों", "व्यवस्थित या विधिवत" तरीके से व्यवस्थित करने और 'इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से व्यक्तिगत पहुंच' के संदर्भ हैं। डेटाबेस सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस पर लागू होती है।

इसलिए, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें अस्पष्टताएँ हैं और डेटाबेस की अवधारणा को हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं समझा जाता है। इस अस्पष्टता का तात्पर्य है कि इस बात पर बहस की गुंजाइश है कि डेटाबेस की सुरक्षा के सर्वोत्तम साधन क्या हैं।

डेटाबेस संरक्षण के बारे में वर्तमान बहस को बस इसी के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है

संकलनों के लिए कॉपीराइट सुरक्षा के दो परस्पर विरोधी मॉडलों के बीच ऐतिहासिक टकराव। पहला मॉडल इस बात की वकालत करता है कि डेटाबेस और तथ्यात्मक संकलन को अपने आप में सुरक्षा मिलती है, यानी रचनात्मकता या मूल लेखकत्व के किसी भी प्रदर्शन के बिना। इस सिद्धांत के समर्थक, जिन्हें "पसीने की मेहनत" या "मेहनती संग्रह" सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, यह तर्क देकर अपनी स्थिति को उचित ठहराते हैं कि डेटाबेस में निहित तथ्यों और सूचनाओं को संकलित करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत और निवेश के लिए पुरस्कार के रूप में डेटाबेस को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा पुरस्कार संकलनकर्ताओं को नए डेटाबेस विकसित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस सिद्धांत के तहत, सुरक्षा संकलन में निहित अन्यथा असुरक्षित तथ्यों तक फैली हुई है।

बौद्धिक संपदा का दूसरा मॉडल इस धारणा को खारिज करता है कि बिना किसी मौलिकता या रचनात्मकता के डेटाबेस को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके बजाय, दूसरे मॉडल के अधिवक्ता केवल डेटाबेस में निहित "अभिव्यक्ति" के लिए कॉपीराइट संरक्षण का विस्तार करेंगे, जो डेटाबेस में तथ्यों के मूल चयन, समन्वय या व्यवस्था तक सीमित है - लेकिन स्वयं तथ्यों तक नहीं।

13.5 डेटाबेस सुरक्षा की आवश्यकता

डेटाबेस सामग्री का उपयोगी संग्रह है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सामग्री के कई आइटमों से स्वतंत्र रूप से मूल्य होता है। वे अक्सर रचनात्मक होते हैं, और आमतौर पर संकलन, प्रस्तुतीकरण और रखरखाव के लिए महंगे होते हैं। सूचना समाज में, उनका आर्थिक महत्व बढ़ता जा रहा है।

जो लोग डेटाबेस बनाते हैं, और जो लोग उसके विकास और रखरखाव में निवेश करते हैं, वे अपने निवेश पर उचित लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एक बार डेटाबेस बन जाने के बाद, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने पर भी इससे वित्तीय लाभ प्राप्त करना कठिन हो सकता है, यदि अव्यावहारिक नहीं, जब तक कि डेटाबेस में किसी प्रकार के संपत्ति अधिकार को मान्यता न दी गई हो।

एक दृष्टिकोण यह है कि डेटाबेस लेना और डेटा को फिर से व्यवस्थित करना, कुछ नया बनाता है और यह मूल डेटाबेस कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। वैकल्पिक दृष्टिकोण यह है कि आजकल डेटाबेस में डेटा किसी विशेष क्रम में कंप्यूटर मेमोरी में नहीं रखा जाता है, और केवल पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए पहला दृष्टिकोण मूल डेटाबेस का उल्लंघन दर्शाता है।

एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि यदि संकलन या डेटाबेस में जाने वाली व्यक्तिगत वस्तुओं के चयन में कोई कौशल नहीं था और यदि व्यवस्था में कोई कौशल नहीं है (कीवर्ड या अनुक्रमण शब्दों को नहीं जोड़ा गया है, केवल एक सूची बनाई गई है), तो ऐसे संकलन को कॉपीराइट का औचित्य नहीं देना चाहिए।

संरक्षण.18

डेटाबेस निर्माता नए अधिकार के लिए अपनी मांग को विशुद्ध रूप से आर्थिक आधार पर रखते हैं, बौद्धिक संपदा के मौजूदा रूपों के विपरीत जो रचनात्मकता को बढ़ावा देने या यूरोपीय परंपरा में "नैतिक अधिकारों" पर दार्शनिक रूप से आधारित हैं। एक लेखक रचनात्मक कार्य पर कॉपीराइट बनाए रखने की कोशिश करता है, भले ही उसे इसके लिए कोई पारिश्रमिक न मिले (जैसा कि इस लेख के मामले में है) बस इसलिए कि अन्य लोग इसे बदल न दें और इसे विकृत रूप में न भेजें।

लेकिन डेटाबेस निर्माताओं को इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लोग उनके संग्रह से प्राप्त तथ्यों का उपयोग कैसे करते हैं, जब तक कि निर्माताओं के बाजार को खतरा न हो।

"अनुचित प्रतिस्पर्धा" और "दुरुपयोग" के सिद्धांतों का उपयोग लंबे समय से डेटाबेस निर्माताओं को, वस्तुओं और सेवाओं के अन्य प्रदाताओं की तरह, प्रतिस्पर्धियों के हाथों व्यापार खोने से बचाने के लिए किया जाता रहा है, जो मूल कार्य को पुनः प्रकाशित करके "मुफ्त सवार" बन जाते हैं।

निर्माता को अधिग्रहण करने में इतना लंबा समय लगा है।

जबकि मुद्रित संकलन हमेशा कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित रहे हैं, कंप्यूटर डेटाबेस की सुरक्षा हाल ही में हुई है। सभी कॉपीराइट कानूनों की तरह, डेटाबेस पर कॉपीराइट केवल मूल कार्यों की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, अधिकांश मामलों में केवल डेटाबेस का लेआउट ही संरक्षित होता है, न कि अंतर्निहित डेटा। फिस्ट पब्लिकेशन्स बनाम रूरल टेलीफोन सर्विस से पहले, सामान्य प्रथा यह थी कि अदालतें डेटाबेस मालिकों को यह तर्क देने की अनुमति देती थीं कि उनके प्रयास - "पसीने की मेहनत" से - डेटाबेस और उसके डेटा को कॉपीराइट के तहत संरक्षित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। हालाँकि, फिस्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तथ्यों के संग्रह को केवल "पतली" सुरक्षा दी जा सकती है, यानी, केवल डेटाबेस की व्यवस्था को संरक्षित किया जाएगा। अंतर्निहित डेटा सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा होगा यदि नया नहीं है क्योंकि केवल मूल स्रोत ही कॉपीराइट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं - "केवल वे लोग जो मानव ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उन्हें जो कुछ भी उन्होंने जोड़ा है, उस पर एक विशेष अधिकार प्राप्त हो सकता है।"

कई वैज्ञानिक क्षेत्रों और इन क्षेत्रों की सेवा करने वाले डेटाबेस के लिए समस्या यह है कि वे केवल तथ्यों के संकलन से संबंधित हैं। डेटाबेस के मालिक, अपने अधिकारों के बारे में अनिश्चित, अपने निवेश को प्रतिस्पर्धियों से बचाने के प्रयास में लंबे और जटिल लाइसेंस बनाते हैं। शिक्षा जगत, जो अपने अधिकारों के बारे में भी अनिश्चित है, लंबी और जटिल बातचीत के साथ जवाब देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे अनुचित स्थिति में नहीं फंसाया जा रहा है। इसके अलावा, वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण डेटाबेस के कई मालिक व्यापार रहस्य कानूनों की पूर्ण सुरक्षा में पीछे हट जाते हैं, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान में और बाधा आती है।

13.6 कॉपीराइट कानून और डेटाबेस निर्देश

यूरोपीय संघ ने डेटा में बौद्धिक संपदा के लिए सामंजस्य स्थापित करने और उसे अधिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने प्रयासों में, EU डेटाबेस निर्देश पारित किया, जिसने डेटाबेस के भीतर की जानकारी को एक नए सुई जेनेरिस अधिकार के तहत संरक्षित करने की अनुमति दी। सैद्धांतिक स्तर पर, सामान्य रूप से कॉपीराइट बनाम विशेष रूप से डेटाबेस के कॉपीराइटिंग (एक सुई जेनेरिस शासन के रूप में) के कारणों को देखना उचित होगा। सामान्य रूप से कॉपीराइट कानून का अंतर्निहित तर्क रचनात्मक कार्यों के निर्माण को बढ़ावा देना रहा है। जबकि कॉपीराइट कानून के पीछे का विचार लोगों को उनके उत्पाद पर एकाधिकार प्रदान करके रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है, डेटाबेस को सुई जेनेरिस सुरक्षा प्रदान करने के पीछे का विचार "वास्तविक" संपत्ति अधिकार (लॉकियन अर्थ में) के समान है। इसलिए, हम पाते हैं कि डेटाबेस सुरक्षा के पीछे तर्क यह है कि जानकारी को "स्वयं संपत्ति" के रूप में माना जाता है, सामान्य रूप से कॉपीराइट के विपरीत, जहां इसे "उद्देश्य के साथ संपत्ति" तक सीमित किया जाता है। पारंपरिक कॉपीराइट कानून के तहत, बौद्धिक संपदा का अधिकार प्रकृति में उद्देश्यपूर्ण था, जिसका अर्थ है कि सांस्कृतिक उत्पादन के साथ "संपत्ति" शब्द का जुड़ाव समाज के सदस्यों द्वारा उत्पादित कार्यों को संरक्षण प्रदान करने के लिए महज एक कल्पना थी।

13.7 डेटाबेस की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

तीन मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो विशेष रूप से संग्रह या संकलन से संबंधित हैं जो परिणामस्वरूप डेटाबेस पर प्रभाव डालते हैं। वे हैं बर्न कन्वेंशन, ट्रिप्स और कॉपीराइट संधि।

13.7.1 बर्न कन्वेंशन

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [196]

साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन (बर्न कन्वेंशन) साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संकलन के लिए काफी कम सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 2(5) साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संग्रह के बजाय सूचना के संग्रह तक सीमित है, जहाँ सूचना के अलग-अलग टुकड़े कॉपीराइट सुरक्षा के हकदार नहीं थे। बर्न कन्वेंशन इसके द्वारा शासित कार्यों को सूचीबद्ध करता है और चूँकि डेटाबेस का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसे या तो “संग्रह” या “साहित्यिक और कलात्मक कार्यों” के रूप में सूची में शामिल किया जा सकता है।

13.7.2 यात्राएं

ट्रिप्स ने डेटाबेस का संदर्भ दिया और उनकी सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा तैयार की। इसका सूत्र डेटाबेस सुरक्षा से संबंधित मुख्य विवादों को सारांशित करता है और हल करता है, इस मौलिक दृष्टिकोण का उपयोग करके कि डेटाबेस में कॉपीराइट इसकी सामग्री के बजाय इसकी संरचना से संबंधित है। यह संकलन का तरीका है जो संरक्षित है, न कि विचाराधीन सामग्री, जिसे विचाराधीन डेटाबेस बनाने के लिए इकट्ठा किया जाता है।

13.7.3 कॉपीराइट संधि

इस संधि के तहत संरक्षण इस शर्त पर है कि संग्रह का चयन या व्यवस्था इस तरह से की जाए कि वह बौद्धिक सृजन का गठन करे। कॉपीराइट संरक्षण से संबंधित अधिक सामान्य प्रावधान भी हैं जो डेटाबेस के कानूनी संरक्षण पर प्रभाव डालते हैं। ये प्रावधान कॉपीराइट सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रसार, सुई जेनेरेस संरक्षण, विनिर्माण, आयात और वितरण पर प्रतिबंध और उन उपकरणों के उपयोग से संबंधित हैं जिनका उपयोग अनुबंध करने वाले पक्षों में सुरक्षा के तकनीकी उपायों को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है, कॉपीराइट संरक्षण के अधीन डेटाबेस के मालिकों को प्रबंधन सूचना के अधिकारों के लिए सुरक्षा प्रदान करना आदि।

13.8 डेटाबेस निर्देश

13.8 .1 संकलन में कॉपीराइट

यह निर्देश संकलन में कॉपीराइट की इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करता है। निर्देश में ही डेटाबेस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसका अर्थ है स्वतंत्र कार्यों, डेटा या अन्य सामग्रियों का संग्रह जो व्यवस्थित तरीके से या पद्धतिगत तरीके से व्यवस्थित किया गया हो और जिसे इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से व्यक्तिगत रूप से एक्सेस किया जा सके।³⁶ यह डेटाबेस में कॉपीराइट की भी अनुमति देता है (इसकी सामग्री से अलग) लेकिन केवल व्यक्तिगत बौद्धिक रचनात्मकता से जुड़े लेखकत्व के आधार पर।

जहां तक सामान्य कानून वाले देशों का सवाल है, यह एक नई सीमा है।

निर्णय जो कुछ अर्थों में लेखक का अपना है, उसे या तो विषय-वस्तु चुनने या व्यवस्था की विधि में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक चयनात्मक शब्दकोश वर्गीकृत टेलीफोन शब्दकोश की तुलना में कॉपीराइट के लिए एक स्पष्ट मामला होगा।

जहाँ यह कॉपीराइट उत्पन्न होता है, यह लेखक का अधिकार है। तदनुसार यह जीवन भर के लिए और 70 वर्षों तक चलेगा; इसलिए कुछ युवा लोगों को प्रोडक्शन टीम में होना चाहिए। लेखक का अधिकार बर्न कन्वेंशन के तहत अमेरिकियों और राष्ट्रीय उपचार के हकदार अन्य लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

यह अधिकार नकल और इसी प्रकार की गतिविधियों, तथा सार्वजनिक संचार और इसी प्रकार के कदमों की एक व्यापक सूची को कवर करता है।

13.8.2 डेटाबेस अधिकार

कॉपीराइट सुरक्षा के अलावा, डेटाबेस के निर्माता (इसे आरंभ करने वाले निवेशक) को डेटाबेस की सामग्री को निकालने या पुनः उपयोग करने के विरुद्ध एक अलग स्वि जेनेरिस अधिकार दिया जाता है। इस संबंध में पाँच बिंदु महत्वपूर्ण हैं:

1. यह अधिकार डेटाबेस पर लागू होता है, चाहे उनकी व्यवस्था कॉपीराइट को उचित ठहराती हो या नहीं और व्यक्तिगत वस्तुओं में कॉपीराइट के संबंध में स्थिति चाहे जो भी हो।
सामग्री.
2. संगठनात्मक संरचना के बजाय विषय-वस्तु पर ध्यान देने का उद्देश्य एक अधिकार प्रदान करना है, जहाँ विषय-वस्तु को पूरी तरह से या काफी हद तक निकाल कर (आमतौर पर कंप्यूटर द्वारा) पुनर्व्यवस्थित किया गया है, ताकि मूल रूप से समान सामग्री को एक बिल्कुल अलग संगठन प्रदान किया जा सके - एक ऐसा पुनर्गठन जो मूल व्यवस्था में कॉपीराइट के उल्लंघन के बराबर नहीं होगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सामग्री की संरचनात्मक व्यवस्था की प्रासंगिकता को कम करके आंका जाए।
3. डेटाबेस को पर्याप्त निवेश का उत्पाद होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह केवल एक साधारण संगीत सीडी पर एकत्रित विभिन्न कार्यों से मिलकर नहीं बन सकता। कुछ यूरोपीय राज्यों में, पहले निर्णय लिए गए थे कि किसी समाचार पत्र या पत्रिका के निरंतर अंकों से लेख, समाचार आइटम या विज्ञापनों की वेबसाइट फ़ाइलें डेटाबेस का गठन करेंगी। यह प्रश्न अब इस मुद्दे से जुड़ गया है कि क्या डेटाबेस की व्याख्या करने से अलग सूचना सामग्री बनाने में निवेश किया गया है।
4. यह अधिकार सामग्री के संपूर्ण या पर्याप्त भाग के "निष्कर्षण" और/या "पुनः उपयोग" की रक्षा करता है, जिसका मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ "निष्कर्षण" का अर्थ है किसी भी माध्यम या रूप से किसी अन्य माध्यम में सामग्री का स्थायी या अस्थायी हस्तांतरण; और "पुनः उपयोग" का अर्थ है किसी भी माध्यम से सामग्री को जनता के लिए उपलब्ध कराना।

यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डेटाबेस के अपर्याप्त भागों को निरस्त और व्यवस्थित रूप से निकालना उल्लंघन जारी रख सकता है।
5. यह अधिकार डेटाबेस के पूरा होने से 15 साल तक या 15 साल की अवधि के दौरान जनता के लिए उपलब्ध होने से 15 साल तक रहता है। हालाँकि, जोड़ने, हटाने या बदलाव करने में आगे पर्याप्त निवेश करने से समय फिर से शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एक जीवित डेटाबेस में अनिश्चित सुरक्षा होती है, ठीक वैसे ही जैसे संशोधित सामग्री वाले नियमित संस्करणों से कॉपीराइट पाठ्यपुस्तक में होती है।

ये समझौते सुरक्षा के न्यूनतम मानक प्रदान करते हैं। अलग-अलग राष्ट्र उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, यूरोपीय संघ के निर्देश का प्रभाव डेटाबेस के लिए कॉपीराइट सुरक्षा को ट्रिप्स और कॉपीराइट में निर्धारित स्तर तक मानकीकृत करना रहा है।

संधि.

13.5 सारांश

फ़ायरवॉल और नेटवर्क-आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियों जैसे नेटवर्क सुरक्षा उपायों के माध्यम से डेटाबेस को हैकर्स के खिलाफ़ काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा गया है। जबकि नेटवर्क सुरक्षा नियंत्रण इस संबंध में मूल्यवान बने हुए हैं, डेटाबेस सिस्टम को सुरक्षित करना और उनके भीतर मौजूद प्रोग्राम/फ़ंक्शन और डेटा, यकीनन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि नेटवर्क तेजी से व्यापक पहुँच के लिए खुल रहे हैं, विशेष रूप से इंटरनेट से पहुँच। यूरोपीय संघ, बौद्धिक संपदा के लिए सामंजस्य स्थापित करने और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने प्रयासों में

डेटा, यूरोपीय संघ डेटाबेस निर्देश पारित किया, जिसने डेटाबेस के भीतर की जानकारी को एक नए सुई जेनेरिस अधिकार के तहत संरक्षित करने की अनुमति दी। सैद्धांतिक स्तर पर, सामान्य रूप से कॉपीराइट के कारणों बनाम विशेष रूप से डेटाबेस के कॉपीराइटिंग (एक सुई जेनेरिस शासन के रूप में) को देखना उचित होगा।

13.10 शब्दावली

1. ट्रिप्स: बौद्धिक अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू
2. डेटाबेस: यह स्वतंत्र घटकों का संग्रह है, जैसे सूचना, डेटा या कार्य के टुकड़े, जो व्यवस्थित या विधिवत तरीके से व्यवस्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से व्यक्तिगत रूप से सुलभ होते हैं।

13.11 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न:

(क) डेटाबेस से आप क्या समझते हैं?

(ख) बर्न कन्वेंशन पर संक्षेप में चर्चा करें।

2. रिक्त स्थान भरें:

(क) सामान्यतः कॉपीराइट कानून का अंतर्निहित तर्क निर्माण को बढ़ावा देना रहा है

का

(ख) ने डाटाबेस का उल्लेख किया और उनकी सुरक्षा के लिए एक ढांचा स्थापित किया।

3 सत्य और असत्य

(क) डेटाबेस सामग्रियों का उपयोगी संग्रह है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी विषय-वस्तु के अनेक मर्दों से स्वतंत्र रूप से मूल्य होता है।

(i) सत्य (ii) असत्य

(ख) डेटाबेस संरक्षण का उद्देश्य अनधिकृत पहुंच जैसी घटनाओं को जन्म देने वाले मैलवेयर संक्रमणों से सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

(i) सत्य (ii) असत्य

13.12 संदर्भ/ग्रंथसूची

1. मनुपत्र

2. चार्ल्स ब्रिल, तथ्यों के संग्रह का कानूनी संरक्षण, 1 कंप्यूटर कानून समीक्षा

& टेक्नोलॉजी जर्नल 2 (वसंत 1998)

3. धारा 2(o), भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957

4. धारा 3ए, कॉपीराइट, डिजाइन और पेटेंट अधिनियम, 1988 (सीडीपीए) (जैसा कि संशोधित किया गया है)

विनियम)

5. <http://www.unc.edu/courses/2006spring/law/357c/001/projects/dougf/node1.html>

6. परिषद निर्देश 96/9, 11 मार्च, 1996 OJ (L 77) 20 (EC) (29 जनवरी, 2011) [http://europa.eu.int/ISPO/](http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/legreg/docs/969ec.html)

infosoc/legreg/docs/969ec.html ; डब्ल्यू.के. खोंग, डेटाबेस में कॉपीराइट और अधिकारों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकास। 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Database_security.

13. 13 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न (क) डेटाबेस की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा करें? (ख) डेटाबेस की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट कानूनों की क्या भूमिका है?

13.14 उत्तर

1. (क) 13. 4 (ख) 13.8.1 2. (क)

रचनात्मक कार्य 3. (क) सत्य

(ख) ट्रिप्स (ख)

सत्य

अंतिम प्रश्नों के उत्तर (ए) 13.7 देखें (बी) 13.6 देखें

इकाई-14

डेटाबेस पर भारतीय कानून

14.1 परिचय

14.2 उद्देश्य

14.3 भारतीय परिदृश्य में संरक्षण

14.4 सारांश

14.5 शब्दावली:

14.6 संदर्भ/ग्रंथसूची

14.7 सुझाए गए पठन सामग्री

14.8 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न

14.9 उत्तर

14.10 अंतिम प्रश्नों के उत्तर

14.1 परिचय

डेटा संरक्षण गोपनीयता कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं के समूह को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण और प्रसार के कारण किसी की गोपनीयता में घुसपैठ को कम करना है। व्यक्तिगत डेटा आम तौर पर उस सूचना या डेटा को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति से संबंधित होता है जिसे उस सूचना या डेटा से पहचाना जा सकता है चाहे वह किसी सरकार या किसी निजी संगठन या एजेंसी द्वारा एकत्र किया गया हो।

भारत का संविधान निजता के मौलिक अधिकार को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, न्यायालयों ने निजता के अधिकार को अन्य मौजूदा मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया है, जैसे कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हालाँकि, भारत के संविधान के तहत ये मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत दिए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं जिन्हें राज्य द्वारा लगाया जा सकता है। हाल ही में, न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के ऐतिहासिक मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन एक मौलिक अधिकार माना है।

भारत में वर्तमान में डेटा संरक्षण या गोपनीयता को नियंत्रित करने वाला कोई स्पष्ट कानून नहीं है।

हालाँकि, भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित प्रासंगिक कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और (भारतीय) अनुबंध अधिनियम, 1872 हैं। निकट भविष्य में भारत में डेटा संरक्षण के विषय पर एक संहिताबद्ध कानून पेश किए जाने की संभावना है।

14.2 उद्देश्य

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [201]

हालाँकि इस दुनिया ने हमारी जीवन शैली को सरल बना दिया है, लेकिन इसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ विसंगतियाँ छोड़ दीं, जिसके परिणामस्वरूप डेटा का अनैच्छिक प्रकटीकरण हुआ। इसका विश्लेषण इन उदाहरणों से किया जा सकता है:

1. साइबर कैफे में ई-मेल खाते में हर बार लॉगइन करने पर पासवर्ड का इलेक्ट्रॉनिक निशान असुरक्षित रूप से वहीं रह जाता था।
2. खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड के प्रत्येक उपयोग पर ब्रांड की पसंद, खरीदारी का स्थान आदि का निशान पीछे छूट जाता है।
3. इंटरनेट पर प्रत्येक लॉगिन पर एक इलेक्ट्रॉनिक निशान छोड़ दिया जाता है, जिससे वेबसाइट मालिकों और विज्ञापन कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की पसंद और वरीयताओं तक पहुंचने में मदद मिलती है।
4. कर्मचारियों पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि नियोक्ता नियमित रूप से कर्मचारियों के ई-मेल और उनके काम की जानकारी प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं।
5. पुलिस के फोन कॉल सिग्नल को नक्सली आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, जिससे उन्हें पुलिस की योजनाओं के बारे में पता चल जाता है।
6. सोर्स कोड की चोरी बदमाशों का सबसे पसंदीदा कार्य है।
7. अनचाहे ई-मेल के माध्यम से भी उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना एक सामान्य प्रक्रिया है।
8. कुकीज़ लगाकर वेब पर गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है और फिर उन्हें इस तरह से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है जिससे उपयोगकर्ता की रुचि, खर्च करने की आदतों और जीवनशैली का विस्तृत विवरण तैयार किया जा सके।
9. हैकिंग के जरिए हैकर्स किसी के भी अकाउंट में मनमाने तरीके से बदलाव कर सकते हैं।

इस प्रकार यह आसानी से बताया जा सकता है कि हम बदमाशों को उनके कृत्यों को बढ़ाने और सरल बनाने के लिए कितनी आसानी से जगह दे रहे हैं और डिजिटल दुनिया की सेवाओं का लाभ उठाना कितना सुरक्षित है।

14.3 भारतीय परिदृश्य में संरक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत डेटाबेस संरक्षण

1999 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर मॉडल कानून (एमएलईसी) और सिंगापुर और मलेशिया जैसे एशियाई देशों में उल्लेखनीय विकास के कारण, भारत ने 13 मई, 2000 को इंटरनेट के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना शुरू किया और अंततः इसे पारित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई, 2000 तक संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को मंजूरी दे दी। इस अधिनियम को 9 जून, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के रूप में राष्ट्रपति की स्वीकृति डिजिटल गतिविधियों को विनियमित करना है। हालाँकि अधिनियम के तहत डेटाबेस सुरक्षा मिली। भारत का लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के माध्यम से सभी प्रदान की गई है जो काफी सीमित है।

डेटा संरक्षण से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की झलकियां:

एसआर	वर्ग	प्रावधान अंतर्गत जानकारी
		प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
1.	43	<p>यह धारा एक करोड़ तक का भारी जुर्माना लगाकर कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत पहुंच के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। डेटा की अनधिकृत डाउनलोडिंग, निष्कर्षण और प्रतिलिपि बनाना भी इसी दंड के अंतर्गत आता है।</p> <p>इस धारा का खंड 'सी' कंप्यूटर वायरस या दूषित पदार्थों के अनधिकृत प्रवेश के लिए दंड लगाता है। खंड 'जी' अनधिकृत पहुंच में सहायता करने के लिए दंड प्रदान करता है।</p>
2.	65	<p>इस धारा में कंप्यूटर सोर्स कोड के बारे में प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या जानबूझकर किसी को ऐसा करने के लिए कहता है, नष्ट करता है, बदलता है या किसी और को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे 2 लाख रुपये तक की कैद या जुर्माना भुगतान पड़ सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर सोर्स दस्तावेजों से छेड़छाड़ के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है।</p>
3.	66	<p>इस धारा के तहत हैकिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है। इस धारा के अनुसार हैकिंग को किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य माना जाता है या यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाई जाएगी और कंप्यूटर संसाधन में मौजूद जानकारी को या तो नष्ट कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए, बदल दिया जाना चाहिए या उसका मूल्य और उपयोगिता कम हो जानी चाहिए। इस धारा के तहत हैकर को तीन साल की कैद या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जाता है।</p>
4.	70	<p>यह धारा संरक्षित प्रणाली में संग्रहीत डेटा को सुरक्षा प्रदान करती है। संरक्षित प्रणाली वे कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क हैं जिनके लिए उपयुक्त सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में राजपत्र सूचना जारी करके इसे संरक्षित प्रणाली घोषित किया है। इस धारा के प्रावधान का उल्लंघन करके उस प्रणाली तक पहुँच या पहुँच को सुरक्षित करने का कोई भी प्रयास करने पर उस व्यक्ति को कारावास की सज़ा दी जा सकती है जो दस साल तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।</p>
5.	72	<p>यह धारा डेटा की गोपनीयता और निजता के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे आईटी अधिनियम और संबद्ध नियमों के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना दस्तावेज या अन्य सामग्री तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं, अगर वह इसे किसी अन्य व्यक्ति को बताता है, तो उसे दो साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।</p>

14.3.1 अनुबंध का कानून

इन दिनों कंपनियाँ अपनी जानकारी की सुरक्षा के लिए अनुबंध कानून पर एक उपयोगी साधन के रूप में भरोसा कर रही हैं। कॉर्पोरेट घराने अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए अन्य कंपनियों, ग्राहकों, एजेंसियों या भागीदारों के साथ कई समझौते करते हैं, ताकि वे इसे सुरक्षित रख सकें। 'गैर-परिहार और गैर-प्रकटीकरण' समझौते, 'उपयोगकर्ता लाइसेंस' समझौते, 'रेफ़रल पार्टनर' समझौते आदि जैसे समझौते वे करते हैं, जिनमें गोपनीयता और निजता खंड शामिल होते हैं और विवाद उत्पन्न होने पर उसे सुलझाने के उद्देश्य से मध्यस्थता खंड भी होते हैं। ये समझौते उन्हें व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। बीपीओ कंपनियों ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन के बीएस 7799 और आईएसओ 17799 मानकों जैसी प्रक्रियाओं को लागू किया है, जो बीपीओ और कॉल सेंटर के कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जा सकने वाले डेटा की मात्रा को सीमित करते हैं।

14.3.2 भारतीय दंड संहिता

यह उन गलतियों के लिए दंड का प्रावधान करता है, जो पिछले दशक तक होने की उम्मीद थी। लेकिन यह डेटा से संबंधित अपराधों के लिए दंड को अपने में शामिल करने में विफल रहा, जो कि दिन-प्रतिदिन की प्रक्रिया बन गई है।

14.3.3 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2006

विदेशी कानूनों के आधार पर, यह विधेयक 8 दिसंबर 2006 को राज्य सभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा और सूचना को किसी संगठन द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित करने की सुरक्षा प्रदान करना, तथा किसी अन्य संगठन द्वारा वाणिज्यिक या अन्य उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को रोकना और व्यक्ति को किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा या सूचना को उसकी सहमति के बिना प्रकट करने के कारण क्षतिपूर्ति या क्षति का दावा करने का अधिकार देना तथा अधिनियम से संबंधित या अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए क्षतिपूर्ति या क्षति का दावा करने का अधिकार देना है। इस अधिनियम में निहित प्रावधान विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले डेटा की प्रकृति और उस उद्देश्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले डेटा की मात्रा से संबंधित हैं। प्रस्तावित अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामलों को देखने के लिए डेटा नियंत्रकों की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है।

14.4 सारांश

भारतीय कानून की तुलना विकसित देशों के कानून से करने पर भारतीय कानून की उचित आवश्यकता का विश्लेषण किया जा सकता है। डेटा की उपयोगिता और महत्व एक समान नहीं होते हैं; उपयोगिता के आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसलिए हमें अलग-अलग उपयोगिता मूल्यों वाले डेटा की अलग-अलग श्रेणियां बनाने की आवश्यकता है, जैसा कि अमेरिका ने किया है। इसके अलावा आईटी अधिनियम के प्रावधान मूल रूप से डेटा निकालने, डेटा को नष्ट करने आदि से संबंधित हैं। कंपनियों को इसके माध्यम से डेटा की पूरी सुरक्षा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उन्हें अंततः अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग निजी अनुबंध करने पड़ते हैं। इन अनुबंधों की प्रवर्तनीयता सामान्य अनुबंध के समान ही होती है।

14.5 शब्दावली:

एमएलईसी: इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर मॉडल कानून

आईटी: सूचना प्रौद्योगिकी

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [204]

1. SAQS a)

डेटा संरक्षण का क्या अर्थ है?

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया?

2. रिक्त स्थान भरें:

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से गोपनीयता को का अधिकार नहीं देता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने को मौलिक अधिकार माना है।

4. सत्य और असत्य:

1. भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार उचित प्रावधानों के अधीन हैं प्रतिबंध।

अ) सत्य ब) असत्य

2. भारत में डेटा संरक्षण विषय पर एक संहिताबद्ध कानून है।

अ) सत्य ब) असत्य

14.6 संदर्भ/ग्रंथसूची

1. मनुपत्र

2. <http://www.legalserviceindia.com/article/I37-Data-Protection-Law-in-India.html>

3. बीएचबी बनाम डब्ल्यूएम हिल, [2004] ईसीआर I-1045, ईसीजे

4. इंदिरा कैर, भारत साइबर-रेस में शामिल: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, 6 (4)
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और विनियमन 122 (2000)

5. श्याम लाल पहाड़िया बनाम गया प्रसाद गुप्ता रसाल, एआईआर 1971 सभी 58; गंगाविष्णु श्रीकिसनदास वि.

6. मोरेश्वर बापूजी हेगिश्ते, आईएलआर 13 (बोम.) 358, 363 (1889); बर्लिंगटन होम शॉपिंग प्रा. लिमिटेड

7. ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम देसाई, एआईआर 2001 दिल्ली 185।

14.7 सुझाए गए पठन सामग्री

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

2. अनुच्छेद 10(2), बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता (अनुलग्नक 1सी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए मारकेश समझौता) (अप्रैल, 15, 1994), 33 आईएलएम 81 (1994); अनुच्छेद 2(5), साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन (24 जुलाई, 1971), (संशोधित 28 सितंबर, 1979)।

3. प्रवीण दलाल, भारत में डेटा संरक्षण कानून

4. एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉज़, साइबर लॉ के डिप्लोमा कोर्स पर अध्ययन सामग्री

14.8 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न

1. भारत में डेटा संरक्षण कानूनों की प्रभावशीलता की व्याख्या करें।

2. डेटा संरक्षण से निपटने में आईटी अधिनियम की क्या भूमिका है?

14.9 उत्तर

1. SAQS (ए) व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता 2. (ए) मौलिक (बी) 2000

अधिकार 3. (1) सत्य (2) असत्य (ख) निजता का अधिकार

14.10 अंतिम प्रश्नों के उत्तर

बौद्धिक संपदा मुद्दे और साइबरस्पेस-भारतीय परिप्रेक्ष्य सीवाईसी (एसईसी) 102 [205]

(1) संदर्भित 14.3 (2) संदर्भित 14.3